"जनपद झाँसी (उ०प्र०) की जनसंख्या : एक भौगोलिक अध्ययन"

"Population of District Jhansi [U. P.] : A Geographical Study"

भूगोल विषय में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की
पी-एच० डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

२००२

निर्देशक :

डॉ० कृष्ण कुमार मिश्र

रीडर, भूगोल विभाग

अतर्रा पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज

अतर्रा (बाँदा)

शोधकर्त्ता :

सूर्यकान्त

शोध छात्र, भूगोल विभाग

अतर्रा पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज

अतर्रा (बाँदा)
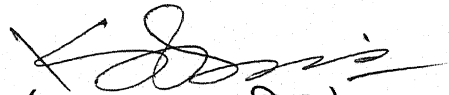
डॉ० कृष्ण कुमार मिश्र
रीडर, भूगोल विभाग
अतर्रा पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज,
अतर्रा (बाँदा), उ०प्र०

निवास :
14/127, ब्रह्मनगर,
अतर्रा (210201) बाँदा,
उ.प्र.
☎ - 05191-47573

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सूर्यकान्त द्वारा मेरे निर्देशन में *'जनपद झाँसी (उ. प्र.) की जनसंख्या : एक भौगोलिक अध्ययन'* शीर्षक पर भूगोल विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु अध्यादेश - 7 के अन्तर्गत उल्लिखित समय में कार्य पूर्ण किया गया है।

यह जनसंख्या के भौगोलिक अध्ययन पर आधारित एक मौलिक शोध प्रबन्ध है, जो मेरे निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में पूर्ण लगन व निष्ठा के साथ सम्पन्न किया गया है।

(कृष्ण कुमार मिश्र)
शोध निदेशक

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध श्रद्धेय गुरुवर डा० कृष्ण कुमार मिश्र, रीडर, भूगोल विभाग, अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यायल अतर्रा (बाँदा) के निरन्तर प्रोत्साहन एवं अहर्निश उपलब्ध निर्देशन से पूर्ण होकर इस रूप में प्रस्तुत हो सका हैं। आपका मार्ग दर्शन, प्रेरणा एव आशीर्वचन मेरें समाजिक एवं नैतिक जीवन में एक अक्षुण पूँजी के रूप में है, जिसका शब्दो सें बखान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से बड़ा ही अमूल्य समय निकाल कर तर्क–विवेचन के माध्यम से शोध को व्यवस्थित ढंग से नियोजित कर यह रूप प्रदान किया। अतः मैं ऐसे मौलिक विचारक एवं महा विद्वान के प्रति सच्चे हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिक़ोहाबाद के पूर्व विभागध्यक्ष स्व० डॉ० एस० क्यू० ए० रिज्वी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिनकी सतत् प्रेरणा से मैं इस स्तर तक पहुँच सका हूँ। मैं शोधकेन्द्र अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ–साथ परास्नातक भूगोल के द्वय छात्रों श्री दिनेश कुमार कुशवाहा तथा श्री राकेश कुमार विश्वकर्मा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य में मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

मैं श्रद्धेया श्रीमती कुसुम मिश्रा एवं उनके मेधावी बच्चों पीयूष, प्रत्यूष, कु० प्रियंवदा तथा पुत्रवधू श्रीमती आराध्या के प्रति भी अपनी स्नेहिल कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे सदैव सद्प्रेरणा व सहयोग प्रदान किया।
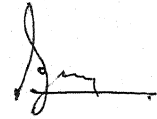
मैं अपने पूज्य पिता श्री रनवीर सिंह तथा पूज्यनीया माता श्रीमती कमलादेवी

एवं समस्त परिवारिक सदस्यों का हृदय से आभारी हूँ जिनके आर्शीवचन एवं प्रेरणा से मेरा यह शोधकार्य पूर्ण हो सका है।

मैं अपनी सुहृदया एवं मृदुलभाषी अर्धागिंनी श्रीमती निर्मला एवं प्रिय पुत्री कु० आकांक्षा तथा स्नेहिल पुत्र दिव्यांशू का भी आभारी हूँ जिन्होंने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इस कार्य को पूर्ण करने में पग–पग पर सहयोग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह कार्य समय से पूर्ण हो सका।

अन्त में मैं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय के सभी सहयोगियों विशेषतया श्री आशापति शास्त्री, श्री महेशमणि एवं अजय मणि, श्री अशोक कुमार, श्री देवनारायन तथा श्री राजकुमार के प्रति आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने लेजर कम्पोजिंग एवं बाइडिंग निर्माण में सहयोग दिया। फलतः यह शोध प्रबन्ध समय से तैयार हो सका।

दिनांक – 20.11.2002

(सूर्यकान्त)

विषय– सूची

अध्याय – 4

111 – 137

जनसंख्या का स्थानिक प्रतिरूप, स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या का स्थानिक वितरण, जनसंख्या घनत्व, आंकिक घनत्व, कार्यिक धनत्व, कृषिगत घनत्व, पोषण घनत्व, नगरीकरण, नगरीकरण का इतिहास, विकास प्रवृत्ति, नगरीकरण की मात्रा।

अध्याय – 5

138 – 174

जनसंख्या संरचना –

लिंग–अनुपात, आयु संरचना, जनसंख्या का संरचनात्मक अनुपात, आयुदर सूचकांक, निर्भरता अनुपात, साक्षरता प्रतिरूप, धार्मिक प्रतिरूप, व्यावसायिक प्रतिरूप, कार्यरत जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप।

अध्याय – 6

175 – 205

जनसंख्या नीति –

जनसंख्या नीति की आवश्यकता, जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन, जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति का मूल्यांकन, बेरोजगारी, बेरोजगारी के अनुमान, ग्रामीण बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, रोजगार नीति, परिवार नियोजन।

सारिणी – सूची

सारिणी		पृष्ठ संख्या

List of Illustrations

अध्याय - १

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

किसी भी प्रदेश का सांस्कृतिक भूदृश्य वहाँ के मानवीय क्रियाओं का प्रतिफल होता है। यह केवल मनुष्य है जो संसाधनों का नियामक व मानव कल्याण हेतु उनका उपयोग करता है। इस प्रकार विविध क्षेत्रों में क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप मनुष्य स्वयं किसी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं। भारत जैसे विकासोन्मुख देश में जहां प्रादेशिक स्तर पर मानव जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि हो रही है, जनसंख्या सम्बन्धी भौगोलिक अनुसन्धान का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

वस्तुतः वर्तमान समय में नाभिकीय युद्ध, अत्यधिक जनसंख्या दबाव तथा अमीर–गरीब की खाई ऐसे मुद्दे हैं जो मानवीय सभ्यता के सम्मुख महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उपस्थित है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्र की समस्याओं के सिलसिलेवार विवरण के साथ–साथ तार्किक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाय। यद्यपि इन समस्याओं से छुटकारा पाने के प्रयास में विश्व स्तर पर किसी न किसी रूप में नीति निर्माता एवं शिक्षाविदों द्वारा एकैडिमिक बहस जारी हैं लेकिन अभी तक क्षेत्रीय विकास की समस्याओं के समाधान हेतु कोई सार्वभौमिक संकल्पना विकसित नहीं की जा सकी हैं।

5025 वर्ग किमी० में विस्तृत झाँसी जनपद वर्तमान शोध समस्या के परीक्षण के लिए चयनित किया गया है। यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसका पिछड़ापन यहाँ की भौगोलिक विषमताओं के साथ–साथ मुख्यतः यहाँ की जनसंख्यात्मक विशेषताओं पर भी आधारित हैं। जनसंख्या की वृद्धि एवं घनत्व में स्थानिक एवं सामयिक स्तर पर पर्याप्त विषमताएं उपलब्ध हैं जिसके परिणामस्वरूप यहाँ पर प्रादेशिक–आर्थिक असन्तुलन विद्यमान हैं। यही कारण है कि यहाँ पर समान रूप से

मानव का विकास नहीं हो सका हैं।

इस क्षेत्र की अधिकांश क्रियाशील जनसंख्या का संकेन्द्रण वस्तुतः गुरसराय, मऊरानीपुर तथा झाँसी तहसीलों में हैं। इन कारणों से इस प्रकार के शोध अध्ययनों का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। क्षेत्र में संसाधनों की सम्भावनाएं अधिक हैं किन्तु इन संसाधनों के उपयोग का स्तर अत्यन्त न्यून है। इसीलिये यह क्षेत्र निर्धनता एवं पिछड़ेपन से ग्रसित है। इन्हीं सब वजहों से इस जनपद के जनसंख्या भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययन की महती आवश्यकता है।

झाँसी सम्भाग के अन्य जनपदों की अपेक्षा झांसी जिले में शहरीकरण की प्रवृत्तियां कुछ अधिक तेजी से प्रस्फुटित हुयी हैं। झाँसी शहर जिला मुख्यालय होने के साथ–साथ सम्भागीय मुख्यालय भी है। यहाँ रेलवे तथा सेना के भी काफी बड़े प्रशासनिक तथा उत्पादक प्रतिष्ठान कार्यरत है। इस कारण यहाँ की स्थानिक जनसंख्या में से यहां कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा भाग कार्यरत है। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर तक की सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज स्थित हैं। यही कारण है कि यह शहर बहु प्रान्तीय, बहुभाषीय तथा बहुसंस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हैं। यातायात के क्षेत्र में देश के चारों दिशाओं से रेल एवं राष्ट्रीय सड़क मार्गो से सम्बद्ध है। यहाँ पर लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर के औद्योगिक प्रतिष्ठान भी कार्यरत हैं।

उपर्युक्त कारणों से इस जिले की जनांककीय प्रवृत्तियां बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य जिलों से भिन्न है। अस्तु उपर्युक्त तथ्यों के विषय में प्रभाविता के अध्ययन हेतु झांसी जनपद को शोध हेतु चयनित किया गया है।

साहित्य सिंहावलोकन (Review of Literature)

वस्तुतः यह कहना बहुत कठिन है कि विश्व में जनसंख्या अध्ययन की शुरूआत

कब हुयी लेकिन विविध तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जनसंख्या अध्ययन उतना ही प्राचीन है जितना जनसंख्या सम्बन्धी ज्ञान की जिज्ञासा मानव को उसके अस्तित्व काल से रही होगी क्योंकि मानव समाज के प्रारम्भिक समय से ही जानांकिकी के विषय क्षेत्र का अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है। भले ही इसे विशिष्ट विज्ञान का दर्जा हांसिल न हो सका हो। अध्ययन बताता है कि ईशा पूर्व 480 में यूनान तथा ईशा पूर्व 435 में रोम में जनगणना की गयी थी। भारत में रामायण तथा महाभारत काल में जनगणना के उल्लेख मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अबुलफजल के 'आइने अकबरी' में भी जनगणना के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है।

यद्यपि जनसंख्या सम्बन्धी तमाम विखरे विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने में जान ग्राण्ट (1662), थामस रावर्ट माल्थस (1796), खशिले गुइलार्ड (1885), अल्फ्रेड लोटका, हेलपटन, वाडलेपर्ल आदि विभिन्न विषय–विशेषज्ञों एवं विचारकों ने अहम भूमिका निभाई, परन्तु भूगोलवेत्ताओं ने जनसंख्या को अपने अध्ययन क्षेत्र का आधार कब बनाया, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। वस्तुतः भौगोलिक अध्ययन में जिस प्रकार स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, कृषि भूमि उपयोग आदि तत्वों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है, वास्तव में इस प्रकार जनसंख्या भूगोल का अध्ययन नही हुआ। चांदना एवं सिद्दू (1980) ने भी यह माना कि भूगोलवेत्ताओं ने यद्यपि जनसंख्या वितरण एवं उसके स्वरूप को नाना रूपों में व्यक्त किया है फिर भी भूगोल में मानव के स्थान को निर्धारित करने में भूगोलविदों के ही विवाद का वर्णन मिलता हैं।

वस्तुतः प्रारम्भिक भूगोल वेत्ताओं द्वारा मानव ज्ञान तथा कौशल की अपेक्षा प्राकृतिक वातावरण–तत्वों को अत्यधिक प्रभावशाली माना गया फलस्वरूप भूगोलवेत्ताओं का ध्यान सर्वप्रथम प्राकृतिक वातावरण के तत्वों की ओर ही आकर्षित हुआ, यद्यपि

यह विचारधारा मानव के सन्दर्भ में अधिक अर्थपूर्ण मानी गयी (क्लार्क 1972) प्रौद्योगिकी के विकास के साथ–साथ भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों की दिशा में भी अध्ययन प्रारम्भ हुये फलतः तभी से भूगोल में मानव का अध्ययन एक कारक के रूप में किया जाने लगा। मानव एवं उसके चतुर्दिक व्याप्त प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धों के अध्ययन से इस तथ्य को बल मिला कि मानव भौगोलिक पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, जो प्राकृतिक संसाधनों का विकास व उपयोग करता है तथा मानव वातावरण का सृजन करता है; प्राकृतिक वातावरण जिसमें मानव क्रियाशील रहता है तथा जिसके संसाधनों का उपयोग करता है; मानवीय वातावरण जोकि मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण एवं संसाधनों के उपयोग का प्रतिफल होता है (ट्रिवार्था 1953)।

जनसंख्या तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं पर भूगोलविदों द्वारा प्रकाशित अनेक शोधपत्रों की संख्या में क्रमागत वृद्धि से जनसंख्या भूगोल के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता का बोध होता है तथा भूगोल के एक सामाजिक विज्ञान होने की पुष्टि भी होती है। भूगोल की विविध शाखाओं में जनसंख्या भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिलाने व सम्मान जनक स्थिति तक पहुॅचाने में (ट्रिवार्था 1953) का योगदान सराहनीय है। इनके द्वारा अमेरिकी भूगोलविद् परिषद की बैठक में प्रस्तुत अध्यक्षीय भाषण विषय का एक मात्र स्पष्ट विवेचन कहा जा सकता है। जिसमें इन्होंने जनसंख्या भूगोल के लिए ठोस तार्किक एवं आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया। जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करते हुये (ट्रिवार्था १९५१) ने बताया कि भूतल पर बसे लोगों की प्रादेशिक विभिन्नता सम्बन्धी ज्ञान में ही जनसंख्या भूगोल के तत्व समाहित है। इनका अभिमत है कि मानव भौतिक भूदृश्य का उपभोगकर्ता और सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माणकर्ता है। इनके अनुसार मनुष्य की संख्या घनत्व और गुण समस्त भूगोल के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करता

है तथा जनसंख्या ही एक ऐसा सन्दर्भबिन्दु है जिससे वे सभी अलग अलग और सामूहिक रूप से महत्व तथा अर्थ प्राप्त करते हैं। लगभग इसी समय से जनसंख्या भूगोल सम्बन्धी कार्यों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही दृष्टिकोणों से आशातीत वृद्धि हुयी है। आज विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इसे सम्मिलित किया जा चुका है तथा अध्ययन का प्रमुख अंग है।

वस्तुतः जनसंख्या भूगोल, भूगोल विषय की एक नवोदित शाखा है जिसे एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यद्यपि भूगोलवेता लम्बे समय से जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में रूचि लेते रहे है तथापि एक प्रथक विषय के रूप में जनसंख्या भूगोल का विकास द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ही दृष्टिगत होता है (हान्सेन एवं कोसिन्की, 1973)।

प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता जेलिन्स्की (1962,1966) के अनुसार जनसंख्या भूगोलविद् जनसंख्या के स्थानिक पक्ष का स्थल की समुच्चयिक प्रकृति के सन्दर्भ में वर्णन करते हैं। अर्थात् जनसंख्या भूगोल वह विज्ञान हैं जो उन विधियों का विश्लेषण करता है जिससे किसी स्थल की भौगोलिक विशेषताएं निर्मित होती हैं तथा जिसके प्रतिक्रियास्वरूप जनसंख्या तत्व की उत्पत्ति होती है। विभिन्न तत्वगत अन्योन्यक्रिया एवं उनके पृथक व्यवहारगत नियम के परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थान तथा समय के सन्दर्भ में परिवर्तित होती रहती है। जेलिन्स्की द्वारा प्रस्तुत यह परिभाषा सर्वाधिक तर्कसंगत प्रतीत होती है। इसमें तीन तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है : मनुष्यों की संख्या एवं विशेषताओं की स्थिति का सामान्य वर्णन; इन संख्याओं तथा विशेषताओं की प्रादेशिक विभिन्नता की व्याख्या तथा जनसंख्या तत्व का भौगोलिक विशलेषण। इनका विचार है कि जनसंख्या भूगोल का अध्ययन उन विशेषताओं तक सीमित रखना चाहिए जिनके विषय में विकसित देशों द्वारा आंकड़े इकट्ठे किये जाते है। डेम्को (1970) ने जनसंख्या भूगोल की सीमा

विकसित देशो की जनगणना की अनुसूची में सम्मिलित विशेषताओं तक सीमित रखने की बुद्धिमतापर सन्देह जाहिर किया क्योकि जनगणना अनुसूची में सम्मिलित विशेषताओं में भिन्न–भिन्न देशों में अन्तर विद्यमान है जबकि चांदना एवं सिद्दू (1980) का मानना है कि यद्यपि जेलिन्स्की के दृष्टिकोण में कुछ व्यावहारिकता अवश्य है लेकिन किसी भी विषय का सीमांकन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सीमित करना सिद्धान्तः उचित नहीं है।

गार्नियर (1966) का मत है कि वर्तमान वातावरण के सन्दर्भ में जनसंख्या भूगोल जनांककीय तथ्यों का वर्णन प्रस्तुत करता है जिसमें उनके कारणों, आधारभूत गुणों तथा सम्भावित गुणों के अध्ययन की भी महती आवश्यकता है। इनके अनुसार जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन तीन अभिमुखों पर आधारित है : भूमि तथा मानव का वितरण; भूतल पर मानव समाज की उत्पत्ति; भूतल पर मानव की सफलता का स्तर।

क्लार्क (1972) का विचार है कि जनसंख्या भूगोल का सम्बन्ध इस बात के प्रदर्शन में होता हैं कि जनसंख्या के वितरण, संघटन, प्रवास तथा वृद्धि में प्रादेशिक विविधताएं भूक्षेत्र की प्राकृतिक विभिन्नताओं से किस प्रकार सम्बन्धित हैं। क्लार्क ने पुनः जनसंख्या भूगोल के सन्दर्भ में बताया कि यह भूगोल जनसंख्या में प्रादेशिक अन्तरों की उनके भौतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भ में जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करता है।

डेम्को (1970) के अनुसार जनसंख्या भूगोल में जनसांख्यकीय विशेषताओं के प्रादेशिक वितरण का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही इसमें प्रादेशिक दशाओं की पारस्परिक क्रिया–प्रतिक्रिया से उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिफलों का भी अध्ययन किया जाता है।

वस्तुतः जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें प्रमुखतया मानव को केन्द्रीय स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल वह उपशाखा है जो मानव जनसंख्या के जनांककीय व अजनांककीय गुणों में पायी जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नता तथा किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न दशाओं के पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धों से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिफलों का अध्ययन करता है।

जनसंख्या भूगोल की उपरोक्त पाश्चात्य विचारधारा रूसी भूगोलवेत्ताओं की विचारधारा से मेल नहीं खाती। इनका विचार है कि जनसंख्या का उत्पादक पक्ष ही जनसंख्या वितरण हेतु उत्तरदायी हैं। यही कारण है कि रूसी भूगोलविदों ने जनसंख्या भूगोल को आर्थिक भूगोल की सीमा के अन्तर्गत स्थान दिया। रूसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुये मेलेजिन (1963) ने स्पष्ट किया कि जनंसख्या भूगोल जनसंख्या वितरण और विभिन्न जनसंख्या समूहों के मध्य पाये जाने वाले उत्पादक अन्तर्सम्बन्ध अधिवासीय तन्त्र की समाज के उत्पादक उद्देश्य हेतु उपयुक्तता तथा प्रभावशीलता का अध्ययन है। इसलिए कावलेव (1959) ने जनसंख्या के भौगोलिक अध्ययन का अभिज्ञान मानव बस्तियों वाले क्षेत्रों की आर्थिक कार्यकारिता के आधार पर करने की वकालत की है।

नोराफेडरिक (1993) आदि विद्वानों ने महिलाओं की स्थिति एवं जनसंख्या परिवर्तन पर विचार प्रस्तुत किया। ओवर मियर (1997), कर्तजर (1997) ने जनसंख्या के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधियों पर प्रकाश डाला। सैसिमों (1999), स्टीफेन एवं उनके साथियों (1997), शरलॉक (1997), वाटर लो एवं उनके सहयोगियों (1990), ब्रोकरहोफ एंव उनके साथियों (1998), ने जनसंख्या के विभिन्न पक्षों, जनांककीय समस्याओं एवं विकासशील देशों में बेतहासा बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न निर्धनता पर अपने विचार व्यक्त किये। इसके अतिरिक्त पीटर्स एवं लारकिन (1997), यूनीसेफ

(1998), शस्चुट्ज (1998), मेक्नीकॉल (1998), फिलमर (1999), वीडीन एवं उनके साथियों (1997), क्लार्क एवं उनके साथियों (1998), कारोलिन एवं ब्लेडशो आदि (1999), ज्लोटानिक (1998), ह्यूगर एवं उनके साथियों (1998), ने जनसंख्या भूगोल के विभिन्न आयामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के साथ–साथ जनसंख्या एवं वातावरण, स्थानान्तरण एवं अन्य विविध समस्याओं पर प्रकाश डाला। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने जनसंख्या भूगोल के विभिन्न पक्षों यथा- जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, विकास एवं स्थानान्तरण, आयु लिंग अनुपात, साक्षरता, कार्यात्मक संरचना, नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या के बदलते स्वरूप, जनसंख्या एवं संसाधन, परिवार नियोजन, जनसंख्या समस्या, नीति एवं नियोजन आदि पर प्रकाश डाला है।

सम्भवतः भारत में जनसंख्या भूगोल के अन्तर्गत क्रमबद्धरूप से अनुसन्धान कार्य सन् 1956 में गोसल द्वारा ट्विार्था के निर्देशन में प्रारम्भ हुआ। गोसल ने भारत वर्ष की जनसंख्या के सभी महत्वपूर्ण पक्षों यथा– वितरण वृद्धि, स्थानान्तरण, लिंग अनुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, नगरीकरण आदि का अध्ययन किया। जनसंख्या भूगोल पर गोसल द्वारा किये गये अध्ययन से प्रभावित होकर एस० पी० चटर्जी ने भारत की जनसंख्या का मानचित्रण विविध पक्षों के आधार पर किया। के० एस० अहमद ने संम्पूर्ण देश के सन्दर्भ में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले घटको का विश्लेषण किया। सन् 1947 में आर० एल० सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की विवेचना की गयी।

गोसल एवं चांदना (1979) ने जनसंख्या भूगोल पर एक विधितन्त्रात्मक लेख प्रस्तुत किया। गोसल (1984) ने भारतवर्ष में जनसंख्या भूगोल एवं जनसंख्या के उपागमों एवं उनके प्रयोग पर विद्वतापूर्ण लेख प्रकाशित किया जो आगामी शोधछात्रों के लिए शोध का आधार प्रस्तुत करता हैं।

जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन में गोसल द्वारा अपनायी गई विधा का अनुशरण करते हुये गोपाल कृष्णन (1968) ने पंजाब के सीमावर्ती जनपदों अमृतसर एवं गुरुदासपुर के जनांककीय गुणों में परिवर्तन पर शोधग्रन्थ प्रस्तुत किया। यह एक बहुत विस्तृत अध्ययन एवं कार्य था जो कि प्रत्येक गांव से प्राप्त आंकड़ो द्वारा तैयार किये गये मानचित्रों पर आधारित था। इसी से मिलता–जुलता कार्य दिल्ली केन्द्र शासित राज्य के सीमावर्ती हरियाणा जनपद पर चांदना (1969), व पंजाब के बिस्ट दोआब पर स्वर्नजीत मेहता (1970), द्वारा प्रस्तुत किया गया। चांदना एवं राजबाला (1979), ने भारतीय जिला मुख्यालयों की जनांककीय विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

यह सच है कि भारतीय पत्रिकाओं में मुख्यतः जनसंख्या के वितरण एवं विकास तथा घनत्व पर अनेक शोधपत्र प्रकाशित हुये लेकिन अभी भी जनसंख्या के अन्य पक्षों यथा– उचित दर, स्थानान्तरण, लिंग अनुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, नगरीकरण आदि पर भौगोलिक अध्ययनों की कमी हैं।

हालांकि जनसंख्या संसाधन सम्बन्धों के अध्ययन में विषय के महत्वपूर्ण विकास के सम्बन्ध में रूचि बढ़ी है जिसका श्रेय जनसंख्या भूगोल पर अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक संध द्वारा प्रायोजित 'भौतिक एवं सामाजिक संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव' विषय पर सम्पन्न संगोष्ठी को जाता है। गोसल (1970) ने इस संगोष्ठी में पंजाब में जनसंख्यात्मक गतिशीलता एवं संसाधनों पर बढ़ते हुये दबाव पर एक महत्वपूर्ण शोधपत्र पस्तुत किया। इन्होंने देश को गतिशील, भावी एवं समस्याग्रस्त प्रदेशों में विभक्त किया। नाथ (1970) ने प्राकृतिक संसाधनों एवं आर्थिक विकास के सन्दर्भ में भारत की जनसंख्या पर अध्ययन प्रस्तुत किया। इसके अलावा कृष्णगोपाल ने उत्तर–प्रदेश में जनसंख्या दबाव की समस्याओं पर अध्ययन किया। इस अध्ययन में इन्होंने जनसंख्या दबाव की मात्रा को मापने के लिए एक तकनीकि विकसित की जो विकासशील क्षेत्रों में प्रयोग की जा सकती हैं।

चांदना (1971) ने जनसंख्यात्मक विशेषताओं के आधार पर प्रोदेशीकरण पर एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखते हुये ग्राम स्तरीय आंकड़ों का प्रयोग किया तथा हरियाणा के रोहतक, गुडगांव क्षेत्र को जनसंख्या प्रदेशों में विभाजित किया। जनसंख्या प्रदेश देश में आर्थिक विकास के नियोजन के लिए महत्वूपर्ण प्रकाश डालते हैं।

चादंना एवं सिद्दू (1980) के अनुसार जनसंख्या भूगोल का सम्बन्ध अधोलिखित तथ्यों से हैं।

(1) जनसांख्यकीय विशेषताओं की प्रादेशिक तथा सामयिक व्याख्या करना।

(2) जनसंख्या के विभिन्न प्रादेशिक तथा सामयिक अभिव्यक्तियों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना।

(3) जनसंख्या सम्बन्धी विभिन्न प्रादेशिक तथा सामयिक दशाओं को उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं का अभिज्ञान एवं विश्लेषण।

वस्तुतः जनसंख्या के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में अनेक शोध कार्य हुये जो इस दिशा में संलग्न शोधकताओं को एक नवीन दिशा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग जनसंख्या भूगोल के अनुसन्धान का प्रमुख केन्द्र बन गया है। चांदना (1994) द्वारा भारत वर्ष की जनसंख्या का मान चित्रों के माध्यन से प्रदर्शन एक सराहनीय कार्य है। इसके अलावा अनेक भारतीय भूगोलवेताओं यथा–भट्ट (1961), कृष्ण गोपाल (1971,1974, 1977, 1978), अग्रवाल (1977), भिण्डे एवं कनित्कर (1983), कायस्थ एवं सिंह (1978), सिंह (1977), राय (1973), रेड्डी (1976), फनीभूषन रॉय (1979), ओमप्रकाश (1973), सिंह (1977), तिवारी (1978), वर्मा (1992), सिंह (1992), यादव (1994), दिवाकर (1994), मिश्र (1989) महादेवन एवं कृष्णन (1993),

लाल (1993), जोशी (१६६६), जमाली (1998), आदि द्वारा जनसंख्या के विभिन्न पक्षों पर प्रस्तुत अध्ययन सराहनीय हैं।

संक्षेप में जनसंख्या–संसाधन सन्तुलन के अध्ययनों की महत्ता पर जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं में सचेतता बढ़ी है किन्तु प्रादेशिक एवं स्थानिक स्तर पर इस प्रकार के अध्ययनों की महती आवश्यकता है। भारत सरकार के कुछ विभाग यथा– केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली, अन्तराष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, मुम्बई, ग्रामीण स्वास्थ्य एंव परिवार नियोजन संस्थान, गांधी ग्राम आदि मुख्य है, जो जनसंख्या एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित अध्ययन में संलग्न हैं।

उद्देश्य (Aims) :–

इस शोध परियोजना का प्रमुख उद्देश्य झाँसी जनपद की जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत करना है। राष्ट्र एवं प्रादेशिक स्तर पर तीव्र गति से बढ़ती हुयी जनसंख्या की आवश्यकताओं की उचित पूर्ति के लिये क्षेत्रीय स्तर पर जनसंख्या के भौगोलिक विश्लेषण की महती आवश्यकता है। मुख्यतः शोध परियोजना से सम्बन्धित उद्देश्य निम्न लिखित हैं–

(1) जनपद झॉसी की प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अवस्थापना सुविधाओं का विस्तृत अध्ययन करना।

(2) जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारको का अध्ययन करना।

(3) जनसंख्या वृद्धि की स्थानिक एवं सामयिक विविधताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करना।

(4) मात्रा एवं गुण के सन्दर्भ में झॉसी जनपद की जनसंख्या का मूल्याकंन करना।

(5) मानव तथा संसाधन से सम्बन्धित सिद्धान्तों का परीक्षण करना।

(6) जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करना।

(7) जनसंख्या नीति की समीक्षात्मक विवेचना करना तथा बेरोजगारी और परिवार नियोजन कायक्रम का विश्लेषण करना।

(8) अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या प्रक्षेपण का निर्धारण करना।

(9) झाँसी जनपद में जनसंख्या की समस्याओं पर प्रकाश डालना।

(10) जनसंख्या के सन्तुलित विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना।

मुख्य परिकल्पनाएं (Major Hypotheses) –

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंख्या के विविध आयामों के अध्ययन के समय जिन मुख्य परिकल्पनाओं का निरीक्षण किया गया है वे निम्नलिखित हैं–

(1) जनसंख्या का वितरण भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है।

(2) जनसंख्या वृद्धिदर एवं लिंग अनुपात प्रतिलोमतः सहसम्बन्धित हैं।

(3) ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय समीपता द्वारा प्रभावित नहीं होता।

(4) आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर तथा प्रजननता में विपरीत सम्बन्ध होता है।

(5) नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा प्रजनन दर कम होती है।

(6) जनसंख्या घनत्व एवं सिंचित क्षेत्र के अनुपात के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है।

(7) जनसंख्या का घनत्व एंव कृषित भूमि का अनुपात प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं।

(8) नगरीय केन्द्रों के समीप स्थित गांवो में साक्षरता का प्रतिशत अधिक पाया जाता हैं।

(9) साक्षरता की उच्चतरदर पुरूष साक्षरता के उच्चतर दर को प्रदर्शित करती है।

(10) साक्षरता का उच्चतर स्तर महिला साक्षरता के उच्चतर स्तर को प्रदर्शित करेगा।

(11) परिवार नियोजन कार्यक्रम पर जातीयता, शिक्षा एवं आयु स्तर का प्रभाव परिलक्षित होता हैं।

(12) वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का तार्किक ढाचां ही अविकसित कृषिगत समाज की जनसंख्या समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता है।

विधितन्त्र (Methodology)

प्रस्तुत शोध परियोजना के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। शासन एंव व्यक्तिगत संगठनों की प्रकाशित एवं अप्रकाशित पत्रावलियों का प्रयोग भी इस शोध परियोजना के अन्तर्गत किया गया है। जनपद गजेटियर, विभिन्न दशकों की जनगणना पुस्तिकाएं (1901-1981) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र व जनगणना कार्यालय से प्राप्त आंकड़े (1991), उ० प्र० जनरल पापुलेशन टेबुल्स, ग्राम्य नगर निदर्शनी (1901-1981), जिला सांख्यकीय पत्रिकाएं, जिला स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनाएं, वार्षिक योजना पत्रिकाएं नगरपालिकाएं तथा नगर क्षेत्र समितियों की पत्रावलियां, विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचनाओं इत्यादि का प्रयोग द्वितीयक आंकड़ो को एकत्र करने में किया जाता हैं। विषय से सम्बन्धित पूर्ववर्ती अध्ययनों की जानकारी हेतु प्रकाशित भौगोलिक शोध प्रबन्धों एवं पुस्तकों की सहायता भी ली गयी हैं।

वर्तमान समय में जनसंख्या में वृद्धि एक गम्भीर समस्या है। इस समस्या का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश की मानव जाति से हैं। इस गम्भीरतम समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नीति के रूप में परिवार नियोजन को महत्व प्रदान किया जा रहा हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि के कारणों, प्रजननता, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति लोगों

के दृष्टिकोण को जानने व बेरोजगारी की समस्या आदि के प्रेक्षण हेतु प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह क्षेत्रीय कार्य करके पूर्व किया गया। इस हेतु प्रमुखतया साक्षात्कार एवं अवलोकन पद्धति का ही प्रयोग किया गया है। अवलोकन का प्रयोग उत्तरदाताओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए किया गया है। तथ्यों के संकलन के लिए अध्ययन यंत्र के रूप में अनुसूची को चुना गया (परिशिष्ट अ)। चूँकि अध्ययन क्षेत्र की अधिसंख्या जनसंख्या आज भी अशिक्षित एवं ग्राम्य वातावरण में निवास करती हैं इसलिए प्रश्नावली को उपयुक्त न मानकर अनुसूची को ही यंत्र के रूप में प्रयोग किया गया। अनुसूची के निर्माण में सावधानी एवं सतर्कता रखी गयी। अनुसूची निर्माण में शोध प्रतिमान एवं उपकल्पनाओं को ध्यान में रखकर प्रश्नों की रचना की गई। उपकल्पनाओं से सम्बन्धित कारकों के सम्बन्ध में कहीं तो सीधे प्रश्न पूछे गये और कहीं उत्तर को सत्यापित करने के लिए दुबारा प्रश्न पूछे गये हैं। परिवार नियोजन की जानकारी के सम्बन्ध में कई बार उत्तरदाताओं के उत्तरों को सत्यापित करने का प्रयास किया गया है।

अनुसूची में संरक्षित एवं असंरक्षित दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया गया है। अनुसूची के अन्त में उत्तरदाताओं को परिवार नियोजन जैसी अनेक समस्याओं के प्रति अपने सुझाव देने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं।

अध्ययन से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये अनुसूची में मुख्यतः तीनप्रकार के प्रश्न रखे गये।

(1) मुक्त, खुले या असंरचित प्रश्न।

(2) बन्द या रचित प्रश्न।

(3) डायकाटामस

ऐसे प्रश्नों की रचना तीन तथ्यों को ध्यान में रखकर की गई हैं–

(1) आधार सामग्री की सम्पूर्ति करने वाले प्रश्न।

(2) प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले प्रश्न।

(3) उक्त दोनों बातों को प्रमाणित करने वाले प्रश्न।

अनुसूची को तीन भागों में बांटा गया –

(1) प्रारम्भिक भाग, (2) मध्यभाग, (3) अन्तिम भाग।

अनुसूची के प्रारम्भिक भाग में उत्तरदाताओं से प्राथमिक सूचनाएं एकत्र करने का प्रबन्ध किया गया। मध्यभाग में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया जानने हेतु प्रश्न बनाये गये तथा इसी भाग में कहीं कहीं प्राथमिक सूचनाओं की यथार्थता को जानने के लिए प्रश्न किये गये। अन्तिम भाग में उत्तरदाताओं के सामाजिक, धार्मिक परिवेश से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ, मध्य भाग में व्यक्त प्रतिक्रियाओं का प्रमाणीकरण एवं निष्कर्ष हैं।

प्राथमिक आंकड़ों की यथार्थता को बनाये रखने के लिए तथा उत्तरदाता शोधकर्ता को प्रश्नों का उत्तर देने में कोई संकोच व शंका न करें, अस्तु निम्नलिखित को भी मध्यस्थ के रूप में सम्मिलित किया गया–

(1) **औपचारिक नेता** – गाँव का सरपंच, प्रधान, पंच, वार्ड मेम्बर आदि।

(2) **सभ्रान्त नागरिक** – गाँव के सम्मानित लोग जैसे– पुरोहित, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, जातीय मुखिया या गाँव का शिक्षित नवयुवक।

(3) **शासकीय कर्मचारी** – गाँव का लेखपाल, ग्राम्यविकास अधिकारी, शिक्षक, डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्त्ता आदि।

इस शोध परियोजना के क्षेत्रीय कार्य के दौरान कुल 300 उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त किये गये।

शोध विषय से प्राप्त तथ्यों के सारणीयन का समस्त कार्य शोधकर्त्ता द्वारा स्वयं किया गया। उत्तरों से परिपूर्ण अनुसूची की जॉच पूर्णतया क्षेत्र में ही कर ली गई थी। अतः सभी अनुसूचियों को विकास खण्ड स्तर पर बॉट दिया गया और उनके क्रमानुसार रखकर कोडिंग की गई। तत्पश्चात विभिन्न विधियों के आधार पर गणना की गई। मानचित्र आरेख निर्माण हेतु अनेक साख्यिकीय विधियों का सहारा लिया गया ताकि शोध प्ररियोजना को विश्लेषणात्मक स्वरूप प्रदान किया जा सके। इसके अलावा सैद्धान्तिक विश्लेषण हेतु कुछ प्रतिमानों का भी प्रयोग किया गया हैं। आंकड़ों की गणना व सांख्यिकीय विधियों द्वारा प्राप्त परिणामों को ...40.. मानचित्रों व आरेखों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अध्येयीकरण (Organization)

विवेचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या भूगोल का यथोचित विकास हुआ हैं, लेकिन किसी क्षेत्र की जनसंख्या के विविध पक्षों का सम्यक अध्ययन वहॉ के भौतिक पर्यावरण के सन्दर्भ में अपेक्षाकृत कम हुआ हैं। विगत दशकों से बेहद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती के रूप में सामने उपस्थित हैं जिसे सन्तुलित करना वर्तमान की महती आवश्यकता है। झाँसी जनपद को आधारमान कर इस सन्दर्भ में विविध अनुक्रियायें अपनाई गई हैं तथा यथा सम्भव शोध प्रबन्ध में इनका समावेश भी किया गया है। सम्पूर्ण अध्ययन आठ अध्यायों में विभक्त हैं। अन्त में परिशिष्ट एवं सन्दर्भ सूची प्रस्तुत हैं। शोध प्रबन्ध में स्वनिर्मित मानचित्रों व रेखाचित्रों, तालिकाओं व परिशिष्टों के सहयोग से झाँसी जनपद की जनसंख्या के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रथम अध्याय में शोध परियोजना की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए जनसंख्या भूगोल की सैद्धान्तिक संकल्पना तथा पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा किये गये कार्यो का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त शोध परियोजना का

उद्देश्य मुख्य परिकल्पनाओं तथा शोध अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न विधियों एवं तकनीकों के सम्बन्ध में भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं का वर्णन चार समूहों में किया गया है। प्रथम वर्ग अर्थात् भौतिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत क्षेत्र की स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच, भ्वाकृतिक विभाग, जलवायु, प्रवाहतंत्र, मिट्टियों, वन एवं उद्यान का अध्ययन किया गया है। द्वितीय वर्ग अर्थात् आर्थिक पृष्ठभूमि में भूमि उपयोग एवं फसल चक्र, शस्य प्रतिरूप, भूसिंचन, खनिज एवं उद्योग धन्धों की विश्लेषणात्मक व्याख्या की गई हैं। तृतीय वर्ग अर्थात् जनसंख्या एवं अधिवास प्रणाली में जनसंख्या के विविध पक्षों यथा– वितरण एवं घनत्व, साक्षरता, आयु–लिंग अनुपात, व्यावसायिक संरचना तथा ग्रामीण एंव नगर अधिवास तंत्र का अध्ययन किया गया है। अन्तिम वर्ग अर्थात् अवस्थापनाओं के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में प्राप्त विविध संयोजनाओं यथा– यातायात एवं संचार व्यवस्था, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा अन्य विविध सामाजिक सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।

तृतीय अध्याय जनसंख्या वृद्धि एवं आकार से सम्बन्धित हैं। इसके अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि के आधारभूत संघटकों का अनुरेखण किया गया है। इसके अलावा प्रजननता, मृत्युदर एवं स्थानान्तरण जैसे महत्वपूर्ण जनसंख्यात्मक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के विकास को स्पष्ट करते हुये आगामी वर्षो में क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को जानने के लिए जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया हैं ताकि जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भावी योजनाएं बनायी जा सकें और अनियंत्रित रूप से बढ़ रही आबादी को रोकने के लिए उपयुक्त जनसंख्या नीति तैयार की जा सके।

चतुर्थ अध्याय जनसंख्या के स्थानिक प्रतिरूप के सम्बन्ध में व्याख्या करता है।

इस अध्याय में सर्वप्रथम उन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व धार्मिक कारकों को जानने का प्रयास किया गया हैं जो स्थानिक स्तर पर जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। तत्पश्चात् ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व की व्यवस्था की गई हैं। वर्तमान समय में गॉवों की अपेक्षा शहरों का तीव्रता से विस्तार हो रहा हैं। अस्तु इस अध्याय में नगरीकरण की प्रवृत्ति एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

पंचम अध्याय जनसंख्या संरचना से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत जनसंख्या के महत्वपूर्ण पक्ष यथा–आयु लिंग अनुपात प्रतिरूप का विश्लेषण किया गया हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में धार्मिक दृष्टि से जनसंख्या के प्रतिरूप की व्याख्या की गयी हैं। जनसंख्या के अतिमहत्वपूर्ण पक्षों यथा– साक्षरता प्रतिरूप, व्यावसायिक प्रतिरूप तथा निर्भरता प्रतिरूप का परीक्षण भी इस अध्याय में किया गया हैं।

षष्टम अध्याय जनसंख्या नीति से सम्बन्ध रखता है। वस्तुतः भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जनसंख्या अनियन्त्रित रूप से व अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है। भारत का कोई भी क्षेत्र जनसंख्या की इस बाढ़ से अब अछूता नहीं है। इससे आर्थिक विकास के लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं तथा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय लाभांस का भाग सतत् छोटा होता जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकते। अतः अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक उचित जनसंख्या नीति की आश्यकता हैं, जिसकी चर्चा इस अध्याय में की गई हैं। बेरोजगारी एवं परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डाला गया हैं। परिवार नियोजन के प्रति क्षेत्र के निवासियों के दृष्टिकोण का पता लगाने का प्रयास किया गया है। बेरोजगारी को दूर करने व परिवार नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपाय भी सुझाये गये है।

जनसंख्या–संसाधन को अध्याय सप्तम में प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत

जनसंख्या के नियोजित पक्ष को प्रस्तुत किया गया हैं। जनसंख्या से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण पक्षों यथा– अनुकूलतम जनसंख्या जनाधिक्य व कम जनसंख्या, जनसंख्या दबाव, जनसंख्या संसाधन सम्बन्धी सिद्धांत एवं जनसंख्या प्रदेश का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं। इसके अलावा जनसंख्या व संसाधन सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियोजन पर प्रकाश डाला गया है ताकि क्षेत्र के सर्वाङ्गीण विकास के लिए उपयुक्त योजना प्रस्तुत की जा सके।

अन्तिम अर्थात् अष्टम अध्याय में पूर्ववर्ती विचार–विमर्शों के आधार पर सांराश एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

REFERENCES

1. Agarwal, S.N. (1977), India's Population Problem, Mc Graw Hill Publication, Delhi. P. 150.
2. Bhat, L.S. (1961), Population Studies : The Need for Regional Approch; Bombay Geographical Magazine, P. 8 and 9.
3. Bhende, Asha A. and Tara Kanitkar (1983), Principles of Population Studies, Himalaya Publishing House, P. 208.
4. Bidean, Alain, Desjardins, Bertrand and Brignoli, Hector Perez (Eds.)(1997), Infan and Child Mortality in the Past, Oxford : Clarendon Press.
5. Brockerhoff, M. and Brennan. E. (1998), The Poverty of Cities in Developing Regions, Population and Development Review, Vol. 24, No. 1.PP. 74-114.
6. Caroline H. Bledsoe etal (Eds.),(1999) Critical Perspectives on Schooling and Fertility in the Developing World, National Academy Press, Washington, 1999
7. Chandna, R.C. (1969), Changes in the Demographic Character of the Rohtak

and Gurgaon Districts, 1951-61: A Geographical Analysis, Unpublished Ph D. Thesis, Punjab University.

8. Chandna, R.C. (1969), Population Regions-A Case Study of Rohtak and Gurgaon Districts (Haryana), Indian Journal of Regional Science III (2), P. 26-35.

9. Chandna, R.C. and Raj Bala (1979), Demographic Characteristics of Indian Districts Headquarters, 1971, Population Geography, I (182) P.P. 68-90.

10. Chandna, R.C. (1994), India's Population : A Cartographic View, Population Geography Vol. 16, No. 182, P.P. 73-76.

11. Chandna, R.C. and Sidhu, M.S. (1980), Introduction to Population, Geography, Kalyani Publishers, New Delhi.

12. Clarke, John I. (1965), Population Geography, Pergamon Press, Oxford.

13. Clarke, J. and D. Noin (Eds) (1998), Population and Environment in Arid Regions, UNESCO & Parthenon.

14. Demko, G.J.et.al. (1970), Population Geography-A Reader, Mc Graw-Hill, New York.

15. Divakar, Ashok (1994), Impact of Population Growth and Development on Environment : A Review, Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 30, No.2, P. 79-85.

16. Filmer, Deon, Pritchett Hant (1999), The Effect of House hold Wealth on Educational Attainment : Evidence from 35 Countries, Population and Development Review, Newyork, Vol. 25, No. 1, PP. 85-120.

17. Garnier, J.B. (1976), Geography of Population, Longman Group Ltd. London, P. 3.

18. Goldstein, J.R. & Schlag, W. (1999), Longer life and Population Growth,

Population and Development Review, Newyork, Vol. 25, No. 4, PP. 741-748.

19. Gosal, G.S. (1956), A Geographical analysis of Indian population,University of Wisconsin,U.S.A. Unpublished Ph.D. Thesis.

20. Gosal, G.S. and Chandna R.C. (1979), Population Geography, Survey of Research in Geography, 1962-72, New Delhi, PP. 170-176.

21. Gosal G.S. (1984), Population Geography in India, in Geography and Population, Approaches and Applications by Jhon I. Clarke(ed.) Pergamon Press, Oxford, PP. 203-214.

22. Grebenik, E. (1997), On Population Studies : Its Origin and Outlook, Population and Development Review, Vol. 23, No. 3, PP. 575-577.

23. Hansen, J.C. and L.A. Kosinski(1973), Population Geography, I.G.U. Commission on Population Geography, Bergen.

24. Hummer, R.A., Rogers, R.G. and Eberstein I.W. (1998), Sociodemographic Differentials in Adult Mortality : A Review of Analytic Approaches, Population and Development Review, Vol. 24, No. 3, PP. 553-578.

25. Joshi, Hemlata, Demographyic Profile of Banswara-APredominantly Trible District of Rajasthan, Geographical Review of India, Sept.1996,Vol.58 No. 3, PP. 219-230.

26. Kayastha, S.L. and M.B.Singh(1978), The Utilization of Human Resources : A Spatial Analysis of Manufacturing Employment in Eastern Utter Pradesh, National Geographical Journal of india, Vol. 24, Part 3 and 4, PP. 16-22.

27. Kertzer, David I. (1997), Qualitative and Quantitative Approaches to Historical Demography, Population and Development Review, New York, PP. 839-846.

28. Krishan Gopal (1968), Distribution and Density of Population in Orissa, National Geographical Journal of India, Vol.14, PP. 250-257

29. Krishan Gopal (1971), A Measure of Population Pressure in Developing Areas : A Case Study of Uttar Pradesh, Journal of Institute of Economic Geography, vol. 2,(1 and 2), PP. 53-57.

30. Krishan Gopal (1974), Regionalization of India on the Basis of Population Potential of Cities, National Geographical Journal of India, Vol. xx(3), PP. 160-164.

31. Krishan Gopal and Madhav Shyam (1977), Literacy in India, Geographical Review of India, Vol 39, Part 2, PP. 117-125.

32. Krishan Gopal (1978), Impact of Population Growth of Rural Housing, Geographical Review of India, Vol 40, Part 2.

33. Lal H. (1986), Jansankhaya Bhogol (Hindi), Vasundhra Prakashan,Gorakhpur.

34. Mahadevan, Kuttan and Parmeshwara, Krishnan(Eds.), 1993, Methodology for Population Studies and Development, Sage Publications, India.

35. Massimo Livi-Bacci and Gustavo De Santis (Eds.),(1999), Population and Poverty in the Developing World, Oxford, Clarendon Press.

36. Mcnicoll, G. Demeny,Paul (1998), The Reader in Population and Development, Earthscan Publications, Newyork.

37. Mehta, S. (1970), Some Aspects of Changes in the Demographic Character of Bist Doab, 1951-61, Unpublished Ph.D. Thesis, Punjab University.

38. Melezin, A. (1963), Trends and Issues in the Sovet Geography of Population, Annals of Association of American Geographers, June P. 144-160.

39. Misra, K.K. and Pal Ketram (1989), Bundelkhand (Uttar Pradesh)

ke Pramukh Samsayayen avam Badhti Jansankhaya, Paper Presented in the National Seminar, 22-23 December, Sovenier, Atarra P.G. College, Altarra.

40. Newell, C. (1998) Methods and Models in Demography, London, Belhavan.
41. Nora Eederici, Karen Oppenheim Mason and Solvi Sogner (Eds.) (1993), Women's Position and Demographic Change, Oxford Clarendon Press.
42. Obermeyer, C.M. (1997), Qualitative Methods : A key to a Better Understanding of Demographic Behaviour, Population and Development Review, Newyork, Vol. 23. No.4, PP. 813-818.
43. Peterr, G.L. and Larkin, R.P. (1979), Population Geographiphy, Problems, Concepts and Prospects, Kendall/Hunt Iowa.
44. Prakash, Om (1973), Population Geography of Utter Pradesh, Unpublished Ph.D. Thesis, B.H.U.
45. Ray, Phanibhushan (1979), Methods of Describing Growth of Population Geographical Review of India Vol. 4, Part 3.
46. Reddy, N.B.K. (1976), Population Geography : A Review and Appraisal, Population Science, Triputi University.
47. Ray, B.K. (1973), Migration Pattern in Uttar Pradesh : A Geographical Analysis, The Deccan Geographer, Vol. xi, Part 1.
48. Schultz, T. Paul (Ed.), 1998. Economic Geography, Cheltenham, U.K. : Edward Elgar, 2 Vols.
49. Sherlock, Peter Lloyd (1997), Old Age and Urben Poverty in the Developing World : The Shanty Towns of Buenos Aires, Macmillan Press, Newyork.
50. Singh C.P. (1977), Urbanization in the National capital Region, Uttar Bharat Bhogol Patrika, Vol. 13, Part 1& 2.

51. Singh R.L. (1997), Process of Urbanization and Urben Development in Mansoon Asia, National Geographical Socity of India, Research Publication No. 24, Varanasi.

52. Singh D.N. (1992), Population Growth, Environment and Development Geo-Science Journal, Vol.VI, Pt. 1 & 2, PP. 1- 4.

53. Stephen, A. Vosti and Thomas Reardon (Eds.)(1997), Sustainability, Growth and Poverty Allvation : A Policy and Agroecological Perspective, Johns Hopkins University Press.

54. Tiwari, R.C. (1978), Temporal and Spatial Trends of population in the Lower Ganga-Yamuna Doab, National Geographer, Vol.XII, Part 2, PP. 125-142.

55. Trewartha, G.T. (1953), A Case for Population Geography Annals of Association of American Geographers, PP. 71-97.

56. UNICEF (1998), The State of the Worlds Children, Oxford University Press.

57. Verma, D.N. (1992), Population Patterns, The Institute of Geographers, India, Lucknow.

58. Waterlow, J.C., Armstrong, D.G., Fowden, Leslie, and Ralph Riley (eds.) (1998), Feeding a World Population of More than Eight Willian People : A Challange to Science, Oxford University Press.

59. Webb, J.W. (1969), Population Geography in R.U. Cooke and J.H. Johnson (Eds.), Trends in Geography, London, Pergamon Press, PP. 90-99.

60. Woods, Robert (1979), Population Analysis in Geography, Longman, London.

61. Yadav, R.P. & Yadav, R.L. (1994), Pattern of Population Growth,North Bihar, Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 30, No. 2, PP.73-78

62. Zelinski W.B.(1962), A Bibliogripic Guide to Population Geography Research Paper No. 80, Department of Geography, University of Chicago.

63. Zelinski, Wilbur (1966), A Prologue to Population Geography, Prentice Hall N.J.

64. Zlotnik, H. (1998), International Migration 1965-96; An Overview. Population and Development Review, Vol. 24, No. 3, PP. 429-468.

अध्याय - २

प्रादेशिक पृष्ठभूमि (Regional Background)

प्रादेशिक पृष्ठभूमि (Regional Background)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के दक्षिण–पश्चिमी भाग में झाँसी जनपद स्थित हैं। झाँसी मण्डल का यह एक प्रमुख जिला है। झाँसी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगरीय केन्द्र है, जो जनपद मुख्यालय होने के साथ–साथ संभागीय मुख्यालय भी है। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार झाँसी नगर तब प्रकाश में आय जब 1613 ई० में ओरछा के बुन्देला नरेश बीरसिंह देव ने वर्तमान झाँसी के बीचोबीच स्थित बंगरा पहाड़ी में एक किला बनवाया। एक बार ओरछा नरेश अपने मित्र जैतपुर नरेश के साथ महल की छत पर बैठे हुए थे। तभी ओरछा नरेश ने अपने मित्र से इस नये किले के नामकरण के विषय में विचारविमर्श किया। जैतपुर नरेश ने वहीं से बंगरा पहाड़ी पर स्थित किले को ध्यानपुर्वक देखा जोकि दूरी पर स्थित होने के कारण स्पष्ट नहीं दिखायी नहीं पड़ता था। अतः उन्होंने स्पष्ट दिखायी न देने के लिये बुन्देलखण्डी भाषा में "झाँई सी" (धुँधला दिखायी देना) शब्द का प्रयोग किया और उसी के अनुसार ओरछा नरेश ने उस दुर्ग का "झाँई सी" नामकरण कर दिया जो कालान्तर में "झाँसी" शब्द के रूप में परिवर्तित हो गया (जनपद गजेटियर 1965)

स्थिति तथा विस्तार– जनपद झाँसी $25^0 6'$ उत्तरी अक्षांस से $25^0 56'$ उत्तरी अक्षांस तथा $78^0 18$ पूर्वी देशान्तर से $79^0 25'$ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। यह जनपद उत्तर प्रदेश के तीन जनपदों जालौन, हमीरपुर, ललितपुर तथा मध्यप्रदेश के चार जनपदों दतिया, टीकमगढ़, सागर व ग्वालियर से घिरा

हैं। इसकी पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 99 किमी० तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 88 किमी० है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 5025 वर्ग किमी० है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झाँसी जनपद का उत्तर प्रदेश में 26 वाँ तथा बुन्देलखण्ड में चौथा स्थान है । प्रशासनिक दृष्टि से यह चार तहसीलों तथा आठ विकास खण्डों में विभक्त है (चित्र संख्या 2.1) । कुल आबाद ग्रमों की संख्या 760 है। 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या **1429698** है जिसमें 767430 पुरूष तथा 662268 स्त्रियाँ है। यहां की 60.39 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण तथा 39.61 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय हैं। सम्पूर्ण जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोगो का प्रतिशत 29.0 है।

भौतिक पृष्ठभूमि (Physical Background)

भूगर्भिक संरचना तथा उच्चावच (Geological Structure and Relief)

भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से जनपद (गजेटियर), झाँसी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

(i) **उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग** – जनपद का यह भाग सममतल तथा उपजाऊ है जोकि क्षेत्रीय नदियों तथा नालों द्वारा लायी मिट्टी से निर्मित हैं। यह भाग उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान का सीमान्त क्षेत्र है (चित्र संख्या 2.2 ए)। दक्षिणी पश्चिमी भाग की तुलना में यह एक निचला क्षेत्र है।

(ii) **दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी उच्च भूमि प्रदेश** – यह भाग पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र है। इस भाग में बिजाबर तथा विन्ध्यक्रम की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। पहाड़ी श्रृंखलाओं के कारण उच्चभूमि प्रदेश के रूप में है। जहाँ पर पहाड़ झाड़ झंखाड़ व जंगल भूमि की अधिकता हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र के

UTTER PRADESH

DISTRICT JHANSI

BOUNDARY - STATE	
DISTRICT	
TAHSIL	
VIKASKHAND	
DISTRICT H.Q	
TAHSIL H.Q	
VIKASKHAND H.Q	
ROAD	
RAILWAY STATION	
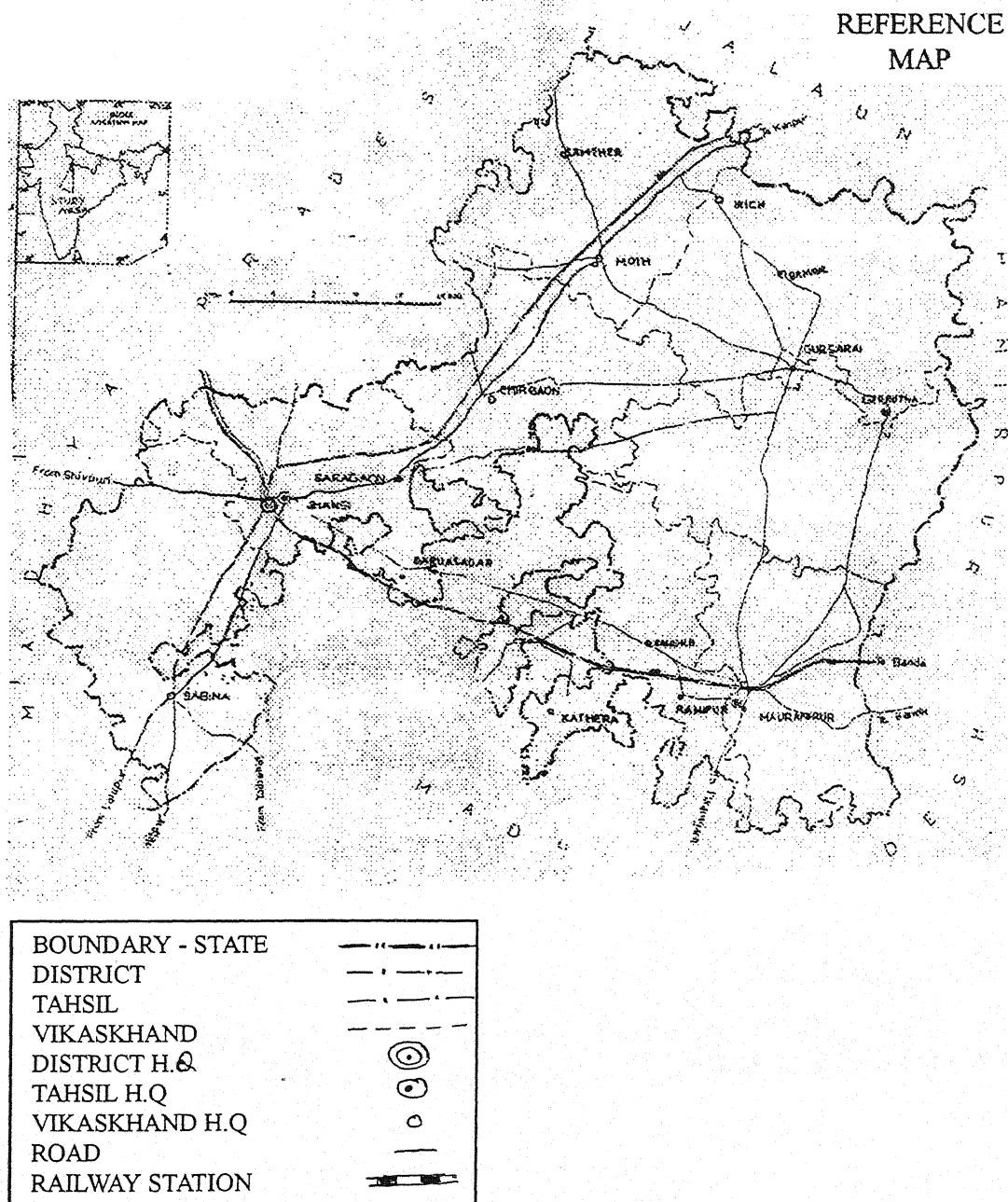
Fig. 2.1

DISTRICT JHANSI
GEOLOGY

North - Eastern Plain Area

Southern & South - Western
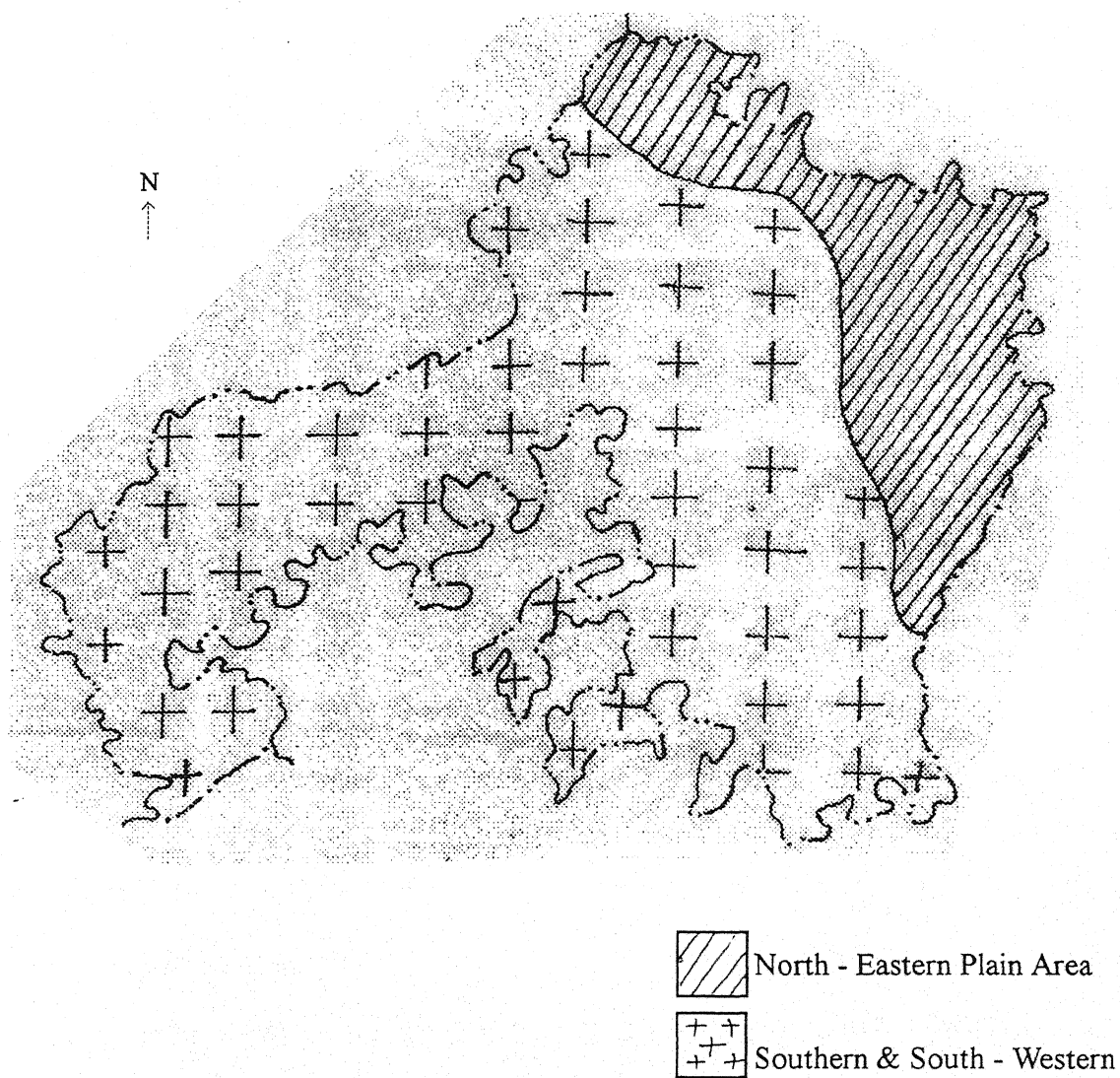
Fig 2.2 A

अधिकांश भाग पर बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट नीस की चट्टाने पायी जाती हैं। जनपद के इस भाग में अनियमित पहाड़ों की दो श्रंखलायें विद्यमान है। पहली श्रंखला बेतवा नदी से प्रारम्भ होकर उत्तर से उत्तर पूर्व तक अर्थात झाँसी से मोंठ तक जाती हैं। जबकि इसकी श्रंखला कटेरा ग्राम से शुरू होकर उत्तर की ओर जाती हैं तथा मगरवारा एवं कचनेवा ग्रमों के पास समाप्त हो जाती हैं। दोनों पहाड़ी श्रंखलाओं की ऊँचाई 185 मी० से लेकर 233 मीटर के आसपास हैं। दक्षिणी भूभाग में विन्ध्याचल श्रंखला की अधिकतम ऊँचाई 522 मीटर है। जोकि उत्तर की ओर जाने पर धीरे धीरे कम होती जाती है। बबीना में इसकी ऊँचाई 307 मी० तथा झाँसी में 274 है। जनपद का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है।

प्रादेशिक विभाग (Regional Devisions)

भूगर्भिक संरचना, भूआकृति, वनस्पति, मिट्टियाँ, जलवायू प्रवाह तंत्र एवं अन्य भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर झाँसी जनपद को चार प्रादेशिक में विभाजित किया जाता है। (चित्र संख्या 2.2 बी)

(i) झाँसी मैदान;

(ii) बेतवा–धसान ऊबड़ खावड़ भूमि;

(iii) मऊरानीपुर उच्च भूमि;

(iv) झाँसी उच्चभूमि।

1. **झाँसी मैदान** – यह भूभाग जनपद के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। जो पूर्व में बेतवा नदी व दक्षिण में 200 मीटर की समोच्च रेखा से 1 फीट है। उसकी औसत ऊँचाई 176 से 189 मीटर तथा प्रदेश का सामान्य ढाल स्तर

DISTRICT JHANSI
REGIONAL DEVISIONS
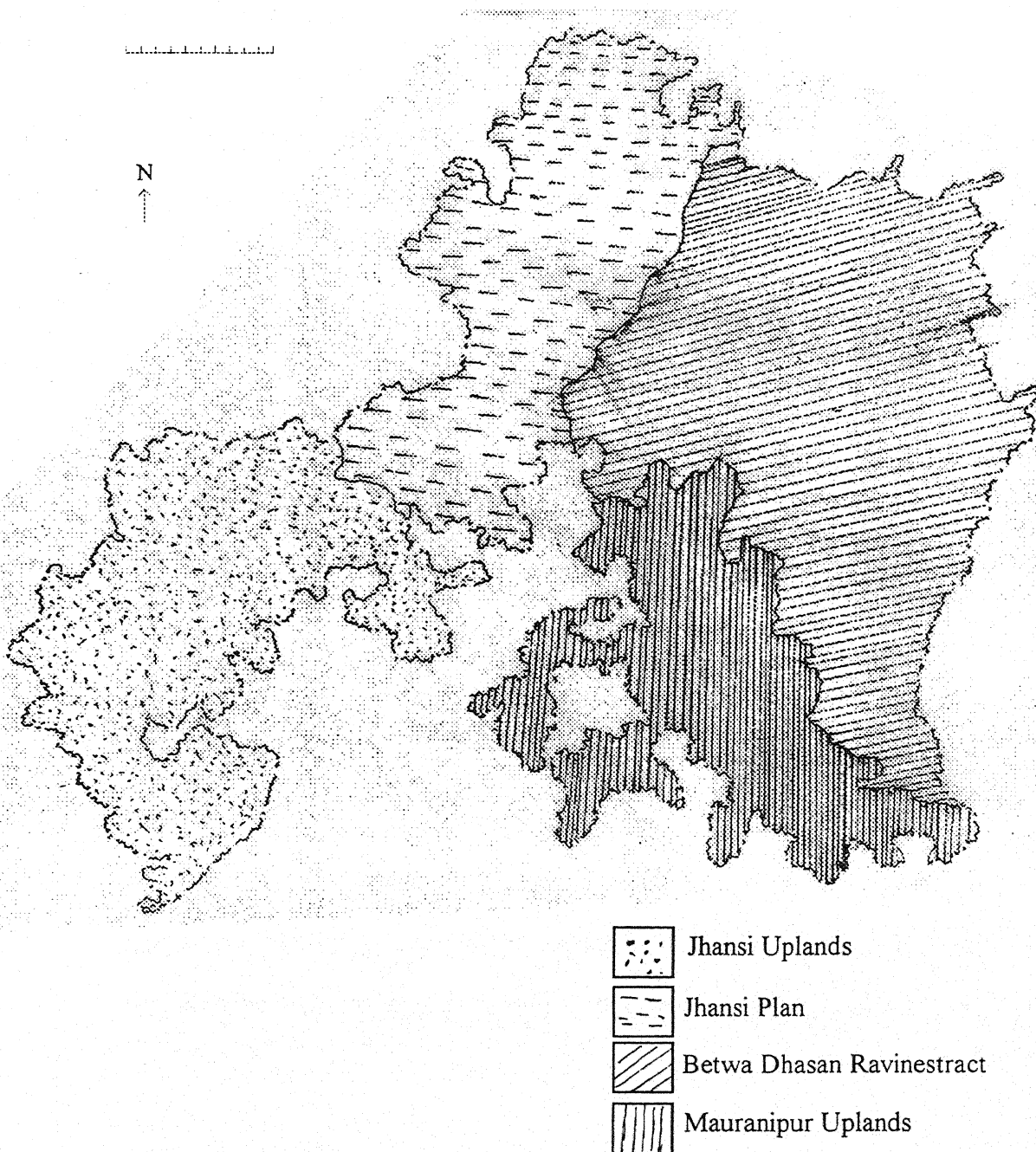
Fig. 2.2 B

उत्तर दिशा की ओर है। बेतवा नदी की समीपवर्ती ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को छोड़ कर सभी भूभाग मैदानी है। दक्षिणी भाग में कुछ टीले पाए जाते हैं। बेतवा व पहुँज नदियों द्वारा यह क्षेत्र प्रभावित हे। उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता जबकि दक्षिणी भाग में बुन्देलखण्ड नीस व ग्रेनाइट पायी जाती है। बेतवा नदी के किनारे कुछ संरक्षित वन भूमि है। उस क्षेत्र में ३१७ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० निवास करते हैं। उस क्षेत्र में 288 गाँव समथर, मोठ, चिरगाँव और अन्य प्रमुख नगर है।

2. **बेतवा–धंसान ऊबड़ खाबड़ भूमि** – इस क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद का अधिकांश पूर्वी भाग सम्मिलित है। यह एक क्षतविक्षत क्षेत्र है। जिसमें अवनालिकाये युक्त असंख्य नाले वृक्षाकार का प्रवाह प्रणाली का निर्माण करते हुए बेतवा व धसान में गिरते हैं। पडुवा व राकर मिट्टी की प्रधानता है। वन क्षेत्र क्षतविक्षत क्षेत्र में पाए जाते हैं।उस क्षेत्र में 15.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० निवास करते हैं। उस क्षेत्र में 289 गाँव व तीन नगर यथा गुरसराँय, टोडी फतेहपुर स्थित है।

3. **मऊरानीपुर उच्च भूमि** – जनपद के दक्षिणी भाग में यह क्षेत्र स्थित है। यह उत्तर दक्षिण दिशा से 200 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा विलग है। अधिकाशतः मऊरानीपुर तहसील का भाग उस क्षेत्र में पाया जाता है। यहां का धरातल अधिकांशतः ऊबड़ खाबड़ है। यत्रतत्र पहाड़ियाँ, झीलें व तालाब स्थित है। उस क्षेत्र की औसत ऊँचाई 234 से 340 मीटर पाई जाती है। यह आर्कियन युग की बुन्देलखण्ड नीस व ग्रेनाइट से बना क्षेत्र है। मिट्टी बहुत उपजाऊ नही है।

195 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० निवास करते हैं। मऊरानीपुर, रानीपुर एवं कटेरा यहां के प्रमुख नगर हैं। 151 गाँव उस क्षेत्र में स्थित है।

4. झाँसी उच्च भूमि – जनपद के पश्चिमी भाग में यह क्षेत्र पाया जाता है। उ० पूर्व में 200 मीटर की समोच्च रेखा झाँसी पठार से यह क्षेत्र प्रथक है। 240 से 335 मीटर के मध्य इस क्षेत्र की ऊँचाई है तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है। बेतवा तथा पहुज नदियों द्वारा यहां का ढाल प्रभावित हुआ है। धरातल काफी क्षत विक्षत व पथरीला है। बेतवा नदी के किनारे किनारे वन भूमि पायी जाती है। आर्कियन युग की बुन्देलखण्ड नीस गेनाइट की प्रधानता है। झाँसी इस क्षेत्र का प्रमुख नगर है, जो रेल सड़क परिवहन का प्रमुख केन्द्र है । 428 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० निवास करते हैं। 142 गॉवो 144996 व्यक्ति निवास करते हैं। झाँसी, बड़गाँव बरूआ सागर व बबीना कैन्ट यहां के नगरीय अधिवास हैं।

जलवायु (Climate)– बुन्देलखण्ड के अन्य जनपदो की भाँति यहां भी जलवायु सम्बन्धी विविधताएं पायी जाती है। यहां गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती हे। वर्षा अधिकांशतः जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह में होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन अत्यधिक गर्म जबकि राते शीतल व सुहावनी होती हैं। जोकि बुन्देलखण्ड की जलवायू की प्रमुख विशेषता है। यहां शीत ऋतु दिसम्बर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से सितम्बर तक तथा बाद का मानसून अक्टूबर से नवम्बर तक। मई–जून में यहां का न्यूनतम तापमान 27° सेन्टीग्रेट तथा अधिकतम तापमान 48.8° सेन्टीग्रेड तक हो जाता है जबकि शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 5° सेन्टीग्रेड तक गिर जाता है। जनपद

झाँसी में अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम के द्वारा वर्षा होती है। यहां वर्षा का वार्षिक औसत 88° मिलीमीटर जबकि अत्तरी भाग में घटकर 550 मिमी० रिकार्ड की गई है। एक वर्ष में औसतन 62 दिन वर्षा होती है।

प्रवाह तंत्र (Drainage System)– बेतवा, धसान, पहूँज तथा लखेरी यहां की प्रमुख नदियाँ हैं जोकि अपने सहायक छोटे नालों तथा जल बितरिकाओं के साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को प्रवाहित होती हुई जनपद में प्रवाह तन्त्र का निर्माण करती हैं।

यहां की प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं –

1. **बेतवा** – जनपद में प्रवाहित हाने वाली यह सबसे वड़ी नदी है जोकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश झाँसी तथा ललितपुर की सीमा बनाती हुई झाँसी जनपद में प्रवाहित होती हैं आगे चलकर यह नदी जालौन जनपद में प्रवेश करती है। झाँसी जनपद में इस नदी पर सुकवाँ–दुकवाँ व पारीछा बाँध निर्मित किये गये हैं। इस क्षेत्र में वर्ष भर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदीहै।

(चित्र संख्या 2.3)

2. **धसान** – इसका उद्‌गम स्थल भी मध्य प्रदेश में है। यह नदी भी ललितपुर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। झाँसी जनपद में प्रवाहित होने वाली यह दूसरी प्रमुख नदी है जोकि झाँसी तथा हमीरपुर जनपदों की सीमा बनाती हुई दक्षिण–पश्चिम से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस पर मऊरानीपुर गरौंठा मार्ग पर लहचूरा नामक स्थान पर लहचूरा बाँध बनाया गया हे जिसमें धसान नहर निकाली गयी है। यह नदी बेतवा की सहायक नदी है।

DISTRICT JHANSI
DRAINAGE PATTERN

Revers

Lakes/Dam
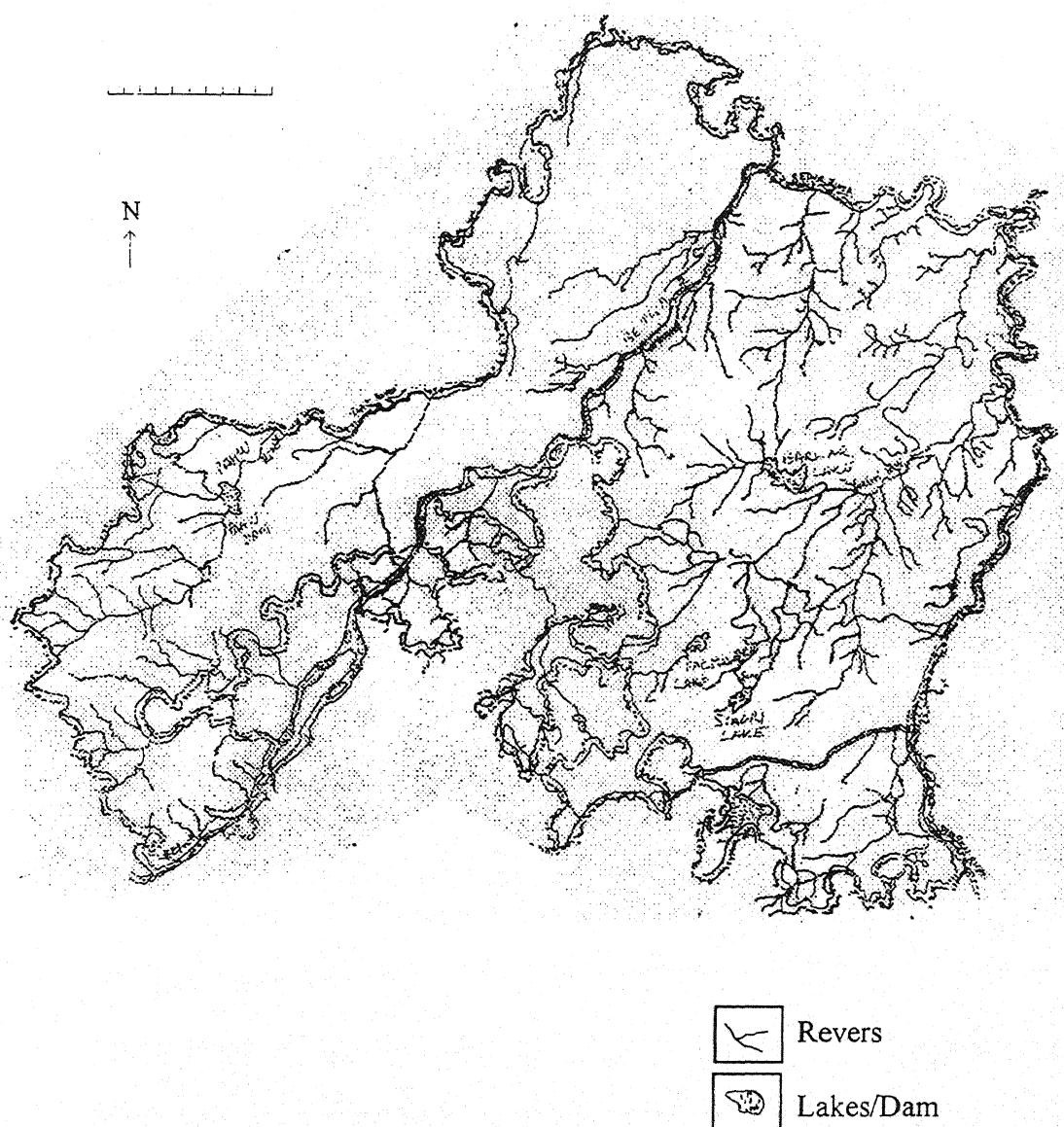
Fig. 2.3

3. **पहूँज** – यह नदी भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास से निकल कर लौलोन्ज (झाँसी तहसील) नामक गाँव के पास झाँसी जनपद में प्रवेश करती है तथा पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। तत्पश्चात यह पुनः मध्य प्रदेश तथा फिर जनपद जालौन मे प्रवेश करती है।

इसके अलावा अन्य अनेक नदी–नाले इस क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं। (चित्र संख्या 2.3)

मिट्टियाँ (Soils) – किसी क्षेत्र के जनसंख्या तथा खाद्य संसाधनों के अध्ययन में मिट्टी का ज्ञान अति आवश्यक है क्योंकि विश्व के प्रत्येक भाग में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा भोजन की पूर्ति के लिए मिट्टी पर निर्भर करता है। मिट्टी कृषि का वास्ततिक आधार है। मिट्टी की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुये खाद्य फसलों के उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए मिट्टी को मानव जीवन का आधार कहा जाता है । एस० पी० राय चौधरी ने यहां की मिट्टी को मुख्य रूप से दो समूहों में विभाजित किया था। 1. काली मिट्टी तथा 2. लाल मिट्टी। प्रथम समूह के अन्तर्गत मार भूमि तथा काबर भूमि और द्वितीय समूह के अन्तर्गत पडुवा तथा रॉकर भूमि सम्मिलित है।

1. **मार भूमि** – मार भूमि जनपद में काली मिट्टी के नाम से पुकारी जाती है। जो ट्रेप चट्टानों के असंगठित होकर टूटने से निर्मित हुई है। यह मिट्टी जनपद झाँसी के कुल कृषि योग्य भूमि के 22 प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। यह मिट्टी मोंठ, मऊरानीपुर तथा गरौठा तहसील में निम्न भूमियों के क्षेत्र में पायी जाती है (चित्र संख्या 2.4)। इसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक है । यदि इस मिट्टी में जौविक खाद्यों का प्रयोग किया जाता है तो इसमें बिना किसी

DISTRICT JHANSI
SOILS
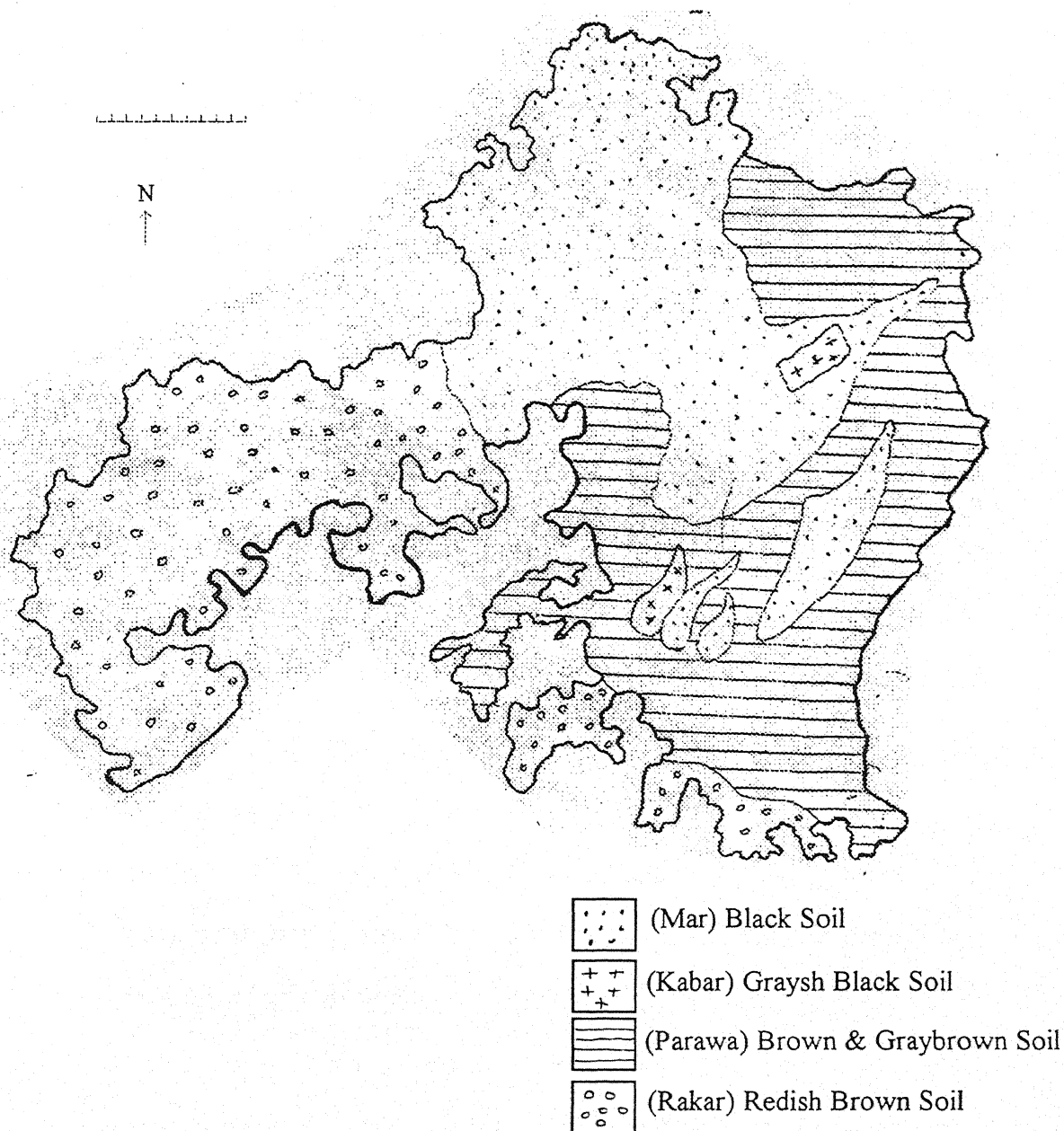
Fig. 2.4

कठिनाई के लगातार फसलें अगायी जा सकती है। यही कारण है कि इस मिट्टी के क्षेत्र में विकसित कृषि की जाती है।

2. **काबर भूमि** – झाँसी जनपद के निचले भागों में यह मिट्टी मिलती है। इसका विस्तार कुल कृषि योग्य भूमि के 20.0 भाग पर है । काबर मिट्टी में एल्यूमिना फेरिक आक्साइड, चूना मैग्नीशियम तथा जैविक पदार्थो की प्रधानता है। झाँसी जनपद के पठारी क्षेत्र में मिलने वाली कावर मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। यहां पर सिचन सुविधाओं का अभाव रहता है। यही कारण है कि पठारी क्षेत्र के निवासी अत्यधिक निर्धन हैं तथा उस भूमि से बहुत कम लाभ हासिल कर पाते हैं।

3. **पडुवा भूमि** – पडुवा भूमि में हल्के रंग की बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसमें चीका और बलुई कॉप का मिश्रण रहता है। इसमें सिचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। **यह मिट्टी** अधिकांशतः नदी के किनारे **मिलती है।** झाँसी जनपद में इस मिट्टी का विस्तार कुल कृषि योग्य भूमि के 21 प्रतिशत भाग पर रासायनिक संरचना की दृष्टि से इसमें लोहा, चूना, फास्फेट तथा नाइट्रोजन की कमी पायी जाती है। इस मिट्टी में अधिक सिचाई हानिकारक है क्योंकि यह क्षारीय होती है।

4. **रॉकर भूमि** – यह एक पथरीली भूमि है। जो झाँसी जनपद के पर्वतीय ढालों एवं नदी कटाव क्षेत्रों में मिलती है। इसमें क्षरण तत्वों की अधिकता होती है तथा अविकसित भूमि हाने के कारण इस मिट्टी में कोई स्तर विकसित नही रहते है। इसमें जैविक तत्वों तथा नाइट्रोजन की कमी पायी जाती है। इसे मोटी रॉकर तथा पतली रॉकर में विभाजित किया जा सकता है। यह मिट्टी झाँसी जनपद

में कुल कृषि योग्य भूमि के 30.0 प्रतिशत भाग पर पायी जाती है। यह मिट्टी सिचाई वाले भागों में अधिक उपयोगी है।

उपर्युक्त मिट्टियों के अलावा गोयंड डांडी, जंगली, तराई कछार, लाल, एवं पीली मिट्टियाँ भी क्षेत्र में यत्र तत्र पायी जाती हैं। किन्तु प्रमुख मिट्टियों की तुलना में इनका क्षेत्र नगण्य है। गौण मिट्टियों का विस्तार झाँसी जनपद की कुल कृषि योग्य भूमि के मात्र 7 प्रतिशत भाग पर है।

भू–क्षरण एवं संरक्षण – प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी के कणों का अलगाव एवं बहाव प्राकृतिक कारकों, द्वारा भूक्षरण या भूमि कटाव कहलाता है। इसके कारण उपजाऊ भूमि भी अनुपजाऊ तथा ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। क्षेत्र के असमतल धरातल में भू–क्षरण को एक जटिल समस्या बना दिया है। साथ ही नदियों का तीव्र प्रवाह नदी खड्ड या कन्दराये, राँकर एवं पडुवा भूमि आदि तत्वों के कारण इस क्षेत्र में भूक्षरण की स्थिति और भी अधिक गम्भीर हो गई है। जनपद झाँसी के अर्न्तगत क्षरण से प्रभावित भूमिका क्षेत्र 4.0 लाख हेक्टेयर है।

भूमि क्षरण का तात्पर्य भूक्षरण रोकने से है। क्षेत्र में भूमि संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1957-58 में प्रारम्भ हुआ था परन्तु इसके लिए प्रभावी कदम तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ही उठाये गये। वर्तमान समय में यहां भूमि संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। भूमि सरंक्षण विभाग अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है।

यद्यपि समतलीकरण, समोच्च रेखा पर जगह जगह खांइयाँ खोदना वानस्पतिक अवरोधक वृक्षारोपण, मेडबन्धी व वन्धियों आदि का निर्माण कर

भूक्षरण रोकने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु अभी भी भूक्षरण की समस्या के समाधान हेतु सघन कार्यकमों के कियान्वयन की आवश्यकता है। वास्तव में इस समस्या का समाधान तभी सम्भव है जब गाँव का प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो योजना के कियान्वयन से पूर्व उसे योजना से सम्बन्धित समस्त पक्ष का ज्ञान हो--ऐसी स्थिति हाने पर भी कर्मचारी तथा जनता में समन्वय स्थापित हो सकेगा तथा ग्रामीण पूर्ण मनोयोग से योजनाओं के कियान्वयन पर नजर रख सकेगें और उसके सही इस्तेमाल पर बल देगें (मिश्र 1999)।

वन एवं उद्यान – (Forest & Orchards) पठारी क्षेत्र का भूभाग होने के कारण अध्ययन क्षेत्र का अधिकांश भाग प्राचीन समय में वनाच्छादित था। जिसमें अनेक वन्य पशु निवास करते थे। आधुनिक समय में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या व उनके लिये विविध संसाधनो के जुटाने के उद्देश्य से निरन्तर वनों का सफाया होता जा रहा है। वर्तमान समय में आज ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों व पहाड़ी भूमि पर ही वनीय भाग सिमट कर रह गया है। वन्य क्षेत्रों का स्थान हरे भरे खेतों ने ले लिया है। वनों में शीशम, महुवा, पलास, पीपल, पाकर, बरगद, बबूल, नीम, खैर, जामुन, करौंदा आदि प्रमुख हैं।

वर्तमान समय में क्षेत्र के अन्तर्गत 6.5 प्रतिशत भूमि वनों के अन्तर्गत आती है। 0.3 प्रतिशत भूमि पर उद्यान, झाड़ियां तथा बगीचे पाए जाते हैं। 0.1 प्रतिशत भूमि चारागाहों के अन्तर्गत आती है। 15.8 प्रतिशत भूमि बंजर एवं परती भूमि के अन्तर्गत आती है। इस भूमि पर आसानी से वृक्षारोपण कर वनों का विकास किया जा सकता है। वर्तमान समय में उपलब्ध वनीय क्षेत्र पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है तथा प्राकृतिक संसाधनों का निरन्तर पुर्नउपयोग हो रहा

है। इससे प्रादेशिक असीमता खतरे में पड़ गई है। अतः जीने के लिए यह जरूरी है कि पृथ्वी के हरे भरे श्रंगार को न उजाड़े तथा प्रकृति के प्रति सदैव संवेदनशील रहे (मिश्र 1999)।

आर्थिक पृष्ठभूमि (Economic Background)

भूमि उपयोग एवं फसल चक (Land use and Crops Rotation) – जनपद झाँसी की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। यहाँ की लगभग 63 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 62.4 प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। अध्ययन क्षेत्र के सामान्य भूमि उपयोग का विवरण सारिणी संख्या 2.1 तथा चित्र संख्या 2.5 ए से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या 2.1

जनपद झाँसी का सामान्य भूमि उपयोग 1995-96

क्रमांक	भूमि उपयोग श्रेणी	क्षेत्रफल लाख (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	कुल प्रतिबेदित क्षेत्र	5.02757	100.00
2	वन	0.32773	6.5
3	उद्यान एवं झाड़िया तथा बाग	0.01988	0.3
4	चारागाह	0.00639	0.1
5	कृषि योग्य बंजर भूमि	0.47201	9.3
6	वर्तमान परती	0.19024	3.7
7	अन्य परती	0.14268	2.8

8	कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि	0.72951	14.2
	१. ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि	0.31601	6.1
	२. अन्य उपयोग में लायी गई भूमि	0.41150	8.1
9	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	3.14063	62.4
10	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	0.51816	10.3
11	सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्र	3.65879	72.7
	१. रबी के अन्तर्गत	2.76528	75.6
	२. खरीफ के अन्तर्गत	0.88358	24.1
	३. जायद के अन्तर्गत	0.00979	0.3
12	कुल सिंचित क्षेत्रफल	1.32725	36.3
	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	1.30887	41.7

स्रोत – साख्यिकीय पत्रिका, जनपद झांसी 1996।

सारिणी संख्या 2.1 के विश्लेषणात्मक अध्ययन के पश्चात शोध क्षेत्र के सामान्य भूमि उपयोग को तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

1. **कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि** – जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 14.2 प्रतिशत भाग कृषि हेतु अनुपलब्ध है। जिसका 6.1 प्रतिशत भाग ऊसर तथा कृषि

DISTRICT JHANSI
LAND USE
(1995-96)

Net Sown Area

Culturable Waste Land

UnCulivale Land

Forest and Orchards
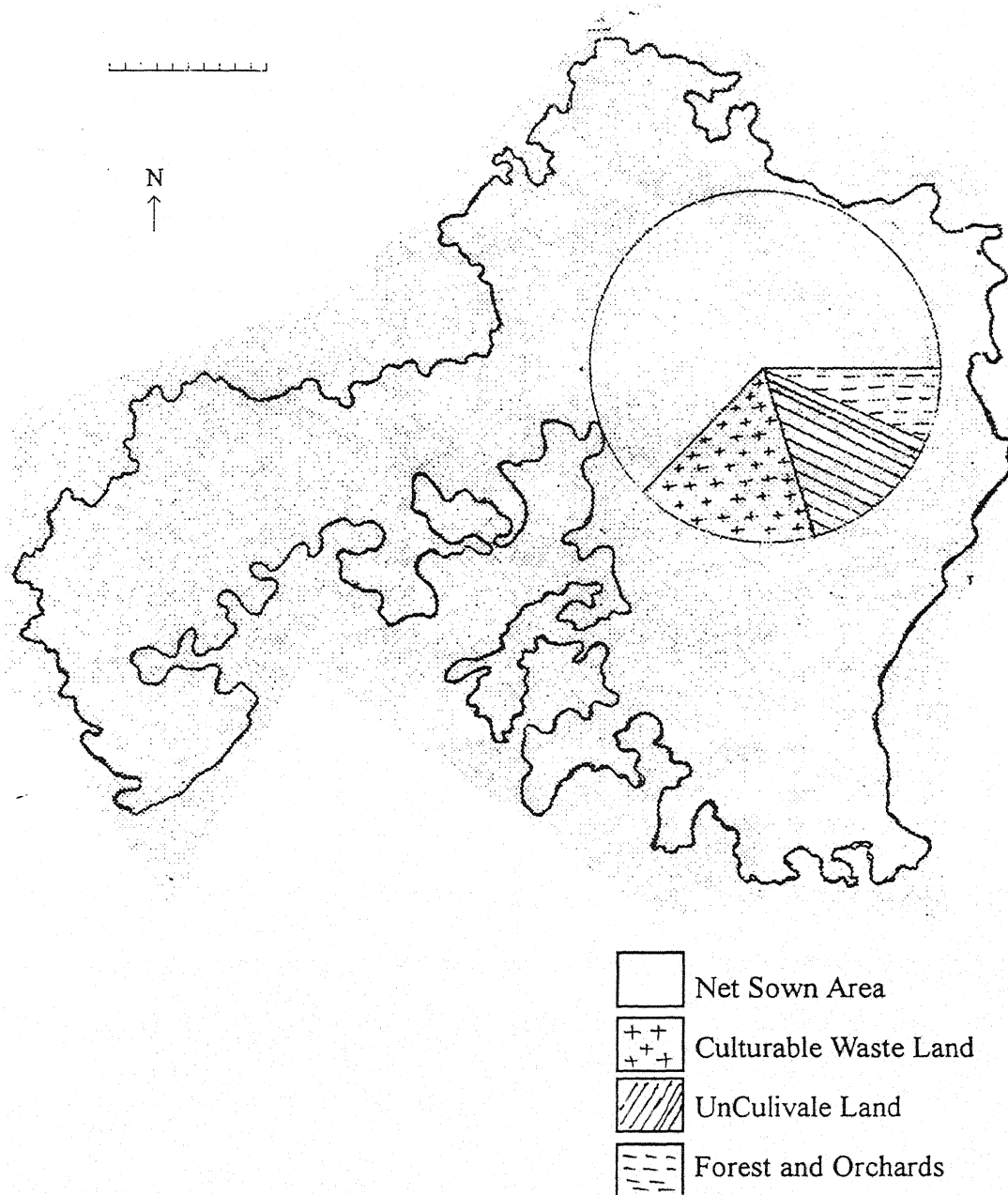
Fig. 2.5 A

अयोग्य भूमि के अन्तर्गत आता है। यह भूमि कृषि की दृष्टि से बेकार है। कुल क्षेत्रफल का 8.1 प्रतिशत भाग बस्ती, सड़क तालाब भीटा तथा अन्य उपयोग के अन्तर्गत होने के कारण कृषि हेतु अनुपलब्ध है।

2. **कृषि योग्य बंजर एवं परती भूमि** – अध्ययन क्षेत्र की 15.8 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि के अन्तर्गत आती हे। वस्तुतः क्षेत्र का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसे कुछ श्रम व पूंजी के विनियोग से कृषि तथा वनोद्यान हेतु विकसित किया जा सकता है।

3. **शुद्ध कृषि योग्य भूमि** – इसके अन्तर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र सम्मिलित है। जिसका क्षेत्रफल 3.14 लाख हेक्टेयर है। जो कि सम्पूर्ण प्रतिवेदित क्षेत्र का 62.4 प्रतिशत है। प्राचीन वसाव, औद्योगीकरण का अभाव तथा न्यून शैक्षिक स्तर आदि के कारण भूमि का अत्यधिक उपयोग कृषि कार्यों में होना स्वाभाविक है।

4. **वन एवं उद्यान** – क्षेत्र में वनों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का मात्र 6.5 प्रतिशत भाग ही आता है। जोकि वर्तमान पर्यावरणीय संतुलन की आनुपातिक दृष्टि से बहुत कम है। क्यों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए कृषि योग्य बेकार भूमि तथा ऊसर भूमि में वृक्षारोपण करके वनों का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। जनपद झांसी में सिंचन सुविधाओं की अपर्याप्ता के कारण केवल 10.3 प्रतिशत भूमि द्विफसली है। वर्तमान जनसंख्या के भरण पोषण हेतु कृषि के सघन उपयोग का अधिक महत्व हैं जिसे कृषि हेतु आवश्यक सुविधओं को बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है।

खरीफ शस्य में भूमि उपयोग – खरीफ शस्य के अन्तर्गत जनपद झाँसी के सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्र का 24.1 प्रतिशत भाग आता है।(चित्र संख्या 2.5 बी)। खरीफ उपजों के अन्तर्गत खाद्यान्न फसलो की प्रधानता है। क्योकि इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्र का लगभग 29 प्रतिशत भाग आता है। खरीफ शस्य के अन्तर्गत प्रमुख रूप से चावल, ज्वार, बाजरा तथा दालें (अरहर 354) आती हैं। इन सब में ज्वार की खेती सर्वाधिक होती है। जो अध्ययन क्षेत्र के 30.03 प्रतिशत भाग पर बोई जाती है। (सारिणी संख्या 2.2)में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या २.२

जनपद झाँसी में खरीफ के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1995-96 (हेक्टेयर में)

कंमाक	फसले	क्षेत्र	प्रतिशत
1	चावल	2173	2.46
2	ज्वार	26535	30.03
3	बाजरा	44	0.05
4	उड़द	14985	16.96
5	मूँग	6655	7.53
6	तिल	4621	5.23
7	अरहर	8416	9.52
8	मक्का	2967	3.36
9	अन्य	21962	24.86

	योग	88358	100.00

स्रोत – साख्यिकीय पत्रिका जनपद झाँसी 1996।

रबी शस्य में भूमि उपयोग – जनपद झाँसी में रबी शस्य के अन्तर्गत कुल बोये गये क्षेत्र का 75.6 प्रतिशत भाग आता है (चित्र संख्या 2.5 बी.)

रबी शस्य के अन्तर्गत बोई जाने वाली फसलें व उनके क्षेत्रफल को सारिणी संख्या 2.3 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 2.3

जनपद झाँसी में रबी शस्य के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1992-93 **हेक्टेयर में**

कमांक	फसलें	क्षेत्र	प्रतिशत
1	गेहूँ	113392	41.01
2	जौ	2422	0.87
3	चना	71073	25.70
4	मटर	28788	10.41
5	मसूर	84364	12.43
6	लाही/सरसो	8380	3.03
7	अलसी	12752	4.61
8	अन्य	5357	1.94
	योग	276528	100.00

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका जनपद झाँसी 1996.

DISTRICT JHANSI
CROPPING PATTERN
(1995-96)
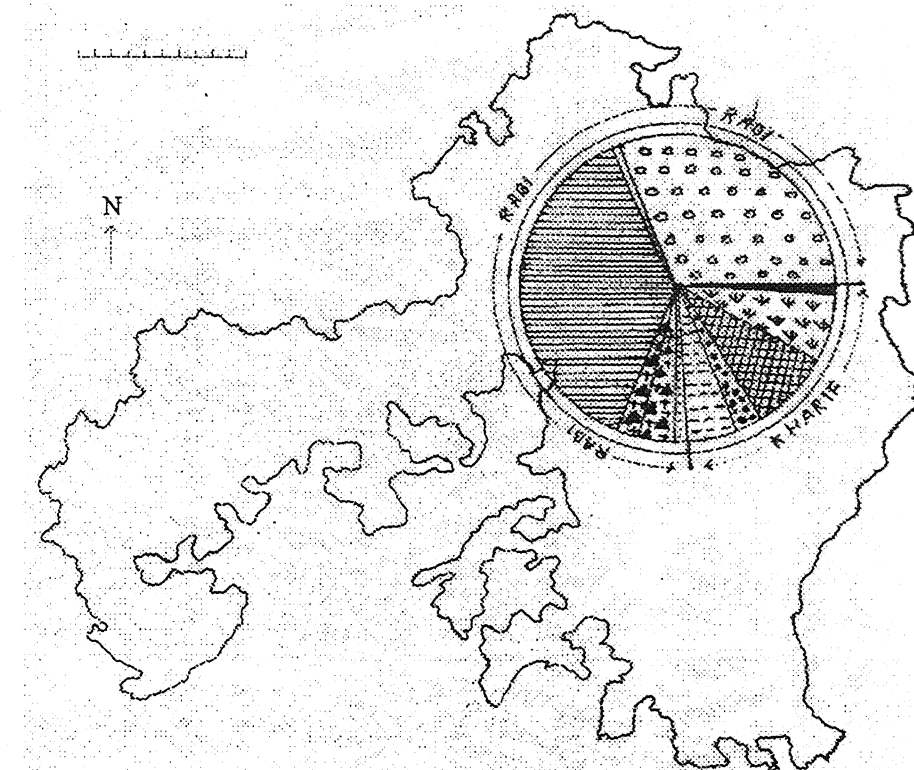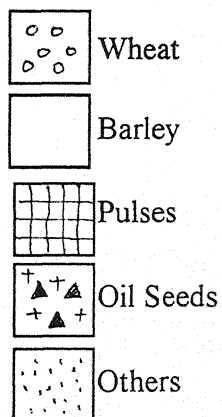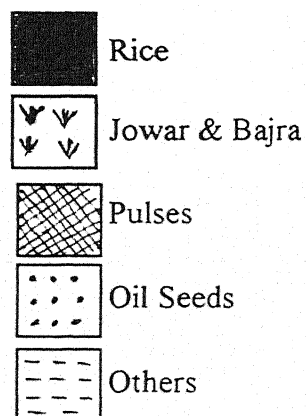
Fig. 2.5 B

सारिणी संख्या 2.3 के परीक्षण से ज्ञात होता है कि रबी के अन्तर्गत कुल कृषित क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भाग खाद्यान्नों के अन्तर्गत आता है जिसमें गेहूँ , चना, मटर, मसूर प्रमुख है। इन फसलों में गेहूँ सर्वाधिक क्षेत्र (41.01प्रतिशत) में बोया जाता है। इसके अलावा तिलहनों में अलसी तथा लाही कमशः 4.61 प्रतिशत एवे 3.03 प्रतिशत भाग पर बोई जाती है।

जायद के अन्तर्गत मात्र 0.3 प्रतिशत भूमि आती है। मुख्यतः जहां सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहां सब्जियाँ बो दी जाती है।

2. **सिंचाई के स्त्रोत** – भारत जैसे मानसून पर निर्भरता वाले कृषि प्रधान देश में सिचाई की सुविधाओं का अत्यधिक महत्व है। जिसे यहाँ की न्यूनाधिक तथा असमय वर्षा ने अपरिहार्य बना दिया है। समय–समय पर विभिन्न फसलों को खेतों में जल पहुँचाना सिचाई कहलाता है। जनपद झाँसी में 1995-96 में शुद्ध बोई गयी भूमि का कुल 41.7 प्रतिशत भाग सिंचित था जोकि 1994-95 में 35.4 प्रतिशत से अधिक है। जनपद झाँसी में विभिन्न साधनों के द्वारा सिचाई की जाती है (सारिणी संख्या 2.4)।

(सारिणी संख्या 2.4)

जनपद झाँसी में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र 1995-96 (हेक्टेयर में)

कमांक	स्त्रोत	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	प्रतिशत
1	नहर	71185	54.39
2	राजकीय नलकूप	1873	1.43
3	निजी नलकूप	2697	2.06

4	कुऐं	48119	36.76
5	तालाब	1218	0.93
6	अन्य	5795	4.43
	योग	130887	100.00

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका जनपद झाँसी 1996।

सारिणी संख्या 2.4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिंचन सुविधाओं में नहरों (54.39 प्रतिशत) तथा कुओं (36.76 प्रतिशत) का योगदान सर्वाधिक है। विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न स्रोतानुसार सिंचित क्षेत्र को सारिणी संख्या 2.5 में दर्शाया गया है।

(सारिणी संख्या 2.5)

जनपद झाँसी में विकास खण्ड स्तर पर स्रोतानुसार सिंचित क्षेत्र 1995-96

(हेक्टेयर में)

विकास खण्ड	नहरें	नलकूप		कुएँ	तालाब	अन्या	योग
		राजकीय	नगरी				
मोंठ	14805	593	376	562	33	413	16787
चिरगाँव	9563	1003	988	4741	132	767	18194
वामौर	16828	122	34	294	121	888	18287
गुरसराँय	9406	-	33	2142	335	1013	12929
बंगरा	4607	-	107	8708	86	465	13973
मऊरानीपुर	8505	55	45	7423	137	712	16877
बबीना	659	-	11	14645	99	288	15414
बड़ागाँव	6812	100	103	9416	270	1249	17950
योग ग्रामीण	71185	1873	2697	47931	1218	5795	130699
नगरीय	-	-	-	188	-	-	188
योग जनपद	71185	1873	2697	48119	1218	5795	130887

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका जनपद झाँसी 1996 सारिणी संख्या 2.5 के परीक्षण से ज्ञात होता है कि विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वामौर ब्लाक तथा सबसे कम सिंचित क्षेत्र गुरसरॉय ब्लाक के अन्तर्गत है। गुरसरॉय

बंगरा तथा बबीना विकासखण्डों में राजकीय नलकूपों का अभाव है। नगरीय क्षेत्र में केवल कुएँ ही एकमात्र सिचाई के साधन हैं।

3. **खनिज तथा उद्योग धन्धे** – जनपद झाँसी में खनिज सम्पदा के रूप में कोई भी महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त नहीं होता किन्तु फिर भी जनपद का दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र पठारी तथा पथरीला होने के कारण यहाँ खनिज सम्पदा के रूप मे ग्रेनाइट डायस्फोर पाइरोफाईलाइट मोरम (बालू) तथा पहाड़ी मोरम आदि खनिज पाये जाते है। इनमें ग्रेनाइट से खण्डा बोल्डर गिट्टी आदि बनाये जाते है। ये मेजर मिनरल कहलाते हैं। इनके लिए जे०के० मिनरल ने गडमऊ, बाबुल, डोडा, पालर, गोरारो, हरपुरा में अपने प्लांण्ट लगाये हैं। जिनमें बोल्डर तथा गिट्टी बनाई जाती है। क्षेत्र में ग्रेनाइट अधिकतम पाया जाता है। जबकि पाइरोफाइलाइट तथा डायस्फोर यत्र तत्र ही मिलते हैं। बालू व मोरम जनपद की लगभग समस्त नदियों में पायी जाती है।

जनपद में मऊ रानीपुर में टेरीकाट उद्योग तथा झाँसी में लोकोशेड व अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित है। यहाँ स्ओन, केशर, मोरम तथा बालू के खनन के अलावा देशी जड़ी बूटियों पर आधारित शर्मायु आर्यूवेद कारखाना अवश्य स्थापित है। इसके अलावा कृषि यन्त्र का निर्माण इन्जीनियरिग्स वर्क्स, वैल्डिंग वर्क्स, लोहे की चादर के बक्से बनाना फर्नीचर बनाना चमड़े के जूते तथा बैग बनाना आभूषण बनाना खादी वस्त्र आदि के अनेक लघु व कुटीर उद्योग है। वस्तुतः गाँवों के परम्परागत उद्योग धन्धे जिनमें गाँवों की लगभग एक चौथाई जनसंख्या कियाशील तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सन्तुलित रूप प्रदान करने में सहयोग देते थे किन्तु आज यह उद्योग मरणासन्न अवस्था में है। सन्तुलित विकास के

लिए इन्हें पुर्नजीवित करने की आवश्यकता है। इनके द्वारा केवल उन्ही उपभोक्ता वस्तुओं को नही बनाना चाहिए जिनकी केवल हमारे किसानों को आवश्यकता है। अपितु ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिनकी जरूरत शहरों में भी रहती है (मिश्र 1997)।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि (Socio-Cultural Background)

1. **जनसंख्या** – वस्तुतः सभ्यता और संस्कृति के विकास के कम में किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार भूत तत्व मानव है। समाज में मनुष्य न केवल संसाधनों के उपयोग के आर्थिक प्रतिरूप का निर्धारण करता है। बल्कि वह स्वयं में एक गतिशील संसाधन है। क्योंकि यही प्राकृतिक संसाधनो के उपयोग की प्रकियाओं को नियोजित एवं प्रतिपादित करता है (खान 1987)। संसाधनों के उपयोग तथा विकास की सम्पूर्ण प्रकिया में मानव स्वयं लाभार्थी भी है। जो विकास के स्तर के निर्धारण हेतु सतत प्रयत्नशील रहता है। अतः इस सन्दर्भ में जनसंख्या के वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्ति का परीक्षण करना आवश्यक है। जिसके अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति घनत्व व्यावसायिक ढाँचा साक्षरता आदि का सटीक अध्ययन किया गया है।

जनसंख्या विकास – 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद झाँसी की सम्पूर्ण जनसंख्या 142998 थी जो 760 आबाद ग्रामों 3 वन ग्रामों तथा 14 नगरीय केन्द्रों में निवास करती है। सम्पूर्ण जनसंख्या में 863342 व्यक्ति ग्रामीण तथा 566356 व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में रहते है। जिनका प्रतिशत क्रमशः 60.39 तथा 39.61 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित वर्ग के अन्तर्गत 412000 लोग आते हैं। जोकि सम्पूर्ण जनसंख्या का 28.8 प्रतिशत है। जनपद

झाँसी के विभिन्न दशकों के (1990 से 1991) जनसंख्या वृद्धि समबन्धी आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जनपद में जनसंख्या की वृद्धि क्रमिक रूप से नहीं हुई।

सारिणी संख्या 2.6

जनपद झाँसी में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि (1901, 91)

वर्ष	आबाद ग्राम	जनसंख्या		प्रतिदशक अन्तर (प्रतिशत में)		
		कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1901	1331	368270	318138	-	-	-
1911	1321	398852	335137	+9.7	+5.3	+22.5
1921	1317	374114	293119	-9.9	-12.5	-3.4
1931	1329	417804	332113	+13.2	+13.3	+13.0
1941	1329	523586	363876	+12.2	+9.6	+18.1
1951	1472	557233	352621	+5.6	-3.1	+24.0
1961	1461	714484	455317	+26.2	+29.1	+21.5
1971	1450	870138	548841	+21.8	+20.5	+24.0
1981	759	1137031	705677	+30.7	+28.6	+24.3
1991	760	1429698	863342	+25.7	+22.3	+31.3
1901-91	-	-	-	+234.9	+171.4	+420.7

सन् 2001 में 23.23 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि (अनुमानतः) प्राप्त हुई है।

स्रोतः सांख्यकीय पत्रिका से प्राप्त आंकड़ों द्वारा संगणित। केन्द्रीय जनगणना कार्यालय लखनऊ।

सारणी संख्या 2.6 के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवल 1911-21 के दशक के अलावा जनसंख्या में प्रत्येक दशक में न्यूनाधिक वृद्धि

हुई है। यह वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या में काफी तीव्र गति से देखने को मिलती है। वस्तुतः 1911-21 के दशक प्राकृतिक प्रकोपों बीमारियाँ, अकाल आदि के चलते न केवल जनपद बल्कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला रहा है। यही कारण है कि उस दशक में जनसंख्या वृद्धि काफी कम रही इसके अलावा अध्ययन क्षेत्र सर्वाधिक दृशकीय वृद्धि 1971-81 में 30.7 प्रतिशत हुई। चिकित्सकीय व्यवस्था में सुधार के कारण जन्म दर में वृद्धि व मृत्युदर में कमी उसका प्रमुख कारण है।

जनसंख्या वितरण – किसी क्षेत्र की जनसंख्या के स्थानिक वितरण में वहा पर उपलब्ध हाने वाले संसाधनों का प्रभाव पूर्णतः परिलक्षित होता हे। इसके अतिरिक्त भौतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के विरण को प्रभावित करते है।

बुन्देलखण्ड के अन्य जनपदों की भाँति उस क्षेत्र में भी जनसंख्या के वितरण का स्वरूप देखने को मिलता है। जनपद झाँसी में जनसंख्या के वितरण हेतु निर्मित विन्दु मानचित्र (चित्र संख्या 2.6) के अवलोकन से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र के दक्षिणी भाग के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र एवं बेतवा धसान लखेरी पहुँज नदियों के क्षतविक्षत क्षेत्र में जनसंख्या का बिखरा हुआ स्वरूप, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या वितरण स्वरूप देखने को मिलता है।

घनत्व – जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या का द्योतक होता है। (चांदना व सिद्धु 1980) मनुष्य एवं भूमि के मध्य अनुपात जो किसी क्षेत्र के दो मुख्य तत्व होते है। वास्तव में सभी जनसंख्या अध्ययनों का मौलिक बिन्दु होते हैं। डेम्को रोज एवं रोन्गल (1970)

DISTRICT JHANSI
DISTRIBUTION OF POPULATION
1991
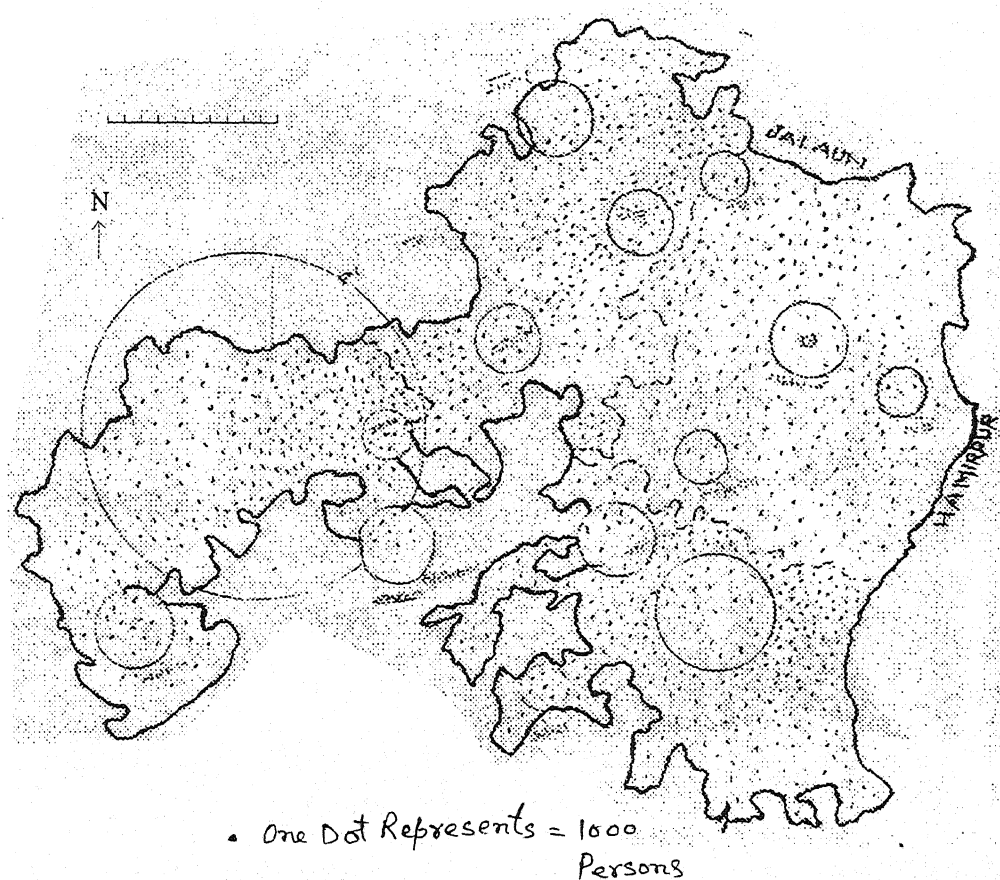
Fig. 2.6

जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किसी क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण का प्रमुख हिस्सा होता है। क्योंकि जनसंख्या वितरण प्रतिरूप की सापेक्ष स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यही एक आसान उपाय है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद झाँसी में जनसंख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है जो कि उत्तर प्रदेश 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० से कम किन्तु सम्पूर्ण भारत के औसत घनत्व 167 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० से अधिक है। सन् 2001 में प्रति वर्ग किमी० जनसंख्या आकलन शोध क्षेत्र में 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० अंकित किया गया है। यदि हम पिछले दशकों में जनसंख्या के घनत्व पर दृष्टिपात करे तो देखेगें कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है जो भूमि पर जनसंख्या के दिनोंदिन बढ़ते दवाब का सूचक है सारिणी संख्या 2.7।

सारिणी संख्या 2.7

जनपद झाँसी में विभिन्न दशकों में जनसंख्या का घनत्व

वर्ष	जनसंख्या	घनत्व (प्रति वर्ग किमी०)
1931	447544	89
1941	535878	107
1951	565933	112
1961	714484	142
1971	870138	137
1981	1137031	226
1991	1429698	285
2001	-	348

स्रोत – साख्यिकीय पत्रिका जनपद झाँसी 1996.

सारिणी संख्या 2.7 के परीक्षण से स्पष्ट है कि 1931 से 1991 तक जनसंख्या का घनत्व तीन गुना से भी अधिक बढ़ा है। विकास खण्ड स्तर पर जनपद झाँसी में जनसंख्या का घनत्व (1991) के अनुसार सारिणी संख्या 2.8 व चित्र संख्या 2.7 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 2.8

जनपद झाँसी में विकास खण्ड स्तर पर जनसंख्या का घनत्व १९९१

विकास खण्ड	मोंठ	चिरगाँव	बामौर	गुरसरॉय	बंगरा	मऊरानीपुर	बबीना	बड़ा गाँव	योग ग्रामीण
घनत्व	184	207	128	145	212	198	199	224	181

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद झाँसी 1996.

शोध क्षेत्र में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व में बहुत बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह घनत्व 181 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी 1991 जबकि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है।

आयु एवं लिंगानुपात – भारत के अन्य भागों की तरह जनपद झाँसी में भी पुरूषों तथा स्त्रियों में युवा वर्ग की अधिकता है जोकि तीव्र उत्पादक शक्ति परिवर्तन तथा उच्च निर्भरता अनुपात का द्योतक है (मिश्र 1996)। उज्जवल भविष्य की आशा संजोये हुए जनसंख्या का यह वर्ग वर्तमान में क्रियाशील जनसंख्या में कमी करके उस पर अधिभार को बढ़ाने वाला है। साथ ही अनेक

DISTRICT JHANSI
POPULATION DENSITY
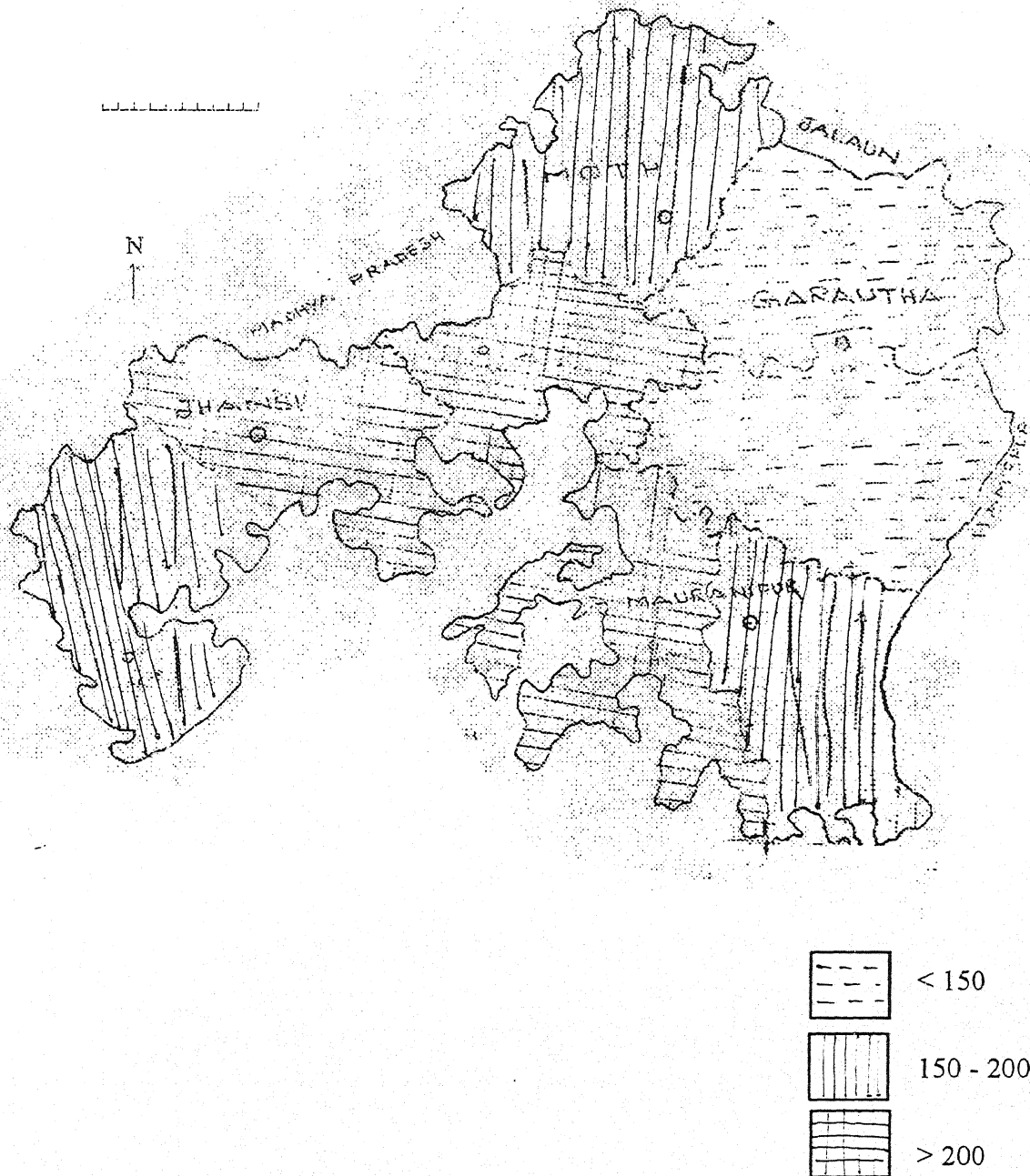
Fig. 2.7

आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को बढ़ाने वाला भी होता है। 1991 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 53.68 प्रतिशत स्त्रियाँ है। यहाँ पर प्रति हजार पुरूषों पर 862 स्त्रियां हैं। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार पुरूषों पर 852 स्त्रियाँ तथा नगरीय क्षेत्र में प्रति हजार पुरूषों पर 880 स्त्रियाँ हैं। 2001 के दशक में क्षेत्र में प्रति हजार पुरूषों पर 870 स्त्रियाँ संगठित की गई है। यह अनुपात स्त्रियों की कमी को दर्शाता है। जबकि 1981 के अनुसार प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या 869 थी। अतः स्पष्ट है कि स्त्रियों की संख्या में निरन्तर हो रही कमी भविष्य में सामाजिक सन्तुलन के लिए चिन्ता का विषय है। इसके पीछे कुछ सामाजिक कुप्रथाये तथा अन्ध विश्वास जैसी धारणाओं को ही जवाबदेह माना जा सकता है। वस्तुतः स्त्री बच्चों की तुलना में पुरूष बच्चों की अधिक उत्पत्ति तथा देखरेख भी इसके लिए उत्तरदायी है। वर्तमान समय में सरकार (शासन) में भ्रूण परीक्षण पर रोक लगाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है (सिंह 1999)। इस क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर लिंगानुपात को सारिणी संख्या 2.9 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 2.9

जनपद झाँसी में विकास खण्ड स्तर पर लिंगानुपात (1991)

विकास खण्ड	मोठ	चिरगाँव	बामौर	गुरसरॉय	बंगरा	मऊरानीपुर	बबीना	बड़ा गाँव
प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	851	856	839	843	865	861	850	848

स्रोत – राष्ट्रीय सुचना केन्द्र जनपद झाँसी से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर (1996) सारिणी संख्या 2.9 के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति हजार पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या सबसे कम वामौर 838 तथा सर्वाधिक संख्या बंगरा 860 विकासखण्ड में है।

साक्षरता – किसी क्षेत्र की जनसंख्या के सामाजिक परिवर्तनों को मापने का साक्षरता एक गुणात्मक उपागम है। वस्तुतः किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति उपदेश के नागरिकों की शिक्षा के स्तर तथा स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के स्तर तथा स्वरूप में सुधार हेतु विशेष प्रयास किये जाते रहे हैं। इसके उन्नयन हेतु न केवल राष्ट्र ही चिन्तित है जबकि 'यूनीसेफ' जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी इस दिशा में क्रियाशील है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद झांसी में साक्षरता का प्रतिशत 41.73 है जिसमें पुरूषों तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 54.37 तथा 27.07 है जबकि 1981 में जनपद में साक्षरता का प्रतिशत कुल 37.06 था जिसमें 20.67 प्रतिशत पुरूष तथा 21.38 प्रतिशत महिलायें साक्षर थी। 2001 के जनगणना वर्ष में 66.69 प्रतिशत व्यक्ति पढ़े–लिखें की श्रेणी में सम्मिलित हैं। 80.11 प्रतिशत पुरूष तथा 51.21 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर पायी गयीं। यद्यपि 1991 के दशक की अपेक्षा सन् 2001 में साक्षर प्रतिशत बढ़ा है फिर भी शास्वत विकास की दृष्टि से यह कम है।

उपर्युक्त दस वर्षो में साक्षरता में मामूली सी वृद्धि हुई जहां क्षेंत्र के पिछड़ेपन तथा जागरूक न होने को दर्शाती है। वही सरकारी नीतियों की उदासीनता और पंगु शैक्षिक नीति को भी उजागर करती है। क्योंकि अज्ञानता से दबी हुई जनता के क्षेत्रों में सरकार शिक्षा प्रसार की नीतियां केवल सरकारी कार्यालयों की फाइलों तक ही सीमित रह जाती है। यदि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता पर दृष्टिपात करें तो क्षेत्र में ग्रामीण साक्षरता 33.04 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता 54.98 प्रतिशत है। क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत सारिणी संख्या 2.10 व चित्र संख्या 2.8 ए में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 2.10

जनपद झाँसी में विकासखण्ड स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत 1991

क्र० सं०	विकासखण्ड	कुल साक्षरता प्रतिशत में	पुरूष साक्षरता प्रतिशत में	महिला साक्षरता प्रतिशत में
1	मोंठ	37.13	52.87	18.63
2	चिरगाँव	38.36	54.85	19.09
3	बामौर	35.00	51.69	15.09
4	गुरसरॉय	34.40	50.47	15.33

DISTRICT JHANSI
LITERACY
(1991)
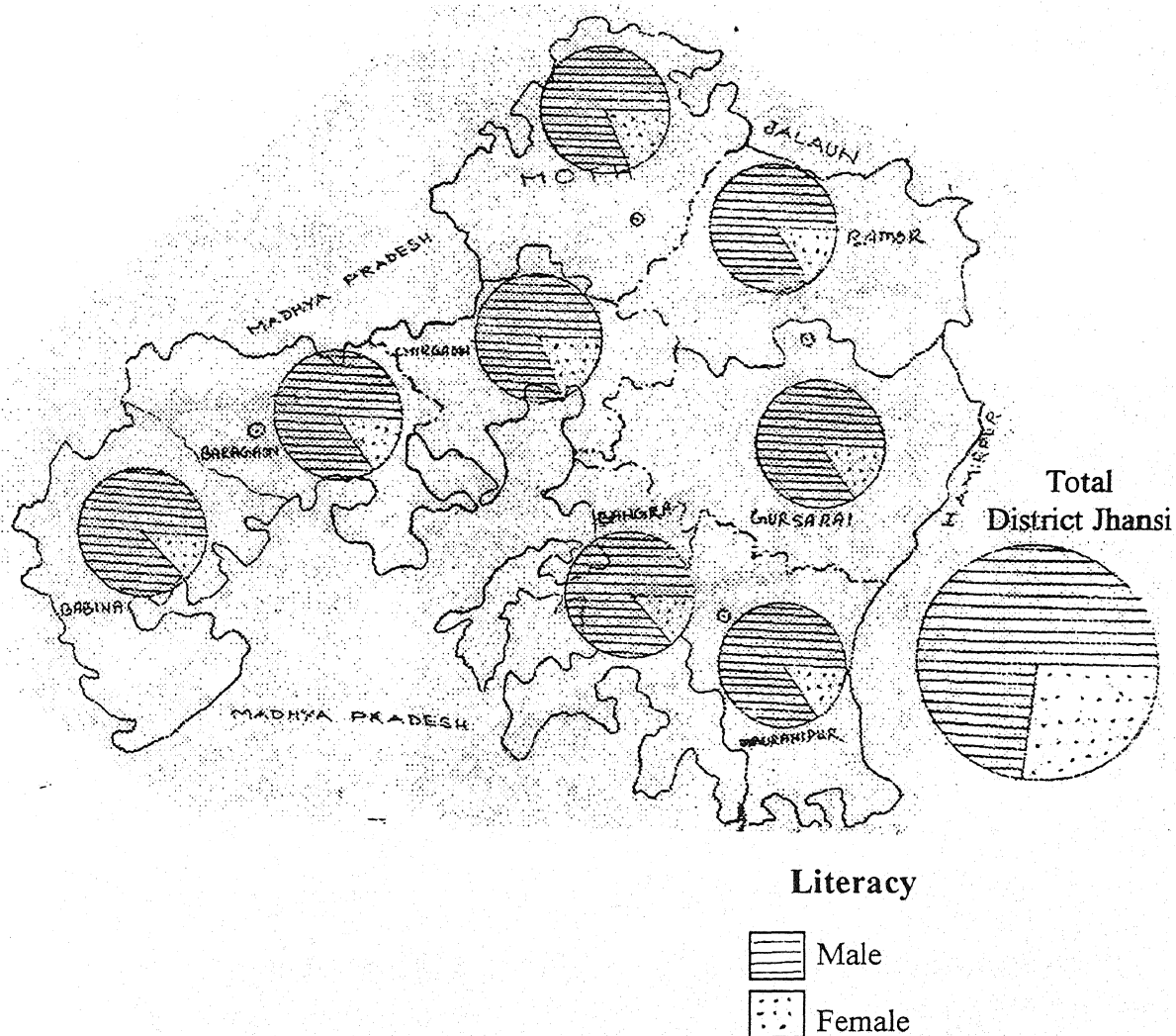
Fig. 2.8 A

5	बंगरा	29.19	42.51	13.77
6	मऊरानीपुर	31.05	44.66	15.24
7	बबीना	26.85	39.21	12.80
8	बड़गाँव	32.55	47.25	15.22

स्रोत – राष्ट्रीय सूचना केन्द्र जनपद झाँसी से प्राप्त जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर।

सारिणी संख्या 2.10 के परीक्षण से स्पष्ट है कि चिरगाँव विकासखण्ड में पुरूष (54.85) तथा महिला 19.09 प्रतिशत साक्षरता सर्वाधिक है जबकि बबीना विकासखण्ड पुरूष (39.21) प्रतिशत तथा महिला (12.80) प्रतिशत साक्षरता में सबसे पीछे है। अतः स्पष्ट है कि जनपद झांसी में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। विशेषता महिलाओं की जागरूकता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

व्यावसायिक संरचना – किसी भी क्षेत्र की सृजनात्मकता तथा आर्थिक विकास के ढांचे को समझने हेतु वहां की कार्यात्मक संरचना का अध्ययन आवश्यक होता है। कार्यात्मक संगठन किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता पर प्रकाश डालने हेतु प्रभावशाली कारक होता है। 1991 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या का ३०.१ प्रतिशत जिसमें ४७.७ प्रतिशत प्रमुख तथा ८.८ प्रतिशत स्त्रियां हैं। जबकि 1981 में 27.81 प्रतिशत जनसंख्या ही विभिन्न क्रियाओं में संलग्न थी जिसमें 47.39 प्रतिशत पुरूष तथा 5.27 प्रतिशत महिलायें थीं। 1981 तथा 1991 के आँकड़ों से स्पष्ट है कि कार्यशील जनसंख्या में खासतौर पर महिलाओं की संख्या में बहुत मामूली प्रगति हुई है।

जो जनसंख्या वृद्धि उसकी तुलना में नगण्य है। विकास खण्ड स्तर पर जनपद झाँसी की व्यावसायिक संरचना को सारिणी संख्या 2.11 में प्रदर्शित किया है।

सारिणी संख्या 2.11

विकासखण्ड स्तर पर जनपद झाँसी की व्यावसायिक संरचना का वितरण

विकासखण्ड	कार्यशील		सीमान्त कार्यशील		अक्रियाशील	
	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
मौंठ	36354	30.6	12324	10.4	69946	58.9
चिरगाँव	35829	34.2	9630	9.2	59354	56.6
बामौर	33934	33.0	7646	7.4	61487	59.6
गुरसरॉय	34703	33.4	9765	9.4	59445	57.2
बंगरा	34957	31.5	6906	6.1	69201	62.9
मऊरानीपुर	40459	34.5	7655	6.5	69006	58.9
बबीना	36491	33.2	4956	4.5	68565	62.3
बड़गाँव	30470	32.2	3959	4.2	60255	63.6
वनक्षेत्र	11	24.4	04	8.8	30	66.6
योग ग्रामीण	283208	32.8	62845	7.3	517289	59.9
योग नगरीय	147759	26.1	5843	1.1	412763	72.8
योग जनपद	430968	30.1	68684	4.8	930052	65.1

स्रोत – जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 1994 तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र जनपद झाँसी से प्राप्त 1991 के आंकड़े के आधार पर संगणित।

सारिणी संख्या 2.11 व चित्र संख्या 2.8 बी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या 30.1 प्रतिशत सीमान्त कार्यशील ४.८ प्रतिशत तथा अकार्यशील जनसंख्या ६५.१ प्रतिशत है। पर अक्रियाशील जनसंख्या का भार है। क्योंकि कमाने वालों से खाने वाले अधिक हैं। सारिणी संख्या 2.6 के सूक्ष्म अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि नगरीय क्षेत्र (26.1 प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में क्रियाशील जनसंख्या 32.8 प्रतिशत अधिक है। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या मऊरानीपुर 34.5 प्रतिशत में है। जबकि सबसे कम कार्यशील जनसंख्या मोंठ 30.6 प्रतिशत विकासखण्ड में है। अध्ययन क्षेत्र की कार्यात्मक संरचना अधिकांशतः सामान्य है। क्योंकि यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। जहां पर कुल कार्यशील जनसंख्या में 46.5 प्रतिशत कृषक तथा 15.6 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रकार कार्यशील जनसंख्या के 62.1 प्रतिशत भाग पर कृषक तथा कृषि मजदूर का वर्चस्व है। इसके अलावा कार्यशील जनसंख्या के 1.0 प्रतिशत लोग पशुपालन व वृक्षारोपरण, 0.2 प्रतिशत उद्योग व खनन, 3.4 प्रतिशत पारिवारिक उपयोग कार्यों, 5.8 प्रतिशत गैर पारिवारिक उपयोग कार्यों 2.0 प्रतिशत निर्माण कार्य 7.4 प्रतिशत व्यापार तथा वाणिज्य, 5.8 प्रतिशत यातायात संचार तथा 12.3 प्रतिशत लोग अन्य कार्यों में लगे हैं। कृषि कार्यों में अधिकांश लोगों के लगे होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफी कम है। जिसका प्रमुख कारण लघु तथा सीमान्त कृषकों की अधिकता है। जो कि आज

DISTRICT JHANSI
OCCUPATIONAL STRUCTURE WORKER, MARGINAL WORKERS and NON MARGINAL WORKERS (1991)

N

MOTH
JALAUN
BAMOR
MADHYA PRADESH
CHIRGAON
GURSARAI
MADHYA PRADESH

Total Jhansi District

Fig 2.8 B

भी परम्परागत कृषि तकनीक अपनाते हुए अपने परिवार की जीविका का निर्वाहन कर रहे हैं। कृषि में नवीन तकनीक अपनाने की हैसियत भी इनमें नहीं है।

सारिणी संख्या 2.12 में कार्यशील जनसंख्या के अन्तर्गत प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यों में लगे लोगों को दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 2.12

जनपद झांसी में प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में संलग्न जनसंख्या का विवरण, विकास खण्ड स्तर पर, 1991

विकासखण्ड	प्राथमिक कार्य (प्रतिशत में)		द्वितीयक कार्य (प्रतिशत में)		तृतीयक कार्य (प्रतिशत में)	
मोंठ	33369	91.8	747	2.0	2238	6.2
चिरगाँव	32327	90.2	1236	3.5	2266	6.3
बामौर	31625	93.2	772	2.3	1538	4.5
गुरसरॉय	31691	91.3	1136	3.3	1877	5.4
बंगरा	29662	84.9	2842	8.1	2453	7.0
मऊरानीपुर	35349	87.4	2526	6.2	2585	6.4
बबीना	28805	78.9	3459	9.5	4227	11.6
बड़गाँव	23692	77.8	2146	7.0	4632	15.2
योग ग्रामीण	246520	87.0	14864	5.3	21816	7.7
योग नगरीय	26712	18.0	33404	22-	87644	59-

				6		3
योग जनपद	273233	63.4	48268	11-2	109460	25-4

स्रोत – राष्ट्रीय सूचना केन्द्र जनपद झांसी से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, संगणित।

सारिणी संख्या 2.12 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या (63.4 प्रतिशत) प्राथमिक क्रियाओं 11.2 प्रतिशत द्वितीयक क्रियाओं तथा 25.4 प्रतिशत जनसंख्या तृतीयक कार्यो में लगी है। द्वितीय कार्यो में जनसंख्या का प्रतिशत कम होने का एक मात्र कारण इस क्षेत्र में उद्योग धन्धों का अभाव है। द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाशील जनसंख्या वर्ग में अधिकांशतः अकुशल श्रमशक्ति कार्यरत हैं। अतः कुशल श्रमशक्ति की वृद्धि हेतु तथा रोजगार के अवसर सुलभ करने के उद्देश्य से उत्पादन मिश्रित एवं तकनीक मिश्रित उपागमों के विकास की आवश्यकता है (मिश्र, 1981)।

अधिवास तंत्र (Settlement System) – अध्ययन क्षेत्र की 60.39 प्रतिशत जनसंख्या (1991) ग्राम्य वातावरण में निवास करती है। जबकि 39.61 प्रतिशत लोग नगरीय परिवेश में रहते हैं। 1981 में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 62.06 तथा 39.94 था ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के तुलनात्मक परीक्षण से स्पष्ट है कि क्षेत्र में धीरे–धीरे ग्रामीण जनसंख्या में कमी आ रही है। जबकि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जिसका प्रमुख कारण न केवल प्राकृतिक विनाश है बल्कि ग्रामीण जनता का नगरों में बसने की प्रवृत्ति तथा नगरीय क्षेत्र की विभिन्न सुविधाओं का आकर्षण

है। इसीलिए वर्तमान समय में लोग गाँव छोड़कर नगरों में रहना अधिक पसन्द करते हैं। नगरीय क्षेत्र की सुविधाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, बिजली, पानी के अलावा सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख है। वर्तमान समय में जनपद झाँसी में 14 नगरीय केन्द्र हैं। जिनमें एक नगर महापालिका पाँच नगर पालिकाएँ सात नगर क्षेत्र समितियाँ तथा एक छावनी क्षेत्र है। इनमें झाँसी नगर जनपद तथा कमिश्नरी मुख्यालय होने के साथ–साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। यह प्रथम श्रेणी का शहर है। जबकि अन्य 13 तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के नगर हैं। जनपद झाँसी में 1981 में आबांद ग्रामों की कुल संख्या 759 थी जो कि 1991 में बढ़कर 760 हो गयी (सारिणी संख्या 2.13)।

सारिणी संख्या 2.13

जनपद झाँसी में ग्रामीण तथा नगरीय केन्द्र (1981-1991)

वर्ष	कुल ग्राम	आबाद ग्राम	गैर आबाद ग्राम	वन ग्राम	नगरीय केन्द्र
1981	840	759	81	N.A.	16
1991	839	760	79	03	14

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका जनपद झाँसी 1996।

जनपद झाँसी में विभिन्न आकारों के आधारों पर आबाद गाँवों की संख्या सारिणी संख्या 2.14 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 2.14

जनपद झाँसी में विभिन्न आकार के आबाद गाँवों की संख्या (1981-91)

जनसंख्या क्रम	200 से कम	200-499	500-1999	2000-4999	5000-9999	10000 से अधिक	योग
आबाद ग्राम 1981	72	183	437	65	02	–	759
आबाद ग्राम 1991	54	169	442	83	12	–	760

स्रोत – राष्ट्रीय सूचना केन्द्र जनपद झाँसी से प्राप्त 1991 के आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर।

सारिणी संख्या 2.14 के परीक्षण से ज्ञात हेता है कि जनपद झांसी में आकार की दृष्टि से आबाद गांवों की सर्वाधिक संख्या 5000-1999 की जनसंख्या वाले गांवों की है। जनपद में 10,000 से अधिक आवादी वाला कोई गांव नहीं है। तथा 5000 से 9999 की जनसंख्या वाले गांवों की संख्या केवल 12 है।

यातायात एवं संचार व्यवस्था (Transport and Communication System) - क्षेत्रीय विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में मानव की सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति एवं आर्थिक विकास में यातायात तथा संचार प्रणाली सदैव से एक महत्वपूर्ण कारक रही है। केवल समयानुसार यातायात तथा संचार के साधनों में परिवर्तन हुआ है। विभिन्न प्रकार की वस्तुयें तथा विचारों को एक

स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली इस यातायात तथा संचार व्यवस्था का विकास किसी क्षेत्र के प्राकृतिक भूदृश्य संसाधन स्वरूप तथा मानव जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति की अवस्था राजनैतिक दशाओं और तत्जनित प्रादेशिक विविधता द्वारा हुआ।

परिवहन व संचार व्यवस्था के अन्तर्गत सड़क तथा रेल, परिवहन, डाकघर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्श तथा टेलीप्रिन्टर आदि आते हैं। झांसी जनपद में रेल यातायात की तुलना में सड़क यातायात का विकास अधिक हुआ है। क्योंकि यहां का धरातल समतल तथा ऊबड़–खाबड़ दोनों प्रकार का है। जनपद झांसी में कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 1218.96 किमी. है, जबकि रेल लाइन की लम्बाई मात्र 171 किमी. ही है। यहां पर 111 बस स्टेण्ड तथा 18 रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित) है। यहां पर प्रति हजार कि०मी० पर सड़कों तथा रेल मार्ग की लम्बाई क्रमशः 247.6 तथा 24.0 किमी. है। यहां के 14 नगरीय केन्द्र तथा प्रमुख गांव एक दूसरे से पक्की तथा कच्ची सड़कों से जुड़े हैं। शोध क्षेत्र से होकर एक राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 25 लखनऊ शिवपुर रोड गुजरता है। झांसी यहां का सबसे बड़ा नगरीय केन्द्र है, जहां से चारो दिशाओं के लिए रेल तथा सड़क मार्ग जाते हैं। झांसी रेलवे का प्रमुख जंक्शन है। यहां से दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कानपुर, आगरा, हैदराबाद, इन्दौर, भोपाल, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा इलाहाबाद जैसे नगरों को रेलवे सुविधा है। डाकतार टेलीफोन सेवा का विकास वर्तमान समय में प्रगति का सूचक है। अध्ययन क्षेत्र में 200 तक डाक घर हैं, जिनमें 167 नगरोय तथा 33 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यहां तार घरों की संख्या 31 तथा टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

9200 है जो इस क्षेत्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। जनपद में प्रतिलाख जनसंख्या पर तारघर 2.1 टेलीफोन 252.6 तथा डाकघर 14.0 है। झांसी जनपद यातायात तथा संचार की दृष्टि से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित जिला है। किन्तु क्षेत्रीय उपयोगिता तथा विकास को देखते हुए प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अभी भी यहां यातायात एवं संचार के साधनों को विकसित करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन गति पर है।

अवस्थापना सुविधाएँ (Infrastructure Facilities) :– लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं की प्रगति के लिए शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की स्थापना ग्राम्य अधिवासों में भी की गयी है। सेवाकार्यों की स्थिति एवं उनके द्वारा विविध प्रकार के गांवों को दी जाने वाली सुविधाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र के अधिकतर गांव विभिन्न सुविधाओं से 5 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित हैं। अर्थात उनको सेवा प्राप्ति हेतु 5 कि.मी. से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। उदाहरणार्थ यदि शिक्षा व्यवस्था को ही देखा जाय तो वर्तमान स्थिति में लगभग 150 गांव ऐसे हैं जहां पर जूनियर बेसिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिये ग्राम्य वासियों के छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने हेतु पांच किमी. से अधिक दूरी तय करके दूसरे गांवों को जाते हैं सीनियर बेसिक स्तर की बालिका वर्ग की शिक्षा सुविधा जनपद के केवल 28 गांवों में ही है, जो बड़ी दयनीय स्थिति प्रकट करता है। क्षेत्र में महिलाओं के लिए अब भी शिक्षा व्यवस्था का पर्याप्त अभाव है यही कारण है कि

वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी धर्म जाति अशिक्षा तथा अज्ञान से दबी रहने को मजबूर हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बालिकाओं को 5 वी कक्षाओं से ऊपर पढ़ाने के लिए बाहर भेजने की व्यवस्था कर पाते हैं। नजदीक दूरी पर बालिका विद्यालयों का अभाव बढ़ती हुई आवश्यकता, अनुशासनहीनता, असुरक्षा तथा सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण माता–पिता अपनी युवा बालिकाओं को अधिक दूरी पर स्थित विद्यालयों में भेजने से कतराते हैं। अतः स्त्री शिक्षा स्तर में वृद्धि हेतु आवश्यकतानुसार बालिका विद्यालय खोलने की महती आवश्यकता है (मिश्र एवं पाल ,1989)। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन बालिकायें उच्च शिक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकती। केवल धनी परिवारों की बालिकाएं ही महिला संरक्षकों के साथ नगरों में पढ़ने जाती है मिश्र एवं नामदेव (1996)। इसी प्रकार स्वास्थ्य बैकिंग संचार सम्बन्धी अन्य सुविधायें भी ग्रामीण क्षेत्रो में बहुत कम स्थापित हैं (सारिणी संख्या 2.15) इसके अतिरिक्त क्षेत्र के 40 प्रतिशत गांवों की दूरी सेवा केन्द्रों से 10 कि.मी. से अधिक है जिसका प्रमुख कारण यातायात तथा परिवहन के साधनों का समुचित विकास न होना ही कारण है कि अध्ययन क्षेत्र में ग्रामवासी वर्तमान आर्थिक विकास युग में भी विकासात्मक उपलब्धियों से आवश्यकतानुसार लाभान्वित नहीं हैं (खान 1987)। इसके अलावा दूरस्थ गांवों तक सेवा केन्द्रों से विकासात्मक नीतियों तथा सरकारी मुख्यालयों से कल्याणकारी नीतियों का उचित प्रसारण नहीं हो पाता और एक बड़ा ग्राम्य समाज राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा के साथ विकास को गति प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः ग्राम्य वातावरण में रहने वाली ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सेवा कार्यों की

स्थापना ग्राम से 3 या 4 किमी की दूरी पर हो और वह केन्द्र सड़क यातायात से अपने चारों ओर स्थित सेवाकेन्द्रों से जुड़ा हो ताकि वर्ष पर्यन्त ग्रामीण जनता को वे आधारभूत सुविधाओं तथा सेवाकेंन्द्रों की प्राप्ति हो, आधार भूत सुविधाओं तथा सेवाकेन्द्रों की प्राप्ति सहजता से हो सके और अत्यधिक पिछड़ा ग्राम्य समाज राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान से वंचित न रह पाये।

सारिणी संख्या 2.15

जनपद झांसी में ग्रामों से दूर सुलभ सुविधायें – 31 मार्च 1996

क्र०सं०	उपलब्ध सेवाएँ/सुविधाएँ	ग्राम में	1 किमी० से कम	1-3 किमी०	3-5 किमी०	5 से अधिक	कुल आबाद ग्राम
1	जूनियर बेसिक स्कूल मिश्रित	622	20	74	29	15	760
2	सीनियर बेसिक स्कूल (बालक)	152	39	139	229	201	760
3	सीनियर बेसिक स्कूल (बालिका)	28	14	49	113	556	760
4	हायर सेकेन्डरी स्कूल (बालक)	27	12	50	97	574	760
5	हायर सेकेन्डरी स्कूल (बालिका)	09	04	18	54	675	760
6	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	39	-	01	06	714	760
7	एलोपैथिकचिकि०/औषधा०/पी०एच०सी०	47	13	33	62	605	760
8	आयूर्वेदिक चिकि०/औषधालय	21	14	37	80	608	760
9	यूनानी औषधालय	-	01	03	13	743	760

10	पारिवारिक कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र	253	44	105	159	199	760
11	पक्की सड़के	237	49	158	179	137	760
12	डाक घर	167	20	184	196	193	760
13	तार घर	06	05	44	99	606	760
14	सार्वजनिक टेलीफोन	38	08	31	30	653	760
15	रेलवे स्टेशन	13	03	36	69	639	760
16	बस स्टेशन/स्टाप	96	42	99	136	387	760
17	सहकारी कृषि ग्राम विकास बैंक	-	03	12	37	708	760
18	व्यावसायिक/ग्रामीण/सह०बैंक	42	28	57	145	488	760
19	समितियाँ	60	14	89	141	456	760
20	कय विकय समितियाँ	-	05	22	56	677	760
21	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र	29	06	58	89	578	760
22	पशु चिकित्सालय/पशुपालनकेन्द्र	22	19	64	90	565	760
23	बीजगोदाम/उर्वरक/कीटनाशक	115	11	33	42	559	760
24	शीत गोदाम	02	-	03	06	749	760
25	थोक मण्डी	03	06	24	62	665	760
26	बाजार/हाट	71	16	103	126	444	760
27	कृषि सुविधा केन्द्र	57	06	48	94	555	760
28	सस्ते गल्ले की दुकान	587	103	80	30	08	760
29	ग्राम सेवक	80	06	83	189	402	760

DISTRICT JHANSI

TRANSPORTATIONAL NETWORK
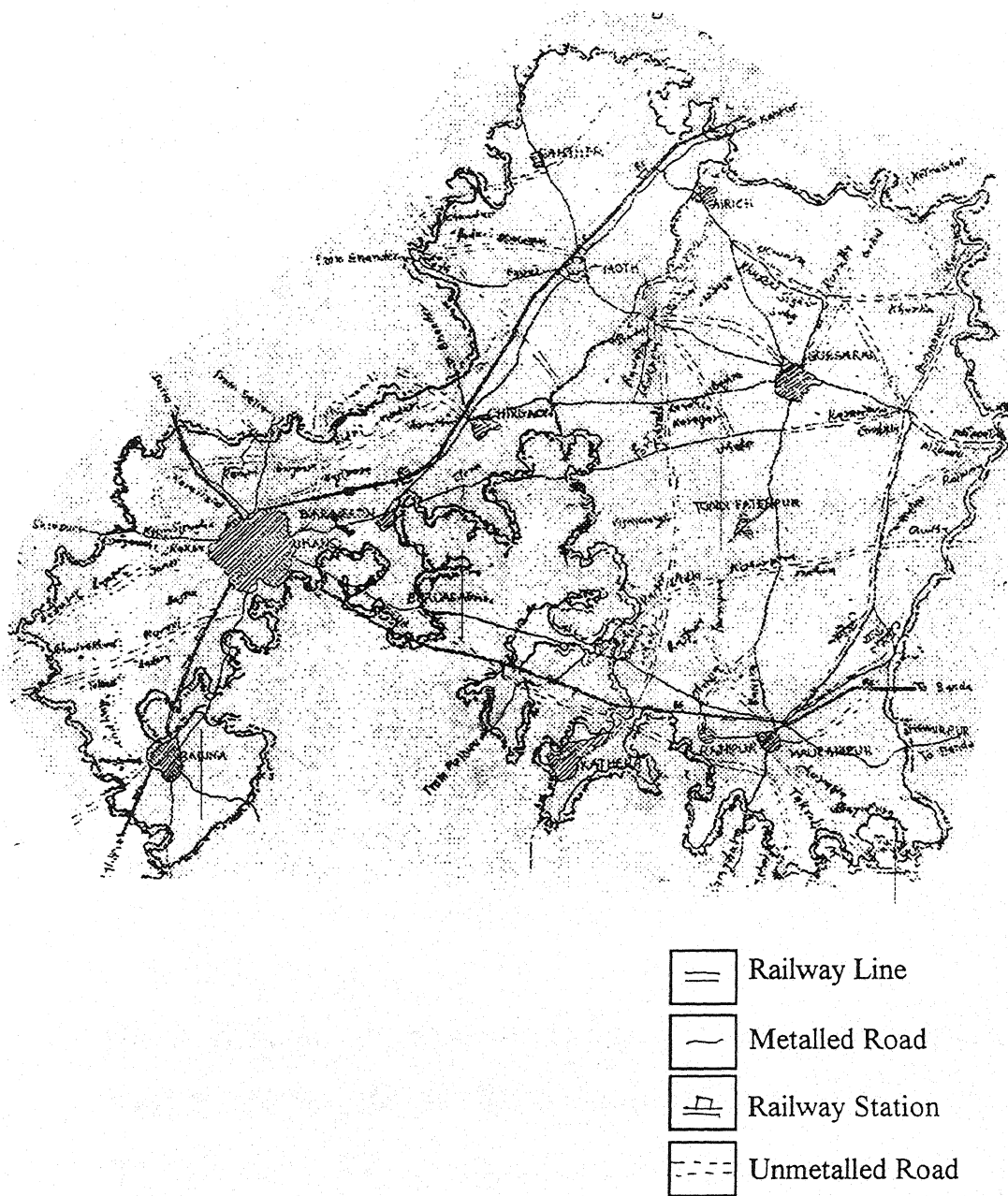
Fig. 2.9

30	सामाजिक सुविधा केन्द्र	05	03	22	55	675	760

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका जनपद झाँसी, 1996।

REFERENCES Chandra, R.C. and Sindhu, M.S. (1980), Introduction to Population Geography, Kalyani Publishers, New Delhi, Page 19.

Demko, G.T., Rose H.M., and Sonel G.A. (1970), Populaiton Geography: A Reader, Mc Graw – Hill book Co. New York, Part IV, P. 22.

Joshi, E.B., State Editior, Gazetteer of India, Uttar Pradesh, Jhansi, 1965, P.I.

Khan, T.A. (1987) Role of Service Centers in the Spatial Development : A Case Study of Maudaha Tahsil of Hamirpur District in U.P., Unpublished Ph. D. Thesis in Bundelkhand University, Jhansi.

Misra, K.K. (1981) System of Service Centres in Hamirpur District, U.P. (India), Unpublished Ph.D. thesis, Bundelkhand University, Jhansi.

Misra, K.K. & Pal, Ketram (1989), Increasing Population of Present Problems of Bundelkhand Region, U.P. Paper Presented in the National Symposium under COHSSIP

Scheme of U.G.C., Atarra P.G. College, Atarra, December 22.23.

मिश्र कृष्ण कुमार (1996), बाँदा जनपद विकास की दृष्टि में, सिद्धार्थ ज्योति अंक। मई, पृष्ठ 23-25.

Misra, K.K. & Namdeo, R.C. (1996), Spatial Distribution and Planning of Social Amenities: A Case Study of Tahsil Orai, U.P. Geo-Science Journal, N.G.S.I., Varanasi, Vol II, Part 1and 2, P.P. 17-26.

मिश्र, कृष्ण कुमार (1997), परम्परागत घरेलू धन्धों और उनका बदलता स्वरूप, कुरूक्षेत्र, जून, अंक 8, पृष्ठ 25।

मिश्र, कृष्ण कुमार (1999), प्राकृतिक संसाधनों के दुरूपयोग से गाँवों की अस्मिता खतरे में, कुरूक्षेत्र, फरवरी, अंक 4, पृष्ठ 21-23.

Misra, K.K.(1999), Soil and Water Conservation in the Hilly Area of Chitrakut Dham Mandal, Paper presented in the National Seminar on Ethnobiology, Sponsered by U.G.C., Janata College, Rewa, November 20-21,Page –6.

सिंह, ए० के० (1999), कृषि नवाचारों के विसरण में सेवाकेन्द्रों की भूमिका, चरखारी तहसील, एक प्रतीकात्मक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय, झाँसी।

Verma, R.V. (1997), भारत का भौगोलिक विवेचन, किताब घर, कानपुर, पृष्ठ 539।

अध्याय - ३

जनसंख्या वृद्धि एवं आकार (POPULATION GROWTH AND SIZE)

जनसंख्या वृद्धि एवं आकार (POPULATION GROWTH AND SIZE)

वस्तुतः निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या आज की ज्वलन्त समस्या है। इसलिए नियोजित विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि एवं आकार के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही है जबकि इस अनुपात में संसाधनों के विकास की गति काफी धीमी एवं सुस्त है। परिणामतः मानवीय आवश्यकताएं अच्छी प्रकार से पूर्ण नहीं हो पा रही है। मानव की सर्वोत्तम कल्याण की सोच के बावजूद भी खाद्य पदार्थों का अभाव उसे खुशहाली व शान्ति प्रदान कर पाने में असमर्थ रहता है। समस्या की यह स्थिति विकासोंन्मुख देशों में काफी गम्भीर रूप धारण किए हुये है। हमारा देश इस संदर्भ में एक प्रमाण है।

वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है जबकि धरातलीय क्षेत्र विश्व का मात्र 2.4 प्रतिशत है। हमारे देश में 1901-11 के दशक के मध्य जनसंख्या की वृद्धिदर 5.75 प्रतिशत थी जो कि 1981–91 में बढ़कर 22.34 प्रतिशत तक पंहुच गई है। भारत अन्य क्षेत्रों की भांति उत्तर प्रदेश में अवस्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी जनपद की जनसंख्या वृद्धि भी विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। जनसंख्या वृद्धि दो समयों के मध्य जनसंख्या में हुये परिवर्तन को कहते हैं। परिवर्तन ऋणात्मक होने पर जनसंख्या घटती है, जिसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं जबकि धनात्मक परिवर्तन होने पर जनसंख्या बढ़ती है, और उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं (रॉय,1979)।

किसी क्षेत्र की जनसंख्या के अध्ययन में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण उपादान है। वस्तुतः जनसंख्या के विभिन्न पक्ष जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित होते है अतः इनका महत्वांकन भी इसी परिप्रेक्ष्य में किया जाता है (चांदना एवं सिद्धू, 1980)।

जनसंख्या वृद्धि वास्तव में क्षेत्र विशेष के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास के साथ–साथ ऐतिहासिक घटनाओं एवं राजनैतिक स्वरूप का प्रतिफल होती है। जनसंख्या में यदि उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है तो यह भूमि पर भार बन जाती है (दास, (1976)। इसके प्रभाव से प्रतिवर्ष खाद्य पदार्थों एव अन्य संसाधनों के अभाव की समस्या बढ़ती जाती है। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्यक्षतः सामाजिक विघटन, स्वास्थ्यवर्द्धक पर्यावरण में गिरावट, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी तथा शैक्षिक असुविधाओं का जन्म होता है जबकि परोक्षप्रभाव के फलस्वरूप प्रदूषित वातावरण, सांस्कृतिक कियाओं की असमानता तथा मनोरंजन के साधनों पर नियंत्रण का अभाव हो जाता है। अतः जनसंख्या सम्बन्धी इस प्रकार के प्रभाव के कारण मानवीय कियाकलाप अव्यवस्थित हो जाते हैं और विकास में रूकावटें आने लगती हैं तथा सुविधा–संरचना में कमी हाने लगती है।

जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक (Main Factors of Population Growth)

किसी भी क्षेत्र के विकास में वहां की जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें समय–समय पर परिवर्तन होता रहता है (हैगेट,1977)। जनसंख्या वृद्धि को विशेष रूप से तीन आधारभूत कारक प्रभावित करते हैं जिनमें जन्मदर, मृत्युदर व जनसंख्या प्रवास मुख्य हैं। अतः क्षेत्र की जनसंख्या तृद्धि की गणना हेतु उक्त तीनों कारकों पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता हैं।

प्रजननता (Fertility)

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार प्रधानतः उसकी प्रजननता एवं मृत्युदर पर निर्भर करता है। यदि जन्मदर मृत्युदर की तुलना में अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी और यदि जन्मदर, की अपेक्षा मृत्युदर अधिक है तो जनसंख्या में कमी होगी । जन्म जनसंख्या की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें एक नया सदस्य शून्य की आयु पर जनसंख्या में प्रवेश होता है। जन्मदर का आंकलन सामान्यतः प्रति

हजार व्यक्तियों पर प्रतिवर्ष हाने वाले जन्मों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार जन्मदर या प्रजननता दर से तात्पर्य किसी समय विशेष में जन्म लेने वाले बच्चों की आवृत्ति से है। स्त्री की प्रजनन क्षमता मानव समाज की निरन्तरता का आधार है। यदि महिलाओं में प्रजनन क्षमता नहीं होती तो सृष्टि का अन्त हो जाता। वस्तुतः प्रजनन क्षमता से तात्पर्य स्त्री के गर्भधारण करने की क्षमता से हैं जबकि प्रजननता का अर्थ पूरे समय बाद महिला द्वारा बच्चे को जन्म देने की क्षमता से है क्योंकि कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिन्हें गर्भ तो ठहरता है लेकिन कुछ समय बाद गर्भपात हो जाता है। अतः वे पूरे समय का बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहती हैं। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि प्रजननता से प्रभावित होती हैं, प्रजनन क्षमता से नहीं। यह भी स्मरण रहे कि प्रजननता भी महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर निर्भर करती है। स्त्रियों की प्रजननता उनकी प्रजनन क्षमता पर आधारित होती है। समान्यतः प्रजननता की जानकारी हेतु अशोधित जन्मदर, प्रजननता, अनुपात एवं सामान्य प्रजननता दर जैसी अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें प्रजननता अनुपात के माध्यम से प्रजनन आकार के सम्बन्ध में अशोधित जन्मदर की तुलना में अच्छे निष्कर्ष प्राप्त होते हैं क्योंकि इसमें जन्मसंख्या की आयु एवं लिंग संरचना को ध्यान में रखते हुए गणना का कार्य सम्पन्न होता है। परन्तु जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण यहां पर अशोधित जन्मदर की भी गणना की गई है। यहां पर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से विभिन्न वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या प्राप्त की गई है। झांसी जनपद की जनसंख्या में उच्च जन्मदर पाया जाता है जो वर्ष 1991 में 32.5 प्रति हजार थीं जबकि 1951 में जन्मदर 40.3 प्रति हजार थी। इसे निरन्तर घटाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है।

क्षेत्र में उच्च प्रजननता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है प्रजननता वृद्धि के कारकों में

कम आयु में विवाह होना, निर्धनता, शिक्षा का अभाव, संयुक्त परिवार प्रथा, जलवायु, न्यूनता जीवन स्तर, परम्परागत जीवन दर्शन व रूढ़वादिता आदि प्रमुख हैं। वस्तुतः शोध क्षेत्र में बाल विवाह प्रथा यहां की जन्मदर को सबसे अधिक प्रभावित करती है क्योंकि 20 वर्ष से कम आयु में ही मां बनने से एक महिला अपनी सम्पूर्ण प्रजनन अवधि में अधिक बच्चों को जन्म देती है। क्षेत्र में सामाजिक विकास की धीमी गति लोगों की निर्धनता, साक्षरता का निम्न स्तर, परिवार नियोजन कार्यक्रमों की धीमी प्रगति आदि इस तथ्य के सूचक हैं कि यहां पर प्रजननता दर अधिक है।

झाँसी जनपद में प्रजननता की विभिन्नता का पता लगाने के लिए झाँसी नगर व उसके आस–पास स्थित तीन गांवों (मथुरापुर, बिजाली, भगवन्तपुर) के विभिन्न धर्मों तथा जाति वर्गों से सम्बन्धित 100 परिवारों (20 उच्च जाति, 25 पिछड़ी जाति, 20 अनुसूचित जाति, 20 मुस्लिम तथा 10 इसाई वर्ग) का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पारिवारिक आय, व्यवसायिक संरचना, शिक्षा स्तर, रीति रिवाज एंव धार्मिक मान्यताएं, ग्रामीण एंव नगरीय परिवेश आदि मानकों को ध्यान में रख गया। सर्वेक्षण से जो तथ्य प्रकाश में आये वे निम्न हैं :–

चयनित गांवों में अन्य जाति वर्ग की तुलना में उच्च वर्ग की 25 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं में बच्चे अधिक पैदा होते हैं जबकि पिछड़े वर्ग में 20–30 आयुवर्ग, में अधिक दलित वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में सर्वाधिक बच्चे 15–20 आयुवर्ग में। अर्थात् इस जाति समूह में बाल विवाह का प्रचलन स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। मुस्लिम महिलाओं में 15-35 वर्ष तक बहुत अधिक बच्चे पैदा होने की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। मुस्लिम महिलाओं में 15-20, 20-25, 25-30 तथा 30-35 आयु वर्गानुसार क्रमशः 1:2.19, 1:1.79, 1:1.88 तथा 1:1.99 प्रजनन अनुपात पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम परिवारों की महिलाओं में बहुत समय तक प्रजनन क्षमता रहती है।

सर्वेक्षण के दौरान 15 से 25 वर्ष की इसाई वर्ग की महिलाओं में अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति पाई गई। 40 वर्ष की उम्र के पश्चात इस वर्ग की महिलाओं में

बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति नगण्य है।

नगर केन्द्र झांसी में उच्च जाति के 20 परिवारों की महिलाओं के सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि 15 से 35 वर्ष के मध्य आयु वाली महिलाओं में प्रजनन अनुपात सर्वाधिक है जबकि 35 से 50 वर्ष की महिलाओं में बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति नगण्य है। 20 से 25 आयु वर्ग की महिलाओं में प्रजनन अनुपात 1.0:2.1 है। पिछड़ी जाति के 25 नगरीय परिवारों की महिलाओं में 20-25 आयु वर्ग में सबसे अधिक बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है इसी प्रकार की स्थिति 20-25 आयुवर्ग की अनुसूचित परिवारों की महिलाओं में पाई जाती है।

ग्रामीण एंव नगरीय आधार पर महिलाओं में प्रजनन विभिन्नता को सारिणी 3.1 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या – 3.1

ग्रामीण एंव नगरीय आधार पर महिलाओं में प्रजनन विभिन्नता

आयु वर्ग	प्रजनन अनुपात	
	नगरीय	ग्रामीण
15-20	2.0	2.03
20-25	2.0	2.50
25-35	2.0	1.32
35-40	1.0	1.49

स्रोतः स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो द्वारा संगणित।

सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रजननता 20-25 की ग्रामीण महिलाओं में दृष्टिगत होती है। 35 वर्ष के प्रश्चात नगरीय महिलाओं में प्रजनन अनुपात शून्य हो जाता है जबकि ग्रामीण महिलाओं में 50 वर्ष की आयु में भी बच्चे

पैदा करने की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है।

वस्तुतः आज भी अधिकांश ग्रामीण बच्चे का जन्म भगवान की देन मानते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजननता दर अधिक है। नगरीय लोगों का विचार है कि बच्चे का जन्म व्यक्ति के प्रजनन सम्बधी क्रियाओं पर निर्भर करता है। अतः वह परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों का उपयोग करके परिवार को सीमित रख सकते हैं। इसके अलावा नगर में व्यक्ति अवकाश के समय में सिनेमा, टेलीविजन, टेपरिकार्डर आदि साधनों व विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों, स्टेडियम में आयोजित विभिन्न खेलकूद कार्यक्रमों आदि में व्यस्त रहता है। अतः उसका ध्यान पारिवारिक प्रजनन सम्बन्धी क्रियाकलापों पर बहुत कम जाता है। यही कारण है कि प्रजननता दर सीमित रहती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन सम्बन्धी साधनों की कमी है अतः उनका अवकाश समय प्रजनन सम्बन्धी क्रियाओं में अधिक व्यय होता है साथ ही परिवार नियोजन के साधनों को भी कम अपनाते है। यहीं कारण है कि इनके परिवारों की संख्या बढ़ रही है।

इससे स्पष्ट होता है कि आय में वृद्धि के साथ–साथ प्रजनन अनुपात में कमी पाई जाती है। निर्धन परिवारों में सम्पन्न परिवारों की तुलना में प्रजनन अनुपात अधिक पाया जाता है। 10,000 से कम आय वाले सर्वेक्षित ग्रामीण परिवारों में प्रजनन अनुपात 1:5.8 पाया गया जबकि नगरीय परिवारों की महिलाओं में उसी आय वर्ग में प्रजनन अनुपात 1:4.3 पाया गया। 10,000 से अधिक आमदनी वाले ग्रामीण परिवारों में प्रजनन अनुपात 1:4.2 जबकि इसी आय वर्ग की नगरीय महिलाओं में यह अनुपात 1.0:3.08 पाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्थिक स्तर और प्रजननता में विपरीत सम्बन्ध है।

व्यावसायिक क्रियाकलापों में संलग्न ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों की प्रजननता अनुपात में विभिन्नता पाई जाती है (सारिणी संख्या 3.2)।

सारिणी संख्या – 3.2

विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापों में संलग्न महिलाओं में प्रजननता अनुपात

व्यावसायिक क्रियाकलाप	**ग्रामीण**	**नगरीय**
कृषि फार्म में संलग्न	4.38	-
खेतिहर मजदूर/दैनिक मजदूर	4.52	4.81
नौकरी	3.31	2.28
दूकान	2.54	2.8

स्रोत: स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो द्वारा संगणित।

सारिणी संख्या 3.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खेतिहर मजदूर वर्ग/दैनिक मजदूरों में संलग्न महिलाओं की प्रजननता विभिन्न नौकरियों में लगे परिवारों की महिलाओं से अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आय के प्रमुख स्त्रोतों व व्यवसाय का परिवार की महिलाओं की प्रजननता पर प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण व नगरीय परिवेश में अन्तर होने के कारण एक ही व्यवसाय में संलग्न परिवारों की महिलाओं की प्रजननता में अन्तर पाया जाता है।

ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में शैक्षिक स्तर के आधार पर प्रजननता में विभिन्नता पाई जाती है इसे सारिणी संख्या 3.3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 3.3

शैक्षिक स्तर के आधार पर प्रजननता

शैक्षिक स्तर	प्रजननता अनुपात	
	ग्रामीण	नगरीय
पूर्व माध्यमिक	4.34	4.12
माध्यमिक	3.98	3.10
स्नातक/परास्नातक	1.64	1.97
निरक्षर	4.89	3.71

स्रोत: स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों द्वारा संगणित।

सारिणी संख्या 3.3 के विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा स्तर में वृद्धि के साथ–साथ महिलाओं की प्रजननता में कमी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी विदित होता है कि एक ही शिक्षा स्तर होने के बावजूद ग्रामीण व नगरीय वातावरण में विभिन्नता के कारण प्रजननता में विभिन्नता पाई जाती है। निरक्षर ग्रामीण व नगरीय महिलाओं में भी यह स्थिति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

उपर्युक्त विभिन्न तथ्यों के अलावा धार्मिक मान्यताओं का प्रजनन पर विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। (सारिणी 3.4) धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ने में कानून व अधिनियम भी फीके पड़ जाते हैं।

सारिणी संख्या 3.4

धार्मिक आधार पर ग्रामीण व नगरीय महिलाओं में प्रजननता विभिन्नता

धर्म	ग्रामीण	नगरीय
हिन्दू	4.20	3.80
मुस्लिम	5.58	5.10
इसाई	4.31	2.64

स्रोतः स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो की गणना पर आधारित।

सारिणी संख्या 3.4 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई सम्प्रदाय महिलाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रजननता विभिन्नता मिलती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी रहस्योद्घाटित होता है कि ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलाओं में अन्य सम्प्रदाय की महिलाओं की अपेक्षा प्रजननता अधिक होती है।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण व नगरीय महिलाओं पर आर्थिक स्तर, व्यवसाय, पर्यावरण, शैक्षिक स्तर व धार्मिक मान्यताओं के फलस्वरूप प्रजननता में विभिन्नता पाई जाती है।

मृत्युदर (Death-Rate)

जनसंख्या वृद्धि के कारणों में मृत्यु एक प्रभावकारी संघटक है क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के उतार–चढ़ाव का निर्धारण मृत्युदर में विभिन्नता के कारण आता है। यदि किसी क्षेत्र की जनंसख्या में समान वृद्धि अत्यधिक जन्मदर या मृत्युदर के कारण होती है, तो वह उस क्षेत्र के अतिरिक्त होने का परिचायक है। इसके विपरीत कम जन्मदर तथा कम मृत्युदर क्षेत्र के विकास का सूचक है। क्षेत्र में मृत्युदर की अधिकता वहां पर अकाल अथवा महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के फलस्वरूप होती है क्योंकि जब क्षेत्र में अकाल एवं महामारी का प्रकोप बढ़ता है तब वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तथा संसाधनों के विकास की परिधि अवरूद्ध (अग्रवाल, 1972) हो जाती है। परिणाम स्वरूप भुखमरी व बेरोजगारी तीब्रगति से बढ़ती है। इससे जनजीवन तबाह होने लगता है और चिन्ता ग्रस्त मानव शारीरिक दुर्बलता से ग्रसित हो जाता है।

झाँसी जनपद बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक पिछड़ा क्षेत्र है। जिसका मुख्य कारण यहां अनुर्वरक एंव ऊबड़–खाबड़ भूमि का पाया जाना एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मंदगति से प्रगति होना है। सन्तुलित एवं पर्याप्त भोजन के अभाव में यहां मानव रूग्णताग्रस्त होकर असमय ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। इस असमयिक मृत्यु का सर्वाधिक प्रभाव बच्चों एवं स्त्रियों पर पड़ता है। क्योंकि क्षेत्र में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का प्रसार अधिक है। अस्तु लड़कियां अल्पायु में ही विवाहित होने से कम आयु मे ही मातृत्व धारण कर लेती हैं। गर्भ–धारण का अन्तराल भी काफी कम होता है। इन्हें पौष्टिक आहार भी नहीं मिलता। परिणामतः वे अत्यधिक दुबली हो जाती है तथा खून की कमी से अस्वस्थ्य रहने लगती है। इनसे उत्पन्न सन्तानें भी काफी दुर्बल एवं रोगग्रस्त होती हैं। उचित देखभाल व पौष्टिक भोजन के अभाव तथा ग्राम्य स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण यह बच्चे असमय ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अस्तु शोध क्षेत्र में बालमृत्यु व मातृमृत्यु

की अधिकता के कारण पारिवारिक जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। सारणी संख्या 3.5 में भारत व क्षेत्र में जन्मदर व मृत्युदर का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारिणी संख्या 3.5

जन्म एवं मृत्युदरों का अनुमान (प्रति हजार में)

क्र.सं.		अध्ययन क्षेत्र		भारत	
	दशक	जन्मदर	मृत्युदर	जन्मदर	मृत्युदर
1	1961-71	40.8	24.15	41.1	18.0
2	1971-81	39.6	16.01	36.6	14.0
3	1981-91	32.5	14.98	30.2	9.7

स्रोतः सोशल इनफारमेशन ऑफ इण्डिया (पृष्ठसंख्या 4) तथा जनगणना, 1991.

झाँसी जनपद में अशोधित मृत्युदर वर्तमान समय में 14.98 प्रति हजार है जबकि 1981 में यह मृत्युदर 16.01 प्रति हजार तथा 1971 में 24.15 प्रति हजार थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में मृत्युदर निरन्तर घट रही है जिसका प्रमुख कारण चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर अत्यधिक विस्तार होना है फिर भी शोध क्षेत्र की यह मृत्यु दर प्रदेश व देश (9.7 प्रति हजार) की तुलना में अधिक है।

स्थानान्तरण (Migration)

वस्तुतः जनसंख्या परिवर्तन में जन्म एवं मृत्यु के अलावा जन–स्थानान्तरण

तीसरा महत्वपूर्ण कारक है (द्विवार्थ, 1959)। जन्म एवं मृत्यु से किसी क्षेत्र की जनसंख्या में गणितीय परिवर्तन होता है जबकि जन–स्थानान्तरण से उसके साथ ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। यही वजह है कि जनसंख्या गत्यात्मकता में इसकी व्याख्या अति महत्वपूर्ण है। बोग (1959) ने ठीक ही कहा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक संगठन जन–स्थानान्तरण का फल होता है। सामान्यतः स्थानान्तरण में मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रव्रजन ही सम्मिलित नहीं होता है अपितु यह स्थानिक सम्बद्धता एंव तज्जनित सूझ–बूझ का परिणाम होता है।

मानव एक गतिशील प्राणी है जब किसी क्षेत्र में जनभार उसके आर्थिक संसाधनों की तुलना में असन्तुलित हो जाता है, तो वह अपने मूल स्थान को छोड़ कर अन्यत्र चला जाता है। परन्तु यह स्थानान्तरण आर्थिक कारणों के साथ ही साथ प्राकृतिक, राजनैतिक व सामाजिक कारणों से भी हो सकता है जैसे यदि कोई व्यक्ति एक स्थान पर जन्म लेता है और जनगणना के समय वह दूसरे स्थान पर रहने लगता है तो उसे जनगणना पुस्तिका में प्रवासी की कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार प्रवसन व स्थानान्तरण मानव संसाधन के सन्तुलन का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

वस्तुतः जनसंख्या स्थानान्तरण आयुप्रधान होता है। इसी लिए बालकों एवं वृद्धों की अपेक्षा कार्यशील युवकों तथा महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों का स्थानान्तरण अधिक होता है। अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा कुशल श्रमिक अधिक स्थानान्तरण करते हैं। नगरों में रोजगार पाने के उद्देश्य से भी अधिकांश लोग स्थानान्तरण करते हैं। यद्यपि स्थानान्तरण से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत कर पाना कठिन है फिर भी जनसंख्या स्थानान्तरण से सम्बद्ध सिद्धान्तों एवं माडलों को प्रस्तुत किया गया है (रोज, 1985)। पूर्व भूगोलविदों ने भी जनसंख्या स्थानान्तरण के लिए विस्तृत प्रकरणों को प्रस्तुत किया है (वेंग), साथ ही जीवन चक्र की परिकल्पना का उल्लेख किया है (चांदना एंव सिद्धू, 1980)। मानव में स्थानान्तरण की प्रवृत्ति मानव इतिहास

के प्रारम्भिक काल से ही देखने को मिलती है किन्तु औद्योगिक विकास से पूर्व मानव का स्थानान्तरण बहुत कम ही होता था। रेविन्स्टीन (1885–89) के अनुसार प्रवसन प्रवाह के उपरान्त रिक्त स्थान की सम्पूर्ति हेतु पूरक प्रवाह की प्रक्रिया भी जन्म लेती है। जिस प्रकार अन्य किसी वस्तु में चंचलता की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार जनसंख्या भी उन स्थानों की ओर प्रवाहित होती है, वहां उसके जीवकोपार्जन हेतु समुचित साधन उपलब्ध होते हैं। लेकिन सामान्यतः ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन प्रगति का परिचायक माना जाता है।

जनसंख्या का स्थानान्तरण मुख्यतः दो घटकों (i) प्रतिकूल घटक (ii) अनुकूल घटक के द्वारा होता है। यही दोनों घटक किसी स्थान की जनसंख्या को वहां से स्थानान्तरित होने के लिए बाध्य करते है। जनसंख्या का स्थानान्तरण उत्पत्ति एवं गन्तव्य दोनों स्थानों पर समुदायों के स्वरूप एवं सांस्कृतिक लक्षणों में भी परिवर्तन लाता हे। इस प्रकार स्थानान्तरण जनसंख्या के गम्भीरतापूर्वक वितरण में सांस्कृतिक विस्तार, सामाजिक एकीकरण एवं उनके परिणामों का एक यंत्र है। जनसंख्या के स्थानान्तरण का आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि स्थान परिवर्तन हेतु अधिकांशतः उत्पादक आयु वर्ग (15–59वर्ष) के व्यक्ति होते है जबकि बाल, बृद्ध एवं दुर्बल व्यक्ति मूल स्थान पर ही रहते हैं। अतः उत्पादक आयु वर्ग के लोग जिस क्षेत्र में पहुँचते हैं, उसे शक्तिशाली बनाकर उसका आर्थिक विकास करते हैं। जबकि बच्चे, बूढ़े एवं दुर्बल लोगों की कार्यिक अक्षमता के कारण मूल क्षेत्र का आर्थिक विकास बाधित हो जाता है।

यद्यपि झांसी जनपद में जनसंख्या का स्थानान्तरण जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है तथापि यहां के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों जैसे–झांसी, चिरगांव, समथर आदि के कारण अस्थाई स्थनान्तरण अवश्य मिल जाता है। इसके साथ ही क्षेत्र में **मौसमी स्थानान्तरण** भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि

अध्ययन क्षेत्र में जब फसलों की कटाई के समय मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है तो इस क्षेत्र की सीमा से लगे जनपदों (उ०प्र० एवं म० प्र०) से लगे लोग कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में आ जाते हैं। स्थानीय भाषा में वे 'चैतुवा' कहलाते हैं जोकि कार्य की तलाश में क्षेत्र के आन्तरिक भागों या अन्य भागों में स्थानान्तरित हो जाते हैं । इससे स्पष्ट है कि भूमिहीन मजदूर कृषकों की अपेक्षा अधिक स्थानान्तरण करते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार झांसी जनपद की कुल जनसंख्या का 87.78 प्रतिशत भाग मूलभूत रूप में यहीं का निवासी है जबकि 6.64 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश के अन्य सीमावर्ती जनपदों से 5.34 प्रतिशत अन्य राज्यों से तथा 0.24 प्रतिशत जनसंख्या देश के बाहर से स्थानान्तरित होकर क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रवासी जनसंख्या के रूप में निवास करती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि मुख्यतः जन्मदर एवं मृत्युदर से प्रभावित होती है। क्षेत्र में जन्मदर, मृत्युदर की तुलना में अधिक है। परिणामतः जनसंख्या में वृद्धि अवश्यसम्भावी है। अस्तु इसे नियंत्रित करने हेतु व्यापक रूप से परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए, अन्यथा यह एक विकराल रूप धारण कर सकती है।

जनसंख्या वृद्धि (Population Growth)

अध्ययन क्षेत्र में आर्यो के पूर्व कोल, भील, गौड़ आदि जनजातियां निवास करती थीं। अनुमानतः लगभग 800 ईसा पूर्व आर्य इस देश में आयें और सम्पूर्ण क्षेत्र को अपने प्रभूत्व में लेकर निवास करने लगे। ऊबड़–खाबड़ स्थलाकृति और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के करण एक लम्बे समय तक यह क्षेत्र अतिविरल आबादी वाला था किन्तु चन्देलों के समय इस क्षेत्र में शान्ति एवं सम्पन्नता का प्रादुर्भाव हुआ जबकि चन्देल राजाओं के अनुवर्ती काल में आपसी कलह के फलस्परूप यह क्षेत्र अशान्तिपूर्ण रहा। सामान्यतः जनसंख्या में वृद्धि का सिलसिला अंग्रेजों के समय से

प्रारम्भ हुआ क्योंकि इनके शासन काल में विभिन्न प्रकार की सुविधओं का विकास किया गया। कुछ प्राकृतिक तत्वों जैसे– असमतल धरातल, अस्वास्थ्यकर जनवायु दशाएं, अनुपजाऊ भूमि आदि तत्वों का क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण और वृद्धि पर विशेष प्रभाव रहा।

भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1881 में नियमित रूप से जनगणना का कार्य प्रारम्भ हुआ, जिसमें मध्य भारत एजेंसी (इम्पीरियल गजेटियर,1908) की जनसंख्या में 9.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गई। वृद्धि की यह प्रवृत्ति अनुकूल जलवायु दशाओं व अन्य सामाजिक कारकों के फलस्वरूप नियमित रूप से 1891 तक चलती रही। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगला दशक 1891-1901 जनसंख्या वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं रहा क्योकि इस दशक में वर्ष 1895 व 1897 में दो भीषण सूखे पड़े। भुखमरी व भीषण गर्मी के परिणामस्वरूप मृत्युदर में वृद्धि हुई तथा काफी जनसंख्या कम हो गयी। अध्ययन क्षेत्र में 9.8 प्रतिशत जनसंख्या गत दशक की तुलना में कम हो गयी।

19वी शताब्दी में जनगणना सम्बन्धी कार्य बहुत ही अनिश्चित एवं अनियंत्रित रहा। अतः यहां पर जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन वर्ष 1901 से प्रारम्भ किया गया। झांसी जनपद व तहसीलों में दशकानुसार जनसंख्या वृद्धि सारिणी 3.6 तथा चित्र संख्या 3.1 में प्रदर्शित किया गया है। परिशिष्ट ब में जनपद व तहसीलों में 1901 से 1991 तक जनसंख्या का दशकीय अन्तर प्रदर्शित किया गया है।

Trend of Population Growth

(In Different Tahsil of Jhansi District)
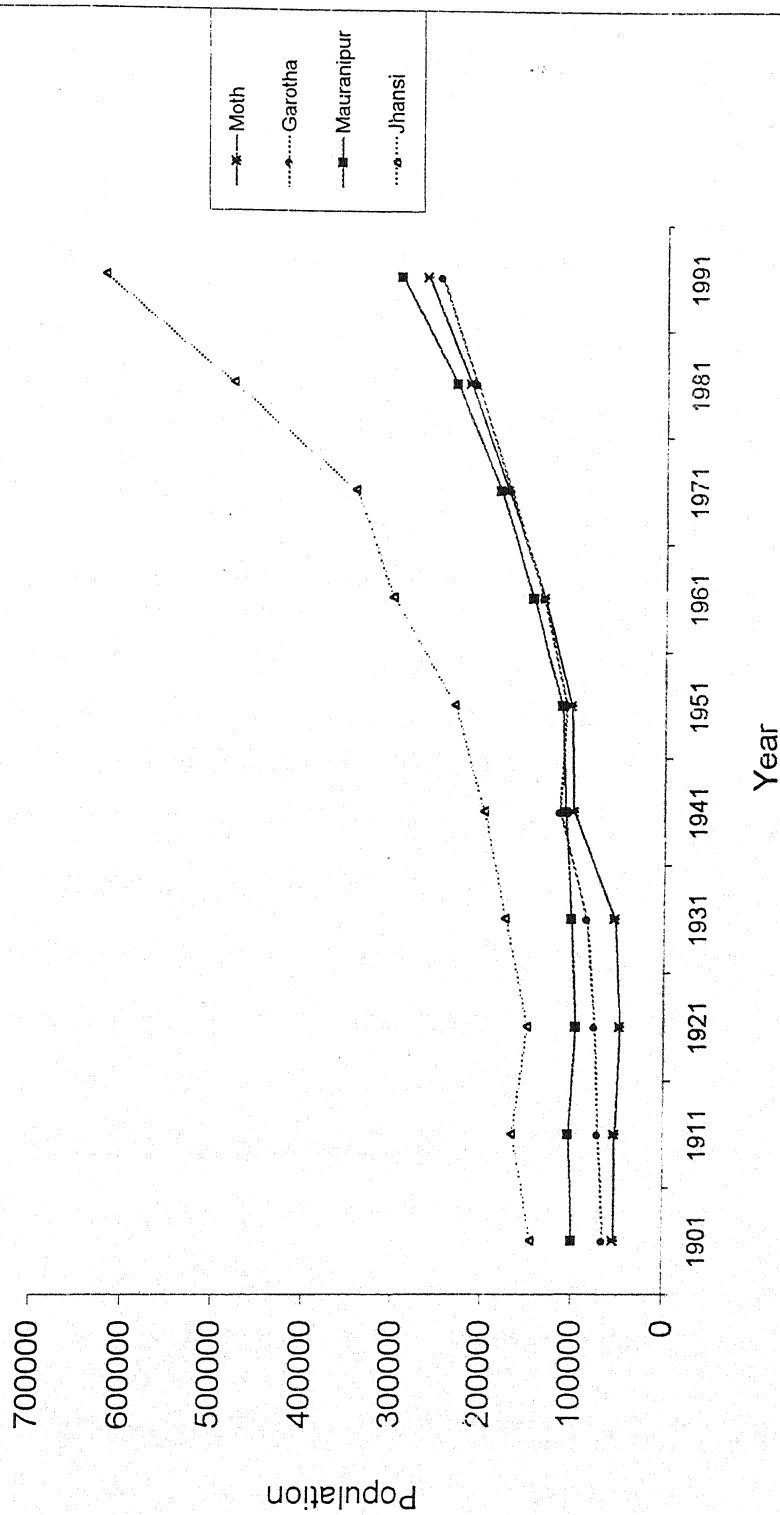
Fig. 3.1

सारिणी संख्या 3.6

झाँसी जनपद में जनसंख्या वृद्धि (तहसील स्तर पर)

क्रम	तहसील	1901-11	1911-21	1921-31	1931-41	1941-51	1951-61	1961-71	1971-81	1981-91
01	मोंठ	-1.13	-8.63	10.39	79.87	2.86	29.34	31.08	24.35	23.00
02	गरौठा	8.45	5.28	11.21	35.66	-5.78	23.67	27.21	22.47	13.30
03	मऊ	3.96	-6.55	4.78	7.18	3.49	28.64	25.06	27.19	31.85
04	झाँसी	14.83	-9.57	16.82	13.58	15.90	30.75	13.68	39.84	28.13
झाँसी जनपद		6.53	-4.87	10.80	34.07	4.12	28.10	24.26	28.46	24.07

स्रोतः जनगणना पुस्तिकाओं से प्राप्त आंकड़ों की गणना पर आधारित।

सारिणी संख्या 3.6 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 1901 में झांसी जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या 368270 थी जो कि 1911 में बढ़कर 398852 हो गई। किन्तु इसी काल में मोंठ तहसील की जनसंख्या में 1:13 प्रतिशत की गिरावट आयी, जिससे यहां ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई। इस दशक में सबसे जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई। इस दशक में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर झांसी (14.83 प्रतिशत) में रही जबकि गरौठा एवं मऊ तहसील में क्रमशः 8.45 प्रतिशत एवं 3.96 प्रतिशत वृद्धि रही। झांसी में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण लोगों का काम की तलाश में झांसी नगर की ओर आकर्षण माना जा सकता है। रेलवे के विकास व सैनिक छावनियों की स्थापना से यहां रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध थे।

यद्यपि 1901-11 दशक के प्रारम्भिक चार वर्ष सम्पन्नता एवं सुख समृद्धि से ओत–प्रोत रहे किन्तु 1904,1905 व 1906 में वर्षा न होने के कारण इस क्षेत्र में अकाल पड गया जिसका प्रभाव वर्ष 1908 तक बना रहा। इस दशक का आधे से

अधिक भाग मलेरिया, हैजा, चेचक आदि महामारियों से ग्रसित रहा जिससे जनसंख्या वृद्धि में कमी आयी। इस दशक में केवल धीमी गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई।
1911-21 के दशक में भी झांसी जनपद भीषण सूखा व महा मारियों के प्रकोप से पीड़ित रहा। वर्ष 1913 में सूखे के परिणाम स्वरूप खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी और भुखमरी के कारण बहुत सारे लोग कालकवलित हो गये। वर्ष 1918 में इन्फ्लूएंजा वथा वर्ष 1920 में काला ज्वर ने अपनी भयंकरता दिखायी फलस्वरूप मृत्युदर में बढ़ोत्तरी हुयी और जनसंख्या में कमी आयी। इस दशक के दौरान अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक क्रम में 4.87 प्रतिशत तक पहुंच गई। वस्तुतः यही एक ऐसा समय था जब इस क्षेत्र की जनसंख्या का एक बड़ा भाग पलायन कर पड़ोसी क्षेत्रों में जाकर रहने लगा और इस प्रकोप की सभाप्ति पर वापस लोग अपने घरों को लौट आये (जनपद जनगणना पुस्तिका, पन्ना, 1961)। इस दशक में मात्र गरौठा तहसील में जनसंख्या वृद्धि 5.28 प्रतिशत अंकित की गई। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में सूखे व महामारी का कम प्रभाव माना जा सकता है। जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत झांसी तहसील में 9.57 प्रतिशत है। तत्पश्चात् मोंठ व मऊ तहसीलों का स्थान आता है जहाँ क्रमशः 8.63 तथा 5.28 प्रतिशत ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही।

1921-31 के दशक में शोध क्षेत्र की जनसंख्या में 10.80 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। जनसंख्या में धीमी वृद्धि का कारण पिछले दशक की महामारियों का प्रभाव था। क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत झाँसी तहसील में 16.82 प्रतिशत रहा तथा निम्नतम प्रतिशत 4.78 मऊ तहसील में अंकित किया गया। शेष दो तहसीलों गरौठा एवं मोठ में क्रमशः 11.21 व 10-39 प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस दशक में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण मृत्युदर में कमी रही क्योंकि इस दशक के दौरान प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप काफी कम रहा तथा व्यक्तियों के स्वास्थ्य का सामान्य स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा था (भारत की जनगणना, 1951)।

1931-41 के दशक के दौरान जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई, जो सम्पूर्ण क्षेत्र में 34.07 प्रतिशत थी। यह वृद्धि राज्य की 13.57 प्रतिशत से काफी अधिक थी। जनपद की समस्त तहसीलों में यह वृद्धि धनात्मक थी। सर्वाधिक वृद्धि मोंठ तहसील (79.87 प्रतिशत) में तथा सबसे कम मऊ (7.18 प्रतिशत) में थी। गरौठा तहसील में 35.66 प्रतिशत तथा झांसी में 13.58 प्रतिशत वृद्धि हुई। क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि में जनपद की कृषित भूमि के विस्तार तथा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रभाव की अहम भूमिका रही है।

1941-51 के दशक में क्षेत्र में 4.12 प्रतिशत की अल्प वृद्धि हुई। गरौठा तहसील में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई जबकि सर्वाधिक वृद्धि झांसी तहसील (15.90 प्रतिशत) तथा सबसे कम वृद्धि मोंठ (2.86 प्रतिशत) रही। इसके अतिरिक्त तहसील मऊ में 3.49 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि अंकित की गयी। इस दशक में राजनीतिक अस्थिरता जैसे–द्वितीय विश्वयुद्ध, वेतवा व यमुना नदियों की 1948 की बाढ़,1946 में प्लेग एवं 1950 में हैजा के भीषण प्रकोप से बहुसंख्य लोग मृत्यु का शिकार हो गये। परिणामतः जनसंख्या वृद्धि भी प्रभावित हुई और उसमें गिरावट आई।

1951-61 के दशक में 28.10 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि अध्ययन क्षेत्र में पायी गई जो इस क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की आत्मनिर्भरता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण हुई मानी जा सकती है। ,खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भारता, सिंचन सुविधाओं विशेषतः नहरों के विस्तार के कारण सम्भव हो सकी। जनपद की झांसी, मोंठ, मऊ तथा गरौठा तहसीलों में कमशः 30.75 प्रतिशत,29.34 प्रतिशत, 28.64 प्रतिशत तथा 23.67 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई।

1961-71 के दशक में क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि 24.26 प्रतिशत रही जो उ०प्र० की जनसंख्या वृद्धि (21.57 प्रतिशत) से अधिक रही। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि

तहसील मोंठ (31.08 प्रतिशत) में अंकित की गई। जनसंख्या वृद्धि की यह दर गरौठा, मऊ तथा झांसी तहसील में कमशः 27.21 प्रतिशत, 25.06 प्रतिशत तथा 13.68 प्रतिशत अंकित की गयी। शोध क्षेत्र के अन्तर्गत दशक 1971-81 में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 28.46 था जो कि 1961-71 से 4.20 प्रतिशत अधिक था। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि झांसी तहसील (39.84) प्रतिशत जबकि अन्य तहसीलों मऊ, मोंठ एवं गरौठा में कमशः 27.19,24.35 तथा 22.47 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि आकलित की गई।

1981-91 के मध्य अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या में विगत दशक की अपेक्षा कम वृद्धि हुई। इस दशक की वृद्धि प्रतिशत 24.07 रहा। तहसील मऊ में (31.85 प्रतिशत) सर्वाधिक वृद्धि तथा सबसे कम वृद्धि गरौठा तहसील (13.30 प्रतिशत) में हुई। झांसी एवं मोंठ में कमशः 28.13 तथा 23.00 प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई। इसका प्रमुख कारण परिवार कल्याण कार्यकमों के प्रति लोंगों के बढ़ते हुए रूझान को माना जा सकता है।

ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (Rural Polutation Growth)

जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभाजन जनांकीय अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सन्तुलित आर्थिक व्यवस्था वाले क्षेत्रों में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में प्रायः समानता पाई जाती है किन्तु जैसे–जैसे क्षेत्र का आर्थिक विकास होता जाता है वैसे–वैसे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जाता है। ग्रामीण जनसंख्या की अत्यधिक प्रधानता औद्योगिक पिछड़ेपन का सूचक है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार झांसी जनपद की कुल जनसंख्या का 60.00 प्रतिशत ग्रामीण है, जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। यहांपर क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि का विश्लेषणात्मक अध्ययन तालिका संख्या 3.7 तथा चित्र संख्या 3.2 में प्रदर्शित किया गया है।

Trend of Population Growth
(Jhansi District)
Total
Rural
Urban
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Population
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
Year
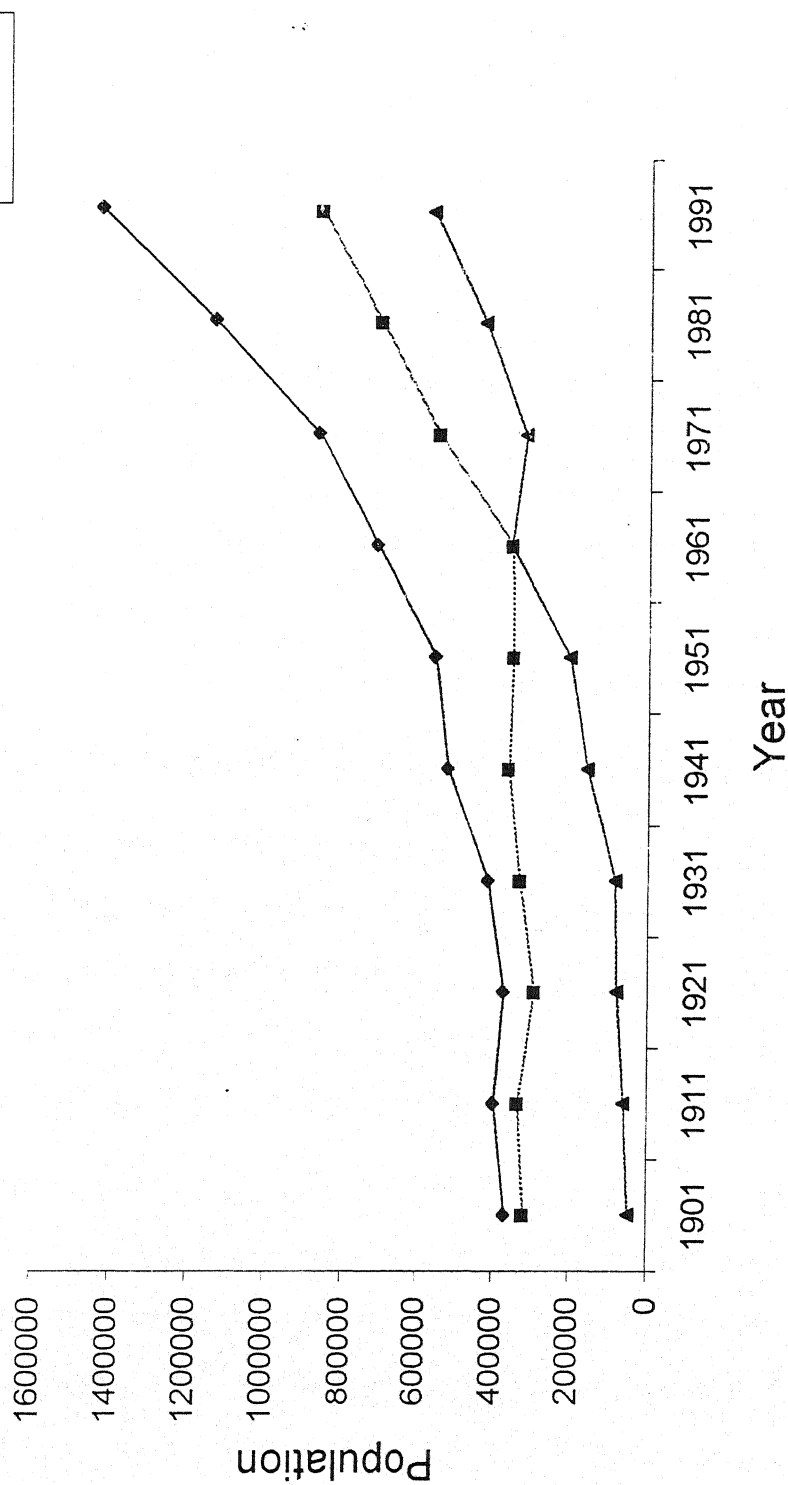
Fig. 3.2

सारिणी संख्या 3.7

झाँसी जनपद में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)

क्रम	तहसील	1901-11	1911-21	1921-31	1931-41	1941-51	1951-61	1961-71	1971-81	1981-91	1991-01
01	मोंठ	0.48	-7.61	11.75	93.40	1.55	30.20	32.38	18.46	24.72	
02	गरौठा	2.23	-6.90	11.69	36.09	-6.47	23.85	26.37	13.22	29.98	
03	मऊ	4.00	-7.93	6.56	7.50	0.50	29.51	25.38	21.88	16.08	
04	झाँसी	7.90	-13.65	17.09	-2.70	4.20	18.39	12.97	19.62	18.44	
झाँसी जनपद		3.65	-5.30	11.97	33.55	0.55	25.51	24.27	17.05	22.30	

स्रोतः जनगणना पुस्तिकाओं से प्राप्त आंकड़ों की जनगणना पर आधारित।

अध्ययन क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या में वर्ष 1901 से 1911 के मध्य 3.65 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई। यह दर अल्पवृद्धि का सूचक है। इस दशक में ग्रामीण जनसंख्या के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि झांसी तहसील में (7.90 प्रतिशत), जबकि मऊ (4.00 प्रतिशत), गरौठा में (2.23 प्रतिशत) तथा मोंठ (0.48 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

अगले दशक 1911-21 में सम्पूर्ण क्षेत्र की जनसंख्या में 5.30 प्रतिशत की कमी आई क्योंकि इस दशक में सम्पूर्ण क्षेत्र सूखा, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित रहा। ऋणात्मक वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत झांसी तहसील (–13.65 प्रतिशत) में रहा। इसके अतिरिक्त दो तहसीलों – मऊ एवं मोंठ में जनसंख्या में घटोत्तरी क्रमशः –7.93 एवं –7.61 प्रतिशत आकलित की गई है। केवल गरौठा तहसील ही ऐसी पाई गयी जहां पर ऋणात्मक वृद्धि 6.90 प्रतिशत पाई गयी।

1921-31 के मध्य के 10 वर्षों में जनपद में ग्रामीण जनसंख्या का औसत वृद्धि प्रतिशत 11.97 थी झांसी तहसील 17.09 प्रतिशत वृद्धि दर पाकर प्रथम स्थान पर जबकि मऊ तहसील 6.56 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त कर अन्तिम स्थान पर रही। गरौठा एवं मोंठ में यह वृद्धि मात्र 0.60 प्रतिशत के अन्तर से 11.69 एवं 11.75 प्रतिशत प्राप्त की गई।

चौथी शताब्दी (1931-41) में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि (33.55 प्रतिशत) अंकित की गई लेकिन झांसी तहसील में –2.7 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि के आंकड़े प्राप्त हुये जिसका प्रमुख कारण ग्रामीण जनसंख्या का जनपद मुख्यालय की ओर आकर्षण माना जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या मे वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत 93.40 मोठ तहसील में तथा सबसे कम वृद्धि मऊ तहसील 7.50 प्रतिशत में पाई गयी। मऊ में ग्रामीण जनसंख्या में कम वृद्धि इस तथ्य का द्योतक है कि इस क्षेत्र की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या मऊ नगर में काम की तलाश में गांवों से स्थानान्तरित होकर बस गई। गरौठा तहसील में 36.09 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुयी।

1941-51 के दशक में अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या की औसतन वृद्धिदर मात्र 0.55 प्रतिशत रही जो कि नाम मात्र थी। इसी दशक में गरौठा तहसील में ऋणात्मक वृद्धि दर (–6-47 प्रतिशत) रही जबकि अन्य तहसीलों झांसी, मोंठ, मऊ में यह वृद्धि कमशः 4.20,1.55 तथा 0.50 प्रतिशत में अंकित की गई।

1951-61 के दशक में क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि 25.51 प्रतिशत के औसत से रही। इस दशक में वृद्धि प्रतिशत मोठ (30.20 प्रतिशत), मऊ (29.59 प्रतिशत) , गरौठा(23.85 प्रतिशत) तथा झांसी (18.39 प्रतिशत) में रहा। आंकड़ों के देखने से यह स्पष्ट होता है कि मोंठ में सर्वाधिक एवं झांसी तहसील में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे कम रहा।

1961-71 के दशक में अध्ययन क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत

औसतन 24.27 रहा। सर्वाधिक वृद्धि 32.38 प्रतिशत मोंठ तहसील में तथा सबसे कम झांसी तहसील में 12.97 प्रतिशत रही। तहसील गरौठा में 26.37 तथा मऊ में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 25.38 रहा। यह जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की आत्मनिर्भरता के फलस्वरूप मानी जा सकती है।

1971-81 का दशक औसतन 17.05 प्रतिशत की ग्रामीणा जनसंख्या की वृद्धि प्राप्त कर सकने में सफल रहा। मऊ तहसील 21.88 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर प्रथम स्थान पर जबकि गरौठा 13.22 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर अन्तिम स्थान पर रहा है। मोंठ एवं झ़ांसी तहसील में यह वृद्धि दर कमशः 18.46 प्रतिशत तथा 19.62 प्रतिशत रही।

दशक 1981-91 के अन्तराल कुल ग्रामीण जनसंख्या में औसत वृद्धि 22.30 आकलित की गई। गरौठा तहसील में सर्वाधिक 29.98 प्रतिशत तथा मऊ तहसील में सबसे कम 16.08 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या में बढोत्तरी हुई। इसके अतिरिक्त मोंठ में 24.72 प्रतिशत तथा झांसी तहसील में 18.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

नगरीय जनसंख्या वृद्धि (Urban Population Growth)

किसी भी क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि क्षेत्र के औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है क्योकि औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। इसी कारण औद्योगिक विकास के क्षेत्र/केन्द्र ही बाद में नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं या उनके समानान्तर, कम में अलग से भी नगरीय केन्द्रों का उद्भव देखने को मिलता है। ऐसा मानना सार्थक प्रतीत होता है कि गाँव के लोग बेरोजगारी, अशिक्षा, परम्परावादी एवं अन्ध विश्वास जैसी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। वस्तुतः गाँवों में सभ्यता पीछे लौटती है जबकि नगरों में सभ्यता आगे बढ़ती है, नगरों के निवासी लोग प्रगतिशील, शिक्षित, फुर्तीले, दूरदर्शी एवं जागरूक होते हैं। वस्तुतः सभी प्रगतिशील विचारों का प्रादुर्भाव शहरों से ही होता

है। अतः किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास और नगरों के प्रति आबादी का आकर्षण आवश्यक है। झांसी जनपद की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में आज भी काफी कम है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की नगरीय जनसंख्या लगभग 40.00 प्रतिशत है। जो कि 14 नगरीय केन्द्रों में निवास करती है।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र की नगरीय सभ्यता अभी भी पिछड़ी हुयी है। जंगलों से मुक्त असमतल धरातल, अनुपजाऊ भूमि, परिवहन के अविकसित एवं अपर्याप्त साधन, औद्योगीकरण का अभाव तथा अन्य अनेक कारक क्षेत्र के नगरीय विकास में बाधक हैं। वैसे वर्तमान समय में क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा ऊंची है। (चित्र संख्या 3.2) जिसे तहसील स्तर पर सारिणी संख्या 3.8 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 3.8

तहसील अनुसार नगरीय जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)

क्रम	तहसील	1901-11	1911-21	1921-31	1931-41	1941-51	1951-61	1961-71	1971-81	1981-91
01	मोंठ	-6.81	12.49	4.91	22.16	11.73	17.96	22.14	67.90	21.62
02	गरौठा	-	-22.66	0.24	24.77	13.32	42.44	43.77	182.35	22.19
03	मऊ	3.77	-0.10	-3.10	5.59	18.36	24.62	23.69	50.54	31.48
04	झाँसी	25.99	-5.37	15.47	35.59	26.76	40.17	14.14	52.73	49.90
झाँसी जनपद		5.74	3.86	4.36	22.03	17.54	31.30	28.45	88.40	31.30

स्रोतः जनगणना पुस्तिकाओं से प्राप्त आंकड़ों की गणना पर आधारित।

1901-11 के दशक में नगरीय जनसंख्या में क्षेत्र में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई क्योंकि क्षेत्र में नगरीकरण की प्रकिया प्रारम्भिक अवस्था में थी। इस दशक में क्षेत्र

में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि झांसी तहसील में सर्वाधिक 25.99 प्रतिशत रही । मऊ में 3.77 प्रतिशत, जबकि मोंठ में यह वृद्धि ऋणात्मक –6.81 प्रतिशत अंकित की गई। गरौठा तहसील में कोई भी नगर न होने से नगरीय जनसंख्या का अभाव था। जनपद की औसत वृद्धि 5.74 प्रतिशत अंकित की गई।

1911-21 के दशक में क्षेत्र में महामारी एवं सूखा जैसी महान प्राकृतिक आपदाओं के कारण नगरीय जनसंख्या में गिरावट का रूख रहा। यहां तक कि गरौठा एवं झांसी तहसील में यह वृद्धि कमशः –22.66 प्रतिशत तथा –5.37 प्रतिशत (ऋणात्मक) रही केवल मोंठ तहसील में 12.49 प्रतिशत तथा मऊ में 0.10 प्रतिशत वृद्धि (धनात्मक) अंकित की गयी।

1921-31 के दशक में मऊ तहसील में ऋणात्मक वृद्धि –3.10 प्रतिशत प्राप्त की गई जबकि सर्वाधिक वृद्धि झांसी तहसील में 15.47 प्रतिशत रही तथा मोंठ एवं गरौठा तहसील में कमशः 4.91 तथा 0.24 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। इस प्रकार झांसी जनपद में औसतन 3.86 की वृद्धि हुयी।

1931-41 दशक के मध्य औसत वृद्धि का प्रतिशत 22.03 रहा। सबसे अधिक वृद्धि झांसी तहसील में 15.47 प्रतिशत रही तथा मोंठ एंव गरौठा तहसील में कमशः 4.61 तथा 0.24 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। इस प्रकार झांसी जनपद में औसतन 4.36 प्रतिशत की वृद्धि हुयी।

1931-41 दशक के मध्य औसत वृद्धि का प्रतिशत 22.03 रहा। सबसे अधिक वृद्धि 35.59 प्रतिशत की वृद्धि झांसी तहसील में हुई तथा सबसे कम वृद्धि 5.59 प्रतिशत मऊ तहसील में अंकित की गई। इसके अतिरिक्त गरौठा तहसील में 24.77 प्रतिशत एवं मोठ तहसील में यह वृद्धि 22.16 प्रतिशत पाई गयी।

1941-51 के दशक में अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या में औसत वृद्धि दर 17.54 प्रतिशत रही है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि झांसी, मऊ, गरौठा, मोंठ तहसील में कमशः

26.76,18.36,13.32 तथा 11.73 प्रतिशत अंकित की गई। झांसी में सर्वाधिक वृद्धि का कारण औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना तथा औद्योगिक व व्यावसायिक प्रगति में विस्तार था।

दशाब्दी 1951-61 के अन्तर्गत क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार एवं सुरक्षा की सुविधाओं के विकास के परिणामस्वरूप नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। क्षेत्र में औसतन 31.30 प्रतिशत की भारी वृद्धि का अनुभव किया गया। सबसे अधिक वृद्धि गरौठा तहसील (42.44) प्रतिशत के नगरीय क्षेत्रों में हुयी तदुपरांत झांसी में 40.17 प्रतिशत, मऊ में 24.62 प्रतिशत तथा मोंठ तहसील में 17.96 प्रतिशत रही।

1961-71 में जनपद झांसी की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत 28.45 रहा है जोकि पूर्व दशक से लगभग २ प्रतिशत कम था। उपर्युक्त दशक में गरौंठा तहसील में 43.77 प्रतिशत सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि आकलित की गयी तथा सबसे कम वृद्धि झांसी तहसील में 14.14 प्रतिशत अंकित की गई। इसके अलावा तहसील मऊ व मोठ में नगरीय जनसंख्या वृद्धि क्रमशः 23.69 प्रतिशत, 22.14 प्रतिशत आकलित की गयी।

1971-81 में अध्ययन क्षेत्र की नगरीय जनसंख्या में औसतन 88.40 प्रतिशत की अपार वृद्धि हुयी। नगरीय जनसंख्या में यह वृद्धि खाद्य पदार्थों की आत्मनिर्भरता, रोजगार की उपलब्धता में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की आत्मनिर्भरता, रोजगार की उपलब्धता में वृद्धि, परिवहन साधनों का विकास तथा स्वास्थ्य एवं औद्योगीकरण की सुविधाओं की उपलब्धता के परिणामस्वरूप सम्भव हुयी। नगरीय जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण दशक कहा जा सकता है। अकेले गरौठा तहसील में 182.35 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि आकलित की गयी। जबकि मऊ तहसील (50.54 प्रतिशत) में न्यूनतम वृद्धि पाई गई। इसके अतिरिक्त मोंठ तहसील में 67.90

प्रतिशत तथा झांसी तहसील में 52.73 प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई।

1981-91 दशक अपने पूर्व दशक की तुलना में लगभग दोगुना 31.30 प्रतिशत पीछे रहा झाँसी तहसील में सर्वाधिक (49.90 प्रतिशत) तथा न्यूनतम 21.62 प्रतिशत रहा जोकि क्रमशः झांसी एवं मोंठ तहसीलों का था। मऊ तहसील 31.48 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त कर तीसरे स्थान पर तथा 22.19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ गरौठा तहसील चौथे स्थान पर रहा। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सतत उपयोग व ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा संरचना के विकास के फलस्वरूप नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में कमी आयी।

जनसंख्या प्रक्षेप (Population Projection)

जनसंख्या प्रक्षेप से अभिप्राय किसी देश, क्षेत्र या स्थान विशेष की जनसंख्या के पूर्वानुमानों या पूर्व आकलनों से है। यह जनसंख्या वृद्धि की पूर्व प्रवृत्ति के आधार पर ज्ञात किया जा है। किसी क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की विकास योजनाओं को लागू करने के पूर्व भविष्य की जनसंख्या के आंकड़े और संसाधन आधार का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतः इस दृष्टिकोण से जनसंख्या प्रक्षेप का विशेष महत्व है।

प्रक्षेप शब्द का उपयोग जनांककीय विज्ञान में किया जात है जो कुछ अपवादों को छोड़कर भविष्य के प्रारूप की प्रवृत्ति का कल्पित संख्याओं के रूप में आंकिक प्रदर्शन करता है (डेविस, 1951)। प्रक्षेपण न तो अनुमान होते हैं और न ही भविष्य वाणियां। बल्कि प्रक्षेपण को हम इन दोनों के बीच की स्थिति मान सकते है। यहां पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि प्रक्षेपित मूल्य सही ही होंगे। फिर भी यह एकदम अटकल या कोरे अनुमान भी नही होते है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रक्षेपण में परिमाण की वैज्ञानिकता की तुलना मे परिशुद्धता कम है।

वर्तमान समय में जनसंख्या प्रक्षेपण हेतु सामान्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है – प्रथम संश्लेषणात्मक विधि, तथा द्वितीय विश्लेषणात्मक विधि। इस विधि का सूत्र निम्नलिखित है–

जनसंख्या प्रक्षेपण हेतु प्रयुक्त सूत्र (प्रथम विधि) –

$$\text{प} = \text{व}(1+\text{द}/100)^{\text{स}}$$

जहां प = प्रक्षेपित जनसंख्या ;

व = वर्तमान जनसंख्या ;

द = जनसंख्या की औसत वृद्धि दर ;

स = वर्तमान और प्रक्षेपित जनसंख्या के मध्य वर्षों की संख्या।

जनसंख्या परिवर्तन की दर प्राप्त करने का सूत्र (द्वितीय विधि) –

$$\text{द} = \frac{(\text{ज}_2 - \text{ज}_1)/\text{स}}{(\text{ज}_2 + \text{ज}_1)/२} \times 100$$

जहां,

द = जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर;

ज_1 = प्रथम बिन्दु (समय) की जनसंख्या;

ज_2 = अन्तिम बिन्दु (समय) की जनसंख्या;

स = ज_1 और ज_2 के मध्य वर्षों की संख्या;

प्रथम विधि जनसंख्या वृद्धि की यथार्थ प्रवृत्ति का आभास कराती है। यहां पर क्षेत्र की जनसंख्या का प्रक्षेपण द्वितीय विधि के आधार पर किया गया है।

Existing & Projected Population
Jhansi District
Population
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Moth
Garautha
Mau
Jhansi
Total
1991
2001
2011
2021
Tahsil/District

Fig. 3.3

झांसी जनपद में जनसंख्या प्रक्षेपण सारिणी संख्या 3.9 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 3.9

झांसी जनपद में जनसंख्या का प्रक्षेपण (जनसंख्या लाखों में)

क्र.सं.	तहसील / क्षेत्र	1991	2001	2011	2021
1	मोंठ	2.65	3.52	4.60	6.23
2	गरौठा	2.49	3.31	4.40	5.86
3	मऊ	2.94	3.91	5.20	6.91
4	झांसी	6.22	8.27	11.00	14.63
5	योग	14.30	19.01	25.20	36.63

इसमें भविष्य के तीन दशकों (2001,2011 एवं 2021) में जनसंख्या प्रक्षेपण करने का प्रयत्न किया गया है। परिणामों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1991 में जो जनसंख्या 14.30 लाख है। वर्ष 2001 में 19.01 लाख, वर्ष 2011 में 25.20 लाख तथा 2021 में 36.63 लाख हो जायेगी। क्षेत्र की सभी तहसीलों में भी जनसंख्या वृद्धि का यही प्रतिरूप मिलता है। क्षेत्र में झांसी तहसील जो कि जनपद एवं मण्डल मुख्यालय भी है, में 1991 की 6.22 लाख जनसंख्या बढ़कर 2001 में 8.27 लाख, 2011 में 11.0 लाख तथा 2021 मे 14.63 लाख हो जाने की सम्भावना है। मऊ तहसील की जनसंख्या 1991 में 2.94 लाख है जो कि 2001,2011 व 2021 में क्रमशः 3.91, 5.20 तथा 6.91 लाख होने की सम्भावना है (चित्र संख्या 3.3[illegible]) इसी प्रकार तहसील मोंठ की जनसंख्या 1991 में 2.65 लाख से बढ़कर सन् 2001,2011 तथा 2021 में क्रमशः

3.52, 4.60 तथा 6.23 लाख हो जाने की सम्भावना है तथा गरौठा तहसील की 1991 की 2.49 लाख जनसंख्या प्रक्षेपित होकर 2021 में 5.86 लाख हो जायेगी।

उपर्युक्त तहसीलों में जनसंख्या प्रक्षेपण की इस गति को देखने से यह कह जा सकता है कि यदि इस सम्बन्ध में पहले से ध्यान नहीं दिया गया तो निकट भविष्य में क्षेत्र की खाद्य समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। साथ ही मानव की आवश्यकताओं के अनुपात में सुविधा संरचना का नितांत अभाव हो जायेगा।

अतः भविष्य में जनसंख्या के बढ़ते हुये इस भार को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हेतु औद्योगिक एवं कृषि विकास के साथ ही सामाजिक उत्थान की भी प्रबल आवश्यकता है जिससे जनसंख्या वृद्धि की इस प्रवृत्ति में नियंत्रण किया जा सकता सके। साथ ही यह भी आवश्यक है कि बढ़ती हुयी इस जनसंख्या के भरण–पोषण हेतु संसाधनों के उत्पादन में भी अनिवार्य रूप से वृद्धि करने की योजना तैयार की जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि एक सुनियोजित योजना के साथ क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्रकार के संसाधनों के समुचित विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाय।

References

(1) Agrawal, S.N. (1972). Population Policy in India, P.138.

(2) Bogue, D.I., (1959), Internal Migration O.D. Duncan and P.M. Houser (eds.), The study of Population: An Inventory and Appraisal, Chicago University Press, Chicago, London.

(3) Chandna, R.C. and Sidhu, M.S. (1980), Introduction to Population Geography, Kalyani Publisher, New Delhi, PP. 31-34 & 70.

(4) Census of India.Vol. II, U.P., Part I-A, Report, 1951, Page 28.

(5) Das,K.K.L. (1976), Population and Agrucultural Land use of Central Mithila, Bihar, Indian Geographical Studies,Bulletin, No.3,P.19.

(6) Davis, K. (1951), Population of India and Pakistan, Prentice Hall, Inc., Engle Wood Cliffs, New Jersey, P.33.

(7) District Gensus Handbook, Panna, 1961,Page XIIV.

(8) Haggett,P.(1977),Geography:A Modern Synthesis, P.145.

(9) Imperial Gazetteer of India, Vol. 14,1908,Page 144.

(10) Ravenstein, E.G. (1885-89), The Laws of Migration, Journal of Royal Sta tistical Society, Vol. XLVIII, PP.241-305.

(11) Rose. I.J. (1985), The Geographical Pattern of European Immigration in Australia, Geographical Review,Vol.48 P. 692.

(12) Roy. Phanibhusan, (1979), Methods of Describing Growth of Population, Geographical Review of India, Vol. 41, P. 258.

(13) Trewartha, G.T. (1959), A Geography of Population: World Patterns, John Wiley and Sons Inc., New York, P.137.

(14) Weng, W.Lee E.S., Toward a Central Theory of Movement, A Theory of Migration, Population Geography: A Reader.

अध्याय - ४

जनसंख्या का स्थानिक प्रतिरूप (SPATIAL PATTERN OF POPULATION)

जनसंख्या का स्थानिक प्रतिरूप

(SPATIAL PATTERN OF POPULATION)

जनसंख्या वितरण का स्थानिक स्वरूप सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का समन्वित प्रतिरूप दर्शाता है। सामाजिक गतिशीलता तथा संसाधनों का पास्परिक सम्बन्ध अनेक ऐतिहासिक विन्दुओं पर मानवीय पक्षों को प्रभावित किया है। स्टील (1955) का विचार है कि जनसंख्या का स्थानिक वितरण किसी क्षेत्र की सामान्य अधिवास्थता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की घटनाओं द्वारा निर्धारित होती है। वास्तव में अनेक प्राचीन ऐतिहासिक गति विधियों से प्रभावित किसी क्षेत्र विशेष का जनसंख्या वितरण प्रतिरूप वर्तमान समय की अनेक चुनौतियों की अथाह सम्भावनाओं को समेटे रहती है। सामान्यतः किसी भी क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या का वितरण उस क्षेत्र की भौतिक गुणों तथा आर्थिक दशाओं पर आधारित होता हैं। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने पर ही क्षेत्र विशेष की ओर मानव जीवन निर्वाह के लिए प्राकृतिक रूप में आकर्षित होता है। ज्ञात हो कि अध्ययन क्षेत्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित है, जहॉ ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक धार्मिक व साहित्यिक, गतिविधियों से पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है। उपर्युक्त दृष्टि से झाँसी जनपद की जनसंख्या को स्थानिक प्रतिरूप का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting the Spatial Distribution)

वस्तुतः अन्य क्षेत्रों की भाँति बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से उस

क्षेत्र विशेष की आर्थिक सम्भावनाओं का कारण और परिणाम होती है। मानव प्रायः वही पर रहना पसंद करता है जहॉ की प्राकृतिक दशाएं सरलता पूर्वक जीवनयापन के लिए अनुकूल होती हैं। उस क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण भी वहां के प्राकृतिक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती है। वस्तुतः जनसंख्या वितरण एक परिवर्तनशील पहलू हैं जो स्थान एवं समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है (क्लार्क 1966)। सामान्यतः जनसंख्या का स्थानिक वितरण प्रतिरूप एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्न लिखित कारक हैं।

भौतिक कारक (Physical Factors)

यह तो सर्वविदित है कि सम्पूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण एवं जमाव एक जैसा नहीं है क्योंकि किसी भी क्षेत्र के भौतिक कारक वहां के मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के साथ–साथ जनसंख्या वितरण प्रतिरूप पर भी इनका स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है। भौतिक वातारण की कठोरता के कारण अत्याधिक, शीत, उष्ण अनुपजाऊ, पर्वतीय, दलदली एवं आर्द्र, उष्ण, आर्द्र कटिबंधों में जनरिक्त क्षेत्र बहुतायत मात्रा में पाये जाते हैं। वास्तव में प्रकृति मानव के लिए सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं हेतु अवसर प्रदान करती है और मानव अपनी बुद्धि तथा प्राविधिकी के द्वारा प्रकृति के बहुत से अवरोधको को समाप्त करता हुआ अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास करता है। परन्तु मानव के वितरण के सम्बन्ध में इन अवरोधको का पूर्ण रूपेण समाप्त होना सम्भव नहीं है। क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप में गहरा प्रभाव डालने वाले भौतिक कारकों में क्षेत्रीय स्थलाकृतियां, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक, वनस्पति भूगर्भीय जलस्तर, और खनिज सम्पदा प्रमुख है।

क्षेत्रीय स्थलाकृति :– स्थल के प्रमुख स्वरूपों जैसे पहाड़, पठार, मैदान एवं ऊँचाई, अपवाह, भूमिगत जलस्तर आदि ऐसे कारक है जो जनसंख्या वितरण एव उसके घनत्व को आदिकाल से ही प्रभावित करते आये हैं। अध्ययन क्षेत्र में स्थलाकृतिक स्वरूपों का जनसंख्या के वितरण एवं धनत्व में पूर्णतः प्रभाव दृष्टिगत होता है। जनपद के दक्षिणी उच्च भू–भागों में जहां 400 मीटर से अधिक ऊँचाई पाई जाती है एवं क्षेत्र की कुल जनसंख्या का केवल 5.0 प्रतिशत भाग निवास करता है।

जलवायु :– भौतिक कारकों में जलवायु सबसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली तत्व है जो मानव की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। अतः मनुष्य उन्हीं भागों में रहना पसंन्द करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ एवं आर्थिक क्रियाओं के अनुरूप हो। जनसंख्या के वितरण में इसका प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में पड़ता है। यह अप्रत्यक्ष ढंग से मिट्टी वनस्पति तथा कृषि को भी प्रभावित करती है। सीमा क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है जिसके फलस्वरूप यहॉ की ग्रीष्म ऋतु काफी गर्म रहती है जबकि शीत ऋतु में औसतन ठंडक पड़ती हैं। तापक्रम एवं वर्षा दोनों ही प्रभावित करते हैं। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ की जनसंख्या घनत्व कम है। क्षेत्र का अधिकांश भाग पठारी है। अतः गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है। पेयजल की आपूर्ति ट्रकों व टैकों द्वारा की जाती है। अतः जनसंख्या विरल है।

मिट्टी – मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जिसमें मानव जीविका का संचालन होता है। जनपद का सम्पूर्ण भाग कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में हैं। इसीलिए मिट्टीयों की उपयोगिता का अधिक महत्व हैं। क्षेत्र की 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यो में लिप्त है जो प्रत्यक्षतः उर्वरा मिट्टी का ही परिणाम है। क्षेत्र का मध्य व पूर्वी भाग जो

कि विशेषतः जलोढ़ मिट्टी से युक्त है, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। उसके अलावा काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता है, संघन जनसंख्या पायी जाती है। पहाड़ी एवं ऊसर भूमि जो पूर्णतः कृषि के अयोग्य है अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी विरल रूप में जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। क्षेत्र के दक्षिणी उच्च भागों में उबड़–खाबड़ तथा पठारी भूमि में विरल जनसंख्या प्रतिरूप दृष्टिगत होता है।

प्राकृतिक वनस्पति – प्राकृतिक वनस्पति सामान्यतः जलवायु पर निर्भर करती है। अतः मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर जो प्रभाव पड़ता है वह परोक्ष रूप में जलवायु का ही प्रभाव है। परन्तु इसका भी प्राकृतिक संसाधन के रूप में मानवीय क्रिया कलापों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र में मात्र 6.5 प्रतिशत भाग पर वन पाये जाते हैं। जो कि जनपदीय क्षेत्रफल की तुलना में काफी कम हैं।

जल प्रवाह एवं भूगर्भीय जलस्तर :– सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत का उत्पादन औद्योगिक जल की पूर्ति पेयजल की सुविधा आदि इसके प्रत्यक्ष प्रभाव है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण तथा मत्स्य व्यवसाय को प्रोत्साहन इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं। जिनका मानवीय क्रिया कलापों से ही नहीं अपितु उसके स्थानिक वितरण से भी गहरा सम्बन्ध है। क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी एवं मध्य भागों में नदियां, छोटी छोटी जल धाराओ एवं नालों के अत्याधिक कटाव के कारण वृहदाकार अधिवासो का विकास सम्भव नहीं हो पाया है। जबकि क्षेत्र का उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला भू–भाग है। इसी प्रकार भू गर्भीय जलस्तर की उपल्बधता से भी जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। यहीं कारण है कि बंगरा, चिरगांव एवं बड़ागॉव विकास खण्डों में जनसंख्या सघनता अधिक है जबकि अन्य विकास

खण्डों में अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या प्रतिरूप दृष्टिगत होता है।

खनिज :– निरन्तर बढ़ती औद्योगिक प्रक्रिया के फल स्वरूप जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में खनिज सम्पदा का महत्व बढ़ा है। क्योंकि क्षेत्र में कृषि संतृप्तावस्था में पहुँच जाती है, तो वहॉ के मानव के लिए जीदिका उपार्जन हेतु खनिज और उद्योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। झांसी जनपद इस क्षेत्र में अग्रगण्य है।

सांस्कृतिक कारक (Cultural Factors)

मानव अपनी क्षमता के अनुसार प्रकृति प्रदत्तव सुअवसरों का अपने हित में सर्वाधिक उपयोग करता है। आधुनिक युग में तकनीकि शिक्षा के विकास के कारण भौतिक कारकों का महत्व कम होता जा रहा है। जिससे सामाजिक चिन्तन तथा नियन्त्रण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में उत्पादक तत्वों तथा सामाजिक क्रिया कलापों का विशेष योगदान होता है। विभिन्न सांस्कृतिक कारकों में आर्थिकी का ढंग प्राविधिक जागरूकता, सामाजिक संगठन एवं प्रवृत्ति तथा सुविधायें प्रमुख हैं। (क्लार्क 1965) के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप एवं सांस्कृतिक कारकों के मध्य गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। जिनमें उस क्षेत्र की आर्थिक दशा आधुनिक प्राविधिक ज्ञान, सामाजिक संगठन महत्व पूर्ण होता है।

किसी क्षेत्र की आर्थिक क्षमता ही मुख्य रूप से मानव के बसाव को निर्धारित करती है क्योंकि क्षेत्र का आर्थिक विकास हो जाने पर जनसंख्या के भरण–पोषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है तथा ऐसे क्षेत्रों में रोजगार की सुविधाये बढ़ने लगती हैं और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति जनसंख्या स्थानिक वितरण को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती है। इसी कारण झांसी जनपद के झांसी, मऊरानीपुर तथा मोठ नगरों

में औद्योगिक विकास होने के कारण जनसंख्या का घनत्व अधिक है जबकि क्षेत्र के अन्य केन्द्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या वितरण को स्थानीय रीतिरिवाज भी प्रभावित करते हैं जिनमें संयुक्त परिवार प्रथा, बाल विवाह, सन्तान उत्पादन की आवश्यकता, परिवार के सदस्यों को पैतृक भूमि के समीप रखने की प्रवृत्ति आदि प्रमुख हैं।

क्षेत्रीय सम्बन्धगम्यता :– किसी क्षेत्र की जनसंख्या का स्थानिक वितरण वहां आवागमन के साधनों के प्रसार से भी प्रभावित होती है। अध्ययन क्षेत्र का झांसी नगर एक विकसित केन्द्र है जहॉ जनसंख्या सकेन्द्रण सबसे अधिक है यह केन्द्र रेल यातायात द्वारा दिल्ली मुम्बई एवं कोलकता आदि अनेक सीधे सम्पर्क में है तथा आस पास के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उस नगर का पर्याप्त औद्योगिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विकास सम्भव हुआ है। इसके अलावा जनसंख्या वितरण का ऐतिहासिक राजनीतिक व धार्मिक कारक भी प्रभावी होते हैं। उपर्युक्त विश्लेषण से यह भलीभांति स्पष्ट है कि जनसंख्या का वितरण भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है।

जनसंख्या का स्थानिक वितरण (Spatial Distribution of Population)

झांसी जनपद में जनसंख्या वितरण पर वस्तुतः आधारभूत भौतिक कारकों एवं जलवायु व विशेषताओं प्राकृतिक संसाधनो बाजार एवं परिवहन की सुविधाओं का सम्मिलित प्रभाव स्पष्ट रूप से परिवर्तित होता है। क्षेत्र की जनसंख्या के वितरण को सारिणी संख्या 4.1 व चित्र संख्या 2.6 में दर्शाया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यहां जनसंख्या का सर्वाधिक संकेन्द्रण जनपद के बड़ागॉव, बबीना व मऊरानीपुर विकासखण्डों मे पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वेतवा नदी के तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में भी जनसंख्या का संकेन्द्रण देखने को मिलता है। बामोर एवं चिरगॉव विकास खण्डों में अपेक्षाकृत निम्न स्तरीय जनसंकेन्द्रण पाया जाता है।

जनसंख्या का वितरण, 1991

क्र.सं.	विकासखण्ड		कुल जनसंख्या	ग्रामीण		योग	नगरीय		योग
				पुरूष	स्त्री		पुरूष	स्त्री	
1	मोंठ	680.85	1,46043	64094	54530	118624	14691	12728	27419
2	चिरगाँव	555.32	1,18719	56469	48344	104813	7377	6529	13906
3	बामोर	827.85	1,17432	56059	47008	103064	7951	6414	14365
4	गुरसराय	734.58	1,31546	56380	47533	103913	14822	12811	27633
5	बंगरा	533.68	1,29847	59559	51505	111064	9955	8820	18783
6	मऊरानीपुर	550.36	1,76803	62937	54183	117120	31533	20150	59683
7	बबीना	739.62	1,52677	59489	50540	110029	22435	20213	42648
8	बड़ा गाँव	521.50	4,6942[illegible]	51239	43473	94712			
	झाँसी जनपद	566,5.18	1429698	466226	397116	863342	301204	265152	566356

स्रोतः सांख्यकीय पत्रिका, १६६६ से प्राप्त आंकड़ो पर आधारित।

इसके अलावा गुरसरॉय बंगरा तथा मोंठ विकास खण्ड में मध्यम जनसंख्या संकेन्द्रण दृष्टिगत होता है। क्षेत्र में जनसंख्या वितरण को तीन वर्गो में विभाजित किया जा सकता है। जो कि निम्नवत हैं।

(क) सघन जन वितरण क्षेत्र

(ख) मध्यम जन वितरण क्षेत्र

(ग) विरल जन वितरण क्षेत्र

सघन जन वितरण क्षेत्र :– अध्ययन क्षेत्र में इस श्रेणी के अन्तर्गत बड़ागॉव, बबीना, मऊरानीपुर तथा वेतवा के तटवर्ती क्षेत्र के भाग आते हैं। समतल भूमि उर्वरा मिट्टी उच्च्य जलस्तर मानव जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु के अलावा भूमि उपयोग जिसमें शस्य प्रतिरूप सुविधायें उपयोग तथा मानव जीवन की सुरक्षा आदि विभिन्न कारकों में ग्रामीण जनसंख्या के सघन वसाव को आकर्षित किया है। जनपद के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जनपद व मण्डल मुख्यालय झांसी नगर स्थित है फलस्वरूप सघन जनसंख्या निवास करती है। जनपद के मऊरानीपुर विकास खण्डों में स्थानीय हथकरघों तथा औद्योगिक विकास व प्रमुख अनाज मण्डी होने के कारण जनसंख्या का सघन बसाव देखने को मिलता है। उसके अतिरिक्त क्षेत्र के प्रमख सेवा केन्द्र होने के कारण, बबीना, रानीपुर व बड़ागॉव केन्द्रो में भी जनसंख्या का बसान अति संघन है।

मध्यम जन वितरण क्षेत्र :– इस श्रेणी के अन्तर्गत झांसी जनपद में मोंठ, बंगरा एव गुरसरॉय विकास खण्ड शामिल किये जा सकते हैं। इन विकास खण्डों में जनसंख्या का वितरण लगभग एक समान है। इस क्षेत्र को उर्बरक क्षमता के आंकलन से पता

चलता है कि इसमें मुख्यतः गेहूँ, चना, दालों एवं अन्य खाद्यानों की कृषि की जाती है। सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहरें ही एक मात्र साधन हैं।

इसके अतिरिक्त यातायात व स्वास्थ्य सुविधाओं की सहन सुलभता वाले गुरूसरॉय, समथर, कटेरा, टोडी फतेहपुर आदि केन्द्रों में भी जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत कम विरल है। यहां के समथर, मोठं गुरूसराय टोडी फतेहपुर कटेरा इत्यादि नगरीय केन्द्रों में है जिनकी जनसंख्या क्रमशः 16895, 10624, 17886, 9747 तथा 5993 है। ये सभी केन्द्र अपने क्षेत्र के सेवा केन्द्र हैं।

विरल जन–वितरण क्षेत्र :– अध्ययन क्षेत्र के चिरगॉव एवं बामोर विकास खण्डों में जन–वितरण विरल है। इन क्षेत्रों में अविकसित कृषि व्यवसाय, एवं औद्योगीकरण बहुत ही सीमित हैं। परिणामतः यह विकास खण्ड विरल जन–वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। उस विरल जन वितरण क्षेत्र में भी असमानता देखने को मिलती है। अत्याधिक उबड़–खाबड़ व पहाड़ी क्षेत्रों में अति विरल जन वितरण मिलता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र में जनसंख्या सकेन्द्रण पश्चिमी तथा पूर्वी दक्षिणी भागों में अधिक है। वेतवा पहुँच क्षेत्र के दक्षिणी भाग में जनसंख्या के उच्च्च संकेन्द्रण का कारण झांसी नगर की केन्द्रीय स्थिति को माना जा सकता है ज़ो जनपद एवं संभागीय मुख्यालय होने के कारण साथ साथ परिवहन का प्रमुख नगरीय केन्द्र भी है।

जनसंख्या घनत्व (Poulation Density)

जनसंख्या घनत्व प्रति ईकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या का द्योतक होता है। चांदना एवं सिदू (1980) मुख्य भूमि के मापन अनुपातः जो किसी जनसंख्या अध्ययनों के आधारभूत विन्दु होते हैं– (डेम्को, 1970)। जनसंख्या का

वितरण एवं धनत्व एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इनका सम्बन्ध भौतिक वातावरण से होता है। जो मनुष्य के नकारात्मक एवं सकारात्मक (फोर्ड, 1953) सम्बन्धों को इगित करते हैं। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए योजनाओं के निर्माण में जनसंख्या घनत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योकि जनसंख्या घनत्व किसी भी क्षेत्र के संसाधन पर आधारित जनसंख्या के भार को प्रदर्शित करता हैं (ट्रिवार्था, 1953)। वस्तुतः जनसंख्या का अध्ययन किसी क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप की सापेक्षिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यही एक आसान उपाय है। जनसंख्या के घनत्व के लिए कई दृष्टिकोण अपनाये जाते है। जिसमें अंकिक घनत्व कार्यिक जनसंख्या घनत्व, कृषि घनत्व तथा पोषण घनत्व मुख्य है। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपर्युक्त सभी घनत्वों की गणना एव उनके वितरण का उल्लेख यहां किया जा रहा है।

आंकिक घनत्व (Arithmatical Density)

आंकिक घनत्व किसी क्षेत्र विशेष के कुल जनंसख्या तथा उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सम अनुपातिक प्रतिफल है। भूगोलविदों एवं अन्य सामाजिक विज्ञान वेत्ताओं द्वारा इसी घनत्व को उपयोग मे लाया जाता है क्योंकि विश्व के अधिकांश भागों की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल सम्बन्धी आंकड़ों की सुलभता हैं। यद्यपि मानव एवं भूमि के पारस्परिक सम्बन्धों को व्यक्त करने के लिए यह एक सरल तरीका है तथापि इससे क्षेत्र विशेष की वास्तविक स्थिति एवं जनसंख्या की आर्थिक दशाओं का ज्ञान नहीं हो पाता है। साथ ही यदि किसी क्षेत्र का एक भाग सघन जनसंख्या वाला है और शेष भाग जनशून्य है, तो ऐसी दशा में जनसंख्या घनत्व की वस्तुस्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो पाती है। आंकिक घनत्व कुछ

हद तक उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ विरल जनसंख्या पायी जाती है। क्षेत्र की जनसंख्या का आंकिक घनत्व सारणी 4.2 एवं चित्र 4.1 A में प्रदर्शित किया जा रहा है।

सारिणी 4.2

जनसंख्या धनत्व विकास खण्डवार 1991

क्र.सं.	क्षेत्र / विकास खण्ड	क्षेत्रफल	कुल जनसंख्या	घनत्व
1	मोंठ	680.86	146043	215
2	चिरगाँव	555.32	118719	214
3	बामोर	827.85	117432	142
4	गुरुसराय	734.58	131546	171
5	बंगरा	533.68	129847	243
6	मऊरानीपुर	550.36	176803	322
7	बबीना	739.62	152777	206
8	बड़ा गाँव	521.50	469421	900
	झाँसी जनपद	566.518	1429698	302

स्रोत : जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आंकड़ो द्वारा संगणित।

सारणी संख्या 4.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्षेत्र में जनसंख्या का आंकिक घनत्व 302 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी० हैं जो कि उ० प्र० के 471 व्यक्ति / प्रति वर्ग किमी. की तुलना में बहुत कम है। क्षेत्र में जनसंख्या के निम्न घनत्व का मुख्य कारण यहां का असमतल धरातल, अविकसित कृषि व्यवसाय, अपर्याप्त सिंचन सुविधायें और पर्याप्त मात्रा में औद्योगीकरण का अभाव हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर सम्पूर्ण क्षेत्र को तीन भागों में बॉटा जा सकता हैं।

(1) उच्च जन घनत्व क्षेत्र (300 व्यक्ति/प्रतिवर्ग किमी. से अधिक);

(2) मध्यम जन घनत्व क्षेत्र (200 से 300 व्यक्ति/प्रति वर्ग किमी.)द्ध

(3) निम्न जन घनत्व क्षेत्र (200 व्यक्ति वर्ग किमी. से कम)।

उच्च घनत्व क्षेत्र :– उच्च जन–घनत्व क्षेत्र के अन्तर्गत बड़ागॉव व मऊरानीपुर विकासखण्ड आते हैं। इनका आंकिक घनत्व क्रमशः 900 व 322 है। इन विकास खण्डों में अधिक जन घनत्व का प्रमुख कारण कृषि व सिचाई सुविधाओं का विकास है। इसके अलावा बड़ागॉव विकासखण्ड में झांसी नगर सम्मिलित होने के कारण सर्वाधिक जन घनत्व कम पाया जाता है। औद्योगिक व्यापारिक व परिवहन सुविधाओं की प्रगति के परिणाम स्वरूप यह उच्चजन घनत्व वाला क्षेत्र है।

मध्यम घनत्व क्षेत्र :– इसके अन्तर्गत झांसी जनपद के चार विकास खण्ड बंगरा (243) बबीना (206) मोंठ (215) तथा चिरगॉव (211) आते हैं। वस्तुतः यहां कृषि व्यवसाय मध्यम स्तरीय है। मोंठ के अलावा अन्य व्यावसायिक केन्द्रों पर विकास कम हुआ है। हां इतना अवश्य है कि यह चारों विकास खण्ड प्रमुख बाजारीय केन्द्र हैं, जो आस–पास की ग्रामीण जनता को विभिन्न सेवायें प्रदान करते हैं।

निम्न घनत्व क्षेत्र :– इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के गुरसंराय एवं बामोर विकाखण्ड आते हैं, जिनका जन घनत्व क्रमशः 170 तथा 142 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है। यह अत्याधिक अविकसित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। पिछड़ी एवं परम्परागत कृषि व्यवसाय, यातायात के साधनों का अभाव तथा अविकसित व्यवसाय तन्त्र के कारण इस क्षेत्र में निम्न जन घनत्व पाया जाता है।

कार्यिक घनत्व (Functional Density)

यह किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा कृषि भूमि के मध्य का अनुपात है, जो

कृषित भूमि के प्रतिवर्ग किमी. में जनसंख्या के अनुपात को व्यक्त करता हैं (चांदना एवं सिद्धू 1980)। इस प्रकार यह घनत्व कृषित क्षेत्र पर जनसंख्या के दबाव को प्रदर्शित करता है। इसमें कृषि के अयोग्य भूमि को छोड़कर घनत्व निकाला जाता है। इस घनत्व का विश्लेषण उन क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी हैं जो कि मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। झांसी जनपद के कार्यिक घनत्व को सारणी संख्या 4.3 तथा चित संख्या 4.1 B में देखा जा सकता हैं। सारिणी व चित्र से स्पष्ट है कि क्षेत्र का भूकार्यिक घनत्व 455 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। क्षेत्र में सर्वाधिक कार्यिक घनत्व झांसी, बड़ागॉव विकासखण्ड में है। झांसी नगरीय केन्द्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों व विभिन्न संस्थानों में रोजगार के अवसरों एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धि के कारण यहां कृषिगत भूमि के कम होने पर भी जनसंख्या का अत्यधिक जमाव पाया जाता हैं।

सारणी संख्या 4.3

बुन्देल खण्ड क्षेत्र में कार्यिक, कृषि एवं पोषण घनत्व 1991

क्र.सं.	विकास खण्ड	कार्यिक घनत्व	कृषिगत घनत्व	पोषणघनत्व
1	मोंठ	284	174	207
2	चिरगाँव	324	188	250
3	बामोर	235	120	203
4	गुरसराय	251	141	191
5	बंगरा	396	208	281
6	मऊरानीपुर	380	213	252
7	बबीना	557	149	328
8	बड़ा गाँव	205.5	182	296
9	जनपद झाँसी	455	172	242

स्रोत : जिला सांख्यकीय पत्रिका, 1996 से प्राप्त आंकड़ो द्वारा संगणित।

JHANSI DISTRICT
DISTRIBUTION OF POPULATION

FUNCTIONAL DENSITY
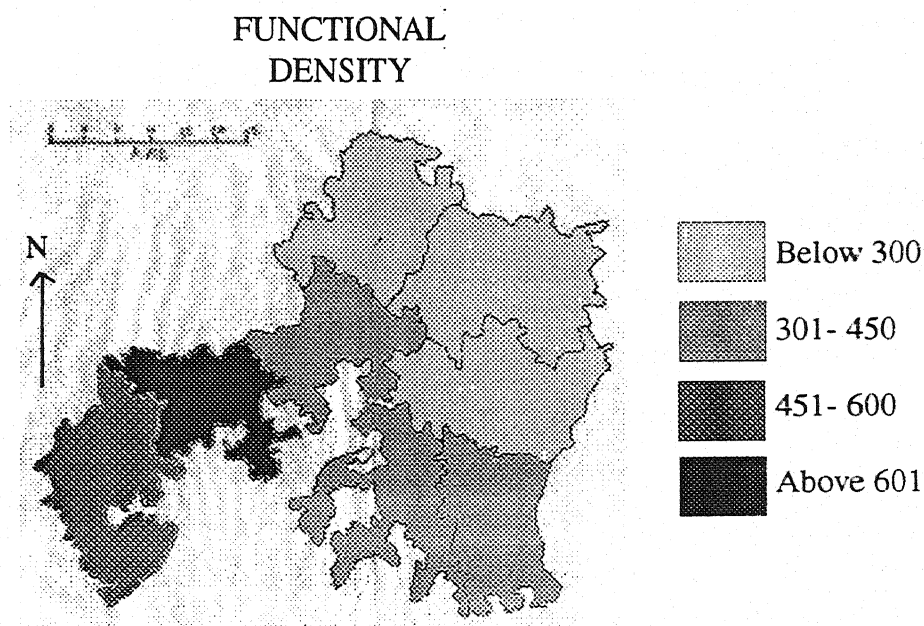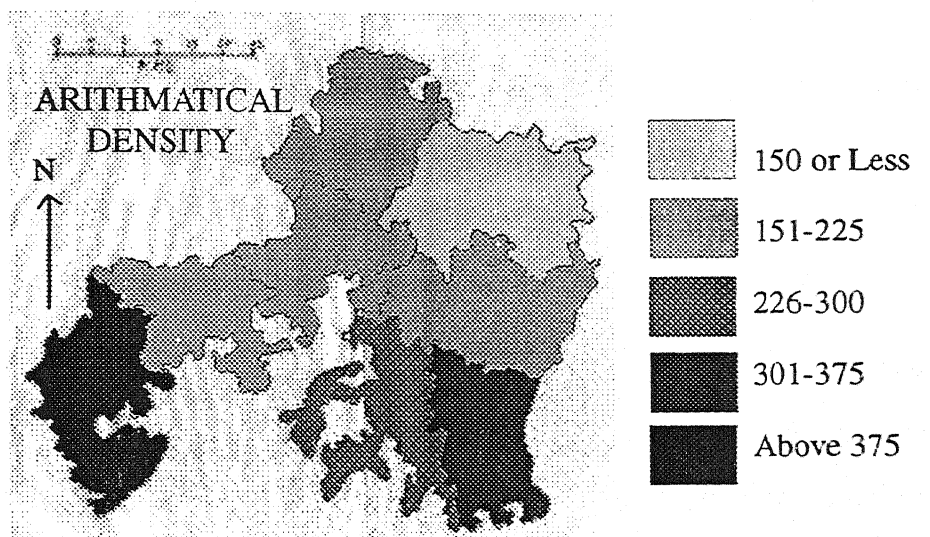
Fig 4.1

इस घनत्व का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमे सम्पूर्ण अधिकृत भूमि को अनुत्पादक मान लिया जाता है जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें सम्पूर्ण अकृषित भूमि का भी विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है तथा अनेक आर्थिक लाभ प्राप्त किये जाते हैं। इसके अलावा इस घनत्व में यह भी मान लिया जाता है कि सम्पूर्ण कृषित क्षेत्र समान गुणों का होता हैं। जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जबकि वास्तव में विभिन्न कृषित क्षेत्रों की भूमि अलग–अलग उर्बरा–शक्ति रखती है और उत्पादन क्षमता और वहन क्षमता भी भिन्न होती है। कुछ लोग कार्यिक घनत्व की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि कृषि प्रधान क्षेत्रों में भी सम्पूर्ण जनसंख्या केवल कृषि भूमि पर ही निर्भर नहीं रहती हैं। ब्ल्कि अन्य व्यवसायों में भी संलग्न रहती है जबकि इसे कृषि पर आधारित मान लिया जाता है। सारिणी 4.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उच्च (235 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.) कार्यिक घनत्व बड़ागॉव विकासखण्ड में जबकि निम्न कार्यिक घनत्व (205.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.) बामोर, विकास खण्ड में पाया जाता है। चिरगॉव बंगरा तथा मऊरानीपुर में क्रमशः 324, 396, व 354 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. कार्यिक घनत्व मिलता है। बबीना विकास खण्ड 557 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. कार्यिक घनत्व पाया जाता है।

कृषिगत घनत्व (Agricaltural Density)

किसी क्षेत्र की कृषि पर आधारित जन संख्या और कृषि भूमि के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। जिसमें कृषित भूमि के प्रति वर्ग किमी. में कृषि पर आधारित जनसंख्या के अनुपात को व्यक्त किया जाता है (चांदना एवं सिद्दू, 1950)। शर्मा (1975) के अनुसार कृषि जनसंख्या घनत्व एक निश्चित समय पर प्रति इकाई कृषि गत भूमिपर कृषि में संलग्न जनसंख्या का द्योतक होता है। वस्तुतः जिस क्षेत्र में कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि व्यवसाय में लगा हो, वहॉ के लिए कृषि घनत्व

मानव भूमि सम्बन्ध को जानने का एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी तरीका है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि घनत्व की गणना करने के लिए यहां की ग्रामीण जनसंख्या को ही कृषि पर आधारित जनसंख्या के रूप में मान लिया गया है क्योंकि झांसी जनपद जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र में दोनों प्रकार की जनसंख्या लगभग एक समान हैं। इसका कारण यहां की लगभग सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित होना हैं।

अध्ययन क्षेत्र के कृषि घनत्व की सारिणी संख्या 4.3 में प्रदर्शित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र का कृषि घनत्व औसतन 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. हैं। क्षेत्र में सबसे अधिक कृषि घनत्व मऊरानीपुर विकासखण्ड में 213 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. तथा सबसे कम कृषि घनत्व 120 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. बामोर विकासखण्ड में पाया जाता है। (चित्र संख्या 4.2 A) उसके अतिरिक्त विकास खण्ड बंगरा में कृषि घनत्व 208 प्रतिवर्ग किमी. है। इन क्षेत्र में उच्च कृषि घनत्व पाये जाने का प्रमुख कारण अनुवर्रक भूमि, सिंचाई सुविधाओं का अभाव और कृषि विकास की प्रतिकूल दशाओं की उपलब्धता है। दूसरे क्रम में वे विकासखण्ड शामिल किये गये हैं जिनका कृषि घनत्व 200 से कम किन्तु 150 से अधिक है। इनमें चिरगॉव बड़ागाँव 182 तथा मोंठ आते हैं। जिनका कृषिगत घनत्व क्रमशः 188,182, व 174 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हैं। बबीना एवं गुरसंराय विकास खण्ड में कृषि घनत्व क्रमशः 149 तथा 141 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. पाया जाता है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र जनसंख्या के अधिक कारकों को वहन कर रहा है। अतः क्षेत्र की कृषि में सुधार कर प्रगतिशील कृषि की विभिन्न तकनीकि का प्रयोग करके यहां की आर्थिक स्थिति को विकसित किया जा सकता है।

पोषण घनत्व (Nutrition Density)

जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में बोई जाने वाली भूमि की

उत्पादकता का अनुपात ज्ञात किया जाता है, उसे पोषण घनत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में कृषि भूमि की प्रत्येक ईकाई से जितने व्यक्ति को भोजन प्राप्त होता है, उन व्यक्ति की संख्या को पोषण घनत्व के रूप में माना जाता है। यह पोषण घनत्व ग्रामीण जनसंख्या तथा बोए गए क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। मानव एवं भूमि उपयोग की गणना करने वाली अन्य विधियों की तुलना में पोषण घनत्व एक स्वच्छ एवं परिष्कृत विधि है। किसी भी क्षेत्र के घनत्व की गणना में यह घनत्व भू–आकृतिक कर्यिक घनत्व की ही भाँति महत्वपूर्ण है। जिस क्षेत्र के लोगों को जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि है, उस क्षेत्र में मानव और भूमि के मध्य के अनुपात का सही मापन इसी घनत्व के द्वारा होता है। झांसी जनपद के पोषण घनत्व को सारिणी 4.3 तथा चित्र संख्या 4.2 B में प्रदर्शित किया गया है। पोषण घनत्व के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मोंठ विकासखण्ड पोषण घनत्व की दृष्टि से साधारण वर्ग में आता है जबकि उच्चवर्ग के अन्तर्गत बबीना का स्थान है। मध्यम पोषण घनत्व के अन्तर्गत चार विकासखण्ड (मोंठ, चिरगाँव, बामोर, बड़ागाँव) आते हैं। जनपद का कुल पोषण घनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. हैं।

नगरीकरण (Urbanization)

नगरीकरण की प्रवृत्ति किसी भी क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास की सूचक होती है। यह औद्योगीकरण प्रक्रिया की उत्प्रेरक तथा विकास का निर्धारक है।

नगरीकरण का अर्थ कुल नगरीय जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में उत्तरोतर वृद्धि अथवा कुल जनसंख्या दृष्टान्तों से यह स्पष्ट है कि नगरीकरण नगरों की जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि के आधार पर सम्भव नही हैं। अतः नगरीकरण की गति तथा स्तर कृषि कार्यो से कृष्येतर– आर्थिक क्रियाओं में क्रियाशील जनसंख्या के प्रत्यावर्तन के साथ ही ग्राम्य जनसंख्या के नगरोन्मुख

JHANSI DISTRICT
AGRICULTURAL DENSITY
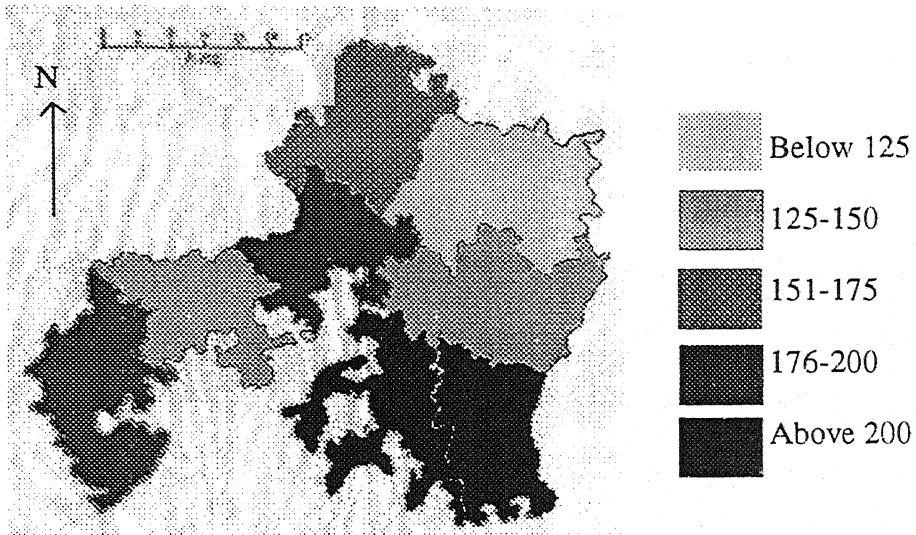
NUTRITION DENSITY
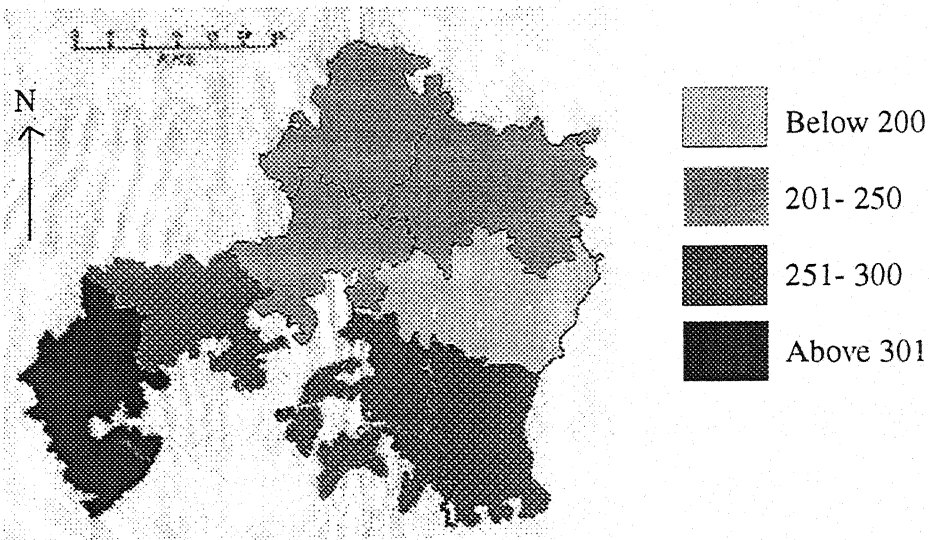
Fig 4.2

प्रवास पर आधारित है (मिश्र 1994)। सिंह (1975) के अनुसार नगरों की उत्तरोत्तर वृद्धि जनसंख्या के उस सतत प्रवाह का प्रतिफल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों से रोजगार तथा रहन–सहन के उच्च स्तर हेतु नगरों की ओर आकर्षित होती है। मिश्र (1978) ने नगरीकरण के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों का संश्लेषणात्मक रूप प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगरीकरण की प्रक्रिया किसी भी समाज के जनांनकीय, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक व पारिस्थितिक पक्षों में स्थानिक, वर्गीय व सामायिक परिवर्तनों के माध्यम से व्यक्त होती है। यह परिवर्तन गाँवों की तुलना में नगरों में बढ़ते हुए जनसंख्या संकेन्द्रण को प्रदर्शित करते है। द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाओं में लोगों की बढ़ती सहभागिता व कुछ निश्चित सामाजिक विशेषताओं को प्रगति पूर्वक अपनाना एक रूढ़िवादी ग्रामीण समाज के लिए विशिष्ट है।

नगरीकरण का इतिहास (History of Urbanization)

वस्तुतः पूर्ववर्ती साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत के नगरीकरण का इतिहास बहुत पुराना हैं। मोहन जोदड़ो तथा हड़प्पा की खण्डहर युक्त संरचना इस तथ्य को रहस्योद्घटित करती हैं कि यहाँ के नगर अति व्यस्त वाणिज्यिक केन्द्र थे (गोखले, 1959)। प्राचीन भारतीय नगरों का उद्भव उच्च उत्पादकता वाले मैदानी क्षेत्रों में हुई। क्रिस्टालर ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि उत्पादक भूमि की एक निश्चित मात्रा नगरीय केन्द्रों के विकास में सहयोग करती है। जबकि असमान धरातलीय क्षेत्रों में नगरीकरण की मात्रा में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है।

वस्तुतः उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में अवस्थित झांसी जनपद की भौतिक दशा पहले नगरीय विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी। क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से आच्छादित तथा ऊबड़–खाबड़ धरातलीय संरचना वाला था। क्षेत्र में अधिकांशतः

आदिवासी निवास करते थे, जो मानव बसाव के विकास को नियन्त्रित करती थे। नगरों का विकास मुख्यतः दसवीं एवं अठारवीं शताब्दी के मध्य हुआ। यहाँ पर अनेक नगर शाही राजवंशों द्वारा विकसित किए गए। नगर का विकास राजकुल की समृद्धि पर आधारित तथा साम्राज्यों के उत्थान पतन के आधार पर नगरों का भी उत्थान एवं पतन हुआ (पाल 1993)। उस समय के विकसित नगरों में एरिच व झांसी का प्रमुख स्थान है। ब्रिटिश शासन काल के समय में नगरीय विकास में वृद्धि हुई। उसका प्रमुख कारण सुविधा संरचना का विस्तृत पैमाने पर विकास होना था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात नगरीकरण की दिशा में तीव्रगति से वृद्धि हो रही है।

विकास प्रवृत्ति (Growth Trend)

नगरीकरण का विकास मुख्यतः आधुनिक समय में हुआ है। उसकी कालिक प्रवृत्ति वर्तमान शताब्दी (1901-91) के प्रथम दशक से ली गई है। 1991 की जनगणना के अनुसार झांसी जनपद में विभिन्न आकार वर्गो के 14 नगरीय केन्द्र हैं जबकि 1901 में मध्यम श्रेणी का एक नगर व चार लघु नगर थे। प्रथम श्रेणी का कोई भी नगर नहीं था। इस प्रकार विगत 10 वर्षो के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई हैं तथा कुल जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या में तीव्रगति से विकास हुआ हैं। नगरीय जनसंख्या के कालिक विकास के विश्लेषण से यह प्रकाश में आया कि सम्पूर्ण समय में नगरीय विकास की प्रवृत्ति समान नहीं रही है। 1921 से पूर्व के दशक की तुलना में 1921 के पश्चात के दशकों में नगरीकरण की प्रवृत्ति में स्पष्ट अन्तर देखने को मिलता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नगरीय जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जनपद में तहसीलवार नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को परिशिष्ट में दर्शाया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी तहसीलों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में पर्याप्त विभिन्नताये दृष्टिगत होती हैं। विभिन्न जनगणना अवधि में

नगरीय अधिवासों के आकार की रूपरेखा को सारिणी 4.4 में दर्शाया गया है।

(1) **प्रथम श्रेणी के नगर** :– झांसी जनपद में 1931 तक प्रथम श्रेणी का एक भी नगर नहीं था। 1941 में झांसी प्रथम श्रेणी का नगर बन गया तथा तब से 2001 तक अकेले झांसी नगर ही इस श्रेणी में हैं। इसकी जनसंख्या के प्रतिशत में उतार–चढ़ाव क्षेत्र में विविध श्रेणी के नगरों की संख्या घटने तथा बढ़ने के कारण मिलता है।

(2) **द्वितीय श्रेणी के नगर** :– 1931 तक झांसी द्वितीय श्रेणी का नगर था। 1941 में इसका प्रथम श्रेणी में प्रवेश हो जाने के कारण १९९१ तक इस श्रेणी में कोई नगर नहीं आया।

(3) **तृतीय श्रेणी के नगर** :– 1951 तक झांसी श्रेणी में कोई नगर नहीं था। 1961 में मऊरानीपुर इस श्रेणी में सम्मिलित हुआ तथा 1981 में अकेले ही इस श्रेणी में बना रहा। १९९१ में बबीना कैण्ट के आगमन के कारण इस श्रेणी के दो नगर हो गये।

(4) **चतुर्थ श्रेणी के नगर** :– 1951 तक मऊरानीपुर चतुर्थ श्रेणी का नगर था 1961 में बबीना को इस श्रेणी में सम्मिलित हो जाने पर इस श्रेणी के नगरों की संख्या दो हो गई। 1971 में समथर के आगमन से इस श्रेणी के नगरों की संख्या तीन हो गई। 1981 में गुरसंराय, चिरगॉव, रानीपुर, व बरूआ सागर चतुर्थ श्रेणी में आने से इस वर्ग के अतर्गत 6 नगर हो गये।

(5) **पंचम श्रेणी के नगर** :– 1901 में समथर पंचम श्रेणी का नगर था। 1991 में रानीपुर के आगमन से इसकी संख्या दो हो गई जो 1941 तक स्थिर रही। 1951 में इस श्रेणी में तीन नगर जबकि वर्तमान समय में पाँच (मोंठ, टोडी, फतेहपुर, कटेरा, इरच व गरौठा) नगरीय अधिवास इस वर्ग में आते हैं।

(6) **षष्टम श्रेणी के नगर** :– झांसी जनपद में 1901 में इस श्रेणी में दो नगर (गुरसंराय, चिरगॉव) थे। 1951 में बबीना के आगमन से इस श्रेणी में तीन नगर हो

सारिणी संख्या 4.4

आकारानुसार नगरों की संख्या

नगराकार वर्ष	प्रथम 100000 से अधिक	द्वितीय 50,000-10,0000	तृतीय 20,000-50,000	चतुर्थ 10,000-20,000	पंचम 5000-10,000	षष्ठ 5000 से कम	नगरो की कुल संख्या
1901	--	1	--	1	1	2	5
1911	--	1	--	1	2	2	6
1921	--	1	--	1	2	2	6
1931	--	1	--	1	2	2	6
1941	1	--	--	1	2	2	6
1951	1	--	--	1	3	3	8
1961	1	--	1	2	4	2	10
1971	1	--	1	3	3	2	10
1981	1	--	1	5	4	2	13
1991	1	--	2	6	5	--	14
2001	1	--					

स्रोत : जिला सूचना केन्द्र व सांख्यकीय कार्यालय से प्राप्त सूचना पर आधारित।

सारिणी संख्या 4.5

झांसी जनपद में नगरीकरण की मात्रा

वर्ष	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
1901	15.75
1911	17.07
1921	19.39
1931	17.61
1941	18.68
1951	21.91
1961	23.83
1971	21.54
1981	38.82
1991	39.61

सारिणी संख्या 4.6

विकास खण्ड पर नगरीकरण की मात्रा **1991**

क्र.सं.	विकास खण्ड	नगरीकरण की मात्रा
1	मोंठ	18.77
2	चिरगाँव	11.71
3	बामोर	12.23
4	गुरसराय	21.01
5	बंगरा	14.46
6	मऊरानीपुर	33.76
7	बबीना	27.93
8	बड़ागाँव	79.82

स्रोत: जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आंकड़ो द्वारा संगणित।

गए किन्तु 1961 में बबीना के चतुर्थ श्रेणी में चले जाने से इस वर्ग में 1981 तक कटेरा व गरौठा इस श्रेणी में बने रहे। 1991 में इस वर्ग के अन्तर्गत एक भी नगर नहीं हैं।

नगरीकरण की मात्रा (Degree of Urbanization)

नगरीकरण की मात्रा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। किसी क्षेत्र के नगरीकरण की मात्रा उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास की प्रतीक होती है। सारिणी 4.5 में विभिन्न दशकों के अन्तर्गत नगरीकरण की मात्रा दर्शायी गयी है। सारिणी 4.5 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि झांसी जनपद में 1901 में नगरीकरण की मात्रा 15.75, 1951 में 21.91 तथा 1991 में 39.61 प्रतिशत थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगरीकरण की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके अलावा विकास खण्ड स्तर पर भी नगरीयकरण की मात्रा का विश्लेषण किया गया है (सारिणी 4.6 एवं चित्र संख्या 4.3) सारिणी 4.6 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चिरगांव बंगरा, बामोर में नगरीकरण की मात्रा क्रमशः 11.71, 12.23, 14.46 प्रतिशत है। इन विकास खण्डों में नगरीकरण की मात्रा अत्यन्त कम है जो यह दर्शाती है कि यहां की आर्थिक संरचना कृषि प्रधान तथा परम्परागत किस्म की है व नगरीकरण प्राथमिक अवस्था में है। इसके अतिरिक्त मोंठ (18.77 प्रतिशत) गुरसराय (21.01 प्रतिशत) में भी नगरीकरण की मात्रा 25.0 से कम है जिससे स्पष्ट होता है कि प्राथमिक क्रियाओं की अधिकता के कारण नगरीकरण की मात्रा का बहुत कम विकास हुआ हैं। इन नगरों पर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता पी० जार्ज (1970) की टिप्पणी उचित प्रतीत होती है कि जिस क्षेत्र की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25 प्रतिशत से नीचे है, उन्हें प्राचीन कृषि सभ्यता वाला क्षेत्र कहा जा सकता है। बबीना तथा मऊरानीपुर विकासखण्ड में नगरीकरण का अधिक विकास हुआ है। यहाँ नगरीयकरण की मात्रा क्रमशः 27.93 व 33.76 प्रतिशत है। बबीना

JHANSI DISTRICT
DEGREE OF URBANIZATION
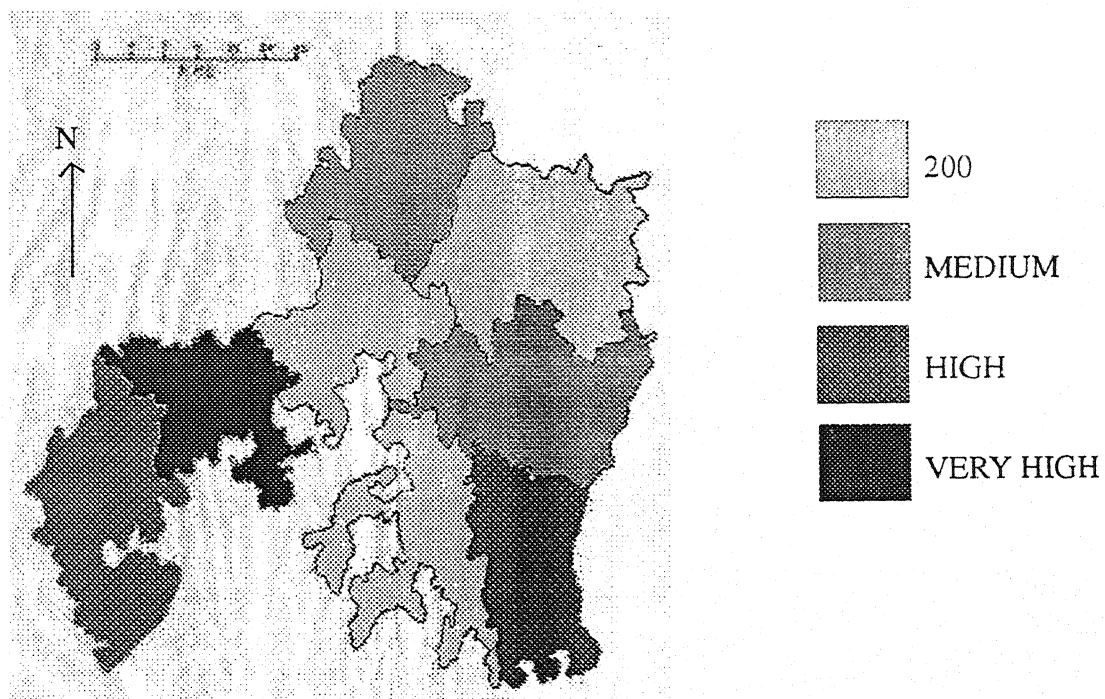
Fig 4.3

एक छावनी केन्द्र तथा मऊरानीपुर औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। इसलिये यहाँ पर नगरीय करण की मात्रा अधिक है। बड़ॉगाव विकासखण्ड मे झांसी नगर की महत्वपूर्ण स्थित होने के कारण नगरीयकरण की मात्रा अधिक है। यह क्षेत्र आर्थिक क्रियाओ के अधिक विकसित होने तथा कृष्येतर कार्यों में अधिकांश जनसंख्या के कार्य करने के फलस्वरूप 79.82 प्रतिशत नगरीकरण की मात्रा पायी जाती है। इसलिए यहाँ तीव्र गति से नगरीकरण में वृद्धि हुई है।

References

1. Quoted in Berry. B.J.L. and Horfon F.K. (Eds.) (1970) Geographic Perspectives on Urban System, Prentice Hall, New Jersey, P. 75
2. Chandna, R.C. and Sidhu, (1980)] Introduction to Population Geography, Kalyani Publisher, New Delhi, pp. 18-19
3. Clarke, John, I (1966), Population Geography. Pergamorn Press, Ox ford. p. 14.
4. Demko, G.T. Rose, H. M. and Sohnell, G.A. (1970), Popalation Geography, A Reader, Mc Graw Hill Book Co. New York, Part iv, p and 22.
5. Ford, C.D. (1953) Habitat, Economy and Society, London, p. 463
6. Gokhle, B. G. (1959) Ancient India, History and Culture, Asia Publish ing House. Bombay, P. 15.
7. मिश्र कृष्ण कुमार (1994), अधिवास भूगोल, कुसुम प्रकाशन अतर्रा, पृष्ठ सं. 115।
8. सिंह रामबली (1975), भारत में नगरीकरण की विशेषतायें, उत्तर भारत भूगोल, भूगोल पत्रिका, अंक 2, संख्या 2, पृष्ठ संख्या 831
9. Misra, R.P. (1970) Million Cities In the Context of World Urbanisaton in

R.P. Misra (edit.) Million Cities in India, Vikas Publishing House New Delhi.

10. पाल, केतराम (1993), बुन्देलखण्ड (उ०प्र०) की विकास प्रक्रिया में लघु एवं मध्यम आकार के नगरों की भूमिका, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय झांसी, पृष्ठ संख्या – 108।
11. Sharma, R.C. (1975), Population Trends Resource and Environmental Handbook on Population- Education, Dhanpa Rai and Sons. Delhi, p. 34
12. Steel R.W. (1953), Land and People in the British Tropical, African Geography, p.40
13. Trewartha, G.T. (1953), A Case For Population Geography, Association of American Geography, Vol XII Page, 911.
14. Quoted in Ullman, E.A. (1967), Theory of Location for cties in Mayer, H.M. Kohn, C.P. (Eds.) Reading in Urban Geography, Central Book Depot., Allhabad, p.203.
15. Zelinesky, W.A. (1966), Prolague to Population Geography,, London.

अध्याय - ५

जनसंख्या संरचना (Population Structure)

जनसंख्या संरचना (Population Structure)

जनसंख्या संरचना के अन्तर्गत जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया है । जनसंख्या की यह उपर्युक्त विशेषताएँ जनसंख्या संरचना का वास्तविक रूप प्रदर्शित करती हैं। इनसे क्षेत्र का प्राकृतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। इस अध्याय के अन्तर्गत लिंगानुपात, आयु संरचना, धार्मिक व साक्षरता प्रतिरूप, व्यावसायिक सरंचना तथा निर्भरता अनुपात का अध्ययन किया गया है। यह तत्व जनसंख्या वृद्धि तथा विकास क्षमताओं और सम्भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इससे स्थान विशेष के सामाजिक आर्थिक एवं जनांककीय स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है (भट्टाचार्य, 1976)।

लिंग–अनुपात (Sex -Ratio)

किसी निश्चित जनसंख्या में पुरूष एवं स्त्रियों के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है (पन्त,1963)। यौनानुपात से दो सम्बन्धित समूहों का आकार ज्ञात होता है(ब्रेसले,1969)। इसके अलावा पुरूषों तथा स्त्रियों का अनुपात विभिन्न सामाजिक समस्याओं को भी उत्साहित करता है। लिंगानुपात प्रति एक सौ स्त्रियों के पीछे पुरूषों की संख्या को बताता है जबकि भारत वर्ष में यह अनुपात प्रति एक हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में आकलित किया जाता है(तिलारा,1979)। झाँसी जनपद में 1901 से 1991 तक के यौनानुपात से स्पष्ट होता है कि 90 वर्षों में यह क्रमशः घटता–बढ़ता रहा है। इसी प्रकार की स्थिति कुछ भिन्नताओं के साथ उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। सम्पूर्ण भारत वर्ष में यौनानुपात प्रदेश तथा जनपद स्तर से भिन्न है, मात्र 1951 में कुछ वृद्धि देखने को मिलती है, शेष वर्षों में सतत् घटोत्तरी प्रदर्शित होती है। उत्तर प्रदेश में 1961 में प्रति हजार पुरूषों पर 909 स्त्रियाँ जबकि 1981 में प्रति हजार पुरूषों पर 885 स्त्रियाँ थी। वर्ष 1971व 1991

में प्रति हजार पुरूषों पर 879 स्त्रियाँ थी। झाँसी जनपद में 1971 से यौनानुपात नें सतत् गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर 1961,1971,1981व 1991 में क्रमशः 896, 871,869 व 863 स्त्रियाँ प्रति एक हजार पुरूषों पर थी।

जनपद में यौनानुपात की बढ़ती–घटती दरों का प्रमुख कारण पुरूष वर्ग का जीविकोपार्जन हेतु जनपद से बाहर आना व जाना है। झाँसी जनपद में लिंगानुपात का प्रदर्शन सारिणी संख्या 5.1 में किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियाँ कम हैं। विकासखण्ड स्तर पर किए गए विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों में स्त्रियों का अनुपात अधिक है (सारिणी संख्या 5.1)।

सारिणी संख्या 5.1

लिंगानुपात, 1991

क्रम संख्या	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या में प्रतिशत		प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या		
		पुरूष	स्त्रियाँ	कुल	ग्रामीण	नगरीय
01	मोंठ	53.58	46.42	856	851	866
02	चिरगांव	53.78	46.22	859	856	885
03	बामौर	54.25	45.75	843	839	877
04	गुरसरॉय	54.13	45.87	847	843	864
05	बंगरा	53.54	46.46	868	865	882
06	मऊरानीपुर	53.46	46.54	871	861	897
07	बबीना	53.75	46.25	861	850	912
08	बड़गांव	53.32	46.68	874	848	880
	झाँसी जनपद	52.28	47.72	863	852	880

स्रोतः जनगणना पुस्तिका व जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आंकड़ों की गणना पर आधारित।

सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात बंगरा विकास खण्ड (865) तथा न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात बामौर (839) विकास खण्ड में है। नगरीय लिंगानुपात की दृष्टि से बबीना (912) का प्रथम स्थान है जबकि न्यूनतम लिंगानुपात गुरसरॉय (864) में मिलता है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से बड़ागांव (874) सर्वोच्च स्थान पर है जबकि बामौर (843) सबसे न्यून स्थान पर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि झाँसी जनपद के लिंगानुपात में विकासखण्ड स्तर पर काफी भिन्नताएँ विद्यमान है। अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या में स्त्री–पुरूष अनुपात का प्रर्दशन मानचित्र 5.1 में किया गया है। लिंगानुपात के उपयुर्क्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र के प्रत्येक भाग में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। स्त्रियों की न्यूनता का मुख्य कारण स्त्रियों की मृत्युदर का अधिक होना है, जिसके लिए यहां का भौतिक वातावरण, पिछड़ापन, गरीबी तथा बाल विवाह जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियाँ, स्त्री शिक्षा का अभाव, असन्तुलित आहार, स्त्रियों के प्रति अनुदारवादी व्यवहार इत्यादि कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। क्षेत्र की स्त्रियाँ अपनी शिशु अवस्था, बाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था में तिरस्कृत रूप में देखी जाती हैं (गोसल,1961)। अतएव स्त्रियों के प्रति इस हेय दृष्टिकोण से भी क्षेत्र का यौनानुपात प्रभावित होता है। पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की मृत्युदर का अधिक होना भी इस तथ्य को प्रमाणित करता है। विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात को चित्र संख्या 5.2 ए व 5.2 बी में प्रदर्शित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की तुलना में लिंगानुपात कम है।

अध्ययन क्षेत्र का ग्रामीण लिंगानुपात 852 तथा नगरीय लिंगानुपात 880 इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा मृत्युदर का अधिक होना है। असुरक्षित ग्रामीण परिवेश भी एक मुख्य कारण है जिससे सम्पन्न परिवारों की ग्रामीण महिलाएँ शहरी क्षेत्रों की

JHANSI DISTRICT

GENERAL SEX-RATIO

Female Per Thousand Males

Below 850

851-860

861-870

Above 870

Fig 5.1
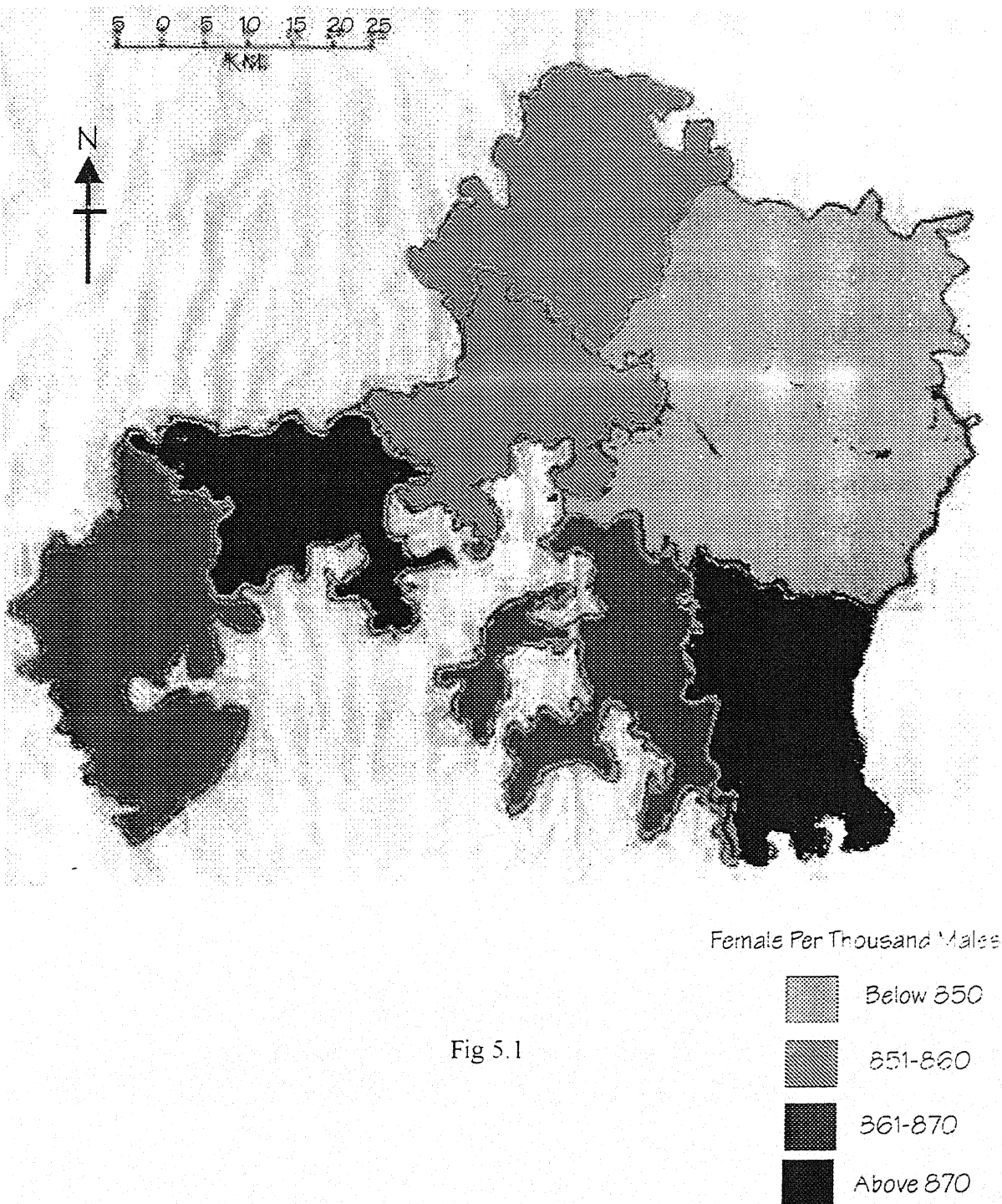
JHANSI DISTRICT
SEX-RATIO
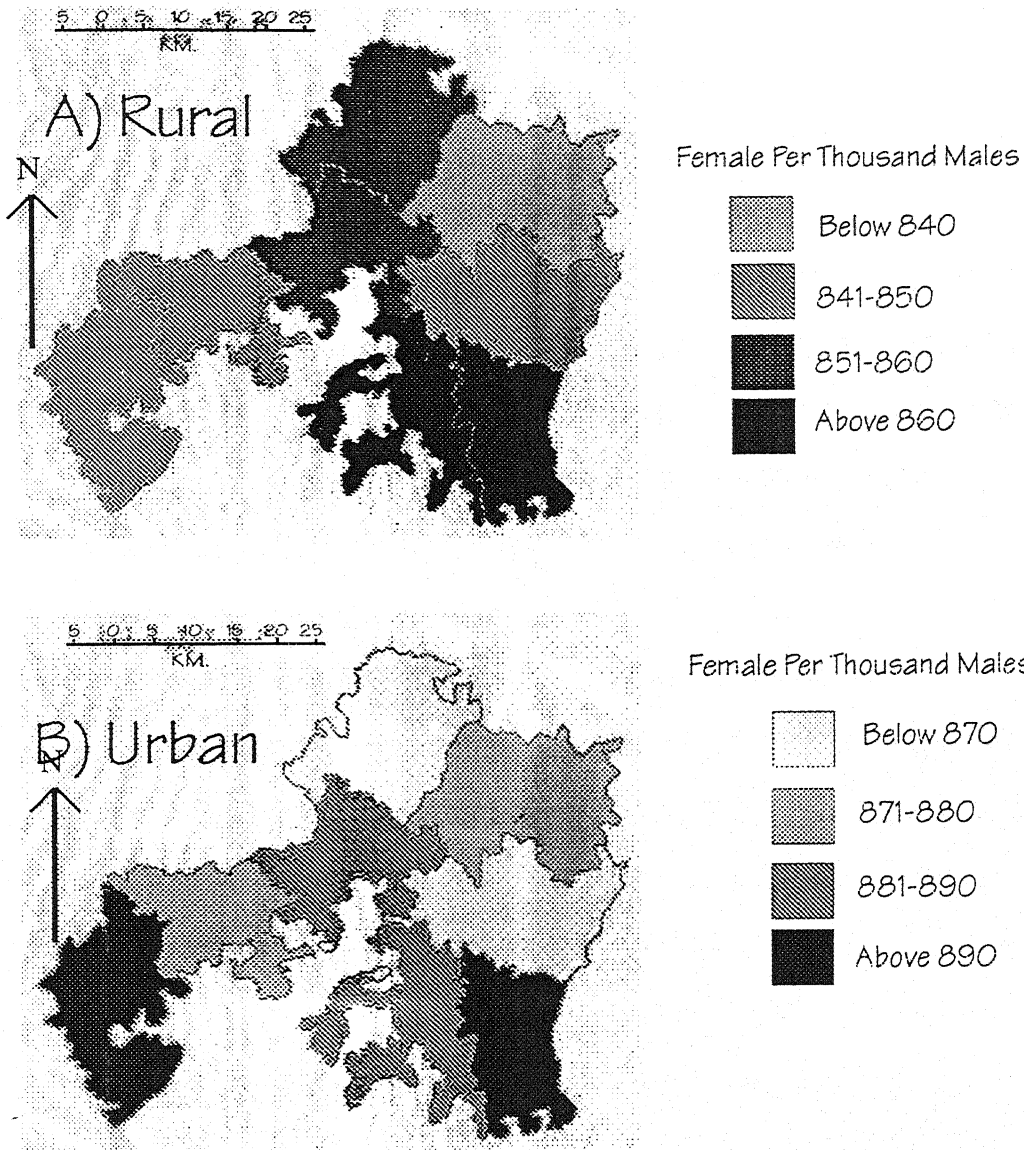
Fig. 5.2

ओर स्थानान्तरित हो गई हैं।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में स्त्रियों की कमी एक सामाजिक खतरा है । इसके निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का समाधान, स्त्रियों की बेहतर शिक्षा हेतु उचित व्यवस्था, प्रसव से सम्बन्धित उचित चिकित्सा सुविधाओं का प्रबन्ध, समाज में स्त्रियों को उचित सम्मान तथा बाल्यावस्था में ही जनसंख्या में लिंग अनुपात में सन्तुलन बनाए रखना, भ्रूण परीक्षण पर रोक आदि अत्यन्त आवश्यक है। वास्तव में स्त्री व पुरूष समान रूप से समाज के महत्वपूर्ण अंग है। अतः सम्यक विकास हेतु इनका सन्तुलित अनुपात आवश्यक है।

आयु संरचना (Age Structure)

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वास्तविक अनुरेखण के लिए उसकी जनसंख्या को आयु के आधार पर विभाजित करना आवश्यक है। जनसंख्या संरचना को समझने का महत्वपूर्ण पक्ष वास्तव में आयु संरचना है। इसके आधार पर भविष्य में जनसंख्या का अनुमान तथा वर्तमान आर्थिक समस्याओं को समझा जा सकता है (पन्त,1893)। आयु मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इससे विद्याध्ययन वर्ष, श्रमशक्ति में प्रवेश, मताधिकार, विवाह वर्ष, कार्य मुक्ति वय इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों की गणना के साथ–साथ मृत्युदर तथा विवाह दर और आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा व्यावसायिक स्वरूप के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। आयु संरचना के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पक्ष हैं–

(1) आयु संरचना किसी जनसंख्या में पराश्रितों के अनुपात को प्रदर्शित करती है।

(2) आयु संरचना के अध्ययन से श्रम–शक्ति की औसत आयु ज्ञात की जा सकती है।

(3) समाज में उपभोग के स्वरूप के निर्धारण में आयु संरचना का महत्वपूर्ण

योगदान है।

(4) आयु संरचना मृत्युदर के निर्धारण में सहायक है।

(5) आयु संरचना वैवाहिक व्यवस्था को भी निश्चित व प्रमाणित करती है।

(6) किसी देश की राजनीतिक विचार धारा को प्रभावित करने में आयु संरचना का महत्वपूर्ण योगदान है।

आयु संरचना के विश्लेषण से बच्चों, युवा तथा वृद्धों की संख्या का आनुपातिक वितरण मालूम होता है। इसके आधार पर भावी योजनाएँ क्रियान्वित करने में मदद मिलती है। झाँसी जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या में सबसे अधिक संख्या 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है। इनमें बालिकाओं का प्रतिशत बालकों से अधिक है। यदि 19 वर्ष तक की जनसंख्या का विश्लेषण किया जाय तो अध्ययन क्षेत्र की 51.39 प्रतिशत जनसंख्या इस उम्र तक की है। सम्मिलित रूप से इस वर्ग में बालिकाओं की संख्या बालकों की अपेक्षा कम (49.85 प्रतिशत) है। सम्पूर्ण जनसंख्या में 20से 59 वर्ष की आयु के मध्य पुरूषों की संख्या 42.88 प्रतिशत तथा स्त्रियों की संख्या 43.50 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि इस आयु वर्ग में 0.62 प्रतिशत स्त्रियों कीसंख्या अधिक है। 60 वर्ष से अधिक उम्र में 6.65 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं (सारिणी 5.2)।

जनसंख्या के आयु वर्ग के सामान्य वितरण के विश्लेषण से यह तथ्य रहस्योद्घाटित होता है कि जैसे–जैसे आयु वर्ग की ज्येष्ठता में वृद्धि होती जाती है, जनसंख्या के प्रतिशत भाग में कमी होती जाती है (चित्र संख्या 5.3)। यह घटोत्तरी प्रत्येक आयु वर्ग में भिन्न–भिन्न दर से हुई है। पुरूषों एवं स्त्रियों के प्रतिशत वितरण के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि 10 से 29 आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या में कमी आयी है। इसका प्रमुख कारण कम आयु में विवाह तथा कम अन्तराल में शिशु प्रसवों के दबाव के फलस्वरूप स्त्रियों की मृत्युदर अधिक है। इसके ठीक विपरीत 9 वर्ष

JHANSI DISTRICT
AGE & SEX PYRAMIDS
FEMALE
MALE
Above 60
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
32 28 24 20 16 12 8 4 0
0 4 8 12 16 20 24 28 32
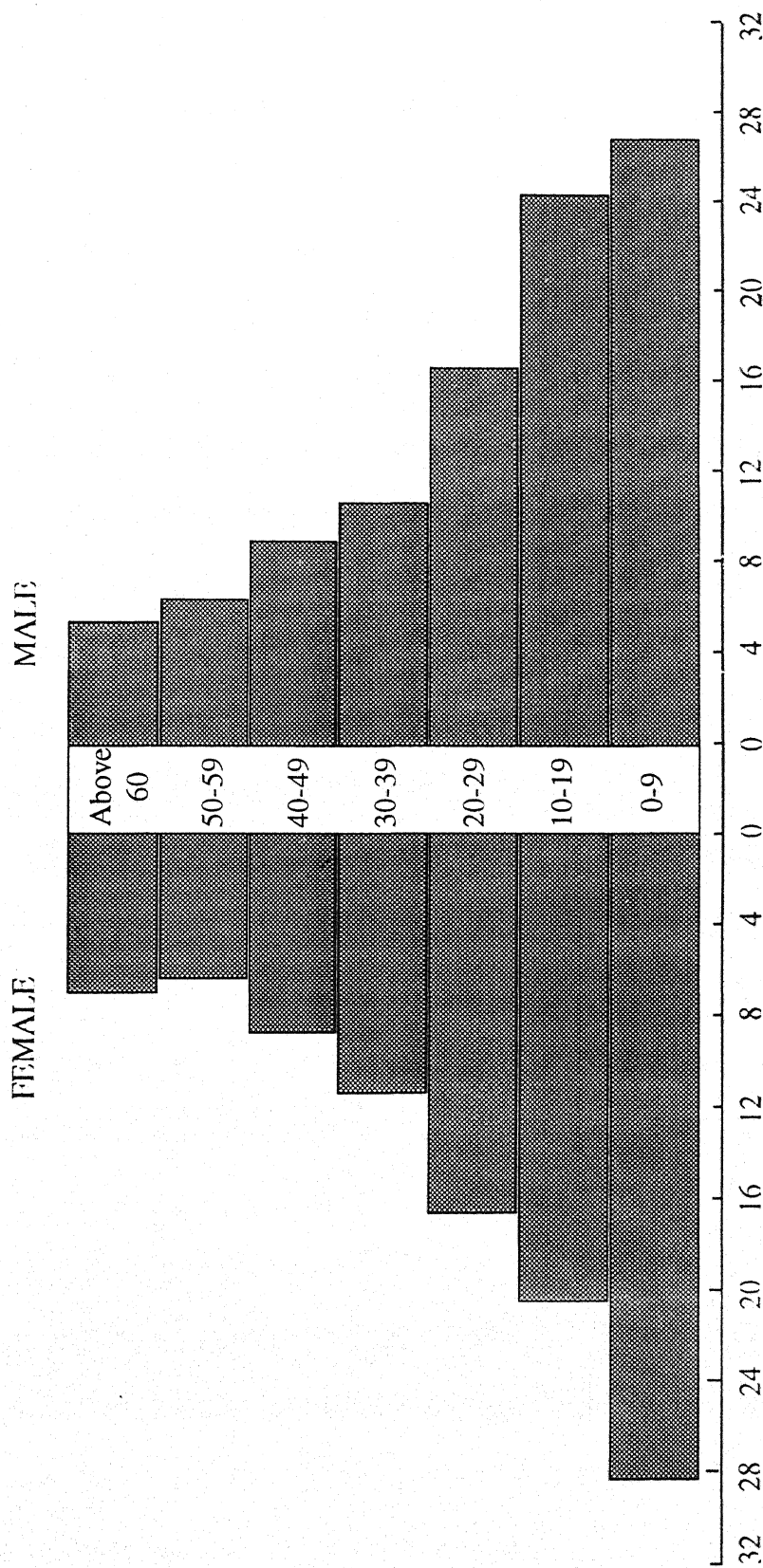
FIG. 5.3

से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पुरूषों की मृत्युदर स्त्रियों से अधिक है। 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में पुरूषों की अधिक मृत्युदर का कारण पुरूषों की औसत आयु स्त्रियों की तुलना में कम है।

ग्रामीण तथा नगरीय आयु संरचना (Rural and Urban Age Structure)

झाँसी जनपद के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में आयु संरचना लगभग सम्पूर्ण जनसंख्या की ही तरह है। 10 से 29 आयु वर्ग में ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या अधिक है (सारिणी संख्या 5.2), क्योंकि इस उम्र में अधिकांश ग्रामीण काम की तलाश में नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या से कम है। इस का प्रमुख कारण यह है कि इस उम्र में सेवानिवृत्त होकर लोग नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों को चले जाते हैं क्योंकि गांवों में उनकी अचल सम्पत्ति होती है।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के तुलनात्मक विवेचन से यह यह भी स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण जनसंख्या की भांति गांवों तथा नगरों में भी 19 वर्ष की आयु तक के शिशु एवं तरूण वर्ग की संख्या अधिक है। इस आयुवर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में 51.39 प्रतिशत पुरूष तथा 48.97 प्रतिशत स्त्रियाँ निवास करती है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में इसी आयु वर्ग के अन्तर्गत 51.36 प्रतिशत पुरूष तथा 51.23 प्रतिशत स्त्रियाँ सम्मिलित हैं। इस वर्ग में अधिक जनसंख्या का प्रमुख कारण उच्च जन्मदर बाल विवाह तथा अशिक्षा जैसी विविध सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएँ जिम्मेदार हैं। वस्तुतः यह एक अविकसित क्षेत्र है जो अनुत्पादक जनसंख्या के अतिरिक्त भार को वहन करने में असमर्थ है। अतएवं विभिन्न आयुवर्गों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सहयोग से सन्तुलन स्थापित करना आवश्यक हैं। उम्र बढ़ने के साथ–साथ गांवों तथा नगरों में सभी आयु वर्ग के लोगों की संख्या कम होती जाती है। 20 से

49 आयु वर्ग में ग्रामीण स्त्रियों की संख्या पुरूषों से अधिक है। यह कार्यशील जनसंख्या है। उसमें पुरूष रोजगार के सन्दर्भ में गांवों से नगरों की ओर चले जाते हैं। यही कारण है कि इस आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या पुरूषों से अधिक है। नगरों में ठीक उसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों की संख्या अधिक है। 50 वर्ष से अधिक उम्र में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है (सारिणी संख्या 5.2)। नियमित जीवन चर्या, तनाव तथा दुश्चिन्ता से दूर होने के कारण स्त्रियाँ पुरूषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। यही कारण है कि उनकी उम्रावधि सामान्यतः बढ़ जाती है।

सारिणी संख्या 5.2

आयु–संरचना 1991 (प्रतिशत में)

आयु वर्ग	कुल		ग्रामीण		नगरीय	
	पुरूष	स्त्रियाँ	पुरूष	स्त्रियाँ	पुरूष	स्त्रियाँ
0-9	27.26	28.39	27.74	28.84	26.46	27.65
10-19	24.13	21.46	23.65	20.13	24.90	23.58
20-29	16.14	16.17	14.91	15.42	18.17	17.37
30-39	11.15	11.83	11.18	12.11	11.20	11.39
40-49	9.23	9.18	9.48	9.72	8.80	8.34
50-59	6.36	6.32	6.77	6.78	5.67	5.69
60 से अधिक	5.73	6.65	6.27	6.99	4.80	5.98

स्रोत :– जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आंकड़ो द्वारा संगणित।

जनसंख्या का संरचनात्मक अनुपात (Structural Ratio of Population)

जनसंख्या का संरचनात्मक अनुपात प्रमुखतया किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के आयु, लिंगानुपात और वैवाहिक स्तर पर निर्भर करता है (क्लार्क,1966)। झाँसी जनपद की जनसंख्या के विश्लेषणत्मक अध्ययन हेतु वयस्क अनुपात, आयु दर सूचकांक तथा निर्भरता अनुपात ज्ञात किया गया है।

वयस्क अनुपात (Youth-Ratio) – 20 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को वयस्क की श्रेणी में गिना जाता है। वस्तुतः यह वह अनुपात होता है, जो सम्पूर्ण जनसंख्या में वयस्क जनसंख्या के प्रतिशत से सम्बन्ध रखता है। 1991 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में 46.29 प्रतिशत वयस्क अनुपात है जबकि 1971 में इनका अनुपात 43.25 प्रतिशत था। इस प्रकार 1991 के दशक में वयस्क अनुपात में वृद्धि हुई। क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का वयस्क अनुपात नगरीय जनसंख्या की अपेक्षा कम है। इससे यह स्पष्ट है कि नगरों की अपेक्षा गांवों में क्रियाशील जनसंख्या कम है। इसका प्रमुख कारण यह है ग्रामीण वयस्क विभिन्न नगरीय आकर्षणों के फलस्वरूप नगरों में स्थानान्तरित हो रहे हैं।

आयुदर–सूचकांक (Age-Rate Index)

आयुदर सूचकांक के माध्यम से बच्चों एवं वृद्धों का अनुपात मालूम किया जाता है। झाँसी जनपद की जनसंख्या का आयुदर–सूचकांक निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया गया है–

$$\text{आयुदर सूचकांक} = \frac{\text{म}}{\text{क}} \times 100$$

अर्थात, म = जनपद में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या, क = जनपद में 20 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की संख्या।

उपयुर्क्त गणना से स्पष्ट हुआ कि जनपद में आयुदर सूचकांक 14.69 प्रतिशत है जो 1971 में 10.77 प्रतिशत था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के फलस्वरूप यह अनुपात बढ़ा है।

निर्भरता अनुपात (Dependency Ratio)

वस्तुतः निर्भरता अनुपात क्रियाशील जनसंख्या पर भार स्वरूप जनसंख्या का मापक होता है(त्यागी,1982)। जनपद की जनसंख्या का निर्भरता अनुपात प्रति सौ वयस्क व्यक्तियों पर निर्भर लोगों की संख्या से ज्ञात किया गया है। इस आधार पर जनपद में 1971 में 113.21 तथा 1991 में 116.04 प्रतिशत निर्भरता अनुपात आंकलित किया गया। इससे स्पष्ट है कि निर्भरता अनुपात बढ़ता गया। वस्तुतः जनपद में जनसंख्या का वयस्क अनुपात कम होने का प्रमुख कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि को माना जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में वयस्क व्यक्तियों पर निर्भर लोगों की संख्या में कमी आयी है।

झाँसी जनपद में शिशुओं तथा वृद्धों के निर्भरता अनुपात के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिशुओं का निर्भरता अनुपात वृद्धों की अपेक्षा बहुत अधिक है। 1991 में जनसंख्या में बच्चों एवं वृद्धों का निर्भरता अनुपात क्रमशः 82.6 प्रतिशत व 10.7 प्रतिशत रहा। बच्चों के निर्भरता अनुपात में अधिकता मुख्य रूप से रहन–सहन का निम्न स्तर, असफल परिवार नियोजन, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की न्यूनता का द्योतक है। झाँसी जनपद की अन्य तहसीलों की अपेक्षा झाँसी तहसील में सामर्थ्यशील जनसंख्या का अनुपात (51.48 प्रतिशत) सबसे अधिक है जिसका प्रमुख कारण यहां के नगरीकरण का उच्च स्तर है। झाँसी नगर बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर है। अतः क्षेत्र के अन्य तहसीलों की जनसंख्या विशेषतः 20 से 59 आयुवर्ग की जनसंख्या रोजगार

की प्राप्ति के उद्देश्य से इस नगर की ओर आकर्षित होती है। झाँसी में पुरूषों की समर्थ जनसंख्या 51.0 प्रतिशत जबकि स्त्रियों की सामर्थ्य जनसंख्या पुरूषों की तुलना में अधिक (52.30 प्रतिशत) है। इसका प्रमुख कारण झाँसी नगर की स्थिति को ही माना जा सकता है जो कि सामर्थ्यशील जनसंख्या के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बिन्दु है।

विकासखण्ड स्तर पर निर्भरता अनुपात (Blockwise Dependency Ratio)

जनपद के जनसंख्या के आयु तथा निर्भरता अनुपात के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आयु वर्ग एवं क्रियाशीलता में शत–प्रतिशत सह–सम्बन्ध नहीं पाया जाता। अतएव निर्भरता अनुपात वास्तविक क्रियाशील जनसंख्या के सन्दर्भ में ज्ञात किया जाना तथ्यपूर्ण है। जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड की क्रियाशील व अक्रियाशील जनसंख्या के आधार पर निर्भरता अनुपात मालूम करने पर स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में 1991 में प्रति सौ कार्यशील जनसंख्या पर आश्रितों की संख्या 186 थी। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति सौ कार्यशील जनसंख्या पर आश्रितों की संख्या 149 तथा नगरीय क्षेत्रों में यह अनुपात 26.0 था।

1991 में जनपद के विकासखण्डों में सबसे अधिक आश्रितों की संख्या बड़ागांव विकासखण्ड (175 व्यक्तियों) में थी सबसे कम आश्रितों की संख्या चिरगांव विकासखण्ड (131 व्यक्ति) आंकी गई। अन्य विकासखण्डों यथा–मोंठ, बामौर, गुरूसरॉय,बंगरा,मऊरानीपुर तथा बबीना में क्रमशः 144,148,134,165,143 तथा 165 व्यक्ति प्रति सौ कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित पाए गए।(चित्र संख्या 5.4 ए)

साक्षरता प्रतिरूप(Literacy Pattern)

साक्षरता किसी देश के आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और प्रजातांत्रिक स्थायित्व के लिए अत्यावश्यक है (चांदना एवं सिद्धू,1980)। किसी भी क्षेत्र की

JHANSI DISTRICT

A) DEPENDENCY -RATIO
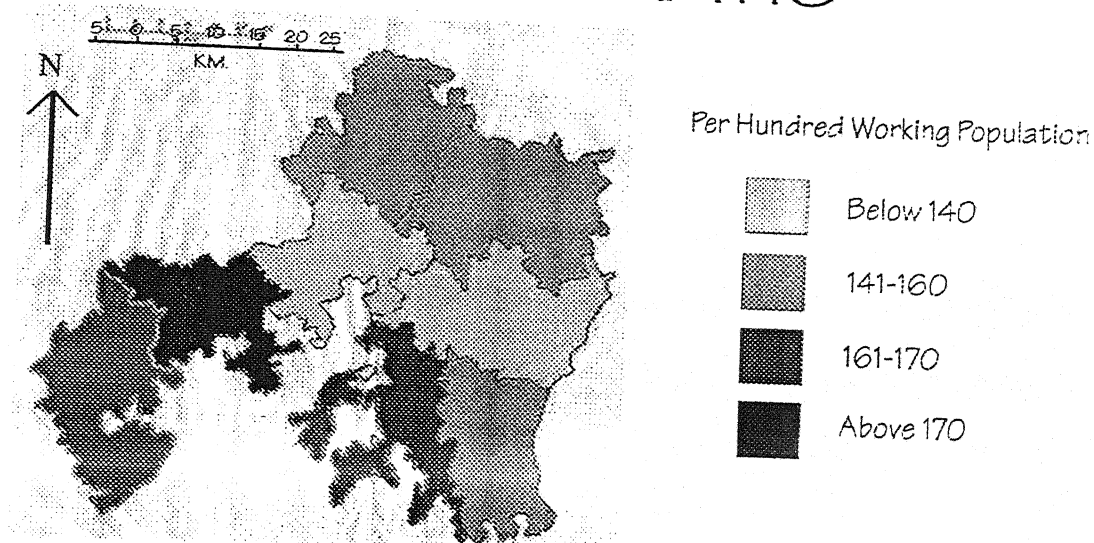
B) GENERAL LITERACY
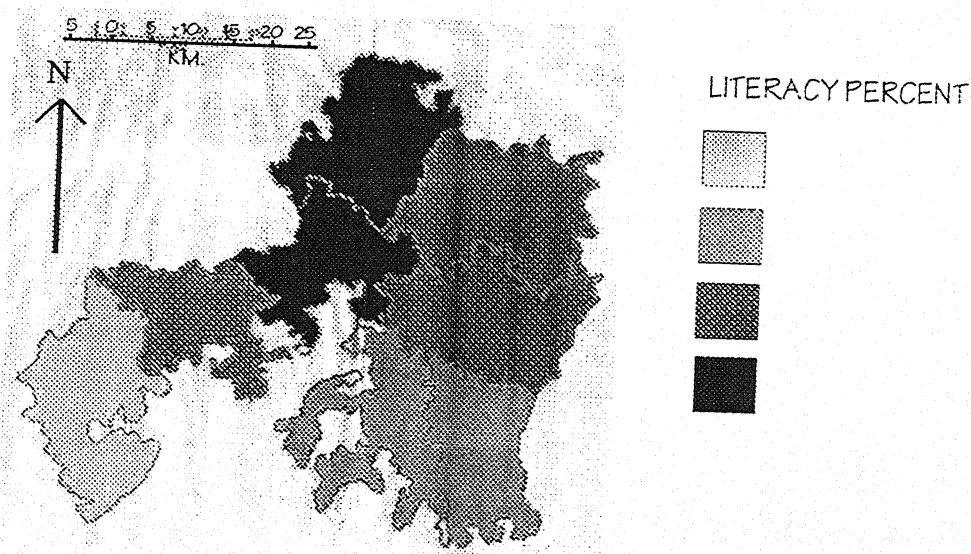
FIG 5.4

अर्थव्यवस्था वहाँ की साक्षरता तथा उस क्षेत्र की साक्षरता का वहाँ की अर्थव्यवस्था पर अन्योन्याश्रय प्रभाव होता है। इसीलिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में न्यून साक्षरता तथा औद्योगिक दृष्टि से विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में अधिक साक्षरता पाई जाती है(गोसल,1969)। सम्पन्न परिवारों में साक्षरता अधिक पाई जाती है क्योंकि उनमें बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत निम्न जीवन स्तर व्यतीत करने वाले परिवारों में साक्षरता दर काफी कम होती है क्योंकि इनके पास साधनों की कमी होती है तथा उनमें परिवार के सम्पूर्ण सदस्य चाहे वह वृद्ध हों या बालक, पुरूष हों या स्त्री समवेत कार्य से अर्जन कर जीविका चलाते हैं।

नगरों की अर्थव्यवस्था गांवों की अपेक्षा भिन्न होती है। नगरों में शिक्षा व रोजगार के विशेष अवसर सुलभ होते हैं। गांवों में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बच्चे भी कार्य में जुट जाते हैं। अतः उन्हे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसके साथ–साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी इसमें सहायक है।

वे समाज जिनमें पुरूषों के समान स्त्रियों को समान अवसर उपलब्ध हैं, वहाँ स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। इसके विपरीत उन समाजों में जहां स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, वहां साक्षरता का स्तर अत्यन्त न्यून होता है। वर्तमान समय में भारत में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका प्रभाव वैवाहिक स्तर पर भी देखने को मिलता है।

नगरों में शिक्षण संस्थाओं की बहुलता है, अतः गांवों की अपेक्षा शैक्षिक सुविधाएँ अधिक हैं। इस समय शासन द्वारा प्रत्येक गांव में शिक्षण सुविधाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है। आर्थिक तंगी की वजह से गांव के बच्चे बाहर जाकर नगरों में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बहुत कम जा पाते हैं। आवागमन व संचार

की सुविधाएँ भी साक्षरता को प्रभावित करती हैं। जिन देशों में तकनीक का अधिक विकास हुआ है, वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या व साक्षरता अधिक है। साक्षरता दर बढ़ाने में सरकारी नीति एक महत्वपूर्ण कारक है। अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि से सम्बन्धित शासकीय नीतियों के फलस्वरूप साक्षरता दर ऊँची हो रही है तथा साक्षरता विकास हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है।

सारिणी संख्या 5.3

साक्षरता प्रतिशत

वर्ष	जनपद			उत्तर प्रदेश			भारत		
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
1961	21.46	5.93	15.83	23.75	4.16	14.34	34.44	12.95	24.02
1971	40.90	15.40	28.90	31.50	10.55	21.70	39.45	18.69	29.46
1981	50.60	21.40	37.00	38.87	14.42	27.38	46.74	24.88	36.17
1991	66.80	33.80	51.60	55.73	25.31	41.60	64.13	39.29	52.21

स्रोत :– सांख्यकीय डायरी, उ०प्र० से प्राप्त आंकड़ों पर आधारीत।

जनपदीय साक्षरता 1961,1971,1981 तथा 1991 में क्रमशः 15.83, 28.90 तथा 37.0 प्रतिशत रही, जो 1991 में बढ़कर 51.60 प्रतिशत हो गई। इनमें पुरूषों की संख्या (66.80 प्रतिशत) स्त्रियों (33.80 प्रतिशत) से अधिक है। जनपद में उत्तर प्रदेश की तुलना में साक्षरता प्रतिशत सभी वर्षों में अधिक है। राष्ट्र की तुलना में 1961, 1971 व 1991 में साक्षरता प्रतिशत कम तथा शेष वर्षों में अधिक रहा है (सारिणी 5.3)। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या की अधिकता है।

स्थानिक साक्षरता प्रतिरूप (Spatial Literacy Pattern)

विकासखण्ड स्तर पर किए गए विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यहां पर साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। विकास खण्ड स्तर पर साक्षरता के प्रतिशत को सारिणी 5.4 व चित्र संख्या 5.4 बी में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.4

विकासखण्ड स्तर पर साक्षरता प्रतिशत (1991)

क्र.सं.	विकासखण्ड	कुल साक्षरता	पुरूष साक्षरता	स्त्री साक्षरता
01	मोंठ	46.0	65.1	23.2
02	चिरगांव	47.3	67.1	23.8
03	बामौर	42.7	62.5	18.6
04	गुरसराय	42.8	61.6	19.0
05	बंगरा	36.5	52.7	17.4
06	मऊरानीपुर	38.6	55.1	19.1
07	बबीना	34.8	49.3	16.0
08	बड़ागांव	41.1	59.2	19.4
	योग	41.1	59.1	19.6

स्रोतः सांख्यकीय पत्रिका, 1996 पर आधारित है।

सारिणी 5.4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 35.0 प्रतिशत से कम साक्षरता के

अन्तर्गत बबीना विकासखण्ड आता है। 35 से 40 प्रतिशत साक्षरता के अन्तर्गत मऊरानीपुर एवं बंगरा विकासखण्ड आते हैं जहां साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 38.6 तथा 34.8 है। 40 से 45 प्रतिशत के मध्य तीन विकासखण्ड सम्मिलित हैं तथा दो विकासखण्ड 45.0 प्रतिशत से अधिक साक्षरता के अन्तर्गत आते है। जिनका साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 47.3 व 46.0 है।

जनपद के विकासखण्डों की पुरूष साक्षरता के स्थानिक वितरण प्रतिरूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पांच वर्गों में विभाजित किया गया है। अति निम्न वर्ग (50 प्रतिशत से कम) के अन्तर्गत बबीना (49.3 प्रतिशत); तथा निम्न वर्ग (50 से 55 प्रतिशत) के मध्य बंगरा विकासखण्ड आता है। मध्यम (55–60 प्रतिशत) के मध्य मऊरानीपुर व बड़ागांव विकासखण्डों का स्थान है। उच्च वर्ग (60–65 प्रतिशत) तथा अति उच्च वर्ग (65 प्रतिशत से अधिक) के अन्तर्गत दो–दो विकास खण्ड आते हैं जिनके नाम क्रमशः बामौर व गुरूसरॉय तथा मोंठ व चिरगांव हैं। यद्यपि परीक्षण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रत्येक विकासखण्ड में स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत अधिक है (चित्र संख्या 5.5 ए व 5.5 बी)।

स्त्री साक्षरता के विश्लेषण हेतु सम्पूर्ण जनपद के विकासखण्डों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्न स्त्री साक्षरता वर्ग (18 प्रतिशत से कम) के अन्तर्गत बबीना व बंगरा विकासखण्ड सम्मिलित हैं। यहां स्त्री साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 17.4 व 16.0 प्रतिशत है। मध्यम वर्ग स्त्री साक्षरता (18–20 प्रतिशत) में बामौर, गुरूसरॉय, मऊरानीपुर व बड़ागांव विकासखण्ड आते हैं। उच्च स्त्री साक्षरता वर्ग (20 प्रतिशत से अधिक) के अन्तर्गत मोंठ व चिरगांव विकासखण्ड आते हैं।

JHANSI DISTRICT

A) MALE-LITERACY
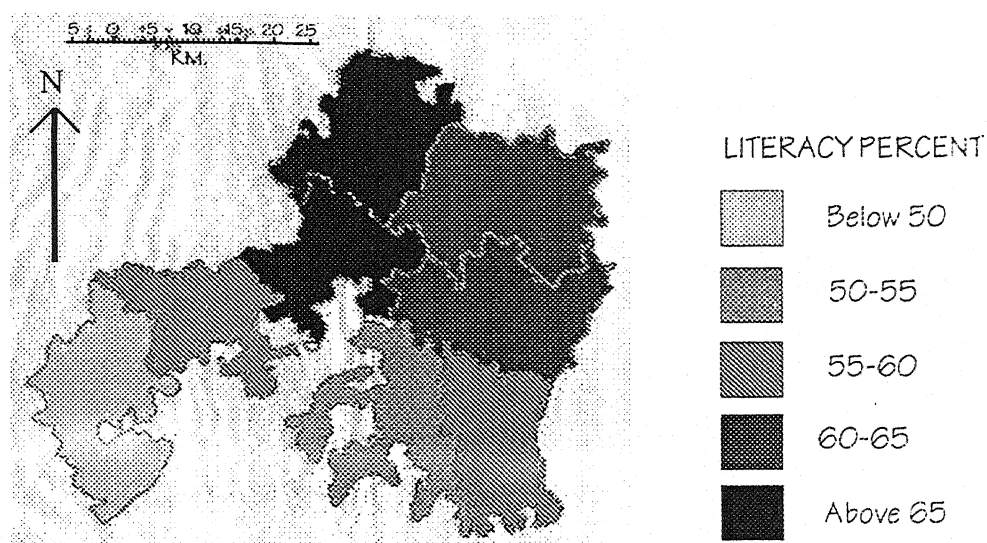
B) FEMALE-LITERACY
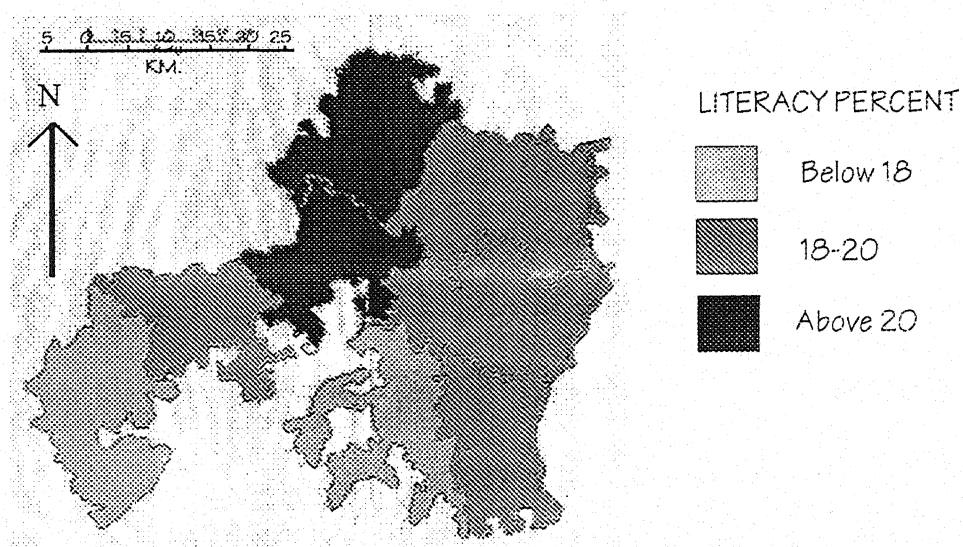
FIG 5.5

इनका साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 23.2 व 23.8 प्रतिशत है। यद्यपि 1961 से लेकर अबतक किए गए विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पुरूष एवं स्त्री साक्षरता में सतत् वृद्धि हुई है लेकिन स्त्री शिक्षा में वृद्धि पुरूषों की अपेक्षा काफी कम है। गांवों में अभी भी निर्धन बालिकाएँ उच्च शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकती। केवल धनी परिवारों की बालिकाएं की महिला संरक्षकों के साथ नगरों में पढ़ने जाती हैं (मिश्र एवं नामदेव,1996)।

नगर केन्द्रों में साक्षरता का स्थानिक वितरण प्रतिरूप

जनपद में 1991 में चौदह नगरीय केन्द्र हैं। यह केन्द्र 1951 में 8 तथा 1961 में 10 थे। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत कठेरा (43.78) तथा टोडी फतेहपुर (43.93) टाऊन एरिया में है। रानीपुर नगर केन्द्र (45.20 प्रतिशत) साक्षरता पाई जाती है। चार नगरीय केन्द्रों (समथर, बरूआसागर, एरिच एवं बड़ागांव में 60.0 प्रतिशत से कम साक्षरता है (सारिणी संख्या 5.5)। मऊरानीपुर, बबीना छावनी, गुरूसरॉय, चिरगांव, मोंठ तथा गरौठा में 60 से 70 प्रतिशत के मध्य साक्षरता पाई जाती है। सबसे अधिक साक्षरता प्रथम श्रेणी के नगर झाँसी (71.0 प्रतिशत) में पाई जाती है। यह उस क्षेत्र का प्रमुख नगरीय केन्द्र है, जहॉ विस्तृत पैमाने पर शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। नगर केन्द्रों में सबसे अधिक पुरूष साक्षरता झाँसी (67.54 प्रतिशत) तथा सबसे कम पुरूष साक्षरता कठेरा टाउन एरिया (46.94 प्रतिशत) में है। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता झांसी नगर समूह (49.58 प्रतिशत) तथा सबसे कम बरूआसागर नगर पालिका (20.93 प्रतिशत) में अंकित है (सारिणी 5.5)।

सारिणी संख्या 5.5

जनपद झाँसी में नगरीय केन्द्रों की साक्षरता,1991 (प्रतिशत में)

क्र.सं.	नगरीय केन्द्र	कुल	पुरुष	स्त्री
01	मऊरानीपुर	62.19	59.88	39.25
02	बबीना छावनी	66.79	59.96	43.68
03	समथर	56.49	58.70	31.43
04	बरूआसागर	51.25	51.69	20.93
05	गुरसॅराय	65.01	65.32	40.15
06	रानीपुर	45.20	47.41	21.61
07	चिरगाँव	69.17	69.84	41.83
08	मोंठ	63.77	63.56	40.03
09	टोडी फतेहपुर	43.93	50.99	17.45
10	एरिच	53.63	57.72	23.86
11	बड़ागाँव	57.53	61.50	28.44
12	गरौठा	60.50	61.54	33.67
13	कठेरा	43.78	46.94	21.24
14	झाँसी	71.00	67.54	49.58
	योग	**69.40**	**78.60**	**54.60**

स्रोत :– जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आंकड़ो की गणना पर आधारित।

जनपद के ग्रामीण व नगरीय साक्षरता को देखने से स्पष्ट होता है कि कुछ लघु नगरों को छोड़कर नगरीय साक्षरता का प्रतिशत ग्रामीण साक्षरता से बहुत अधिक है।

वस्तुतः निम्न जीवन स्तर के ग्रामीण परिवारों की मानसिकता है कि जबतक बड़े होकर यह पढ़ेंगे तब तक मजदूरी करके अपना व अपने परिवार की जीविका चलाएंगे। उसके अलावा गाँव के निम्न आय स्तर के लोग शिक्षा विशेषतया स्त्री

शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि गांवों में शहरों की तुलना में साक्षरता प्रतिशत न्यून है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय दूर–दूर हैं। अतः निम्न जीवनस्तर तथा मजदूरवर्ग के लोग अपने बच्चों को विद्यालय न भेजकर काम में लगाना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं।

आयु वर्गानुसार साक्षरता (Literacy According to Age Interval)

आयु वर्गानुसार साक्षर व्यक्तियों में 5 वर्ष के नीचे के समस्त लोगों को अनपढ़ मान लिया जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है। आजकल 5 वर्ष की उम्र से नीचे वाले बालक भी लिखना बोलना जान जाते हैं। क्योंकि शहरों में नर्सरी विद्यालयों को खोलकर लोग बच्चों को शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं और अच्छा धनप्राप्त करते हैं।

जनपद में 10-14 वर्ष के सर्वाधिक व्यक्ति साक्षर हैं। इस आयु वर्ग में 39.36 प्रतिशत लोग साक्षर थे जिसमें 53.44 प्रतिशत पुरूष तथा 14.82 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। किन्तु नगरों में इस वर्ग के अन्तर्गत 59.37 प्रतिशत पुरूष और 19.89 प्रतिशत स्त्रियाँ शिक्षित हैं। नगरों में गांवों की अपेक्षा स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत ऊँचा है। इसका मुख्य कारण यह है कि नगरों में स्त्रियों की शिक्षा पर काफी ध्यान दिया जाता है। गांवों में पुरूषों का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत 15-19 आयुवर्ग में है किन्तु स्त्रियों का सर्वाधिक प्रतिशत 10-14 आयु वर्ग हैं। इसके बाद के वर्षो में पुरूषों में धीरे–धीरे कमी आयी है जबकि स्त्री साक्षरता में तीव्र गति से कमी देखने को मिलती है। वस्तुतः स्त्री और पुरुष परिवार के दो महत्पूर्ण पक्ष है। एक के अधिक विकसित होने तथा दूसरे के पिछड़े रह जाने पर परिवार का सही सन्तुलन स्थापित नहीं होता। यही कारण है कि वे परिवार जहां पुरूष और स्त्री को समान शिक्षा व नीतिगत निर्णयों में भागीदारी होती है, उन्नति कर जाते है। यह तभी सम्भव है, जब नर–नारी शिक्षित हों। नारी शिक्षा का उच्चतर स्तर साक्षरता के उच्चतर स्तर को प्रदर्शित करता है।

धार्मिक प्रतिरूप (**Religious Pattern**) :–

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के अध्ययन में धार्मिक विशेषताओं का ज्ञान अत्यधिक महत्वूपर्ण हैं क्योंकि पैदा होते ही मनुष्य सामाजिक बन्धनों में जकड़ जाता

है, जिसका सम्बन्ध किसी न किसी धर्म से अवश्य होता है। भारत विभिन्न धर्म एवं सम्प्रदायों का देश है। यहाँ मुख्य रूप से हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, एवं बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। धर्म भारतीय सामाजिक संगठन का आधार है (भट्टाचार्य 1976)। यह जनसंख्या भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका अन्य पक्षों की तुलना में कम अध्ययन मिलता है (क्लार्क 1977)। धार्मिक मान्यताएँ जनसंख्या विकास की भावी गति को प्रभावित करती है। अस्तु धर्म के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन बहुत उपयोगी है। वस्तुतः समाज में अनेक क्रियाकलाप धार्मिक संस्तुतियों के आधार पर सम्पन्न होते हैं, जैसे विवाह की उम्र, पुनर्विवाह की प्रथा, स्त्रियों की व्यावसायिक संरचना आदि कारण व्यक्तिगत होने के साथ–साथ समुदाय, जाति तथा धर्म से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा लोगों का खानपान, रहन–सहन तथा सामाजिक विचारधाराओं पर भी धर्म का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है।

हिन्दू धर्म यहाँ का प्रमुख व मूल धर्म है। इसलिए यहाँ पर हिन्दू धर्म के अनुयायिओं की संख्या सर्वाधिक है। सारिणी 5.6 के अनुसार यहाँ की सम्पूर्ण जनसंख्या में 90.30 प्रतिशत व्यक्ति हिन्दू हैं। दूसरा स्थान मुस्लिम जनसंख्या (8.42 प्रतिशत) का है। शेष ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा अन्य धार्मिक सम्प्रदायों का प्रतिशत क्रमशः 0.49, 0.27, 0.09, 0.42 तथा 0.02 है।

सारिणी संख्या 5.6

जनपद में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या, 1991 (प्रतिशत में)

क्र.सं.	नगरीय केन्द्र	कुल	ग्रामीण	नगरीय
01	हिन्दू	90.30	94.56	83.78
02	मुस्लिम	8.42	5.10	13.47
03	ईसाई	0.49	0.10	1.10
04	सिख	0.27	0.03	0.63
05	बौद्ध	0.09	0.11	0.04
06	जैन	0.42	0.08	0.94
07	अन्य	0.02	0.02	0.04
	योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत :– सांख्यकीय पत्रिका जनपद झांसी, 1996 द्वारा संगणित।

तहसील स्तर पर किए गए विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि झाँसी (85.33 प्रतिशत) तहसील को छोड़कर शेष सभी तहसीलों – मोंठ, गरौठा व मऊरानीपुर में क्रमशः 93.97,94.63 तथा 93.62 प्रतिशत हिन्दू, झांसी में 12.29 प्रतिशत मुसलमान तथा शेष अन्य तहसीलों में 5.0, 6.0 प्रतिशत के मध्य मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। झांसी (2.38 प्रतिशत) को छोड़कर शेष सभी तहसीलों में 0.50 प्रतिशत से कम अन्य धार्मिक सम्प्रदायों के लोग निवास करते हैं।

सारिणी संख्या 5.7

झांसी जनपद में तहसीलवार धार्मिक संरचना

क्र.सं.	तहसील	हिन्दू	मुसलमान	अन्य
01	मोठ	93.97	5.74	0.29
02	गरौठा	94.63	5.00	0.37
03	मऊरानीपुर	93.62	5.88	0.50
04	झाँसी	85.33	12.29	2.38

स्रोत :– जिला सूचना केन्द्र द्वारा प्राप्त सूचना पर संगणित।

चूँकी झाँसी इस क्षेत्र का प्रमुख नगर है तथा व्यावसायिक दृष्टि से प्रमुख रूप से विकसित है। इसलिए अन्य तहसीलों की अपेक्षा यहाँ अन्य सम्प्रदायों के लोग बड़ी मात्रा में निवास करते हैं।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में धार्मिक जनसंख्या के स्वरूप में काफी विभिन्नता

पाई जाती है। गांवों में हिन्दुओं की संख्या (94.56 प्रतिशत) नगरों (83.68 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक है। मुसलमानों की संख्या गांवों (5.10 प्रतिशत) की तुलना में नगरों (13.47 प्रतिशत) में काफी अधिक है। ईसाइयों की संख्या गांवों (0.10 प्रतिशत) की अपेक्षा शहरों (1.10 प्रतिशत) में बहुत ज्यादा है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र में हिन्दू जनसंख्या अधिक है। यहां पर हिन्दुओं की अधिकता का प्रमुख कारण क्षेत्र में काफी समय से हिन्दू राजाओं (चन्देल एवं राजपूत आदि) का आधिपत्य रहा है तथा इन राजाओं ने अन्य धार्मिक सम्प्रदायों के लोगों को विकास के अवसर नहीं दिए। चूंकि क्षेत्र में मुस्लिम शासकों का कुछ समय तक शासन रहा। इसलिए क्षेत्र में हिन्दुओं के पश्चात् मुस्लिम धर्म के अनुयाइयों की संख्या अधिक है। अन्य सम्प्रदायों के लोग यहां पर अपने धर्म के प्रचार–प्रसार व व्यावसायिक दृष्टि से आए तथा इस क्षेत्र में निवास करने लगे। यही कारण है कि इनकी संख्या इस क्षेत्र में काफी कम है।

व्यावसायिक प्रतिरूप (Ocupational Pattern)

किसी भी क्षेत्र के मानव का एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलाप होता है, जिससे वह अपनी जीविका चलाता है तथा जिसके आधार पर उसका जीवन स्तर निर्धारित होता है। वास्तव में मनुष्य जिस किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न रहता है तथा उससे उसका जीविकोपार्जन होता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। जनसंख्या का व्यावसायिक स्वरूप किसी भी समाज की आर्थिक स्थिति तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त करता है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र के अर्थतन्त्र में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। व्यावसासिक प्रतिरूप (गार्नियर, 1978)प्राकृतिक क्रियाओं तथा सामाजिक और पेशेवर विशेषताओं पर भी आधारित है। क्रियाशील तथा अक्रियाशील जनसंख्या के मध्य घटते–बढ़ते अनुपात और उससे प्राप्त परिणाम के आधार पर भावी योंजना तैयार करने में मदद मिलती है।

किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को मालूम करने से पहले,

कार्यशील जनसंख्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। सम्पूर्ण जनसंख्या को दो वर्गों में विभाजित किया जाता हे–

(1) कार्य करने वाली जनसंख्या ;

(2) कार्य न करने वाली जनसंख्या।

कार्य करने वाली जनसंख्या के अन्तर्गत उन्हे सम्मिलित किया जाता है जो किसी व्यवसाय, उद्योग, रोजगार तथा नौकरी आदि में कार्यरत हैं। इसके विपरीत कार्य न करने वालों में उन लोगों को समाहित किया जाता है जो किसी प्रकार का व्यवसाय/उत्पादन कार्य नहीं करते, जैसे बच्चे, बूढ़े आदि। अनाथालयों, जेलों तथा चिकित्सालयों में रहने वाले लोगों को भी कार्य न करने वालों में सम्मिलित किया जाता है। कार्य प्राप्ति के अनुसार कार्यशील जनसंख्या को भी दो भागों में विभक्त किया गया है– पूर्णकालिक तथा सीमान्तिक। जिन व्यक्तियों ने गत वर्ष में 6 माह से कम समय तक कार्य किया था उन्हें सीमान्तिक कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है। भारत में जनगणना वर्ष 1901 में 46.61 प्रतिशत क्रियाशील जनसंख्या थी जो 1951 में 39.10 प्रतिशत रह गई। कार्यशील व्यक्तियों की संख्या में कभी कुछ कमी तथा कभी कुछ वृद्धि हुई (सारिणी संख्या 5.8)।

सारिणी संख्या 5.8

भारत में क्रियाशील/अक्रियाशील जनसंख्या (प्रतिशत में)

वर्ष	क्रियाशील	अक्रियाशील
1901	46.61	53.39
1931	46.92	53.08
1951	39.10	60.90
1561	42.97	57.03
1971	32.09	67.91
1981	33.44	66.56
1991	37.50	62.50

स्रोत : जनगणना कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों द्वारा संगणित।

सारिणी 5.8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1961 के पश्चात् कार्यरत लोगों की संख्या कम अथवा तटस्थ है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के सुअवसर बढ़े हैं लेकिन जनसंख्या की अधिक वृद्धि के कारण अधिक विकास के प्रभाव तटस्थ हो गए हैं।

प्रान्तों के अन्तर्गत क्रियाशील जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात तमिलनाडु में (55.57 प्रतिशत) तथा सबसे कम पश्चिमी बंगाल (33.16 प्रतिशत) में है। उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 39.12 प्रतिशत है। झाँसी जनपद में भी आयु वर्ग तथा कार्यशीलता में पूर्ण सह–सम्बन्ध न हाने से क्रियाशील जनसंख्या की तुलना में अक्रियाशील जनसंख्या का अनुपात अधिक है। साथ ही अध्ययन क्षेत्र में निर्भरता अनुपात भी अधिक है।

सारिणी संख्या 5.9

जनपद में क्रियाशील/अक्रियाशील जनसंख्या (प्रतिशत में)

वर्ष	**क्रियाशील**	**अक्रियाशील**
1971	28.69	71.31
1981	30.13	69.87
1991	34.95	65.05

स्रोत :– जनगणना पुस्तिका 1971 व 1981 तथा जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त 1991 के आंकड़ों द्वारा संगणित।

जनपद में कार्यरत तथा अकार्यरत जनसंख्या के परीक्षण से स्पष्ट है कि रोजगार के अवसरों में तो वृद्धि हुई है लेकिन जनसंख्या की अत्यधिक बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप अक्रियाशील जनसंख्या में भी उतनी ही अधिक वृद्धि हुई है। 1991 में 34.95 प्रतिशत क्रियाशील जनसंख्या है जिसमें 4.8 प्रतिशत सीमान्तिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या है। इसके अन्तर्गत मौसमी श्रमिक– खेतों में कटाई, बुआई तथा निराई के समय, ईंट–भट्टों पर कार्य करने वाले तथा कुछ छात्र/छात्राएँ जो विद्याध्ययन के साथ–साथ अन्य कार्य भी किया करते हैं, आते हैं।

जनसंख्या भूगोल में व्यावसायिक संरचना का विशिष्ट महत्व है क्योंकि इसके माध्यम से क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था कृषि, अद्योग आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके विश्लेषणात्मक अध्ययन से क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास स्तर के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त होती है। प्राथमिक उत्पादन कार्यों (कृषि, वन, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि) में कार्यरत अधिकांश जनक्षेत्र विकास के प्रथम चरण में आते हैं। विकास के द्वितीय चरण के अन्तर्गत कुटीर व विनिर्माण उद्योग आदि सम्मिलित है। तृतीयक उत्पादन कार्य (सेवा तथा भारी मशीन निर्माण उद्योग) विकसित अर्थव्यवस्था के द्योतक हैं। भारत देश की विकसित देशों से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि भारत में लगभग 72.0 प्रतिशत कृषि क्रिया में संलग्न व्यक्ति हैं जबकि विकसित राष्ट्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका (12.5 प्रतिशत) तथा जापान (19.4 प्रतिशत) व्यक्ति ही कृषि कार्य में संलग्न हैं। इसके विपरीत भारत देश में उद्योगों के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या मात्र 19.7 प्रतिशत है जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 30 प्रतिशत तथा जापान में 29.3 प्रतिशत लोग उद्योग धन्धों में लगे हैं।

तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के फलस्वरूप भारतीय व्यावसायिक ढांचे में कोई आधारभूत परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। यही स्थिति उत्तर प्रदेश व अध्ययन क्षेत्र की भी देखने को मिलती है। झाँसी जनपद में प्राथमिक व्यावसायिक वर्ग में कृषि महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि कार्य में भी सामाजिक स्तर पर विविधताएँ देखने को मिलती हैं। कुछ किसानों के पास निजी भूमि होती है जिस पर वे स्वयं कार्य करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो खेती तो करते हैं किन्तु उस भूमिपर उनका स्वामित्व नहीं होता। जनपद में कार्यशील जनसंख्या की तुलना में अकार्यशील जनसंख्या अधिक है। जनगणना के तीन वर्षों में सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या 1991 में थी। कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत सतत् 1971 से बढ़ा है।

सारिणी संख्या 5.10

व्यावसायिक संरचना

व्यवसाय	1971	1981	1991
क्रियाशील जनसंख्या	28.69	30.13	34.95
अक्रियाशील जनसंख्या	71.31	69.87	65.05
कृषक	55.16	48.46	46.55
कृषक मजदूर	16.43	12.38	15.60
उद्योग एवं निर्माण कार्य	7.37	5.17	3.45
अन्य	21.04	33.99	34.40

इसके अतिरिक्त 1971 से लगातार अक्रियाशील जनसंख्या में गिरावट आयी है। क्षेत्र की क्रियाशील जनसंख्या को चार व्यावसायिक वर्गों में विभाजित किया गया है– कृषक, कृषक मजदूर, उद्योग एवं निर्माण कार्य तथा अन्य। अन्तिम अन्य कार्य के अन्तर्गत पशुपालन, बागवानी, वृक्षारोपण, खनन कार्य, व्यापार तथा वाणिज्य, यातायात, संग्रहण तथा संचार व अन्य सेवा कार्यों को सम्मिलित किया गया है। कृषकों का सबसे अधिक प्रतिशत 1971 में 55.16 प्रतिशत था। 1971 के पश्चात् कृषकों की संख्या में धीरे–धीरे कमी आयी है। सर्वाधिक कृषक नजदूर 1971 (16.43) जो 1991 में घटकर 15.60 प्रतिशत रह गए। उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगी जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत 1971 (7.37 प्रतिशत) में रहा, जो घटकर 1981 तथा 1991 में क्रमशः 5.17 तथा 3.45 प्रतिशत रह गया। 1971 के पश्चात उद्योगो में रोजगार वृद्धि की तुलना में जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुई। अन्य व्यवसायों में सर्वाधिक प्रतिशत 1991 (34.40 प्रतिशत) रहा। यद्यपि 1971 से ही इस वर्ग में लगे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है। पशुपालन, वृक्षारोपण, व्यापार तथा विभिन्न सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण इस वर्ग में सतत वृद्धि हुई है।

कार्यरत जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप (Distributional Pattern Of Working Population)

झाँसी जनपद में अकार्यशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या कम है। 1991 की जनगणना के अनुसार क्रियाशील जनसंख्या सीमान्तिक क्रियाशील जनसंख्या सहित 34.95 प्रतिशत है। क्रियाशील जनसंख्या में कमी रोजगार में वृद्धि की तुलना जनसंख्या में वृद्धि के कारण हुई है। क्रियाशील जनसंख्या के आधार पर जनपद के विकासखण्डों को तीन भागों में (सारिणी संख्या 5.11, चित्रसंख्या 5.6) विभाजित किया जा सकता है।

JHANSI DISTRICT
WORKING POPULATION
PERCENT
Below 40
40-42
Above 42
N
5 0 5 10 15 20 25
KM.
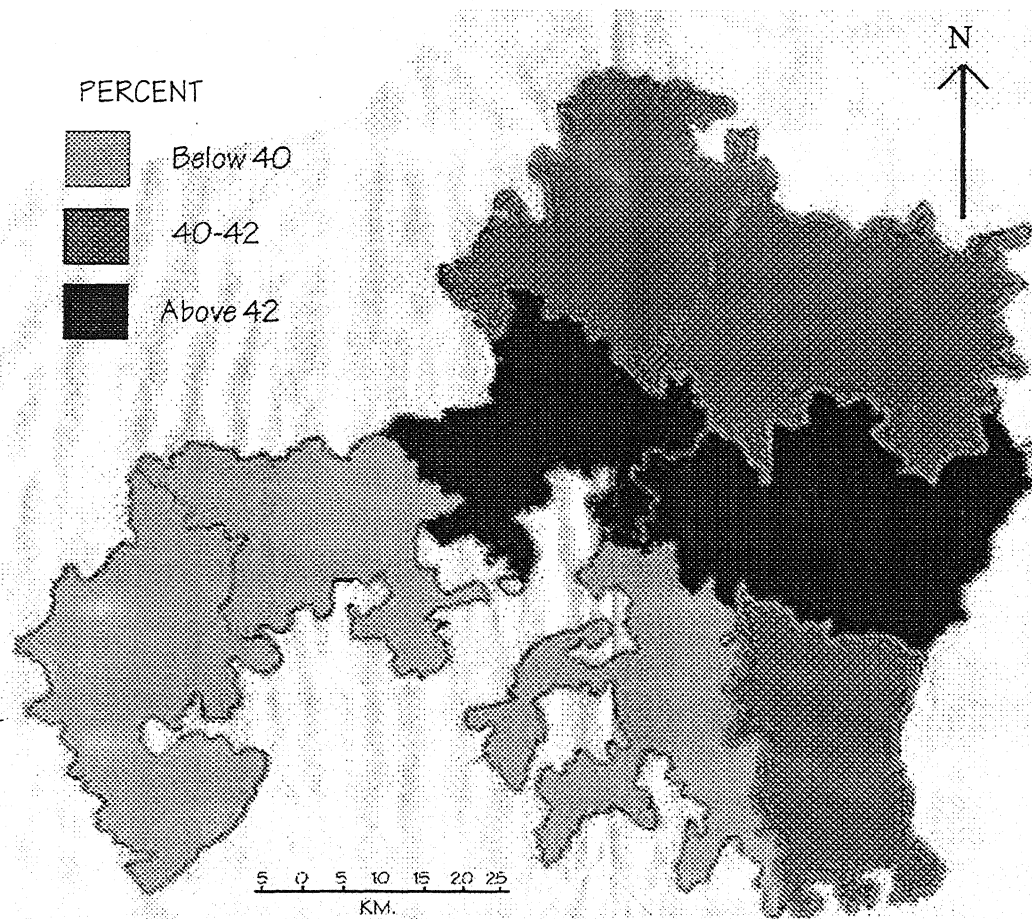
FIG 5.6

सारिणी संख्या 5.11

कार्यरत जनसंख्या का श्रेणीगत वितरण

श्रेणी	कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत	विकास खण्डो की संख्या	विकास खण्डो के नाम
निम्न	40 से कम	3	बंगरा, बबीना, बड़ागॉव
मध्यम	40-42	3	मोंठ, बामौर मऊरानीपुर
उच्च	42 से अधिक	2	चिरगांव, गुरसराय

स्रोत :– जिला सूचना केन्द्र, झाँसी द्वारा प्राप्त आंकड़ों की गणना पर आधारित।

सारिणी 5.11 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बंगरा, बबीना तथा बड़ागांव विकासखण्डों में क्रमशः 37.6,37.9 व 36.4 प्रतिशत कुल क्रियाशील जनसंख्या निवासित है। यह निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत मोंठ, बामौर व मऊरानीपुर विकासखण्ड आते है, जहां 40.4 प्रतिशत से लेकर 41.0 प्रतिशत तक क्रियाशील जनसंख्या है। चिरगांव (43.3 प्रतिशत) तथा गुरसंराय (42.8 प्रतिशत) विकासखण्ड कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि में उच्च श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित हैं।

कृषकों का वितरण प्रतिरूप (Distributionl Pattern of Cultivator's)

जनपद में कार्यरत जनसंख्या में कृषक सबसे अधिक हैं। इसमें 1971,1981 तथा 1991 में क्रमशः 55.16,48.46 तथा 46.55 प्रतिशत कृषक हैं। जनसंख्या में द्रुतगति से वृद्धि तथा भूमि में सतत कमी के परिणामस्वरूप अन्य व्यवसायों तथा बागवानी, पशुपालन आदि में कार्य करने से कृषक जनसंख्या में कमी आयी है। विकासखण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रतिरूप की स्थिति को सारिणी संख्या 5.12 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.12

विकासखण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रतिरूप,1991

क्र.सं.	विकासखण्ड	कृषक	कृषक मजदूर	उद्योगएवं निर्माण कार्य	अन्य कार्य
01	मोंठ	72.41	18.23	6.01	3.35
02	चिरगांव	67.27	22.16	3.53	7.04
03	बामौर	69.41	22.91	2.24	5.44
04	गुरसराय	68.13	22.42	3.27	6.18
05	बंगरा	65.64	18.64	7.27	8.45
06	मऊरानीपुर	62.71	23.86	6.24	7.19
07	बबीना	60.52	17.48	9.47	12.53
08	बड़ागांव	55.36	19.71	7.04	17.89

स्रोतः जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आकंड़ों की गणना पर आधारित।

सारिणी 5.12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विकासखण्ड में सर्वाधिक कृषक मोंठ (72.47 प्रतिशत) विकास खण्ड तथा सबसे कम कृषक (55.36 प्रतिशत) बबीना विकासखण्ड में है (चित्रसंख्या 5.7 ए)। 60 से 65 प्रतिशत कें मध्य कृषक मऊरानीपुर व बबीना विकास खण्ड में जबकि 65 से 70 प्रतिशत के मध्य कृषक चार विकासखण्डों अथा– चिरगांव,बामौर,गुरूसंराय तथा बंगरा में पाए जाते हैं।

कृषक मजदूरों का वितरण प्रतिरूप (Distributional Pattern of Agricultural Labourers)

जनपद की क्रियाशील जनसंख्या में महत्वपूर्ण स्थान कृषक मजदूरों का है। 1971,1981 तथा 1991 में जनपद में क्रमशः 16.43, 12.38 व 15.60 प्रतिशत कृषक मजदूर रहे। जनसंख्या वृद्धि के कारण 1991 में कृषक मजदूरों की संख्या बढ़ी है। विकासखण्ड स्तर पर कृषक मजदूरों की संख्या सबसे कम बबीना तथा

सबसे अधिक मऊरानीपुर में है। 18 से 21 तथा 21 से 23 प्रतिशत के मध्य तीन–तीन विकासखण्ड (मोंठ,बड़ागांव,बगरा तथा चिरगांव, बामौर, गुरसराय) आते हैं (चित्र संख्या 5.7 बी)। कृषि मजदूरों की घटती प्रवृत्ति से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है।

उद्योग एवं निर्माण कार्य में कार्यरत जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप (Distributional Pattern of Working Population of Industry & Construction Works)

जनपद में क्रियाशील जनसंख्या में संलग्न व्यक्तियों का तीसरा वर्ग उद्योग तथा निर्माण कार्य में लगी जनसंख्या का है। इस श्रेणी में सबसे कम व्यक्ति लगे हैं। जनगणना वर्ष 1971,1981 तथा 1991 में क्रमशः 7.37, 5.17 तथा 3.45 प्रतिशत व्यक्ति थे। उद्योगों के अभाव के कारण इस क्षेत्र मे इस वर्ग के अन्तर्गत लगे लोगों का प्रतिशत घटता है। विकासखण्ड स्तर पर विश्लेषण से स्पष्ट है कि बामौर (2.24 प्रतिशत) विकासखण्ड इस दृष्टि से काफी पिछड़ा है जबकि बबीना विकासखण्ड (9.47 प्रतिशत) का सर्वोच्च स्थान है। गुरसरॉय तथा चिरगांव विकासखण्ड 3 से 6 प्रतिशत के मध्य जबकि मोंठ, बंगरा, मऊरानीपुर तथा बड़ागांव विकासखण्ड 6 से 9 प्रतिशत के मध्य आते हैं। पारिवारिक तथा गैरपारिवारिक उद्योग धन्धों के विकास के कारण बबीना, बड़ागांव व बंगरा विकासखण्डों में उद्योग तथा निर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या अधिक है (चित्र संख्या 5.7 सी)।

अन्य व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण प्रतिरूप(**Distributional Pattern of Working Population in Works Other)**

जनपद में अन्य व्यवसाओं के अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 1971,1981 तथा 1991 में क्रमशः 21.04, 33.99 तथा 34.40 प्रतिशत थी। इस वर्ग में

DISTRIBUTIONAL PATTERN OF WORKING POPULATION
A) CULTIVATORS
N
KM.
Percent
Below 60
60-65
65-70
Above 70
B) AGRICULTURAL LABOURERS
N
KM.
Percent
Below 18
18-20
21-23
Above 23
C) INDUSTRY & CONSTRUCTIOL WORKS
N
KM.
Percent
Below 3
3-6
6-9
Above 9
D) OTHER OCCUPATIONS
N
KM.
Percent
Below 5
5-10
10-15
Above 15

Fig- 5.7

पशुपालन बागवानी, खननकार्य, व्यापार व वाणिज्य,यातायात, संग्रहण तथा संचार व अन्य सेवा कार्य सम्मिलित हैं। अन्य व्यवसायों में लगी जनसंख्या का प्रतिशत निरन्तर बढ़ा है। रोजगार हेतु नित नए स्त्रोतों में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

विकासखण्ड स्तर पर मूल्यांकन से स्पष्ट है कि इस वर्ग के अन्तर्गत सर्वाधिक जनसंख्या (17.89 प्रतिशत) बड़ागांव में है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस क्षेत्र में व्यवसाय तथा सेवाकार्यों में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। इस वर्ग के अन्तर्गत सबसे कम प्रतिशत मोंठ विकासखण्ड (3.35 प्रतिशत) में पाया जाता है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ विकास के कई अवसर उपलब्ध हैं। बबीना विकासखण्ड (12.53 प्रतिशत) का स्थान बड़ागांव के पश्चात् आता है। क्षेत्र के पांच विकासखण्ड (चिरगांव,बामौर,गुरसराय,बंगरा तथा मऊरानीपुर) 10-15 प्रतिशत वर्ग में आते हैं (चित्रसंख्या 5.7 डी)।

REFERENCES

(1) Bhattacharya, P.J. & Shastri, G.N. (1976), Population of India, Vikash Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, Page 51&63.

(2) Braclay, W.G., (1969), Techniques of Population Analysis, John Wiley and sons, Inc., London, Page 21.

(3) Chandna, R.C. and Sidhu, M.S. (1980), Introduction to Population Geography, Kalyani Publishers, Ludhiyana, Page 96.

(4) Clark, J.I. (1972) Population Geography, Oxford, Page 66.

(5) Clark, J.I. (1977), Population Geography, (II Edition), Pergaman

Press, Oxford, Page 103.

(6) Garnier, J.B. (1978), Geography of Population, Longmans London, Page 307.

(7) Gosal,G.S. (1961), The Regionalism of Sex Composition of India's Population, Rural Sociology, Vol. 26, Page 124.

(8) Gosal, G.S. (1969) Literacy in India and Interpretative Study, Rural Sociology Vol. 29.

(9) Misra, K.K. and Namdeo, R.C., (1996), Spatial Distribution and Planning of Social Amenities: A Case Study of Tahsil Orai, U.P. Geo-Science Journal, NGSI, Varanasi, Vol. II, Part 18.2, Page 22-23.

(10) Pant, J.C. (1983), Demography (Hindi) Goyal Publishing House, Subhash Nagar Meerut, PP. 331-332 Page. 338-339.

(11) Tilara, K.S. (1979), Principles of Demography (Hindi), Publishing Centre Doliganj Railway Crossing, Sitapur Road, Lucknow Page 163.

(12) Tyagi, N. (1982), Geographical Study of Hill Resorts of U.P., Himalaya, Ph.D. Thesis, University of Gorakhpur, Page 151.

अध्याय - ६

जनसंख्या नीति (Population Policy)

जनसंख्या नीति (Population Policy)

जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर ने मानव जीवन के सामाजिक–आर्थिक विकास के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है। यह निर्विवाद है कि ज्यों–ज्यों जनसंख्या में वृद्धि होती जायेगी त्यों–त्यों खाद्य सामग्री, वस्त्र आपूर्ति, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं, परिवहन सुविधाओं, रोजगार के अवसरों, आवास आदि की बड़े पैमाने पर कमी होती जायेगी। यही नहीं जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि के कारण प्रदूषण, पारिस्थितिकी के असन्तुलन, जीवनस्तर को ऊँचा उठाने, मानव कल्याण एवं सुरक्षा जैसी अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं। अतः शाश्वत विकास के लिए यह आवश्यक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए एक सुविचारित जनसंख्या नीति बनाई जाय तथा उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाय।

जनसंख्या नीति की आवश्यकता (Need of Population Policy)

वस्तुतः जनसंख्या का उसके विकास स्तर से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः जनसंख्या एवं सीमित साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियन्त्रण हो। जनसंख्या अविवृद्धि से व्यक्तिगत परिवारिक एवं सामाजिक विघटन उत्पन्न होते हैं, साथ ही अपराध, आत्महत्या, तथा भ्रष्टाचार आदि की दर में तीव्र गति से वृद्धि होती है। व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण तथा आहार की सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता है। (मिश्र, 1996) अस्तु मानव जीवन के कल्याण को ध्यान में रखकर ऐसी सुनियोजित एवं सुविचारित जनसंख्या नीति की आवश्यकता हैं जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो और मानव जीवन से सम्बन्धित आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अध्ययन क्षेत्र में तीव्रगति से बढ़ रही जनसंख्या के लिए गरीबी, अशिक्षा धार्मिक, अन्धविश्वास, सामाजिक परम्परायें, धीमा आर्थिक विकास आदि मुख्य रूप

से उत्तरदायी है। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास के पथ पर चलते हुए क्षेत्र ने आर्थिक विकास की दिशा में कुछ सफलता अवश्य प्राप्त की है लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप आर्थिक विकास निष्प्रभावी ही है। बेरोजगारी की समस्या दिन–प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। आंकड़े इस बात के साक्षी है कि देश व क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा होने के कारण जितने हाँथों को रोजगार मिलता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण उससे भी ज्यादा हाँथ बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। रोजगार की तलाश में लोगों का गांवो से शहरों की ओर पलायन हो रहा है जो शहरों में कई–एक समस्याओं को जन्म दे रहा है (जमुकार, 1996)। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि तथा निर्धनता का आपस में ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। आठवीं योजना का दस्तावेज बताता है कि आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या अधिक है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या दबाव है। हमारे यहां बेहतर जीवन स्तर को जीवन वृद्धि के सफर से निपटने का आधार माना गया है किन्तु तीव्रदर से जनसंख्या वृद्धि के कारण तमाम शासकीय प्रयासो के बावजूद लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पाया है। अतः जनसंख्या नियन्त्रण आज हमारी मौलिक आवश्यकता बन गयी हैं।

जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन (Implementation of Population Policy)

यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल (1951-56) में जनसंख्या दबाव की ओर नियोजकों का ध्यान गया और जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि भारत में जनसंख्या समस्या है, जिससे आर्थिक विकास की गति मन्द पड़ती जा रही है। अतः जनसंख्या में कमी करने के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। तभी से भारत सरकार ने अपनी एक जनसंख्या नीति निर्धारित की हुई है जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण लगाने के विभिन्न उपयों को अपना कर

उसे निर्धारित स्तर पर रोकना है। जनसंख्या नीति से तात्पर्य उस शासकीय नीति से है जिसके अनुसार वह अपने देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है। सामान्यतः ''जनसंख्या नीति'' शब्दावली का प्रयोग संकुचित अर्थो में किया गया है जिसके अनुसार जनसंख्या नीति को जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी नीतियों का पर्यायवाची मान लिया जाता हैं जबकि जनसंख्यानीति दोनों ही प्रकार की हो सकती है। अर्थात् ऐसी नीति जिससे जनसंख्या का नियन्त्रण सम्भव हो तथा ऐसी नीति जिससे जनसंख्या वृद्धि सम्भव हो। आज विश्व के अनेक देशों के सम्मुख तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या है। अतः अधिकांश देशों की जनसंख्या नीतियाँ नियन्त्रण से सम्बन्धित हैं। **जैन के मतानुसार** जनसंख्या नीति केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विचार पूर्वक बनायी गयी और क्रियान्वित की गयी नीति होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रजनन क्षमता को घटाकर जनसंख्या की दर को घटाना है। उपर्युक्त कुछ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों से स्पष्ट है कि एक उपर्युक्त जनसंख्या नीति के अग्रलिखित प्रमुख उद्देश्य होने चाहिये –

(1) देश की आवश्यकतानुसार जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी।

(2) ऐसी सुनियोजित जनसंख्या नीति जो तीव्रगति से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करे।

(3) जनसंख्या में गुणात्मक सुधार।

(4) मृत्यु दर में कमी करना।

वस्तुतः जनसंख्या नीति के उद्देश्यों में उन समस्त नीतियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके अन्तर्गत वह जनसंख्या की मात्रा व प्रकार अथवा भौगोलिक वितरण में बदलाव लाता है। व्यापक अर्थ में यह वस्तुतः सामाजिक नीति ही होती है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण सामाजिक स्वरूप पर पड़ता है। मिरडाल का यह विचार उचित प्रतीत

होता है कि जनसंख्या संकट का यदि विवेक पूर्ण समाधान करना है तो हमे समस्त सामाजिक उद्देश्यों एंव कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करना होगा। नीति निर्धारकों ने सन् 1951-52 में धनात्मक जनसंख्या नीति का प्रतिपादन किया फिर भी जनसंख्या नियन्त्रण की दिशा में उसकी उपलब्धि संन्तोषजनक नहीं रही। स्वतन्त्रता के पूर्व तीन दशकों में भारतीय औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 1.3 प्रतिशत थी जो 1961-71 दशक में 2.25 प्रतिशत वार्षिक उच्चदर पर पहुँच गयी। स्वतन्त्रतोपरान्त तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर का बहुत कुछ कारण स्वास्थ्य एवं सफाई दशाओं में सुधार तथा प्राण घातक रोगो की रोकथाम के कारण मृत्युदर में कमी है, पर इसे ही एक मात्र कारण नहीं कहा जा सकता। जनसंख्या वृद्धि समस्या का अद्‌भुत रूप सन् 1961 की जनगणना में सामने आया जब वृद्धि दर हर अनुमानों को तोड़कर आगे बढ़ गयी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के गठनकर्ताओं ने बहुत स्पष्ट रूप में जनसंख्या नीति की घोषणा की। एक समुचित अवधि में जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाना नियोजित विकास का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। इस कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसमें शिक्षा तथा भारी मात्रा में परिवार नियोजन उपकरणों तथा सेवाओं का ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में प्रसार हो, अधिक महत्व रखते हैं (चान्दना, 1965)। इस प्रकार जनसंख्या नीति में भारी परिवर्तन आया और पहले के औषधि उपागम के स्थान पर शिक्षा प्रसार उपागम पर बल दिया गया जिसके माध्यम से दूरवर्ती क्षेत्रों में भी प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों के जाल विस्तार द्वारा परिवार नियोजन सन्देश और सेवाओं के पहुँचाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस प्रकार छोटे परिवार के भाव जागरण, परिवार नियोजन सेवाओं को सर्वसुलभ करना, परिवार नियोजन योग्य दम्पत्तियों को प्रभावकारी परिवार नियोजन उपकरणों की उपलब्धि, विवाह आयु की वृद्धि के भाव उद्‌दीपन, स्त्रियों की शिक्षा एवं रोजगार में वृद्धि, समग्र विकास पर बल तथा स्रोतव्य शोध एंव मूल्यांकन आवश्यकता पर जोर दिया गया

(चान्दना, 1995)। इस प्रकार तृतीय योजना में परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रम विविध उपकरण तथा नवीन भाव जागरण के कारण 6-8 प्रतिशत लाख लोगों ने परिवार नियोजन हेतु नसबन्दी करायी। तृतीय योजना की समाप्ति तक लगभग 15 लाख लोगों ने नसबन्दी करायी। चतुर्थ योजना मे जनसंख्या नीति अत्यधिक घनात्मक सिद्ध हुई और परिवार नियोजन कार्यक्रम योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु बन गया। इस योजना में जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि जन्मदर को 39 व्यक्ति प्रति हजार से सन् 1978-79 तक 23 व्यक्ति प्रति हजार तक लाना इस योजना के अन्त तक 87 लाख व्यक्तियों की नसबन्दी की गयी और 60 लाख दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के अन्य उपकरण उपलब्ध कराये गये। पंचम पंच वर्षीय योजना अवधि में परिवार नियोजन पर 500 करोड़ रूपये खर्च किये गये और परिवार नियोजन कार्यक्रमों में एक आधारभूत परिवर्तन लाया गया। इस योजना में आवश्यक परिवार नियोजन, आर्थिक उद्दीपन एवं दण्ड प्रावधान, गर्भपात वैधता आदि नवीन आयाम संयुक्त किए गये। आपात काल के दौरान 16 अप्रैल 1978 को संसद में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय की अनुसंशा पर जनसंख्या नीति की घोषणा की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च जनसंख्या वृद्धिदर में प्रभावकारी ढंग से कमी करना था। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गयी। स्त्री शिक्षा की प्रगित पर ध्यान दिया गया। नसबन्दी हेतु नगद प्रोत्साहन दिया गया आदि। चूँकि इस नीति के अन्तर्गत जबरन नसबन्दी कार्यक्रम चलाया गया। इस लिए यह नीति अपने लक्ष्य पर न पहुँच सकी, पुनः 1977 के आम चुनावों के बाद नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गयी। स्वैछिक परिवार नियोजन की प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया और इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम नाम प्रदान किया गया। छठी योजना में देश के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ–साथ परिवार नियोजन की वरीयता यथावत

बनी रही। सातवीं योजना में जनसंख्या नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और जनसंख्या नियन्त्रण को ध्यान में रखते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया। 1991 में प्रारम्भ हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना नें विगत कार्यक्रमों की असफलता को ध्यान में रखते हुए और वृहद स्तर पर योजना तैयार की गयी। अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं की आपूर्ति करना निश्चित रूप से असम्भव होगा। अतः योजना के अन्त तक जन्मदर को घटाकर 26 व्यक्ति प्रति हजार तक लाने का लक्ष्य रखा। इसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम में विकेन्द्रीकृत आयोजन और क्रियान्वयन की नीति अपनायी गयी। जिलापरिषद, ग्राम पंचायतो और स्वयंसेवी संस्थाओं की इस सन्दर्भ में विशेष भूमिका को स्वीकारा गया। महिलाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि, जनपद को प्रदान अनुदान राशि को परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता से सम्बन्धित करना, वृद्धावस्था में सुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु नसबन्दी कराने वालों को दीर्घकालीन वित्तीय बाण्ड जारी करना आदि कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। अतः लोगों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियन्त्रण को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। शासन ने प्रसार और प्रोत्साहन का माध्यम अपनाकर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने का प्रयत्न किया। 1990 की प्रति हजार जनसंख्या पर 29.9 प्रतिशत की जन्मदर को 1997 में घटाकर 26 प्रति हजार प्रतिवर्ष पर लाया जायेगा (योजना विभाग)। नवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य व शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया जाता है ताकि उपचारात्मक तथा निरोधक माध्यमों को अधिक सार्थक रूप से लागू किया जा सके। इस योजना में गर्भ निरोधकों की आपूर्ति बढ़ाने तथा शिशु मृत्यु दर की तीव्रता से घटाने पर जोर दिया जाएगा। विभिन्न नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से देश में जनसंख्या परिदृश्य की सन् 2000 तक की अग्रकित उपलब्धियां रही है (त्रिपाठी, 2001)।

(1) जन्मदर 40.8 (1951) से घट कर 26.4 प्रतिशत हुई।

(2) मृत्युदर 25.0 (1951) से घटकर 9.0 प्रतिशत हुई।

(3) जीवन प्रत्याशा 37 वर्ष से बढ़कर 62 प्रतिशत हुई।

(4) कुल प्रजनन दर 6 प्रतिशत (1951) से घटकर 3.2 प्रतिशत हुई।

(5) परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा उसकी विधियों के प्रति विस्तृत पैमाने पर जागरुकता आदि।

जनसंख्या नीति, **2000** (Populotion Policy, 2000)

डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञदल (1994) की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। इस जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित सेवातन्त्र की स्थापना तथा गर्भ निरोधकों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के आधारिक ढॉचे की आवश्यकताऍ पूरी करना है। सन् 2010 तक जनन क्षमता 2.1 की दर प्राप्त करना है। इसका दीर्घ कालीन उद्देश्य जनसंख्या में सन् 2045 तक स्थायित्व प्राप्त करना है। इससे स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली को मजबूत करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रवाह की दिशा को ग्रामोन्मुख करने पर विचार किया जाता है। जनसंख्या नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित प्रयास किए जायेंगे—

(1) 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करना।

(2) प्रति हजार बच्चों पर शिशु मृत्युदर 30 से कम करना।

(3) जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भ का पंजीयन कराना।

(4) एड्स का प्रसार रोकना।

(5) संक्रामक रोगों को रोकना।

(6) बच्चा, मृत्यु, अनुपात प्रति एक लाख सन्तानों में एक सौ से कम करना।

(7) सभी को सूचना, परामर्श तथा जनन क्षमता नियमन की सेवायें तथा गर्भ निरोधकों के विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराना।

इसके क्रमबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भी गठित किया जाता है।

जनसंख्या नीति का मूल्यांकन (Evaluation of Population Policy)

यद्यपि जनसंख्या नीति के सन्दर्भ में समय–समय पर किए गये प्रयासों से यह प्रतीत होता है कि योजना काल में जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु विविध प्रयास किए गए। इससे बढ़ती जनसंख्या व बड़े परिवारों की असुविधाओं से सभी परिचित हो गए हैं। निश्चित रूप से परिवार–आकार के प्रति लोगों के दृष्टिकोंण में बदलाव आया है। गांव तथा नगर क्षेत्रों में अवस्थापनाओं में वृद्धि हुई है। वास्तव में जनसंख्या नीति तथा उससे सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि को रोकना है फिर भी इस दिशा में सफलता काफी सीमित है। जनसंख्या वृद्धि में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आयी है। देश में 11 मई 2000 को एक अरबवे बच्चे का जन्म हुआ। अनुमान है कि 2047 तक भारत की जनसंख्या 158 करोड़ हो जायेगी। इसके लिए 400 मिलियन टन आनाज चाहिये जबकि वर्तमान में मात्र 194 मिलियन टन आनाज पैदा होता है। पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। जल व जमीन काफी कम है। अतः जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण पर गम्भीर दवाब बढ़ेगा। इसलिए समग्ररूप से जनसंख्या नियन्त्रण की आवश्यकता सर्वोपरि है। लोगों में जन संख्या के प्रति नवीन दृष्टिकोण पैदा करने हेतु आवश्यकता इस बात की है कि मानव समाज को विस्तृत जानकारी सुलभ कराने के उद्देश्य से जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

को अनिवार्य रूप से लागू किया जाय, इससे युवा वर्ग में परिवार, देश, राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी तथा विद्यार्थियों नें इस स्थिति के प्रति तर्क पूर्ण दृष्टि तथा उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार करने की भावना विकसित की जा सकेगी। जनसंख्या सम्बन्धी विभिन्न तथ्यों की जानकारी से मानव चिन्तन में बदलाव आयेगा तथा जीवन शैली को एक नई दिशा मिलेगी (मिश्र, 1996)। निष्कर्षतः जनसंख्या पर नियन्त्रण तभी सम्भव है व जनसंख्या नीति तभी सार्थक सिद्ध होगी जब सरकार ही नही बल्कि सम्पूर्ण जनता भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाये और यह कार्य जागरूकता अभियान अथवा जनसंख्या शिक्षा से ही सम्भव है।

बेरोजगारी (Unemployment)

सामान्यतः बेरोजगारी से तात्पर्य उत्पादन कार्य में न लगा होना हैं किन्तु मात्र अक्रियाशीलता से अथवा अप्रयुक्त श्रम शक्ति की मात्रा से ही बेरोजगारी का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह गैर–रोजगार की अवस्था भी हो सकती है। आधुनिक समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनसे स्वयं की आजीविका कमाने हेतु कार्य की आशा नहीं की जा सकती। श्रम शक्ति के कार्य में संलग्न अथवा बेरोजगारी होने की स्थिति को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है– (1) ऐच्छिक बेरोजगारी (2) अनैच्छिक बेरोजगारी (पन्त, 1989) ।

जब किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने की इच्छा ही न हो, तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी कहते है। यदि कोई व्यक्ति चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो, और उसे कार्य न मिल पा रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जा सकता है। अनैच्छिक बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे – घर्षणात्मक बेरोजगारी, तकनीक मूलक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अल्प रोजगार

तथा छिपीहुई बेरोजगारी एक उत्पादन स्थान से दूसरे उत्पादन स्थान परिवर्तन करने पर कुछ समय के लिए व्यक्ति रोजगार से विलग रहता है। ऐसी दशा को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तकनीकी ज्ञान तथा कार्यकुशलता की कमी के कारण जब व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है, तो उसे तकनीकी मूलक बेरोजगारी कहते हैं। विकासशील क्षेत्रों में प्राविधिक उन्नयन से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कृषि तथा कृषि सम्बन्धी अन्य उत्पादन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती हैं, जहां फसल विशेष के समय ही लोगों को कार्य मिल पाता है। आर्थिक मन्दी या आर्थिक क्रियाओं में उत्तार– चढ़ाव की स्थिति में चक्रीय बेरोजगारी को जन्म मिलता है। आर्थिक संवृद्धि होने पर इस प्रकार की बेरोजगारी स्वतः समाप्त हो जाती है। पूर्णकालिक अथवा नियमित रोजगार न मिल सकने वाले व्यक्तियों को अल्प रोजगार की श्रेणी में रखते हैं। इनकी क्षमता का पूर्ण विदोहन नहीं हो पाता है। सामान्यतः अल्प रोजगारी तथा छिपी हुई बेरोजगारी को एक ही श्रेणी में रखते है। यदि किसी उत्पादन क्षेत्र में श्रमिकों को कुछ समय के लिए पृथक कर दिया जाय तथा कुल उत्पादन पर कोई असर न आए, तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में बेरोजगार ही हैं। ऐसे लोगों की सीमान्त उत्पादकता लगभग शून्य होती है। बेरोजगारी वस्तुतः सभी क्षेत्रों के लिए एक अहम समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। इसके कारण निर्धनता, अकाल, कुपोषण तथा अल्पपोषण की समस्याएं जन्म लेती हैं। इससे लोगों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। लोग कुंठा और तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। अल्प पोषण तथा कुपोषण के कारण विभिन्न बीमारियों से तृसित रहते हैं। सामान्यतः भारत व विशेष रूप से स्थानिक क्षेत्रों में बेरोजगारी में हो रही सतत् वृद्धि के अनेक कारण हैं।

(1) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि।

(2) परिसम्पत्तियों का असमान वितरण।

(3) अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि।

(4) पूँजी प्रधान प्रविधियों पर जोर।

(5) कृषिकार्य की मौसमी प्रवृत्ति।

(6) श्रमिकों की गतिशीलता में कमी आदि।

बेरोजगारी के अनुमान (Estimates of Unemployment)

योजनाकाल में रोजगार सृजन के प्रयासों के बाद भी बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। बेरोजगारी के समयबद्ध तथा व्योरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी यत्र–तत्र बिखरे आंकड़ो के क्रमबद्ध करने पर बेरोजगारी की मात्रा तथा उसकी प्रवृत्ति का आभास होता है। भारत में प्रथम योजना के आरम्भ में बेरोजगारों की संख्या 3.3 मिलयन थी, जो योजना के अन्त में 5.3 मिलियन हो गई। दूसरी योजना के अन्त में बेराजगारों की संख्या बढ़कर 7.1 मिलियन तथा तीसरी योजना के अन्त में 9.6 मिलियन हो गई (तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961)। रोजगार कार्यलयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1981 में 17.8 मिलियन थी जो बढ़कर 1992 में 36.7 मिलियन से अधिक हो गई (आर्थिक सवेक्षण, 1995-96)।

ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)

भारत में बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में है। वास्तव में ग्रामीण जनंसख्या जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, या तो बेरोजगार है या अल्प बेरोजगार की अवस्था में है। यही कारण है कि इन्हें भरण पोषण हेतु निम्नतम आय भी प्राप्त नहीं होती। इनके पास वर्ष भर के लिए कोई लाभदायक रोजगार नहीं होता। वर्तमान समय में अधिकांश शिक्षित युवक अपने को परम्परागत व्यवसाय में समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेरोजगारी की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। इसके कारण एक नवीन सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः बेरोजगार लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। मुख्यतः अल्प बेरोजगारों की संख्या

अधिक है। क्षेत्र में लघु एंव सीमान्त कृषकों, लघु ग्रामीण व्यापारियों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पकारों को पूरे समय का कार्य नहीं मिल पाता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारों की भी अधिकता है, जो वर्ष के 5 से 6 महीने बेरोजगार रहते हैं। एक फसली क्षेत्रों वाले भूभागों में मौसमी बेरोजगारों की संख्या अधिक है। यही कारण है कि झांसी जनपद में मौसमी बेरोजगारों की संख्या अधिक हैं। सिंचन सुविधाओं के अभाव के कारण यहाँ मुख्यतः एक फसल ही मिलती है। सर्वेक्षण बताता है कि क्षेत्र में केवल 23.4 प्रतिशत परिवारों के सदस्य अपने गॉव को छोड़कर अन्यत्र वैकल्पिक रोजगार की खोज में जाने के इच्छुक पाए गए। लघु किसान परिवारों के 49.8 प्रतिशत परिवारों के सदस्य वैकल्पिक रोजगार पाने की तलाश में बाहर जाने के लिए लालायित पाये गए। गाँवों में बेरोजगार महिलाओं का औसत पुरूष श्रमिकों की तुलना में अधिक है। इनमें गतिशीलता के अभाव का प्रमुख कारण अशिक्षा, पारिवारिक दायित्व तथा पारिवारिक लगाव माना जा सकता है। गाँवों में बेरोजगारी की प्रकृति का प्रमुख कारण भूमि का असमान वितरण भी है। कुछ ग्रामीण परिवार भूमि हीन हैं जिसके पास अपना आवास बनाने तक की जगह नहीं है। क्षेत्र के 11.0 प्रतिशत परिवारों का कुल ग्रामीण क्षेत्र की परिसम्पति में मात्र 1.0 प्रतिशत का अंश था, जबकि दूसरी ओर 10 प्रतिशत परिवार ग्रामीण परिसम्पत्ति के 51 प्रतिशत भूमि के मालिक हैं।

शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)

वस्तुतः शिक्षितों की योग्यता तथा आकांक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी दिनोंदिनं बढ़ रही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि तथा शैक्षणिक परिवेश से शिक्षित श्रम की पूर्ति बढ़ी हैं लेकिन तदनुरूप रोजगार की मात्रा में वृद्धि न होने के कारण बरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। बरोजगारी के क्षेत्र में प्राथमिक तथा मिडिल स्तर के शिक्षितों की संख्या

अधिक है जबकि बेरोजगारी की सर्वोच्च दर (36.77 प्रतिशत) स्नातक तथा उससे अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में है। इस प्रकार उच्च शैक्षिक वर्ग में बेरोजगारी की दर अधिक होती जाती है (आठवी पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ 118)। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह वर्ग अपने को कुछ अवधारणाओं से जोड़ लेता है। अशिक्षित व्यक्ति में बेरोजगारी की दर मात्र 3.97 प्रतिशत पाई जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह वर्ग कम प्रतिफल वाले तथा असंगठित क्षेत्रों के भी रोजगार को स्वीकार कर लेता है। शिक्षित अप्रतिष्ठित बरोजगारी समाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालती है। भविष्य के प्रति अनिश्चितता तथा असुरक्षा के माहौल में विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर रहा है। शिक्षण संस्थाओं में हड़ताल का एक कारण यह भी है। रोजगार कार्यालय में रोजगार हेतु पंजीकृत शिक्षित अभ्यर्थियों को बहुत कम रोजगार मिल सका है, जैसा कि सारिणी संख्या 6.1 से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या 6.1

जनपद में पंजीकृत अभ्यर्थियों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत (1971-1995)

वर्ष	वर्ष
1971	7.1
1973	8.7
1975	4.1
1977	5.4
1779	5.3
1781	5.3
1995	1.85

स्रोत :– जनपद रोजगार कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर संगाणित।

सारिणी संख्या 6.1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1991 में 7.1 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ था जबकि 1995 में मात्र 1.85 प्रतिशत व्यक्तियों को ही रोजगार प्राप्त हो सका है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में बेरोजगारी की विकट समस्या विद्यमान है। यद्यपि रोजगार वृद्धि हेतु शासन द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। 1987-88 तथा 1993-94 अवधि में भारत में नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि कम रही है, जैसा कि सारिणी 6.2 से विदित हैं।

सारिणी संख्या 6.2

रोजगार की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)

रोजगार क्षेत्र	1987-88	1993-94
ग्रामीण	1.46	1-84
नगरीय	2.97	3.59
योग	1.77	2.33

स्रोत :– एप्रोच पेपर – नवीं पंचवर्षीय योजना।

रोजगार नीति (**Employment Policy**)

वस्तुतः रोजगार नीति सम्पूर्ण आर्थिक नीति का वह पक्ष है जिसमें अधिक मात्रा में अधिक लाभकारी रोजगार अवसरों के सृजनार्थ शासन द्वारा नाना प्रकार के प्रयास किए जाते हैं (नाबा गोपाल दास)। यद्यपि बेरोजगारी की समस्या प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही विद्यमान है फिर भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं बनाई गयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शासन ने इस दिशा में प्रयास किए। तृतीय पंवचवर्षीय योजना तक रोजगार सृजन को विकास के परिणाम

के रूप में ही देखा गया और रोजगार सृजन हेतु कोई अलग से नीति नहीं बनाई गई। इस सम्बन्ध में जो विशिष्ट प्रोग्राम चलाए भी गए, उनका प्रभाव अंशकालिक अथवा अत्यन्त सीमित रहा। इसलिए बेरोजगारी की संख्या वृद्धि ही बनी रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा उसके पश्चात् असंगठित क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर बढाने हेतु अनेक प्रयास किए गये, ताकि समाज के कमजोर वर्गो को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस उद्देश्य हेतु अनेक विशेष रोजगार कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए जिसमें समन्वित ग्रामीण विकास संयोजना (1976-77), ट्राइसेम (ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979), जवाहर रोजगार योजना (1989-90), रोजगार आश्वासन योजना (1993), प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (1992) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999) आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार शासन द्वारा समय–सयम पर यद्यपि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी बेरोजगारी की समस्या हल होने का नाम नहीं लेती। इसलिए बढ़ती हुई बेरोजगारी को हल करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यावहारिक नीति व अधिक प्रभावी कार्यक्रम बनाए जांय। यदि निम्नांकित क्षेत्रों में उपचारात्मक प्रयास किए जांय तो बहुत हद तक सफलता प्राप्त हो सकती है–

(1) कृषि व उससे सम्बन्धित अनेक क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाओं का प्रसार व सुधार कर रोजगार में वृद्धि।

(2) ग्रामीण गैर कृषि रोजगार यथा– ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्राम सड़क, भवन निर्माण तथा कृषि सेवा केन्द्रो का विकास, ग्रामीण औद्योगीकरण आदि का विकास रोजगार मे सहायक है–

(3) भूमि सुधार अनुत्पादक भूमि को सुविधायुक्त बनाकर कमजोर वर्गो को आवंटित करना।

(4) स्थानीय संसाधनों, आवश्यकताओं तथा स्थानीय लोगों की अनुकूल अनुक्रिया

को ध्यान में रखकर ग्रामीण योजनाओं का क्रियान्वयन।

(5) श्रम की मांग तथा पूर्ति का स्थानिक स्तर पर गहन सर्वेक्षण के माध्यम से आंकलन।

(6) रोजगार तथा व्यवसाय मूलक शिक्षा प्रणाली।

(7) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाओं का समन्वित रूप से तीव्र विकास, आदि।

परिवार नियोजन (Family Planning)

जनसंख्यात्मक स्थिति के सन्दर्भ में स्पष्ट है कि इस देश में अनियन्त्रित जन्मदर के कारण जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए परिवार नियोजन के माध्यम से जन्म दर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में परिवार नियोजन का तात्पर्य मुख्यतः दो तथ्यों से है (क) तीन से अधिक बच्चे न होने देना, (ख) बच्चों की उत्पत्ति में पर्याप्त अन्तर। परिवार नियोजन अपने आपमें एक व्यापक शब्द है। परिवार नियोजन का सरल अर्थ है, नियोजित परिवार अर्थात् अपनी आय के अनुकूल परिवार के सदस्यों की संख्या का निर्धारण। परिवार की आय कितने सदस्यों के जीवन स्तर को व्यवस्थित ढंग से बनाये रख सकती है ताकि उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में कोई गिरावट न आने पाये। वस्तुतः परिवार नियोजन सामाजिक एवं पारिवारिक रूपान्तरण का उपकरण है। इसका उद्देश्य अच्छे माता–पिता, स्वस्थ्य बच्चे व सुखी परिवार का निर्माण करना है और विवाहितों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत करने का प्रयास करना है। परिवार नियोजन वास्तव में परिवार का, परिवार के लिए, परिवार के द्वारा एक योजना है। नीति निर्माताओं ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को जनसंख्या नियन्त्रण हेतु आवश्यक बताया है। वास्तव में परिवार नियोजन वर्तमान में एक व्यापक शब्द हैं और इसलिए

इसके अन्तर्गत वे सभी विशेषतायें आती है, जिनसे परिवार एवं समुदाय में अधिक से अधिक सुख एंव समृद्धि आ सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे परिवारों का महत्व समझाने का कार्य तथा अधिक संतान से बचने के लिए उपायों को बताने के साथ ही साथ उन निरोधात्मक साधनों को उपलब्ध कराना भी है, जिनसे लोग अवांछित संतान से बच सकें तथा छोटे परिवारों का महत्व समझे। इस प्रकार परिवार नियोजन का क्षेत्र जन्म नियन्त्रण से अधिक विस्तृत है। यह केवल जनसंख्या कम करने का भौतिक साधन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य व समृद्धि समाज की नींव डालने वाला एक नया दर्शन है, सामजिक रूपान्तरण का एक उपकरण है। इसका उद्देश्य मातृ–पितृत्व, स्वस्थ बच्चों व सुखी परिवार का निर्माण करना हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में बाधाएँ (Hindrances in The Family Planning Programme)

अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है जिनके व्यवहारों को वहॉ के परम्परागत सांस्कृतिक मूल्य निर्धारित करते हैं। वस्तुतः भारतीय ग्रामों का सामाजिक परिवेश आज भी वहाँ के लोगों को पुराने ढंग से सोचने व व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित एवं बाध्य करता है, जिसके कारण बहुत कम लोग नवीन, वैज्ञानिक व प्रगतिशील दृष्टिकोणों से सोचते हैं। इस अप्रगतिशीलता का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव ही हैं। अशिक्षा और रूढ़िवादी दृष्टिकोण के अतिरिक्त कुछ और भी महत्वपूर्ण तत्व हैं जो परिवार नियोजन के प्रचार और प्रसार में बाधक हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं –

(1) शिक्षा का निम्न स्तर ;

(2) परम्परागत बाधायें व रूढ़ियाँ ;

(3) निम्न आय का स्तर ;

(4) भेदभाव की भावना ;

(5) मातृत्व ;

(6) भाग्यवादी दृष्टिकोण ;

(7) बाल विवाह।

अन्य बाधाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य आधारभूत बाधाये भी हैं, जैसे– सामाजिक बाधाओं में संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, विधवा विवाह पर निषेध, भाग्यवादी दृष्टिकोण, स्त्री शिक्षा में अभाव, संयुक्त परिवार में नारी की स्थिति आदि। संयुक्त परिवार में जन्मदर अधिक होने के दो प्रमुख कारण हैं –

(1) संयुक्त परिवार में सम्मिलित सम्पत्ति होने के कारण उत्तरदायित्व भी सम्मिलित होता है परन्तु परिवार का मुखिया ही परिवार के सदस्यों के पालन पोषण का उत्तरदायी माना जाता है। इसलिए परिवार के अन्य सदस्य पति–पत्नि अपनी कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। कभी–कभी संयुक्त परिवारों में संतानोत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से होता है।

(2) संयुक्त परिवार के सदस्यों का परम्परागत रूढ़वादी दृष्टिकोण भी गर्भ निरोध के साधनो के प्रयोग में बाधक होता है। परिवार नियोजन के प्रचार–प्रसार में भी बाधा आती है। क्योंकि परिवार के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करने से पूर्व आवश्यक है कि परिवार के मुख्यिा को उसकी जानकारी होनी चाहिए। संयुक्त परिवार की स्त्रियों से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित करना और भी कठिन होता है। चाहे भले ही सम्पर्क करने वाली महिला डाक्टर या नर्स ही क्यों न हो।

परिवार नियोजन एवं धर्म (Family Planning and Religion)

वस्तुतः धर्म का सहारा लेकर कुछ सम्प्रदाय परिवार नियोजन कार्यक्रम को उपयुक्त नहीं मानते, इस प्रकार के विचार अति रूढ़िबादी एवं अशिक्षित व्यक्तियों के

माने जा सकते हैं, वह चाहे हिन्दू हों या मुसलमान। शिक्षित व्यक्तियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है रोटी, इसलिए इस प्रश्न को व्यापक सन्दर्भो में समझने की आवश्यकता हैं। क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न समुदायों को परस्पर अविश्वास को संकीर्णिता से निकल कर उदार राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। वैसे इन वर्गो में जो समझदार हैं, वे परिवार नियोजन को अपने जीवन में अपना रहे हैं। जो अब भी इसका मतलब नहीं समझते, वे सिसक रहे हैं। जिस वर्ग में समझ की जितनी कमी है वह उतना ही पिछड़ा हुआ है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा व्यक्त विचार उपयुक्त है हमारा एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम जो हैं, उनकी तरफ सब लोगो को देहात और शहर दोनों को अपना ध्यान देना है, खाली इसलिए नहीं कि आबादी कम हो बल्कि इसलिए भी कि हर एक माता पिता अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर सके कि जितने उनके पास साधन हैं। वह देखें कि जितने हमारे बच्चे हैं उनको हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं और अन्य जो उनकी आवश्यकतायें हैं, वे पूरी कर सकते हैं कि नहीं। तो आइये, धार्मिक संकीर्ण मनोवृत्ति का परित्याग कर हम खुशहाल जीवन की ओर बढ़ें और देश को भी खुशहाली की ओर अग्रसर करने में मदद दें।

निवासियों का परिवार नियोजन के प्रति दृष्टिकोण (Observations of Residents about Family Planning)

अध्ययन क्षेत्र के निवासियों का परिवार नियोजन के प्रति दृष्टिकोण जानने के लिए साक्षात्कार विधि को अपनाते हुए विभिन्न धर्मो एवं जातियों के 300 उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों को आंकड़ो के माध्यम से परखने का प्रयास किया गया। साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जिले के निवासियों का परिवार–नियोजन के प्रति दृष्टिकोण अनुकूल है। परिवार नियोजन हेतु अपनाएँ

जाने वाले तरीकों में कोई न कोई तरीका अधिकतर व्यक्ति (पति अथवा पत्नी) अवश्य अपनाते हैं।

नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन :– नसबन्दी/नलबन्दी परिवार नियोजन का एक स्थायी व सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान में भारत सरकार ने स्त्री व पुरूष दोनों की नसबन्दी/नलबन्दी को परिवार नियोजन में सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण को सारिणी संख्या 6.3 तथा चिंत्र संख्या 6.1 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या 6.3

जाति के आधार पर नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन के प्रति उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण (प्रतिशत में)

जाति	चयनित परि. की संख्या	प्रोत्साहित	हतोत्साहित	तटस्थ
ब्राह्मण	60	65	10	25
ठाकुर	20	73	20	07
वैश्य	30	40	20	40
अनुसूचित जाति	60	15	60	25
अनुसूचित जनजाति	10	18	52	30
अन्य पिछड़ी जाति	100	30	20	50
मुसलमान	20	12	05	83

स्रोत :– स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ो की गणना पर आधारित।

Observation of Residents about Tubectomy/Vasectomy (in%)
Households
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Brahmin
Thakur
vaishya
S.C
S.T
O.B.C
Muslim
Castes
Stimulated
Disheartned
Neutral
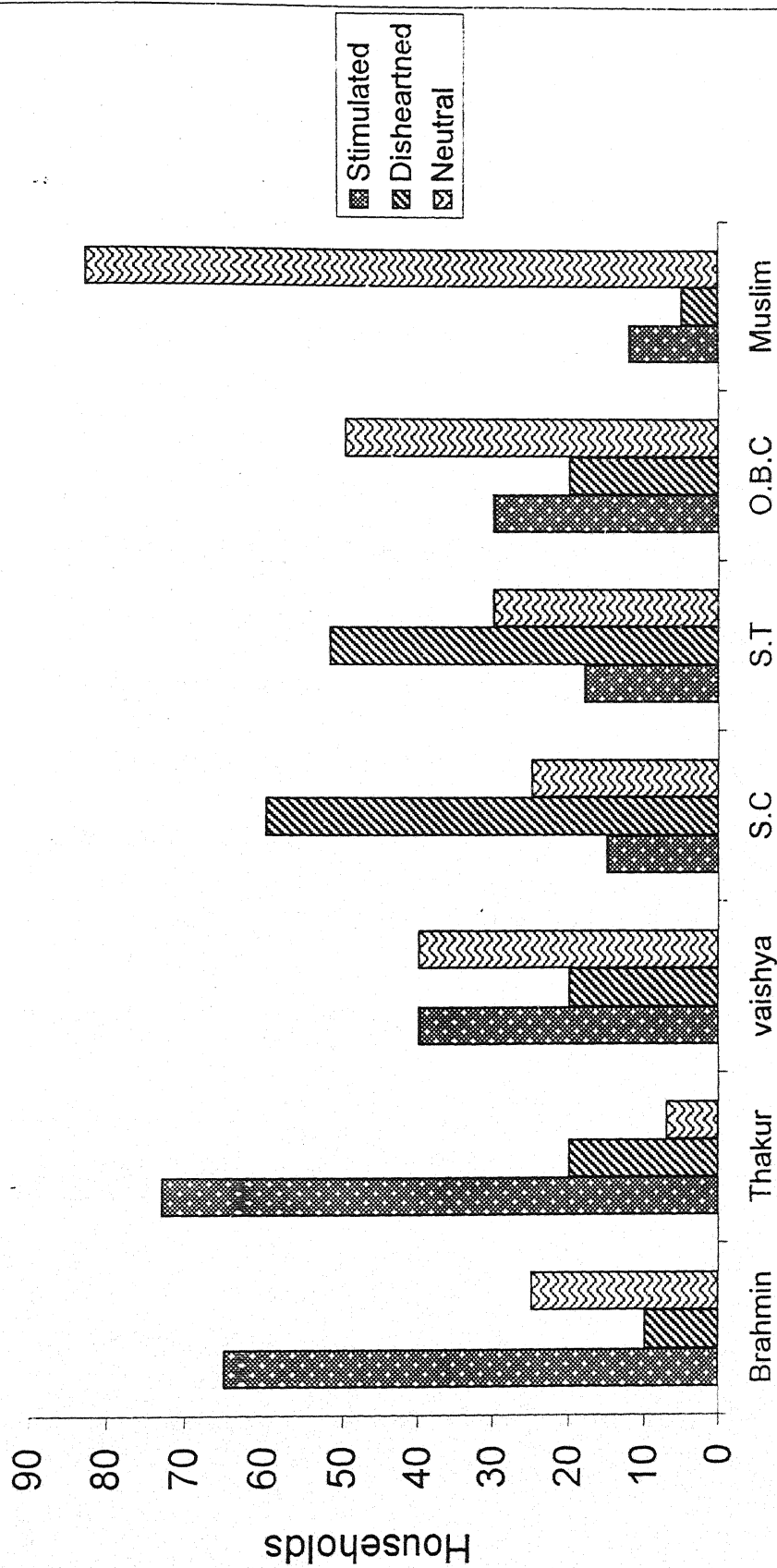
Fig No. 6.1

सारणी संख्या 6.3 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिक सन्तान से बचने के लिए यदि कोई व्यक्ति नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन कराता हैं तो उसे प्रोत्साहित, हतोत्साहित या तटस्थ में अधिकांश लोग प्रोत्साहित करते हैं। जाति वर्ग के आधार पर प्रोत्साहित वर्ग में ठाकुर ब्राह्मण एवं वैश्य उत्तरदाताओं का प्रमुख रूप से स्थान है जबकि हस्तोत्साहित वर्ग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उत्तरदाताओं का स्थान आता है। तटस्थ का भाव सबसे अधिक मुसलमानों में पाया गया। तत्पश्चात् अनुसूचित जातिय एंव वैश्य उत्तरदाताओं का स्थान आता है। इसी प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन को आयु और शिक्षा के आधार पर नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन प्रोत्साहन, हतोत्साहन तथा उदासीनता को सारणी क्रंमाक 6.4 व 6.5 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 6.4

आयु के अनुसार नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन के प्रति प्रोत्साहन (प्रतिशत में)

आयु समूह	च.परि. की संख्या	प्रोत्साहित	हतोत्साहित	तटस्थ
25 वर्ष से कम	85	58	22	20
25-35 वर्ष के मध्य	120	46	30	24
35 से अधिक	95	24	21	55

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो द्वारा संगणित।

सारणी संख्या 6.5

शिक्षा और नसबन्दी आपरेशन प्रोत्साहन (प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	च.परि. की संख्या	प्रोत्साहित	हतोत्साहित	तटस्थ
कक्षा 5 से 8 तक	75	48	23	21
कक्षा 9 से 12 तक	42	67	07	26
स्नातक/स्नात्कोतर	33	98	02	-
अशिक्षित	150	20	30	50

स्रोत :– स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों द्वारा संगणित।

सारिणी क्रमांक 6.4 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कम उम्र के लोग अधिक सन्तान से बचने के लिए नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन कराने वालों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोत्साहित करते हैं तथा अधिक आयु वाले कम। 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले उत्तरदाताओं में तटस्थता का भाव अधिक देखने को मिलता है (चित्र संख्या 6.2)। सारिणी क्रमांक 6.5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ–साथ प्रोत्साहन का प्रतिशत भी बढ़ता जाता है। जाति, आयु एवं शिक्षा के आधार पर सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि अधिक सन्तान से बचने के लिए 50.0 से अधिक लोगों की राय नसबन्दी/नलबन्दी कराने के पक्ष में हैं। नसबन्दी/नलबन्दी कराने में नवयुवकों का प्रतिशत अधिक उम्र वालों की अपेक्षा अधिक पाया गया। अशिक्षितों से शिक्षितों का पक्ष मजबूत रहा। हिन्दुओं में अनुसूचित जाति तथा गैर हिन्दुओं में मुसलमान उत्तरदाता नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन के मामले में पीछे पाये गये।

Stimulancy About Tubectomy/Vasectomy According to Age Group
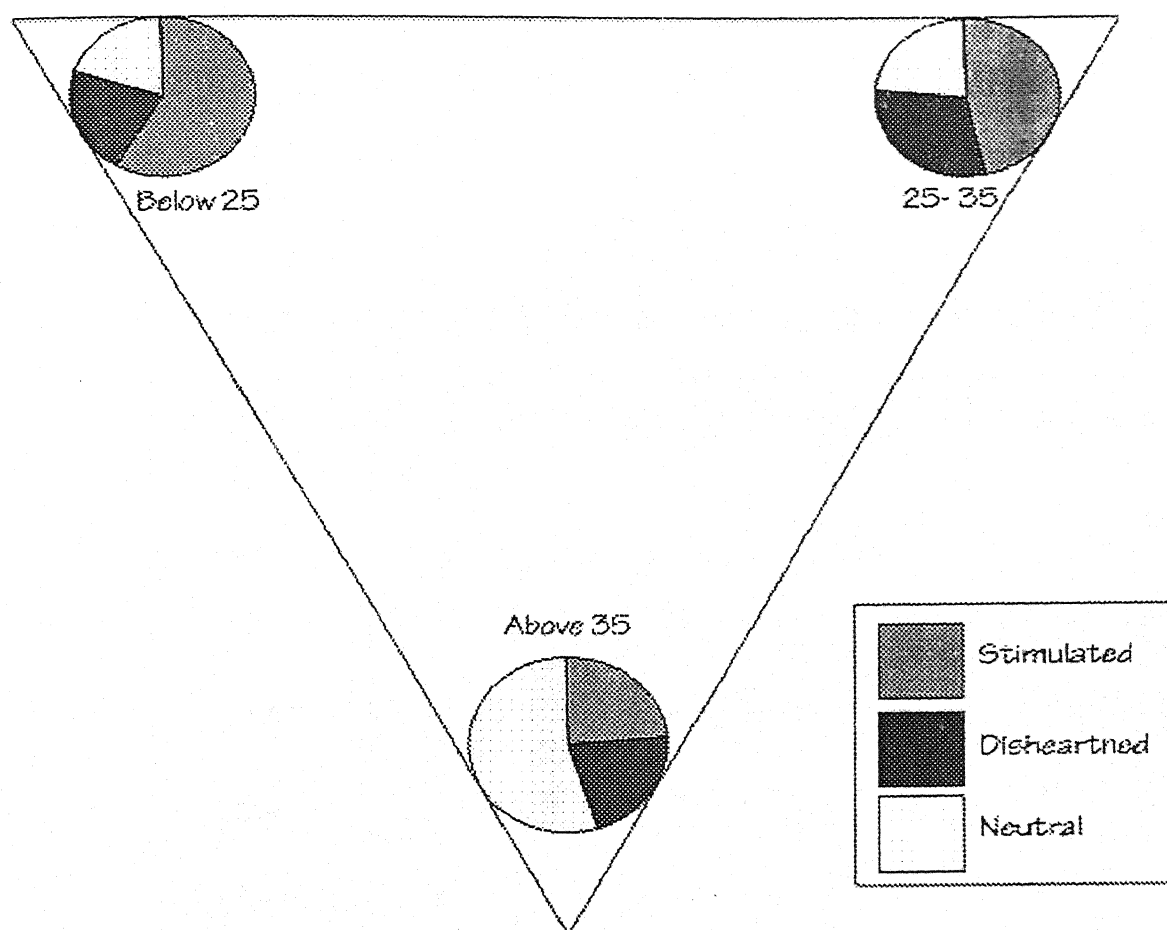
Fig 6.2

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जानकारी, स्वीकृति तथा प्रयोग :— परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के प्रति लोगों की जानकारी, साधनों को अपनाने के प्रति स्वीकृति तथा विभिन्न साधनों का प्रयोग करने के प्रति उत्तरदाताओं से प्रश्न पूँछे गये। उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना को सारिणी क्रमांक 6.6 तथा चित्र संख्या 6.3,4 व 5 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी क्रमांक 6.6

परिवार नियोजन के प्रति जानकारी, स्वीकृति तथा प्रयोग (प्रतिशत में)

जाति	च.परि. की संख्या	जानकारी		स्वीकृति		प्रयोगकर्ता	
		है	नही	है	नहीं	है	नहीं
ब्राह्मण	60	88	12	68	32	58	42
ठाकुर	20	98	02	98	02	80	20
वैश्य	30	77	23	66	34	57	43
अनुसूचित जाति	60	40	60	44	56	24	76
अनुसूचित जनजाति	10	31	69	04	96	03	97
अन्य पिछड़ी जाति	100	62	38	64	36	42	58
मुसलमान	20	84	16	30	62	33	67

स्रोत :— स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो द्वारा संगणित।

सारिणी संख्या 6.5 के परीक्षण से स्पष्ट है कि परिवार नियोजन के प्रति

Information About Uses of Family Planning (in %)
120
100
80
60
40
20
0
Households
Yes
No
Brahmin
Thakur
vaishya
S.C.
S.T.
O.B.C.
Muslim
Castes
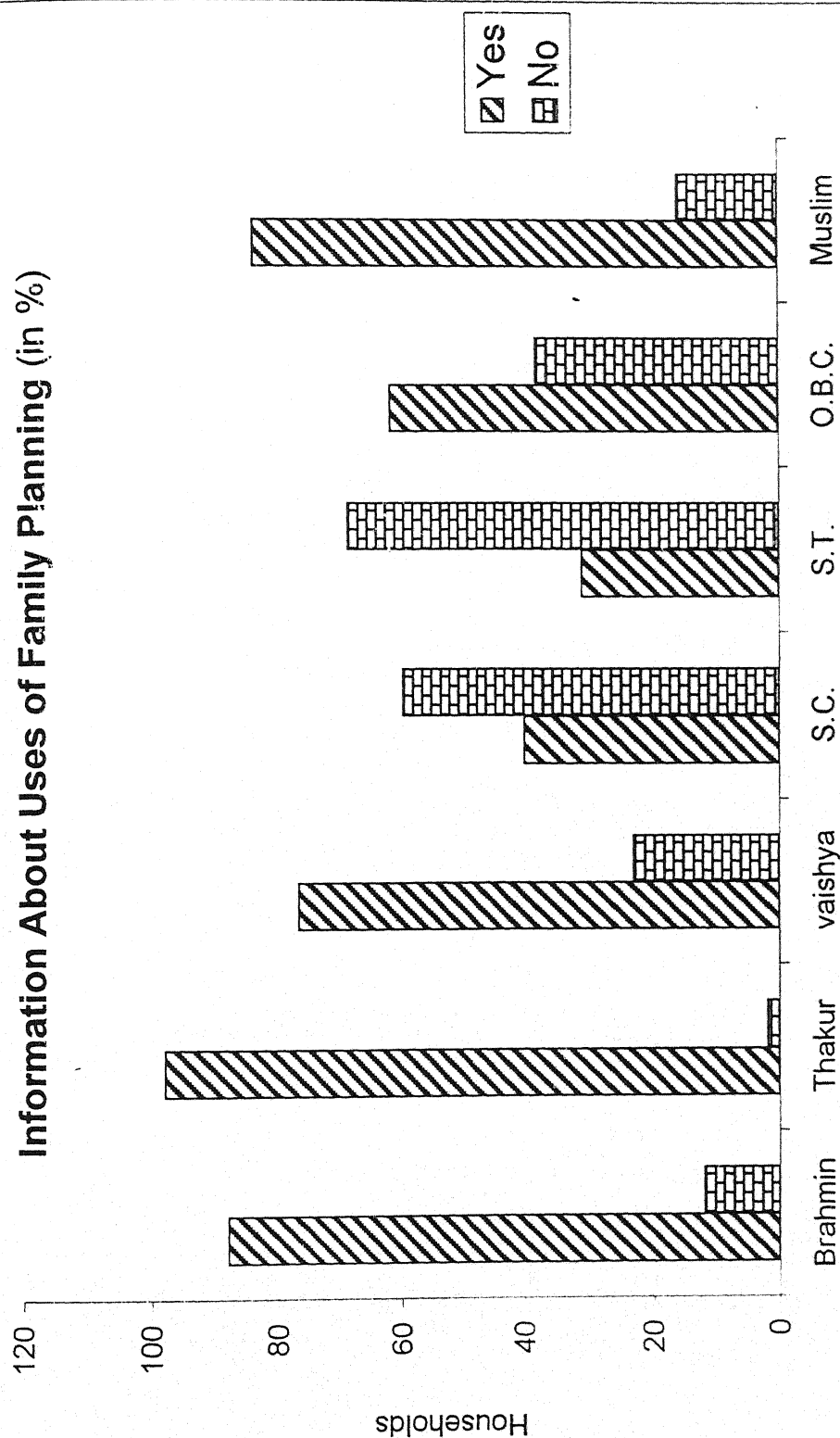
Fig No. 6.3

Acceptance About Uses of Family Planning (in %)
120
100
80
60
40
20
0
Households
Yes
No
Brahmin
Thakur
vaishya
S.C.
S.T.
O.B.C.
Muslim
Castes
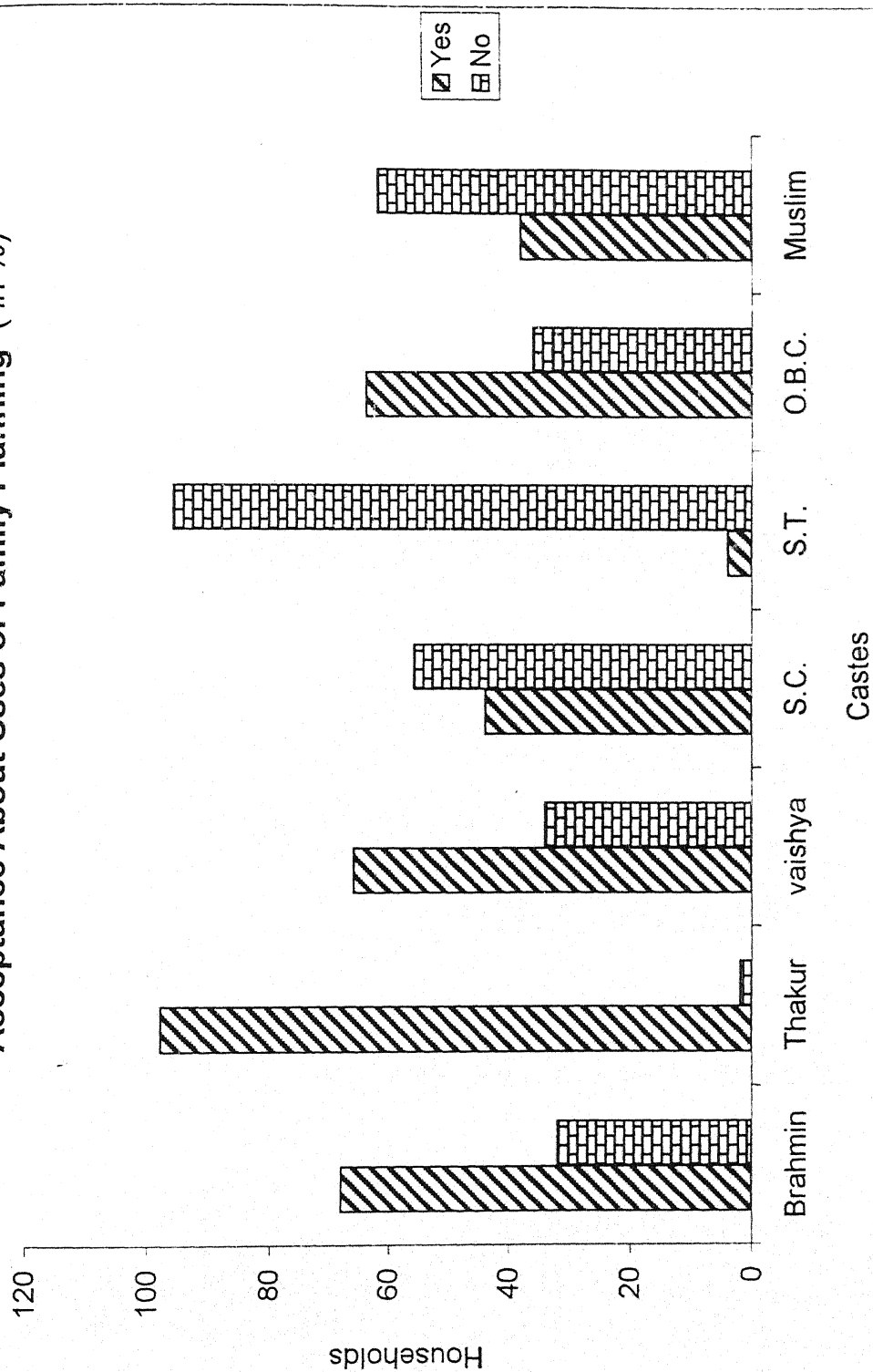
Fig No. 6.4

Users of Family Planning (In %)
120
100
80
60
40
20
0
Households
Brahmin
Thakur
vaishya
S.C.
S.T.
O.B.C.
Muslim
Castes
Yes
No
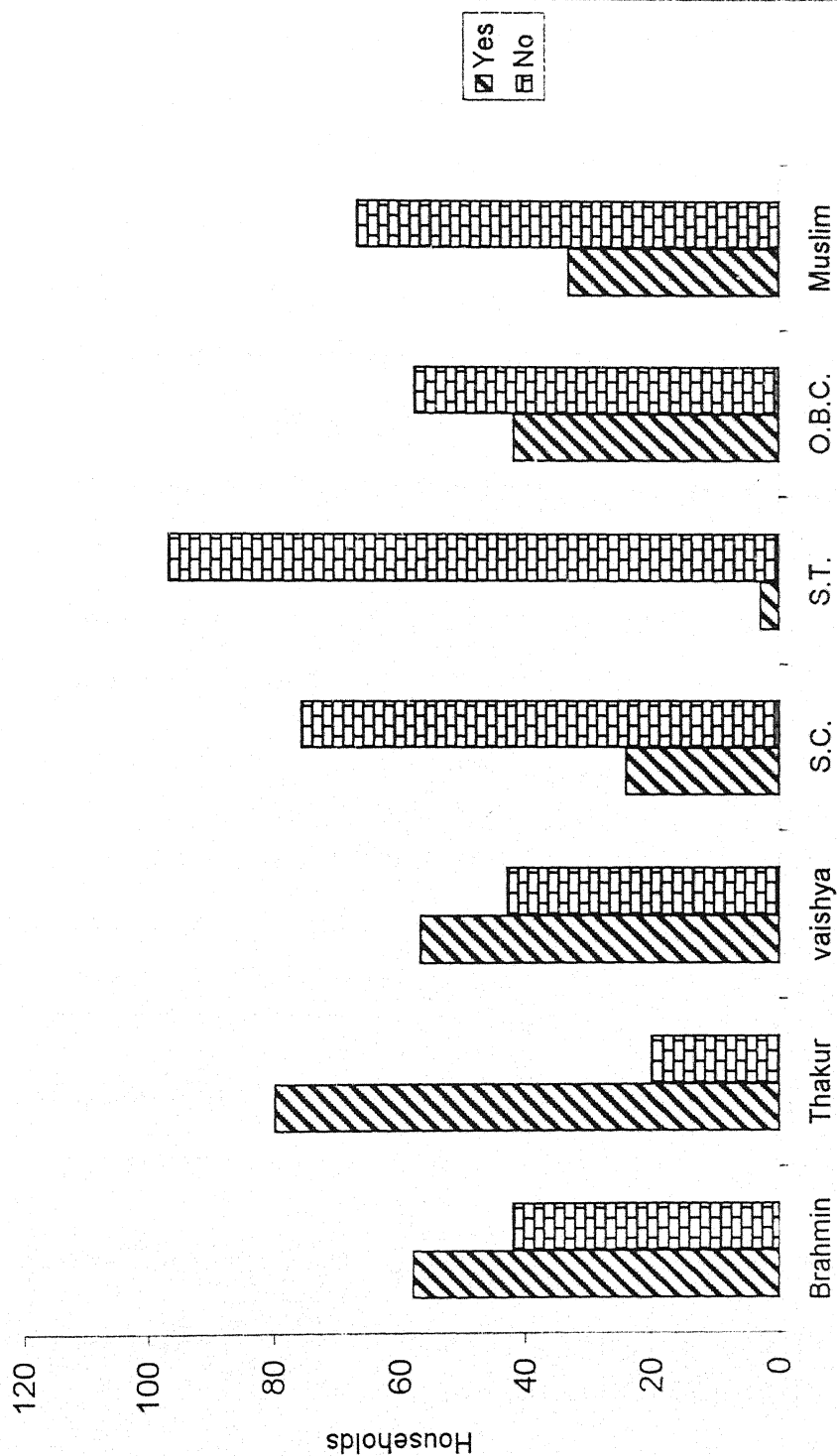
Fig 6.5

अधिक सन्तान से बचने के लिए जिन विधियों का प्रयोग होता है, उनके सम्बन्ध में क्षेत्र के अधिकांश लोगों को जानकारी है। इसके प्रति लोागें में काफी जागरूकता पाई गई, किन्तु जितनी मात्रा में लोगों ने परिवार नियोजन को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की है, उतने लोगों ने प्रयोग नहीं किया। विश्लेषण से यह अवश्य स्पष्ट है कि प्रयोग करने वालों ने बहुत अधिक निराश भी नहीं किया। परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी, स्वीकृति तथा प्रयोग का सबसे निम्न स्तर अनुसूचित जनजातियों का रहा, जबकि ठाकुर, ब्राह्मण व वैश्य का स्थान सबसे अधिक रहा। परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में विश्वास आयु संरचना को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति लोगों के विश्वास को जानने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में साक्षात्कार से प्राप्त परिणमों को सारिणी क्रमांक 6.6 तथा चित्र संख्या 6.6 में दर्शाया गया हैं।

सारिणी क्रमांक 6.6

आयु के आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति उत्तरदाताओं का विश्वास (प्रतिशत में)

आयु समूह	च.परि. की संख्या	परिवार नियोजन कार्यक्रम पर विश्वास		यदि विश्वास नहीं तो कारण				
		है	नहीं	सामाजिक	धार्मिक	चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं	आपरेशन सही नहीं	शारीरिक कमजोरी
25 वर्ष से कम	85	68	32	68	—	13	19	—
25-35 वर्ष के मध्य	120	64	36	56	—	16	20	08
35 वर्ष से अधिक	95	51	49	32	11	—	10	47

स्रोत :– स्वयं के सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ो द्वारा संगणित।

सारिणी 6.6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम से

Confidence/Doubt of Respondents about Family Planning According to Age Group
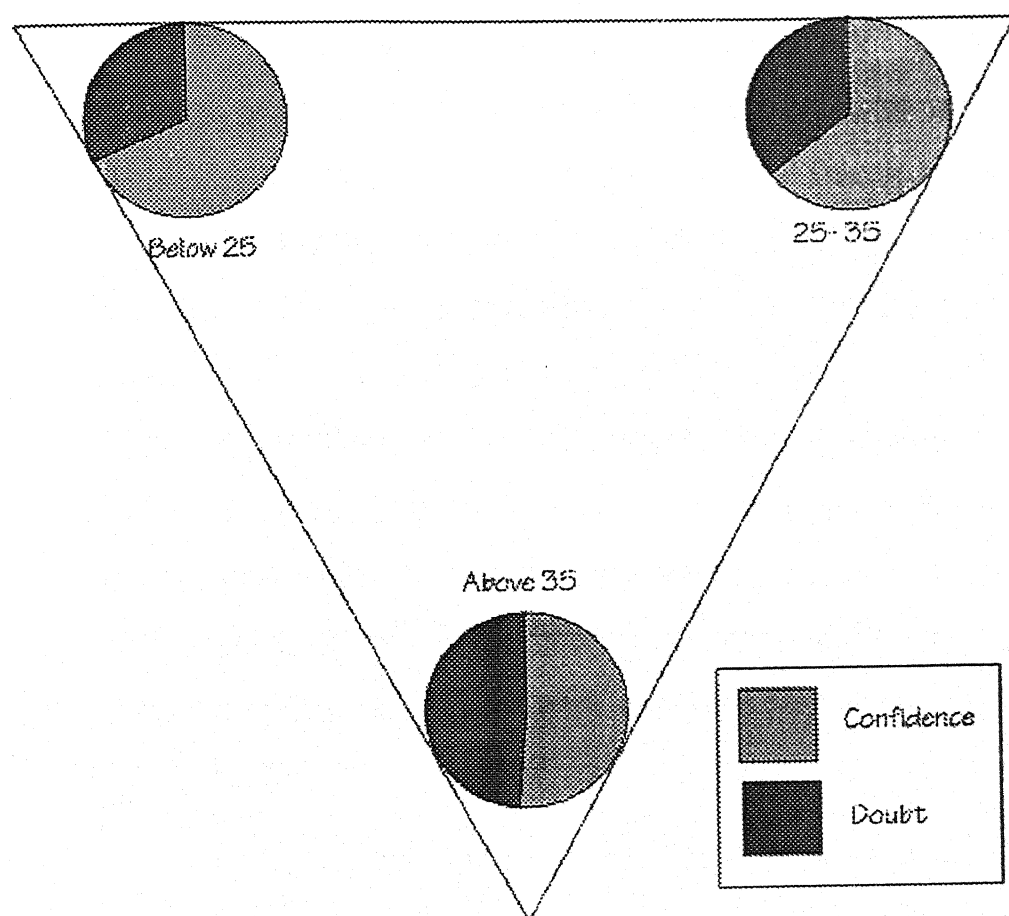
Fig 6.6

सम्बन्ध में 25 वर्ष से कम उम्र के उत्तरदाताओं में 68 प्रतिशत विश्वास करते हैं तथा 32 प्रतिशत विश्वास नहीं करते। विश्वास न करने वालों में 78 प्रतिशत सामाजिक कारण से, 13 प्रतिशत चिकित्सा व्यवस्था में कमी के कारण व 19 प्रतिशत सही आपरेशन न होने के डर से विश्वास नहीं करते हैं। 25 से 35 वर्ष वाले वर्ग समूह में 64 प्रतिशत विश्वास करते हैं तथा 36.0 प्रतिशत विश्वास नहीं करते। परिवार नियोजन कार्यक्रम पर विश्वास न करने वालों में 56 प्रतिशत सामाजिक कारण से, 16 प्रतिशत चिकित्सा व्यवस्था ठीक न होने के कारण, 20 प्रतिशत आपरेशन असफल होने के डर तथा 8 प्रतिशत शारीरिक कमजोरी के भय से विश्वास नहीं करते। 35 वर्ष की अवस्था से ऊपर वाले व्यक्तियों में 51 प्रतिशत विश्वास करते हैं तथा 49.0 प्रतिशत विश्वास नहीं करते हैं। 35 वर्ष से अधिक वायु वर्ग के विश्वास न करने वाले व्यक्तियों में 32 प्रतिशत सामाजिक व्यवस्था के भय से, 11 प्रतिशत धार्मिक कारणों से, 10 प्रतिशत आपरेशन के असफल हो जाने के भय से तथा 47 प्रतिशत शारीरिक कमजोरी की वजह से परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर विश्वास नहीं करते हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लोगों के मन में नसबन्दी आपरेशन के फेल हो जाने तथा शारीरिक कमजोरी के भय को मिटाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाय। लेकिन उस पर प्रतिबन्ध तभी सफल हो सकता है जब दहेज प्रथा पर अंकुश, बुढ़ापे की असुरक्षात्मक स्थिति का समाधान तथा बालिकाओं के लिए उचित शिक्षण व्यवस्था का प्रबन्ध हो। साथ ही जनसंख्या शिक्षा के विकास पर बल दिया जाय। इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय। सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास तथा रोजगार के अवसर सुलभ कराने का प्रयत्न किया जाय। प्रचार माध्यम इस स्तर तक प्रभावी बनाएं जाँय ताकि लोग स्वतः इसके प्रति अग्रसर होने लगें।

अन्त में हम सबको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण नहीं होगा तब तक दरिद्रता कुपोषण, बीमारी, प्रदूषण, निरक्षरता आदि समस्याएं सुलझ नहीं सकती।

References

1. चान्दना, आर० सी० (1995), जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिसर्स नई दिल्ली, पृष्ठ 317 तथा 318।
2. Government of India, Economic Survey, 1995-96.
3. Naba Gopal Das, Unemployment and Employment Planning P.54.
4. जगुवार, रविशंकर (1996)ए बढ़ती जनसंख्या, एक गम्भीर चुनौती, कुरूक्षेत्र, पृष्ठ संख्या 27-30।
5. मिश्र, कृष्ण कुमार (1996), बुन्देलखण्ड (उ० प्र०) की बढ़ती जनसंख्या एवं तज्जनित समस्याएं, मन्दाकिनी, अंक 23, पृष्ठ संख्या 15-19।
6. Pant, S.C. (1989), Labour Problems of India, Chaitanya Publishing House, Allahabad, Page- 202.
7. Planning Commission, Third Five Year Plan, 1964, Page- 47.
8. Planning Commission, Eighth Five Year Plan, 1992-97, Vol. II, Page 118.
9. त्रिपाठी, बद्री विशाल (2001), भारतीय अर्थव्यस्था (नियोजन एवं विकास), किताब महल, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या. 95।

अध्याय - ७

जनसंख्या एवं संसाधन (Human and Resource)

जनसंख्या एवं संसाधन (Human and Resource)

जनसंख्या तथा संसाधन परस्पर सम्बन्धित हैं। इनके परस्पर सम्बन्ध की व्याख्या का जनसंख्या भूगोल में विशिष्ट महत्व है। वस्तुतः मनुष्य स्वयं ही एक संसाधन है। जनशक्ति के योजनावद्ध तरीके से इस्तेमाल करने से ही किसी चीज का आर्थिक विकास सम्भव है। संसाधनों का उपयोगकर्ता मानव है। इसलिए मानव विहीन भूमि संसाधन का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी वस्तु मानव के उपयोग तथा आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में ही संसाधन बनती है। मानव संसाधनों का सृजनकर्ता है। तकनीकी क्षेत्र में मानवीय ज्ञान के विकास के साथ ही उसमें संसाधनों को विस्तारित करने तथा नवीन संसाधनों के सृजन की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। **जेलिंस्की** (1966) का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि मानव ज्ञान तथा श्रम ही सबसे बड़ा संसाधन है। सामान्यतः जनसंख्या संसाधन अनुपात राजनीतिक व धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित होते है। इनका मूल्यांकन प्रति व्यक्ति आय के सर्वोच्च संभावित स्तर से सम्बद्ध होता है परन्तु आर्थिक तत्वों के आधार के साथ ही सांस्कृतिक घटकों को समाहित करना भी जरूरी है। अग्रांकित आठ कारकों के आधार पर जनसंख्या प्रवृत्ति का निर्धारण तथा उसके प्रभाव की विवेचना की जा सकती है। इन कारको में (i) प्रति व्यक्ति आय, (ii) रोजगार का स्तर, (iii) उपयोगिता हास, (iv) स्थानान्तरण की मात्रा तथा दिशा, (v) उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन, (vi) जीवन प्रत्याक्ष (vii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तो में परिवर्तन, तथा (viii) जनसंख्या घनत्व की माप (लाल 1989) प्रमुख हैं। समाजिक आर्थिक विकास की एक विशेष अवस्था में जनसंख्या तथा संसाधनों के मध्य सन्तुलन समाप्त हो

जाता है, तो अल्प जनसंख्या या जनाधिक्य की समस्या पैदा हो जाती है। यदि उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक है तो जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत यदि उपलब्ध संसाधन अधिक और जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है तो जनसंख्या की कमी या अल्प जनसंख्या की स्थिति पैदा हो जाती है। वस्तुतः संसाधन तथा जनसंख्या के मध्य पूर्ण सन्तुलन स्थापित करना एक कठिन कार्य हैं, लेकिन जनसंख्या का अनुकूलतम होना सम्भव है।

अनुकूलतम जनसंख्या (Optimum Population)

वस्तुतः अनुकूलतम जनसंख्या की आधारभूत विशेषता आर्थिक है किन्तु एक जनांककीय भूगोलवेत्ता के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसका विषय क्षेत्र जनसंख्या संसाधन से सम्बन्धित है। सावे (1966), ने इसे एक उपयोगी उपकरण की संज्ञा दी है किन्तु इसके यथार्थ मापन में उन्होंने नाना किस्म की कठिनाइयों की संम्भावना व्यक्त की है। टाबर(1970), ने तो इसे आकर्षणपरक संकल्पना बताया किन्तु इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि व्यावहारिक रूप में यह पूर्णतः भ्रमात्मक है। राविन्सन (1964) ने इस संकल्पना को रूचिपूर्ण तथा लक्षणों से युक्त माना किन्तु व्यावहारिक रूप में इस अवधारणा का अनुत्पादक बताया। उपयुर्क्त विचार इस संकल्पना के सीमित उपयोग को दर्शाते हैं। चांदना (1994) के अनुसार किसी भी क्षेत्र की अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिससे जीवन की उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त होती है। जीवन की गुणवत्ता से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, पर्याप्त शुद्ध जल, शुद्ध वायु, पर्याप्त कच्चामाल जिससे वह अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का निर्माण कर सके, स्वास्थ्य सुविधाएँ, मनोरंजन की सुविधाएँ तथा संस्कृतियों के विकास के सभी मार्ग प्राप्तकर सके। प्रेस्टन क्लाउड,(1970) के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह हैं जो एक निश्चित सीमा रेखा में सन्निहित उसकी संख्या पर्याप्त हो जिससे अपने सभी निवासियों में निरन्तर पूर्ण उच्चजीवन स्तर प्राप्ति हेतु निर्माण

क्षमता का पूर्ण विकास किया जा सके, लेकिन संख्या इतनी अधिक भी न हो जिससे जीवन स्तर में गिरावट या पर्यावरण संयोजन के विवेकपूर्ण युक्त प्रबन्ध में कमी आ जाये। अनुकूलतम जनसंख्या के सम्बन्ध में सावे, (1966) का विचार है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिससे प्राप्त संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो तथा पूर्ण रोजगार, दीर्घ जीवन प्रत्याशा, बेहतर स्वास्थ्य, ज्ञान तथा संस्कृति–सामाजिक सामन्जस्य और पारिवारिक स्थिरता हांसिल की जा सके। उपयुर्क्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुकूलतम जनसंख्या में प्रति व्यक्ति उत्पादन, औसत जीवन स्तर, रोजगारस्तर जीवन प्रत्याशा की अवधि, निर्भरता अनुपात, परिष्कृत बौद्धिक कार्यों का विकास, प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थों का उपयोग, खाने वाली चीजों पर होने वाले खर्च का अनुपात, बुद्धिमत्तापूर्ण भूमि उपयोग, संतुलित जनसंख्या संरचना तथा संसाधनों का समुचित विकास इत्यादि प्रमुख है।

जनाधिक्य या जनसंख्या आधिक्य (Over Population)

जिस क्षेत्र की जनसंख्या उसके पोषण सामर्थ्य से अधिक हो जाती है, उसे जनाधिक्य का क्षेत्र कहते है। सामान्यतः किसी क्षेत्र में जनाधिक्य की स्थिति तब देखने को मिलती है, जब उस क्षेत्र के भौतिक संसाधनों का विकास जनसंख्या वृद्धि की गति से कम होता हैं तथा तृतीयक सेवाओं का विकास तकनीकी उन्नति से काफी दूर रहे। पूर्ण जनसंख्या आधिक्य को सापेक्ष जनसंख्या आधिक्य से पृथक किया जा सकता है। पूर्ण जनसंख्या आधिक्य उस स्थिति का प्रतीक है जिसमें उत्पादन की यथार्थ सीमा हांसिल कर ली गई होती हैं लेकिन जीवन स्तर निम्न होता है। इसके विपरीत सापेक्ष जनाधिक्य में वर्तमान उत्पादन वहाँ की जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है, यद्यपि उत्पादन की प्रबल सम्भावनाएं विद्यमान रहती है। पूर्ण जनाधिक्य की तुलना में सापेक्ष जनाधिक्य काफी प्रचलित है। जनाधिक्य राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर पाया जा सकता है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर

भी जनाधिक्य की उपलब्धता में काफी विभेद देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कि राष्ट्र स्तर पर जनाधिक्य न हो लेकिन उसके किसी प्रान्त में जनाधिक्य हो सकता है। ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रो में जनाधिक्य दृष्टिगत होता है। ग्रामीण जनाधिक्य निम्न कारणों से हो सकता है –

(1) तीव्र ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि।

(2) कृषि भूमि का असमान वितरण।

(3) कृषि यन्त्रीकरण में वृद्धि तथा कृषक मजदूरों की मांग में कमी।

(4) गांवो में अकृषि क्षेत्रों का सीमित विकास।

(5) कृषि में अधिक भार वहन करने की सामर्थ्य में कमी।

(6) सामाजिक विकास का निम्न स्तर।

मृत्युदर में कमी तथा जन्मदर में वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से जारी है। संसाधन सीमित है तथा जनसंख्या समस्यायें अधिक हैं। यही कारण है कि अविकसित क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर विकासदर की अपेक्षा अधिक है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, रोजगार प्राप्ति के अवसरों में कमी, भूमिहीन कृषकों में सतत् वृद्धि ग्रामीण जनाधिक्य की विशेषताएं हैं। इसके समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास से भी इस समस्या को कुछ हद तक हल किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापनाओं के विकास, व्यवसाय परक एवं प्रौयोगिकी शिक्षा के विकास, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना आदि से जनाधिक्य को संतुलित किया जा सकता है। ग्रामीण जनाधिक्य की अपेक्षा औद्योगिक जनाधिक्य कुछ कम स्पष्ट होता है, क्योंकि कृषि भूमिओं की अपेक्षा औद्योगिक श्रमिकों में गतिशीलता अधिक होती है। इस प्रकार की स्थिति या तो तकनीकी उन्नति के

फलस्वरूप श्रमिकों के अकुशल होने अथवा सम्पूर्ण उद्योग या औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आने से होता है।

कम जनसंख्या (Minimum Population) –

किसी क्षेत्र की जनसंख्या जब उस क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से काफी कम होती है तो उसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते है। इसके अतिरिक्त कम जनसंख्या उस स्थिति का भी द्योतक होती है जब किसी क्षेत्र के संसाधन वर्तमान समय में उसमें निवास कर रहे लोगों से अधिक लोगों के जीवन यापन में सक्षम होते हैं। जीवनस्तर में किसी भी प्रकार की कमी के लिए बिना बेरोजगारी अथवा अल्प बेरोजगारी की समस्या के बिना और अधिक लोगों को उस क्षेत्र में बसाया जा सकता है। सम्पूर्ण न्यून जनसंख्या की अपेक्षा सापेक्ष न्यून जनसंख्या की स्थिति अधिक सामान्य है। सम्पूर्ण जनसंख्या की स्थिति की सम्भावना कम होती है। विकसित व अविकसित दोनों स्थितियों में न्यून जनसंख्या मिल सकती है। ऊबड़–खाबड़ व पहाड़ी–पठारी क्षेत्रों में जहाँ निवास हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं, वहाँ इस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है।

जनसंख्या दबाव (Population Pressure)

उपयुर्क्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि जनसंख्या संसाधन सन्तुलन की स्थिति बहुत कम दृष्टिगत होती है। जनसंख्या और संसाधन में असन्तुलन के कारण नाना प्रकार की विसंगतियां उद्भुत हो जाती हैं जिसे जनसंख्या दबाव कहते हैं। जनसंख्या दबाव का तात्पर्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उपलब्ध संसाधनों का अनुपात है। जनसंख्या के भारी दबाव के फलस्वरूप जनसंख्या तथा संसाधन का पारस्परिक सन्तुलन बिगड़ जाता है जिससे मानव समाज को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ब्राउनिंग (1970) के अनुसार किसी समुदाय के संसाधन तथा उसकी जनसंख्या के फलस्वरूप जनसंख्या दबाव की समस्या पैदा

होती है।

शोध क्षेत्र में जनसंख्या का ग्रामीण दबाव निरन्तर बढ़ रहा है। आज भी जनपद की 60 प्रतिशत जनसंख्या गांवो में निवास करती है जिसके भरण–पोषण का आधार प्रमुखतः कृषि व्यवसाय है। जनपद का जनसंख्या घनत्व 2001 में 348 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है जबकि सन् 1991 में यहाँ 282 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी० निवास करते थे। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व में निरन्तर वृद्धि हो रही है। स्थानिक विश्लेषण से यह रहस्योद्घाटित होता है कि कृषि योग्य भूमि का विकास संतृप्तता अवस्था की दिशा में अग्रसर है। यही कारण है कि ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर काम पाने की तलाश में त्वरित गति से भाग रही है। जनपद की अर्थ व्यवस्था वस्तुतः कृषि पर आधारित है, जो प्रमुख रूप से मिट्टी संसाधनों पर निर्भर करती है। यद्यपि ऊसर एवं बंजर भूमि का विकास कर कृषि से सम्बन्धित कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है लेकिन ऐसे क्षेत्रों के सुधार एवं विकास में लाभ की अपेक्षा खर्च अधिक है। सिचाई के साधनों का अभाव है अतः यहाँ की कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। 1995 में यहाँ की कुल बोई गई भूमि का मात्र 51.0 क्षेत्र सिंचित है।

जनपद में प्रति व्यक्ति घटती हुई भूमि (सारिणी क्रमांक 7.1) की प्रवृत्ति से परिलक्षित हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव निरन्तर बढ़ रहा है। केवल सिंचित क्षेत्रफल में प्रति व्यक्ति भूमि में कुछ इजाफा हुआ है; जो प्रगति का सूचक है लेकिन जनसंख्या वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि काफी कम है। जनपदों में लगभग 80 प्रतिशत किसान लद्यु एवं सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। यह आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। अशिक्षा व गरीबी के कारण यह लोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढाने में असमर्थ है। इसके साथ ही जनसंख्या दबाव के कारण भूमि भी घट रही है। यही कारण है प्रति व्यक्ति या प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से जनसंख्या दबाव। विकसित क्षेत्रों की तुलना में फसल उत्पादकता भी कम है।

सारिणी क्रमांक 7.1

प्रति व्यक्ति भूमि (हेक्टेयर में)

वर्ष	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कृषि योग्य भूमि	शुद्ध बोई गई भूमि	सफल बोई गई भूमि	एक से अधिक बार बोई गई भूमि	सफल सिंचित भूमि	खाद्यानों केअन्तर्गत भूमि
1981	0.6974	0.5511	0.4300	0.4778	0.0478	0.1296	0.4441
1991	0.5824	0.4584	0.3599	0.4041	0.0442	0.1493	0.3541

स्रोत :— सांख्यकीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर संगणित।

त्वरित गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसीलिए रोजगार की तलाश में ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर तीव्रगति से पलायन हो रहा है। इससे नगरों में भी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। सह–सम्बन्धीय विश्लेषण से भी यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनसंख्या घनत्व तथा सफल बोये गये क्षेत्रफल तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के मध्य उच्च सह सम्बन्ध है। वन उद्यान एवं चारागाह के अन्तर्गत भूमि निरन्तर कम हो रही है। अस्तु तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य पूर्ति हेतु अधिक सिंचन सुविधाओं, दो फसली क्षेत्रफल तथा बंजर – ऊषर भूमि के विकास की महती आवश्यकता है ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके।

जनपद में जनसंख्या का घनत्व 348 है। जिन विकास खण्डों में कृषि योग्य भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, दो फसली क्षेत्रफल, शस्य गहनता तथा सिंचाई की सुविधाएँ अधिक हैं। यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ संसाधनों के विकास की समस्या काफी जटिल है। यह समस्या आर्थिक विकास के प्रगतिशील प्रयासो

(डंकन, 1977) को प्रभावित करती है। भारत जैसे विकासोन्मुख क्षेत्र इस समस्या से बहुत प्रभावित है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या को न केवल अपर्याप्त खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, बल्कि उसके आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी तथा असन्तुलन है। उसके आहार में दूध, फल, हरी सब्जियाँ, मांस, अण्डे इत्यादि पौष्टिक पदार्थो की कमी रहती है।

यहाँ के व्यक्ति अधिकांशतः भोजन में पोषण तत्वों के रूप में अन्न (हेडी, 1973) का इस्तेमाल अधिक करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भोजन वह उपयोग में लाते हैं, उसमें गुणों (स्टैम्प, 1964) की कमी होती है। यही कारण है कि यहां के निवासी सामान्यतः अस्वस्थ्य रहते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। बच्चों के भोजन में भी पोषण तत्वों का अभाव पाया जाता है। फलतः बाल्यकाल से ही बच्चे शारीरिक रूप से रोगग्रस्त तथा कमजोर हो जाते है। भारत के लगभग सभी प्रान्तों में यह समस्या अपना गम्भीर रूप धारण किए हुए है। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र तो इस समस्या से पूर्ण रूपेण प्रभावित है। यद्यपि शासन द्वारा कुपोषण दूर करने की दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन यह बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए बूँद–बूँद टपकने की भांति है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में क्रियान्वित एक सर्वेक्षण के अनुसार यहां पर लगभग 40.2 प्रतिशत ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग 65.0 प्रति व्यक्ति अक्रियाशील हैं अथवा कुछ कृषि कार्य कर लेते हैं। मात्र 34.95 प्रतिशत व्यक्ति क्रियाशील वर्ग में आते हैं। सर्वेक्षण बताता है कि बुन्देलखण्ड में 25 प्रतिशत ग्रामीण तो पर्याप्त भोजन पाते हैं परन्तु 35 प्रतिशत केवल सामान्य तथा 40 प्रतिशत एक वक्त ही भोजन कर जीवन निर्वाह करते हैं, (मिश्र,1989)। इससे यह स्पष्ट है कि क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका समाधान आवश्यक है। यदि इस समस्या पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया गया तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। इस हेतु

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या नियन्त्रण तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना अति आवश्यक है। इसके अलावा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप नाना प्रकार की समस्याएं यथा–वस्त्र आपूर्ति, आवासीय, चिकित्सीय, रोजगार, यातायात, परिस्थितिकी असन्तुलन एवं प्रदूषण, मानव कल्याण एंव सुरक्षा आदि में वृद्धि हो रही है।

वास्तव में जनसंख्या का उसके विकास स्तर से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः जनसंख्या एवं सीमित साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियन्त्रण हो। जनसंख्या अभिवृद्धि से व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन उत्पन्न होते हैं। साथ ही अपराध, आत्महत्या, भ्रष्टाचार, बेकारी की दर तीव्रता से बढ़ती है। व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आहार आदि की सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता है। अतः शाश्वत विकास के लिए जनसंख्या तथा संसाधन में सन्तुलन स्थापित होना आवश्यक है।

जनसंख्या के सिद्धान्त (Theories of Population)

यद्यपि जनसंख्या तथा संसाधन सम्बन्ध की विचारधारा प्लेटो के समय से मानी जा सकती है किन्तु इस सम्बन्ध में व्यवस्थित ढंग से विचार प्रस्तुत करने का श्रेय रावर्ट माल्थस को है। इसके पश्चात अनेक विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के उपाय बताने का प्रयास किया है। वस्तुतः विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्तों को दो वर्गो में बाँटा जा सकता है। (1) प्राकृतिक नियमों पर आधारित सिद्धान्त, (2) सामाजिक नियमों पर आधारित सिद्धान्त। प्राकृतिक नियमों पर आधारित सिद्धान्तों के प्रणेता मुख्यतः माल्थस, थामस सैन्डलर, थामस डब्बलडे, हबर्ट स्पेन्सर आदि थे तथा सामाजिक नियमों पर आधारित सिद्धान्तों का प्रतिपादन हेनरी जार्ज, अरसीन ड्यूमॉट, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स आदि विद्वानों ने किया।

जनसंख्या वृद्धि का मानव कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव के विश्लेषण हेतु माल्थस (1796) ने जनसंख्या सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। यह सिद्धान्त दो मान्यताओं पर आधारित था। (1) मानव जीवन के लिए खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं, (2) दो विभिन्न लिंगों में कामभाव की स्वभाविकता। इनका सिद्धान्त यूरोप की जनसंख्या की समस्या के अनुभवों पर आधारित था। इनका मानना था कि जनसंख्या के बढ़ने की शक्ति भूमि की जीवन निर्वाह करने वाली सामग्रियों को उत्पन्न करने की शक्ति की अपेक्षा अधिक है। माल्थस का यह विचार था कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों में कोई रूकावट नहीं आयी तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दो गुनी हो जाएगी। अनियन्त्रित जनसंख्या गुणेत्तर क्रम (1,2,4,8,16,32,64..........) में बढ़ती है जबकि खाद्य सामग्री अंकगणितीय क्रम (1,2,3,4,5,6,7⁻) में बढ़ती है। इस प्रकार जीविका प्रदान करने की भूमि शक्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की शक्ति अनन्त हैं।

मानव सहित समस्त प्राणियों में उत्तरोत्तर अपनी संख्या बढ़ाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के कारण यदि उन्हे स्वतन्त्र कर दिया जाय तो कालान्तर में वे इतनी तेजी से बढ़ने लगते हैं कि खाद्य वस्तुओं की वृद्धि पीछे छूट जाती है। फलतः खाद्यान के साथ जनसंख्या अतिरेक को सन्तुलित रखने के लिए जनसंख्या को कम करने हेतु भूचाल, बीमारियों, युद्ध, बाढ़, अकाल इत्यादि, प्राकृतिक प्रकोपों को माल्थस ने सक्रिय अवरोधों की संज्ञा दी है। इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप सन्तुलन कायम होने तक क्रियाशील रहते हैं। माल्थस का विचार था कि जब तक मानव जाति अपनी इस प्राकृतिक प्रवृत्ति का अज्ञानता पूर्वक अनुसरण करती रहेगी तब तक समाज में प्राकृतिक अवरोधों की पुनरावृत्ति होती रहेगी।

माल्थस के सिद्धान्त की समीक्षात्मक विवेचना करते हुए विद्वानों का मत है कि

न तो जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय और न ही जीवन निर्वाह संसाधनों की वृद्धि दर गणतीय रही हैं। माल्थस की यह मान्यता भी सत्यापित नहीं हो सकी कि जनसंख्या में 25 वर्षो में दूना होने की प्रवृत्ति है। जनसंख्या दोगुनी होने की अवधि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न है जो वहां के आर्थिक स्तर, वैज्ञानिक तथा तकनीकि विकास पर निर्भर होती है। माल्थस ने परिवार नियोजन कृत्रिम संसाधनों पर भी ध्यान नहीं दिया जबकि उस समय फ्रांस में परिवार नियोजन कार्यक्रम का जोरो पर प्रचलन था। यही नहीं उन्होंने बदलती प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक संरचना पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह भी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि जनसंख्या वृद्धि एक जैवकीय सीमा होती है जिसके आगे उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती।

उपयुर्क्त आलोचनाओं के बावजूद भी माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त में काफी योगदान है। उन्होंने जनसंख्या तथा जीवन निर्वाह संसाधनों के सन्तुलन पर ध्यान केन्द्रित किया। माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त के परिणाम स्वरूप सिद्धान्त निरूपण परम्परा की शुरूआत हुई जो उनकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि मानव कल्याण के सन्दर्भ में सोचे जाने की विचारधारा वास्तव में माल्थस के ही समय से व्यवहार रूप में आयी।

मॉयकल थामस सैडलर एक समाज सुधारक व अर्थशास्त्री थे। शोधात्मक विश्लेषण से इन्होंने पाया कि मानव की जनसंख्या में वृद्धि की इच्छा तथा जनसंख्या घनत्व में ऋणात्मक सह–सम्बन्ध हैं। इनका मत है कि जनसंख्या घनत्व की बढ़ोत्तरी के साथ मानव में वृद्धि की प्रकृति घटती है। अन्य वस्तुएं समान रहने पर मानव संख्या वृद्धि उस बिन्दु पर आकर ठहर जाती है जहाँ पर अधिकतम लोगों का अधिक से अधिक कल्याण तथा खुशहाली होती है। इस प्रकार इनके अनुसार किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बढ़ाने पर लोगों की प्रजनन क्षमता कम होती है।

थामस डब्लडे (1847) एक अर्थशास्त्री व सामाजिक दर्शनशास्त्री थे इन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि का खाद्यपूर्ति से विपरीत सह सम्बन्ध है। इनके अनुसार सुन्दर खाद्य पूर्ति क्षेत्र में खाद्य पूर्ति तथा विलासतापूर्ण सामग्री की पूर्ति से जनसंख्या वृद्धि में लगातार कमी आती है। इस प्रकार प्रत्येक समाज में जनसंख्या वृद्धि पर खाद्य पूर्ति एक महान नियन्त्रक है। सामान्यतः खाद्य पूर्ति की स्थिति जहां ठीक है, वहां जनसंख्या स्थायी होती है।

सैंडलर और डब्लडे की भांति हरबर्ट स्पेन्सर (1867-68) ने मत व्यक्त किया कि जनसंख्या का एक प्राकृतिक नियम है जो मानव को जनसंख्या नियन्त्रण के उत्तरदायित्व से मुक्त करता हैं। मानव जैसे–जैसे व्यक्तिगत, वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास से सम्बन्ध होता जाता है वैसे–वैसे उसकी जनसंख्या वृद्धि की मनोवृत्ति सुस्त होती जाती है। इनका मानना था कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत विकास के लिए जितना प्रयत्नशील होगा, उसकी जनसंख्या उत्पादन में अभिरूचि उतनी ही कम होगी। इस प्रकार व्यक्तिकरण तथा उत्पादकता में विपरीत सम्बन्ध है। इस तरह मानव की पुनरूत्पादन क्षमता विशेषतया महिलाओं की, कम होती है क्योंकि उन्हें स्वयं के व्यक्तिपरक विकास में काफी समय व शक्ति लगानी पड़ती है। ऐसी स्थिति होने पर प्रजनन क्षमता अपने आप घटने लगती है और जनसंख्या वृद्धि दर सुस्त पड़ने लगती है।

हेनरी जार्ज (1905) ने मानव की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति तथा उसके जीवन निर्वाह सामर्थ्य के परस्पर विरोधी–सह–सम्बन्ध की अवधारणा पर सवाल उठाते हुए बल पूर्वक कहा कि अन्य जीवित प्राणियों के विपरीत जनसंख्या बढ़ने पर खाद्यपूर्ति में बढ़ोत्तरी होती है। इन्होंने यह भी बताया कि प्राकृति मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करती अपितु उसका मुख्य कारण त्रुटि पूर्ण सामाजिक

समायोजन होता है।

अरसीन ड्यूमाट ने फ्रान्स की जनसंख्या वृद्धि को आधार मानते हुए सामाजिक कोशिकीयता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार भौतिक कोशिकीयता की तरह मानव में भी उच्च स्तर पाने की लालसा होती है, जिसे सामाजिक कोशिकीयता कहते हैं। मानव की इसी लालसा के फलस्वरूप प्रजनन क्षमता में कमी आती है। परिणामतः वह अपने प्रजातीय कल्याण की भावना को विस्तृत कर देता है तथा स्वयं को उच्च शिखर में पहुंचने के लिए कार्यशील हो जाता है। इस प्रकार एक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर सतत वृद्धि जनसंख्या कमी का प्रत्यक्ष कारण होती है। इस भाँति किसी देश/प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि तथा व्यक्ति विशेष के विकास में विपरीत सम्बन्ध होता है (थाम्पसन तथा ल्यूइस, 1976)।

डयूमॉट का मानना था कि उन समाजों में जहाँ उच्च वर्ग में सहजता पूर्वक परिसंचरण सम्भव है, वहां सामाजिक कोशिकीय गुरूत्व के नियम की भाँति बनी रहती है। इसीलिए फ्रान्स में जन्म में तीव्रता से कमी आयी जबकि भारत में स्थिति इसके विपरीत थी। वर्तमान समय में जनसंख्या सान्द्रण प्रमुख तथा बड़े नगरों में केन्द्रित है। इन नगरों से सामाजिक कोशिकीयता का जब पृष्ठ प्रदेश में फैलाव होगा तो जन्मदर में कमी आएगी तथा बड़े नगरों से दूर व्यक्तिगत विकास के दुर्बल मनोभावों वाले क्षेत्रों में जन्मदर अधिक होगी।

डेविड रिकार्डो का मत है कि किसी अर्थव्यवस्था में जहाँ कृषि योग्य भूमि पायी जाती है, वहाँ उर्वरता तथा स्थिति की दृष्टि से सबसे अच्छी भूमि पर खेती प्रारम्भ की जाती है। जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य सामग्री की मांग बढ़ती है। इस लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान पूर्ति हेतु उत्तमता के दृष्टिकोण में क्रमशः कम उर्वरक भूमियों को स्वीकृत करना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी दर

श्रम संभरण (जनसंख्या वृद्धि) तथा पूंजी संचय पर आधारित होता है। उनका मानना था कि जनसंख्या का नियमन सेवा नियुक्ति सुविधाओं के अनुरूप होता है। इस भाँति जनसंख्या में वृद्धि या कमी पूँजी संचय के अनुसार होती है (रिकार्डो, 1951)।

इस तरह श्रम की मांग व पूर्ति में एक सन्तुलन तल स्थापित हो जाता है। सन्तुलन तल के एक बार पा लेने पर पूँजी संचय प्रक्रिया रूक जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन नियम सक्रिय हो जाता है। निर्धनता का बोल–बाला होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को केवल जीवनयापन हेतु, मजदूरी मिलती है। माल्थस की भाँति रिकार्डो भी अपनी बाजार पद्धति में यह स्वीकार करते हैं कि प्राकृतिक संकट तथा निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का अवश्यभावी प्रतिफल है।

कार्ल हेनरिक मार्क्स का सिद्धान्त मुख्यतः श्रम का सिद्धान्त है। यह पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्थाओं पर आधारित है। इनके अनुसार धनी वर्ग लाभ अर्जित करता है, जिससे पूँजी इकट्ठा होती है। इसके विपरीत निर्धन वर्ग जनसंख्या वृद्धि के माध्यम से श्रम संचय करने का प्रयास करता है क्योंकि यही एक मात्र उसकी सम्पत्ति होती है (मार्क्स, 1967)। मार्क्स का मानना है कि निर्धनता और आपदा स्वाभाविक है क्योंकि ए पूँजीवादी व्यवस्था की बुराइयों का प्रतिफल है। यदि साम्यवादी व्यवस्था का अनुपालन होगा तो यह बुराइयां समाप्त हो जाएगी। गरीबी और दुःख बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप जन्म लेती हैं, चाहे जनसंख्या वृद्धि कम हो या ज्यादा।

मार्क्स का विचार था कि माल्थस के जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धान्त का आधार पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था है। सामाजिक सुधार कार्यक्रम के माध्यम से पूँजीवादी व्यवस्था से निजात मिल सकती है। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि तथा

अधिक उत्पादन को ध्यान में रखकर इन्होंने प्रौद्योगिकी परिवर्तन पर बल दिया। सम्पूर्ण समस्या के समाधान हेतु इन्होंने सिस्टम उपागम का सुझाव दिया जिसमें सम्पूर्ण तन्त्र को गतिशील बनाने की क्षमता है। इससे एक नवीन संकल्पना व नए वर्ग का जन्म होगा जो पूँजीवादी तन्त्र से निराकरण प्रदान करेगा (हार्वे, 1977)।

इस प्रकार जनसंख्या समस्या के इस विशिष्ठ उपागम के माध्यम से इन्होंने समाज के ऐसे परिवर्तन को दर्शाया कि दुख तथा निर्धनता का समाधान सम्भव हो सके क्योंकि यह समस्या कोई प्रकृति प्रदत्त नहीं है। इन्होंने साम्यवादी उत्पादन पद्धति की क्षमता में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर चाहे जो हो, सबको सुन्दर जीवन स्तर तथा रोजगार प्राप्त हो सकता है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक उत्पादन स्वरूप का अपना आर्थिक और जनसांख्यकीय नियम होता है। जन्मदर, मृत्युदर तथा छोटा–बड़ा परिवार का मजदूरी स्तर से विपरीत सम्बन्ध होता है। इनके अनुसार विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के जीवन में निर्वाह हेतु उपलब्ध संसाधन जैसे–जैसे बढ़ते हैं, जन्मदर, मृत्युदर, तथा परिवारों का आकार उसी क्रम से घटता है। जिन श्रमिकों की मजदूरी दर का स्तर निम्न होता है उनमें जन्म एवं मृत्युदर ऊंची होती हैं।

जनसंख्या संसाधन प्रदेश (Population Resource Region)

मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वह प्राकृतिक संसाधनो का खोजकर्ता, उपभोक्ता तथा सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माणकर्ता है। जनसंख्या संसाधन के अध्ययन से स्थानिक स्तर पर जनसंख्या का महत्व तथा समस्या के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है। बघेलखण्ड प्रदेश के जनसंख्या संसाधन प्रदेश का निर्धारण करने के लिए सिंह (१६७६) ने पाँच कारकों यथा– जनसंख्या घनत्व, वृद्धिदर साक्षरता, कृष्येतर कार्यों में लगी जनसंख्या तथा नगरीयकरण की मात्रा को आधार

माना है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक विद्वानों ने संसाधन प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानक माने हैं। शोध क्षेत्र के अन्तर्गत संसाधन प्रदेश ज्ञात करने के लिए जनसंख्या का आंकिक घनत्व, वृद्धिदर, कृष्येतर कार्यो में लगी जनसंख्या, साक्षरता, तथा नगरीकरण का आधार माना गया है। इन कारको का मानक सूचकांक ज्ञात करके सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र को तीन जनसंख्या प्रदेशों में विभक्त किया गया है।

सारिणी क्रमांक 7.2

जनसंख्या संसाधन प्रदेश

संसाधन प्रदेश	सूचकांक	विकास खण्ड
गत्यात्मक प्रदेश	100 से अधिक	बड़ागांव
सम्भाव्य प्रदेश	60-100	मोठ, चिरगांव, बंगरा, मऊरानीपुर, बबीना
समस्यात्मक प्रदेश	60 से कम	बामौर, गुरुसराय

स्रोत – विभिन्न मानको की गणना पर आधारित।

(1) **गत्यात्मक प्रदेश** – इसके अन्तर्गत जनपद का एक विकास खण्ड (बड़ागॉव) आता है। यह भू–भाग 10.25 प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला है। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण जनपद की 32.83 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस विकास खण्ड में उच्च जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, कृष्येतर कार्यों में लगी हुई अधिक जनसंख्या, नगरीकरण की मात्रा, जनसंख्या वृद्धि दर को गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश के रूप में परिभाषित करने में महत्वपूर्ण मानक माना जा सकता है। इस क्षेत्र में झांसी नगर समूह, बड़ागांव तथा बरूआसागर नगरीय केन्द्र सम्मिलित हैं।

(2) सम्भाव्य प्रदेश – इस प्रदेश में पाँच विकास खण्ड यथा मोंठ, चिरगांव, बंगरा,, मऊरानीपुर तथा बबीना सम्मिलित है जो 56.97 प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण जनपद की 49.76 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यद्यपि इन विकास खण्डों में संसाधनों के विकास की प्रचुर सम्भावनाएं विद्यमान हैं किन्तु सामाजिक आर्थिक अवस्थापनाओं की कमी तथा प्राविधिकी के अभाव में इन संसाधनों का विकस नहीं हो पाया है।

(3) समस्यात्मक प्रदेश :– इस प्रदेश के अन्तर्गत बामौर तथा गुरसंराय विकासखण्ड आते हैं। यह क्षेत्र 32.78 प्रतिशत भू–भाग में फैला हुआ है। इन विकासखण्डों में सम्पूर्ण जनपद की 17.41 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। उपर्युक्त विकासखण्ड की अपेक्षा यहां अवस्थापनाओं का पर्याप्त मात्रा में अभाव है। इसके अलावा कम घनत्व, कृष्येतर कार्यों में बहुत कम मात्रा में लगी जनसंख्या, कम साक्षरता तथा न्यून नगरीकरण की मात्रा के फलस्वरूप ये विकास खण्ड समस्यात्मक प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं।

जनसंख्या नियोजन (Population Planning)

जनपद झांसी के प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्वरूप में जनसंख्या नियोजन से सम्बन्धित निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत हैं जिससे जनसंख्या संसाधन एवं आवश्यकताओं के मध्य सन्तुलन कायम रह सके। जनसंख्या नियोजन में अधोलिखित तथ्यों का समावेश जरूरी है। वस्तुतः अग्राकिंत बिन्दुओं पर ध्यान देने से क्षेत्र का समन्वित विकास सम्भव है।

(1) कृषि उत्पादन में सुधार – तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कृषि के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार की सम्भावनाएं अत्यन्त कम होती जा रही है। जनपद में एक लाख से भी अधिक प्रतिवर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवनयापन हेतु प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान

JHANSI DISTRICT
HUMAN RESOURCE REGIONS
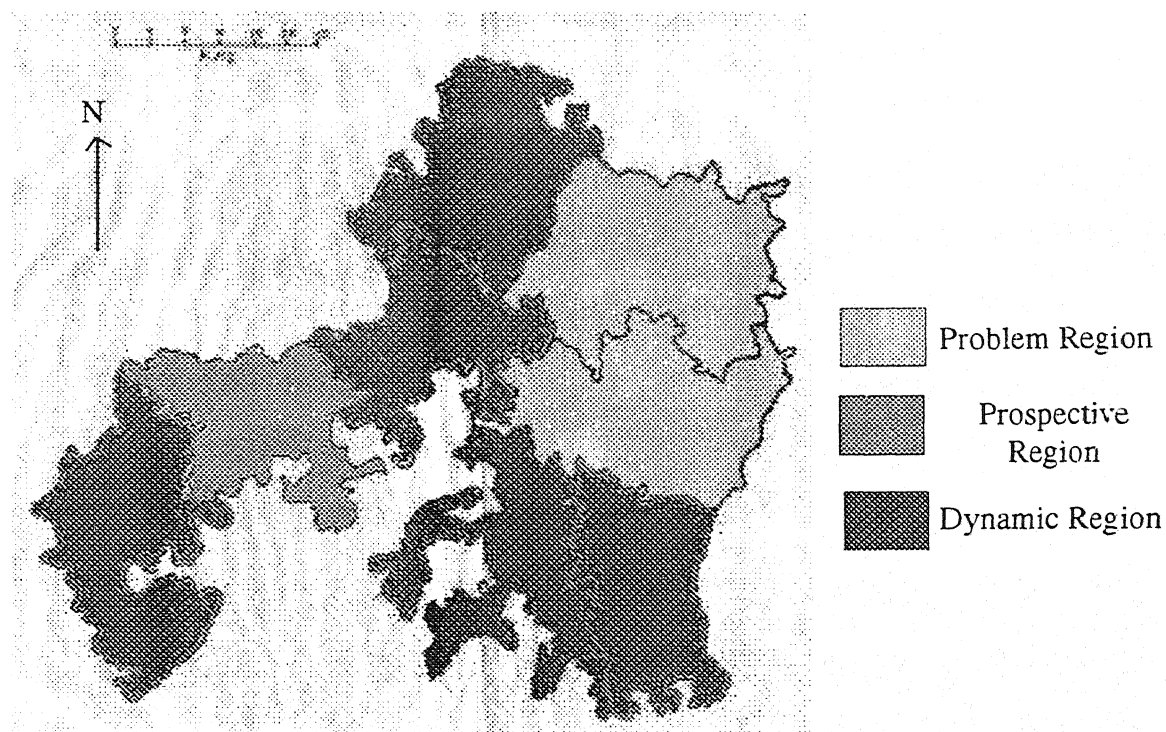
Fig 7.1

केन्द्रित करने की आवश्यकता है। अधिक उपज देने वाली फसलों का उपयोग, सामयिक तथा समुचित विद्युत तथा सिंचाई का विकास, फसल चक्र का ज्ञान, कृषक मजदूरों के स्थानान्तरण को कम करके तथा अन्य दूसरी सुविधाओं का विकास करके बहु फसल चक्र तथा गहन कृषि पद्धति के साथ भूमि की उत्पादकता कायम रखते हुए तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। इसके अलावा मत्स्यं पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन तथा डेरी उद्योग को विकसित करके कृषि पर होने वाले जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सकता है।

औद्योगीकरण – जनपद की क्रियाशील जनसंख्या को द्वितीयक तथा तृतीयक उत्पादन क्रियाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु/कुटीर/पारिवारिक उद्योगों का विकास किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही इन उद्योगों के लिए पूँजी तथा बाजार का भी समुचित प्रबन्ध किया जाना जरूरी है। ऐसा किया जाने पर जनपदीय लोगों के प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन स्तर में सुधार होगा और इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण जनपद का विकास होगा।

शैक्षिक विकास – सन्तानोत्पादन तथा शिक्षा स्तर के मध्य अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। सामान्यतः साक्षरों की तुलना में निरक्षरों के अधिक बच्चे होते हैं। शिक्षित व्यक्ति जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक महत्व देते हैं तथा कम सन्तान सुखी इन्सान की विचार धारा रखते हैं। शिक्षा स्तर से जन्म दर प्रभावित होता है। सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में ज्यों–ज्यों सुधार होता है, त्यों–त्यों सन्तानोत्पादन की संख्या में कमी आती जाती है। अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विकास में निम्न साक्षरता बाधक है। स्तरीय साक्षरता पर विशेष ध्यान केन्द्रित रखते हुए गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके लिए छात्रवृत्तियों

तथा सेवाओं में आरक्षित पदों की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार पुरूष तथा स्त्री शिक्षा में विषमता का निवारण करके जनपद का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा सकता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता में स्त्री शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

शिक्षा का विकास प्रक्रिया पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। चौधरी (1974), के अनुसार कृषि उत्पादकता एवं शिक्षा के विकसित स्तर में एक सहयोगी सम्बन्ध पाया जाता है। शिक्षा के विकास हेतु जनपद में एक ही शिक्षा प्रणाली तथा हर वर्ग के लिए हाईस्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। क्षेत्र में किए गये सर्वेक्षण से यह रहस्योद्घटित होता है कि जनपद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मात्र कागजी बनकर रह गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रशासन की ओर से शिक्षा के सफल क्रियान्यवन हेतु एक निरीक्षक अधिकारी की नियुक्ति की जाय जो समय–समय पर विशेष निगरानी करते हुए अकर्मण्य तथा लापरवाह अधिकारियों दण्डित कर सके। इसके साथ ही जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से माध्यमिक तथा स्नातक स्तर की कक्षाओं में लागू किया जाय।

वस्तुतः जनसंख्या वृद्धि रोकने का महत्वपूर्ण आयाम जनसंख्या शिक्षा है। यह एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के बहुआयामी विकास को दिशा दी जा सकती है। इसके माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं से होने वाले प्रभावों से लोगों को जागरूक कराया जा सकता है तथा व्यक्ति स्वयं परिवार एवं राज्य/प्रदेश/राष्ट्र के कल्याण हेतु उचित एवं वांछित निर्णय लेने में सक्षम हो सकेगा (मिश्र, 1996)।

आश्रित जनसंख्या भार में कमी – यह वृद्धि जनसंख्या भार में कमी करके तथा जनपद में रोजगार के अवसर सुलभ कराकर, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करके कम किया जा सकता है। इसके साथ–साथ कृषि पर आधारित उद्योगों तथा कुटीर लघु उद्योगों को विकसित करके यह भार कम किया जा सकता है। जनपद में तीव्र

गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामस्वरूप जनसंख्या तथा अन्य संसाधनों के मध्य असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जनपद में जन्मदर मृत्युदर की तुलना में अधिक है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। जनपद के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जो प्रयास किए गये हैं; उनका लाभ आशा के अनुकूल जनपद वासियों को नहीं प्राप्त हो सका है। त्वरित गति से बढ़ती हुई जनसंख्या जनपद के तीव्र आर्थिक विकास के प्रभाव को निष्क्रिय कर रही है। यही कारण है कि जनपद की लगभग आधी अबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है।

कुछ लोगों का मत है कि जनसंख्या वृद्धि गरीबी की देन हैं। इसके साथ ही साथ निरक्षरता तथा स्थानान्तरण, शिशु तथा मातृ मृत्युदर तथा कम आयु में विवाह और धार्मिक कुरीतियों आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या समस्या को प्रभावित करते है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं को गरीबी और अधिक बढ़ा देती है।

जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु विकास के नवीन आयामों की खोज करना आवश्यक है; क्योंकि निर्धनता तथा पिछड़ेपन का सम्बन्ध प्रतिव्यक्ति उत्पादकता तथा संसाधनों की वितरण व्यवस्था से सम्बद्ध है। सरकार द्वारा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परिवार नियोजन सम्बन्धी जनसंख्या नियन्त्रण की नीति बनानी चाहिए। इस हेतु यहाँ कुछ सुझाव प्रस्तावित हैं।

(1) शासकीय कर्मचारियों पर इस बात के लिए दबाव डाला जाय कि इनके अधिकतम दो ही बच्चे हों।

(2) स्कूल कालेजों तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रो, आंगनवाड़ी व अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी पाठ्यक्रम की विशेषरूप से व्यवस्था की जाय। समय–समय पर इनका निरीक्षण किया जाय तथा उदासीन अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही स्त्री

शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय।

(3) परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति समर्पित व्यक्तियों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए परिचय पत्र बनाए जांय। परिचय पत्र दिखाने पर उन्हें उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्तुओं को प्राथमिकता से प्रदान किया जाय।

(4) राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों का पर्याप्त मात्रा में प्रचार व प्रसार किया जाय।

(5) मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान की जाय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो/उपकेन्द्रों को हर दृष्टि से प्रभावशाली बनाया जाय।

(6) लड़कों एवं लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक आयु कम से कम क्रमशः 25 व 21 वर्ष की जाय तथा इसका कड़ाई से अनुपालन कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

(7) स्वास्थ्य विभाग के अलावा सभी विभागों को जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के उपायों को जन–जन तक पहुँचाने में लगाया जाय, लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने के लिए किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती न की जाय।

(8) परिवार नियोजन अपनाने वाले निर्धन व कमजोर किसानों को सन्तोष प्रद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त ऋण के व्याजदर में कम से कम 1 प्रतिशत की कमी की जाय।

(9) लड़का–लड़की को समान दर्जा दिलाने का प्रयत्न किया जाय। उनके खान–पान व अन्य व्यवस्था में कोई विभेद न रखा जाय।

(10) पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा परिवार नियोजन का अत्यधिक मात्रा में प्रचार–प्रसार किया जाय। जिन गांवों में साक्षरता व परिवार नियोजन में लक्ष्य

के अनुकूल सफलता मिले उहें आदर्श गाँव का दर्जा देकर अत्यधिक विकसित किया जाय।

जनपद में एक ओर जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर आधारित है वहीं दूसरी ओर यह औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ेपन को भी प्रदर्शित करता हैं। इसके विपरीत नगरों में जनसंख्या, व्यापार, उद्योग तथा अन्य व्यवसायों की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है तथा गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन तीव्र गति से हो रहा है। यही नहीं जनपद की ग्रामीण जनसंख्या देश के अन्य बड़े नगरों में रोजी–रोटी की तलाश में जाकर बस रही है, जिससे इन नगरों में भी अनेक समस्यायें पैदा हो रही है। इसका प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ़ता शिक्षित बेरोजगार, आधुनिक शिक्षा पद्धति, मशीन से बने हुए सामान का गॉव–गॉव पहुँचना, ग्रामीण जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव, सरकारी काम–काज में बढ़ोत्तरी, गाँव में लघु एवं कुटीर उद्योगों की कमी, यातायात के साधनों की सुलभता, संचार साधनों का विकास, गॉव में बढ़ती हुई कानून व्यवस्था आदि को माना जा सकता है। फलस्वरूप वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति गाँव से नगरों में बसने के लिए उतावले हैं।

अस्तु निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र के अधिकांश अविकसित समाज को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगीकरण का विकेन्द्रीकरण कर ग्राम्य स्तर पर लघु उद्योगों का विकास किया जाय। साथ ही कृषि में तकनीक का अधिक प्रयोग करके खाद्यान उत्पादन पर बल दिया जाय। इस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का ढांचा प्रस्तुत करके यहाँ के अविकसित कृषि समाज की जनंसख्या समस्या को हल किया जा सकता है और तभी जनपद का चहुँमूखी विकास हो सकता हैं।

References

1. Browning, H.L (1970), Some Sociological Considerations of Population Pressure on Resources, in Geography and Crowding World. Edited by W. Zelinsky and Others, Oxford University Press, NewYork p.72.

2. चन्दना, आर०सी० (1994), जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिसर्स, पृ.सं.286 ।

3. Chaudhari, D.P. (1974) , Effect of Farmer's Education of Agricultural Productivity and Employment; A Case Study of Punjab and Haryana States of India, I.L.O. Jeneva

4. Cloud, Preston (1970), Resource Population and Quality of Life" in Is There An Optimum Level of Population, Edited by S. Fred Singer, A Population on Council Book, McGraw Hill Company, New York, PP. 8-21.

5. Doubleday, Thomas (1847), The True Law of Population Shown to be Connected with Food of People, 2nd edition, George Pierce, London.

6. Duncan, E. R. (1977), Dimensions of World Food Problems, The Iowa State University Press, Iowa, P. 37.

7. George, Henery (1905), Progress and Poverty, Doubleday Doran & Co., NewYork.

8. Harvey, D. (1977), Population, Resources and the Ideology of Science in Radical Geography, edited by Richard Peat, Methuen & Co. Ltd., London.

9. हीरालाल (1989), जनसंख्या भूगोल, बसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, पृ. 318 ।

10. Heady, O.E. and Charles, F.F. (1973) World Food Problem, Demand and Trade, Iawa State University Press, Iawa, P. 68

11. Marx, K.H. (1967), Capital, vol.13, International Publishers, NewYork

12. Malths, Robert (1796), An Essay on the Principle of the Population and its Affects to Future Improvement of Society.

13. मिश्र, कृष्णकुमार (1989), ग्रामीण विकास प्रक्रिया : मूल्यांकन एवं सम्भावनाएँ, अर्न्तवस्तु की प्रस्तुति, स्मारिका, अखिल भारतीय संगोष्ठी, 22-23 दिसम्बर ।

14. मिश्र, कृष्णकुमार (1996), बुन्देलखण्ड (उ०प्र०) की बढ़ती जनसंख्या एवं तज्जनित समस्याएँ, मन्दाकिनी, अतर्रा, अंक 23, पृ. 15-19 ।

15. Ricardo, David (1951), Principles of Political Economy, Cambridge Univeristy Press, London.

16. Robinson, W.C. (1964) The Development of Modern Population Theory, American Journal of Economics and Sociolagy, Vol.23 No.4, Page 384

17. Sauvy, A. (1966), A General Theory of Population, Weidenfeld and Nicolson, London, pp. 36-41.

18. Singh, R.L., Rana P.B Singh and Singh, C.B. (1976), Baghelkhand Re gion : A Study in Population Resource Regionalization and Develop ment Models.

19. Spencer, Herbert (1867-68), The Principles of Biology, Vol.2 D Appleton

and Co., NewYork.

20. Stamp, L.D. (1964), The Geography of Life and Death; P.95.

21. Taeuber, I.B. (1970) Population Dynamics and Population Pressure : Geographic Demographic Approaches in Geography and A Crowding World, Edited by Wilbur Zelinsky, Oxford University Press, NewYork. P.56

22. Thompson, W.S. and Lewis, D.T. (1976), Population Problems, Tata McCrow-Hill Publishing Co., NewYork

23. Zelinsky, W. (1966) A Prologue to Populotian Geography. Prentice Hall N.J.

अध्याय – ८

सारांश एवं निष्कर्ष

सारांश एवं निष्कर्ष (Summary and Conclusion)

मानव भूतल का एक महत्वपूर्ण प्राणी है जो प्राकृतिक वातावरण का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करके सांस्कृतिक वातावरण का सृजन करता है। मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण सामान्यतः देश तथा विशेष रूप से किसी क्षेत्र की उन्नति का सूचकांक होता है। इससे मानवीय आर्थिक कियाएँ भी प्रभावित होती हैं। मानवीय सांस्कृतिक वातावरण में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार के निर्णय मानव अपने पूर्व ज्ञान, बौद्धिक स्तर, वैज्ञानिक विकास तथा पूर्वजों से विरासत में प्राप्त सांस्कृतिक आधारों पर निश्चित करता है। इस प्रकार विविध क्षेत्रों में कियान्वयन के फलस्वरूप मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है । भारत जैसे विकासोन्मुख देश में जहां प्रादेशिक स्तर पर मानव जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्य सम्बन्धी भौगोलिक अनुसन्धान का महत्वपूर्ण स्थान है। 5025 वर्ग किमी० में विस्तृत झाँसी जनपद को वर्तमान शोध समस्या के परीक्षण हेतु चयनित किया गया है।

शोध परियोजना की विषय सामग्री को आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक अध्ययन में परिकल्पनाओं का परीक्षण भी करने का प्रयास किया गया है जो कि शोध प्रबन्ध के प्रस्तावना नामक अध्याय में वर्णित है। जनसंख्या के विविध आयामों के सम्बन्ध विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कार्यों का विवरण तथा जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन के औचित्य पर प्रकाश डाला गया है। शोध परियोजना के उद्देश्यों तथा शोध परियोजना के अध्ययन हेतु प्रयुक्त विभिन्न विधियों के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई है। वस्तुतः वर्तमान समय में नाभिकीय युद्ध, आतंकवाद, निरन्तर बढ़ता

छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्र की समस्याओं के सिलसिलेवार विवरण के साथ--साथ तार्किक समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की जाय। इस हेतु राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता तथा शिक्षाविदों के स्तर से प्रयास जारी हैं किन्तु अभीतक इन समस्याओं के समाधान हेतु कोई सार्थक परिणाम हासिल नहीं हो सका है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं एवं इनको निराकरण आदि के सम्बन्ध में इस शोध परियोजना के माध्यम से विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है ताकि जनसंख्या संसाधन संतुलन की दिशा में प्रगति हो सके।

अध्ययन क्षेत्र झाँसी का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 5025 वर्ग किमी० है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जनपद चार तहसीलों तथा आठ विकासखण्डों में विभाजित है। कुल आबाद गांवों की संख्या 760 है। झाँसी नगर समूह तथा तेरह अन्य नगरीय केन्द्र हैं। भूगर्भिक संरचाना की दृष्टि से इसका उत्तरी–पूर्वी भाग मैदानी तथा दक्षिणी व दक्षिणी–पश्चिमी भाग ऊंची–नीची कंकरीली–पथरीली भूमि से युक्त है। भूगर्भिक संरचना, भूआकृति, वनस्पति, मिट्टी, जलवायु, प्रवाहतन्त्र तथा अन्य भौगोलिक परिस्थितयों को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र को चार प्रादेशिक भागों (झाँसी मैदान, बेतवा–धसान ऊबड़–खाबड़ भूमि, मऊरानीपुर उच्च भूमि तथा झाँसी उच्च भूमि) मु विभाजित किसया गया हे। यहां की जलवायु बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों की भांति मानसूनी है जहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन अत्यधिक गर्म जबकि रातें शीतल व सुहावनी होती हैं। वर्षा अधिकांशतः जुलाई, अगस्त व सितम्बर माह में होती है। औसत वार्षिक वर्षा 880 मिमी० तक अंकित की गई है। बेतवा, धसान, पहूँज, लखेरी आदि यहां की प्रमुख नदियाँ हैं जोकि अपने सहायक छोटे नालों तथा जन वितरिकाओं के साथ दखिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। यहां प्रमुखतया चार प्रकार (रांकर, पडुवा काबर तथा मार) की मिटि्टयाँ पाई जाती हैं।

वन, उद्यान, चारागाह तथा बंजर एवं परती भूमि के अन्तर्गत कमशः 6.5,0.3,0.1 तथा 15.8 प्रतिशत भूमि आती है। उपलब्ध वनीय क्षेत्र पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।

जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 62.4 प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। शेष भूमि परती, वन एवं उद्यान, चारागाह तथा कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि के अन्तर्गत आती है। क्षेत्र की कुल शुद्ध बोई गई भूमि का 41.7 प्रतिशत भाग सिंचित है। सिंचन सुविधाओं में नहरों (54.39 प्रतिशत) तथा कुओं (36.76 प्रतिशत) का सर्वाधिक योगदान है। क्षेत्र का अधिकांश भूभाग वर्षा आधारित खेती पर निर्भर करता है। यही कारण है कि मैदानी भागों की तुलना में यहां प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। यहां पर खनिज सम्पदा के रूप में ग्रेनाइट, डायास्फोर, पाइरोफाईलाइट व मोरम आदि उपलब्ध है। झाँसी मे लोकोशेड, व अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थिति तथा मऊ में टेरीकाट कपड़ों के कारखानों की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। देशी जड़ी–बुटियों पर आधारित शर्मायु आयुर्वेद कारखाना का विशिष्ट स्थान है। इसके अतिरक्त इन्जीनियरिंग, वर्क्स रसायन, फर्नीचर उद्योग, जूते तथा बैग आदि निर्माण के सम्बन्ध में कई कारखाने कार्यरत हैं।

अध्ययन क्षेत्र की (कुल जनसंख्या 1429698 (1991) है जिसमें) 60.39 प्रतिशत जनसंख्या ग्राम्य वातावरण में निवास करती है जबकि 39.61 प्रतिशत व्यक्ति नगरीय परिवेश में रहते हैं। वर्तमान में झाँसी जनपद में 14 नगरीय केन्द्र हैं जिनमें एक नगरमहापलिका, पांच नगरपालिकाएँ, सात नगर क्षेत्र समितियों तथा एक छावनी क्षेत्र है। इनमें झाँसी नगर जनपद तथा कमिश्नरी मुख्यालय होने के साथ–साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। यह प्रथम श्रेणी का नगर है जबकि अन्य 13 तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के नगर हैं। रेल एवं सड़क परिवहन की दृष्टि से बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यह एक विकसित क्षेत्र है फिर भी ग्राम्य स्तर

सड़क मार्गों की कमी है। अवस्थापनाओं के विकास की दृष्टि से झाँसी जनपद का ग्रामीण क्षेत्र काफी पिछड़ा है। क्षेत्र 40.0 प्रतिशत गांवों की दूरी सेवा केन्द्रों से 10 किमी० से भी अधिक है जिसका प्रमुख कारण अवस्थापनाओं का समुचित विकास न होना कहा जा सकता है।

निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या आज की ज्वलन्त समस्या है। 1901-11 के दशक में यहा पर जनसंख्या वृद्धि दर मात्र 6.53 प्रतिशत थी जो 1951-61 में बढ़कर 28.10 प्रतिशत तथा 1991 से 2001 के मध्य लगभग 23.0 प्रतिशत वृद्धि दर है जो पिछले दशकों से कुछ घटी अवश्य है, लेकिन सन्तोष जनक नहीं कही जा सकती। कमोवेश यही स्थिति तहसील क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1931-41 के दशक में दृष्टिगत होती है जबकि अन्य दशकों की जनसंख्यास वृद्धि में काफी अतार--चढ़ाव देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण रोजगार के सुअवसरों की सुलभता में विभिन्नता को माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएँ, स्थानान्तरण, अवथापनाओं का विकास आदि कारण भी जनसंख्या की वृद्धि व कमी के लिए उत्तरदायी है। 1901-11 के दशक में नगरीय जनसंख्या में क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई क्योंकि क्षेत्र में नगरीकरण की प्रकिया प्रारम्भिक अवस्था में थी। 1951-61 के दशक में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार एवं सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के कारण नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन मिला तथा क्षेत्र में 31.30 प्रतिशत की भारी वृद्धि का अनुभव किया गया । सबसे अधिक नगरीय वृद्धि झाँसी (40.17 प्रतिशत) तथा गरौठा (42.44 प्रतिशत) तहसीलों में हुई। 1971-81 का दशक नगरीय जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दशक कहा जा सकता है क्योंकि अकेले गरौठा में 182.35 प्रतिशत की अभूत पूर्व वृद्धि आकलित की गई। उके पश्चात् मऊ, मोंठ व झाँसी तहसीलों का स्थान आता है। 1981-91 के दशक में भी गांवों की अपेक्षा नगरों में जनसंख्यसा वृद्धि तीव्र गति से हुई। यद्यपि इस दशक में

पूर्वदशक की तुलना में नगरीय जनसंख्या में कम वृद्धि (31.30 प्रतिशत) अंकित की गई। झाँसी तहसील में 49.90 प्रतिशत, मऊ में 31.48 प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई जबकि अन्य तहसीलों में 22.0 प्रतिशत के आस पास जनसंख्या वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की प्रगति तथा नगरों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभाव से नगरीय जनसंख में कम वृद्धि का कारण माना जा सकता है।

जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक प्रजननता, मृत्युदर व स्थानान्तरण है। यहां पर वर्ष 1991 में जन्मदर (32.5 प्रति हजार) था जो काफी अधिक है। सर्वेक्षण बताता है कि दलित वर्ग में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है अतः 15-20 आयु वर्ग की महिलाओं में सर्वाधिक बच्चे होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विभिन्न जाति वर्ग की महिलाओं में वय वर्ग के अनुसार प्रजनन अनुपात में विभिन्नता मिलती है। यह विभिन्नता ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में अलग–अलग विद्यमान है। नगरों में 15-35 वर्ष के मध्य आयु वाली महिलाओं में प्रजनन अनुपात सर्वाधिक जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 20-25 आयु वर्ग में अधिक बच्चे पैदा होते हैं। इस आयु के बाद भी बच्चे पैदा करने की लालसा में दिखलाई पड़ती हैं जबकि नगरीय क्षेत्र में इसमे काफी कमी आ जाती है।

वस्तुतः आज भी अधिकांश ग्रामीण बच्चे का जन्म भगवान की देन मानते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजननता दर अधिक जबकि नगरीय व्यक्ति बच्चे का जन्म व्यक्ति के प्रजनन सम्बन्धी क्रियाओं पर निर्भर मानते हैं। अतएव यह ग्रामीणों की अपेक्षा परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों का अधिक उपयोग करते हैं। 10,000 से कम आय वाले ग्रामीण परिवारों में प्रजनन अनुपात 1:5.8 पाया गया जबकि नगरीय परिवारों की महिलाओं में 1:4.3 प्रजनन अनुपात पाया गया। 10,000 से अधिक आमदनी वाले ग्रामीण परिवारों में प्रजनन अनुपात 1:4.2 जबकि नगरीय महिलाओं में यह अनुपात 1:3.08 पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि आर्थिक स्तर और

प्रजननता में विपरीत सम्बन्ध होता है । शैक्षिक स्तर में वृद्धि के साथ–साथ महिलाओं की प्रजननता में कमी पाई जाती है। अतः शैक्षिक स्तर और प्रजननता में विपरीत सम्बन्ध स्पष्ट होता है। शिक्षा स्तर होने के बावजूद ग्रामीण व नगरीय वातावरण में विभिन्नता के कारण प्रजननता में अन्तर पाया जाता है। निरक्षर ग्रामीण व नगरीय महिलाओं में भी यह स्थिति देखने को मिलती है।

धार्मिक दृष्टि से किए गए सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई महिलाओं में अलग–अलग धार्मिक मान्यताओं के कारण प्रजननता अनुपात में अन्तर है। मुस्लिम महिलाओं में अन्य सम्प्रदाय की तुलना में प्रजननता अधिक पाई जाती है। अस्तु यह प्रमाणित होता है कि हर दृष्टि से ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या में प्रजनन दर कम होती है। जनपद में मृत्युदर 14.98 प्रति हजार है जो 1971 की तुलना मे काफी कम है। इससे सिद्ध होता है कि ग्रामीण व नगरीया क्ष्जेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण मुत्युदर निरन्तर घट रही है।

अध्ययन क्षेत्र में मौसमी स्थानान्तरण की प्रवृत्ति अधिक है। फसलों की कटाई के समय बड़ी संख्या में यह स्थानान्तरण देखने को मिलता है। इस प्रकार के मजदूरों को स्थानीय भाषा में चैतवा कहते हैं। जनपद की कुल जनसंख्या का 87.78 प्रतिशत यहाँ के मूल निवासी हैं जबकि 6.64 प्रतिशत व्यक्ति सीमावर्ती जिलों (उ०प्र०) से, 5.34 प्रतिशत अन्य राज्यों से तथा 0.24 प्रतिशत जनसंख देश के बाहर से स्थानरान्तरित होकर यहां प्रवासी जनसंख्या के रूप में निवास करती है।

जनसंख्या प्रक्षेपण से स्पष्ट है कि 1991 में जो जनसंख्सय 14.30 लाख है, वह वर्ष 2001 में 19.01 लाख वर्ष, 2011 में 25.20 लाख और वर्ष 2021 में 36.63 लाख हो जाएगी। कमोवेश जनसंख्या वृद्धि का यह प्रतिरूप सभी तहसीलों में भी मिलता है। अतः भविष्य में जनसंख्या के बढ़ते हुए इस भाग को ध्यान में रखकर क्षेत्र की

आत्मनिर्भरता हेतु औद्योगिक एवं कृषि विकास के साथ ही अवथापनाओं के विकास व सामाजिक उत्थान की प्रबल आवश्यकता है।

चतुर्थ अध्याय वस्तुतः जनसंख्या के स्थान के प्रतिरूप की व्याख्यसा करता है। क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण व जमाव सर्वत्र समान नहीं है। कहीं जनसंख्या का बसाव अधिक तो कही कम । जनसंख्या के इस असमान वितरणस्वरूप को भौतिक कारकों में स्थलीकृतियाँ, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, भूगर्भीय जलस्तर तथा खनिज सम्पदा; सांस्कृतिक कारकों में ामाजिक कियाकलाप तथा आर्थिक प्रगति तथा क्षेत्रीय सम्बन्ध गम्यता आदि प्रभावित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनपद की जनसंख्या का वितरण भौतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। क्षेत्र में जनसंख्या वितरण को ती जन–वितरण क्षेत्रों सघन, मध्ययम, विरल में विभक्त किया गया है। बड़ागांव, बबीना व मऊरानीपुर क समतल उर्वरा भूमि वाला क्षेत्र तथा नगरीया केन्द्र के आसपास का भाग इसके अन्तर्गत आता है। मध्यम व निम्न जन वितरण के अन्तर्गत कमशः मोंठ, बंगरा, गुरूसराय तथा चिरगांव व बागौर विकासखण्ड आते हैं।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार क्षेत्र में 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० निवास करते हैं। 1991 में यह घनत्व 302 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० था। जनसंख्या घनत्व के आधार पर सम्पूर्ण क्षेत्र को तीन भागों (उच्च जनघनत्व क्षेत्र : 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० निम्नतम घनत्व क्षेत्रः 200-300 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० से कम) में विभाजित किया गया। यहां पर उच्च घनत्व पाये जाने का प्रमुख कारण सघन कृषि विकास, सिंचन सुविधाओं की उपलब्धता व नगरीकरण की मात्रा अधिक होना है। क्षेत्र का कार्यिक घनत्व 455 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है। क्षेत्र में सर्वाधिक कार्मिक घनत्व झाँसी व बड़ागांव विकासखण्ड में है। झाँसी नगर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों व विभिन्न संस्थानों में रोजगार के अवसरों तथा अन्य सुविधाओं के उपलब्धता के

कारण यहां कृषिगत भूमि कम होने पर भी जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलता है। सम्पदा का विगत घनत्व 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है। सबसे अधिक कृषि घनत्व मऊरानीपुर विकासखण्ड में 213 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० तथा सबसे कम कृषि घनत्व 120 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० बामौर विकासखण्ड में पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र जनसंख्या के अधिक कारकों को वहन कर रहा है। अतः प्रगतिशील कृषि के विभिन्न तकनींकों का प्रसोग करके क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को विकसित किया जा सकता हैं। जनपद का कुल पोषण घनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है।

अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नगरीकरण की मात्रा 1901 में 15.75 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1991 में 39.61 प्रतिशत हो गई। क्षेत्र में चिरगांव, बंगरा तथा बामौर विकासखण्ड में नगरीकरण की मात्रा काफी कम है जो यह दर्शाता है कि यहां की आर्थिक संरचना कृषि प्रधान तथा परम्परागत किस्म की है व नगरीकरण प्राथमिक अवस्था में है। मोंट व गुरूसराय विकासखण्ड में भी 25-0 प्रतिशत से कम नगरीकरण की मात्रा है जिससे यह स्पष्ट है कि यहां भी प्राथमिक कियाओं का वर्चस्व है। बबीना एक छावनी केन्द्र है तथा मऊरानीपुर औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। इसलिए यहां अपेक्षाकृत नगरीकरण की मात्रा अधिक है। झाँसी नगर की महत्वपूर्ण स्थिति होने के कारण बड़ागांव में नगरीकरण की मात्रा 79.82 प्रतिशत है। आर्थिक कियाओं का यहां सर्वाधिक सकेन्द्रता है तथा कृष्णयेतर कार्यों में अधिकांश जनसंख्या कार्यरत है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में तीव्रगति से नगरीकरण में वृद्धि हुई है।

देश एवं प्रदेश की भांति झाँसी जनपद में यौनानुपात में निरन्तर गिरावट देखने को मिलती है। यहां पर प्रति एक हजार पुरूषों पर 863 स्त्रियों का पाया जाना इस तथ्य का प्रतीक है कि क्षेत्र में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। ग्रामीण

क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की तुलना में लिंगानुपात कम है। गांवों तथा नगरों में प्रति एक हजार पुरूषों पर क्रमशः 852 व 880 स्त्रियाँ पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थय सुविधाओं की कमी तथा मृत्युदर का अधिक होना है। असुरक्षित ग्रामीण परिवेश, स्त्रियों के प्रति हेय दृष्टिकोंण, सम्पन्न घरों की महिलाओं का शहरों की ओर स्थानान्तरण आदि भी यौनानुपात की कमी में सहायक है। चूंकि स्त्री व पुरूष समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। अतः पुरूषों की भांति स्त्रियों को उचित सम्मान देते हुए लिंग अनुपात में सन्तुलन बनाए रखना नितान्त आवश्यक है।

जनसंख्या संरचना को समझने का महत्वपूर्ण पक्ष वास्तव में आयु संरचना है। आयु संरचना के निम्ननिखित महत्वपूर्ण पक्ष हैं।

1 - आयु संरचना किसी जनसंख्या में पराश्रितों के अनुपात को दर्शाती है।

2 - आयु संरचना के अध्ययन से श्रम–शक्ति की औसत आयु ज्ञात की जा सकती है।

3 - समाज के उपभोग के स्वरूप के निर्धारण में आयु संरचना का महत्वपूर्ण योगदान है।

4 - आयु संरचना मृत्युदर क निर्धारण में सहायक है।

5 - आयु संरचना वैवाहिक व्यवस्था को भी निश्चित व प्रमाणित करती है।

6 - किसी देश की राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित करने में आयु संरचना का महत्वपूर्ण योगदान है।

जनसंख्या के आयु वर्ग के सामान्य वितरण के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे आयु वर्ग की ज्येष्ठता में वृद्धि होती जाती है, जनसंख्या के प्रतिशत भाग में कमी होती जाती है। यह घटोत्तरी प्रत्येक आयु वर्ग में भिन्न–भिन्न दर से

दृष्टिगत होती हैं। सम्पूर्ण जनसंख्या में 20 से 59 वर्ष की आयु के मध्य पुरूषों की संख्या 42.88 प्रतिशत तथा स्त्रियों की संख्या 43.50 प्रतिशत है। इस प्रकार इस आयुवर्ग में 0.62 प्रतिशत स्त्रियाँ अधिक हैं। ग्रामीण तथा नगरीय आयु संरचना में काफी अन्तर देखने को मिलता है। 10 से 29 आयु वर्ग में ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या अधिक है क्योंकि इस उम्र में अधिकांश ग्रामीण काम की तलाश में नगरों को चले जाते हैं। 50 वर्ष से अधिक उम्र में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक हैं। नियमित दिनचर्या, तनाव तथा दुश्चिन्ता से दूर होने के कारण स्त्रियाँ पुरूषों की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रहती हैं।

जनपद में कुल जनसंख्या का 46.29 प्रतिशत वयस्क हैं। विभिन्न नगरीय आकर्षणों से प्रभावित होकर ग्रामीण वयस्क शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। इसलिए नगरों की तुलना में ग्रामीण वयस्कों की संख्या कम है। क्षेत्र में आयुदर सूचकांक 14.69 प्रतिशत है। चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप आयुदर सूचकांक में सतत् वृद्धि हो रही है। 1991 में यहां का निर्भरता अनुपात 116.04 प्रतिशत आंकलित किया गया। शिशुओं का निर्भरता अनुपात (82.6 प्रतिशत) वृद्धों (10.7 प्रतिशत) की अपेक्षा बहुत अधिक है। बच्चों के निर्भरता अनुपात में अधिकता मुख्यतः रहन–सहन का निम्न स्तर, असफल परिवार नियोजन, आशिंक, बेरोजगार, तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की न्यूनता का प्रतीक है।

जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 51.60 प्रतिशत है। इसमें पुरूष साक्षरता 66.80 प्रतिशत व स्त्री साक्षरता 33.80 प्रतिशत है। इस प्रकार साक्षरता की उच्च दर पुरूष साक्षरता के उच्चतर दर को प्रदर्शित करती है। 35.0 प्रतिशत से कम साक्षरता के अन्तर्गत बबीना विकासखण्ड; 35-40 व 40 से 45 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत से अधिक साक्षरता के अन्तर्गत कमशः दो, तीन व दो विकासखण्ड आते हैं। प्रत्येक

विकासखण्ड में स्त्रियों की अपेक्षा पुरूष साक्षरता अधिक है। गांवों में अभी भी निर्धन बालिकाएँ उच्च शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकती। नगरों (69.40 प्रतिशत) की अपेक्षा गांवों(41.1 प्रतिशत) में साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है। इसका प्रमुख कारण गांवों में नगरों की अपेक्षा शैक्षिक सुविधाओं का अभावा माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण निर्धनों की मानसिकता है। यह भी कि पढ़ने की अपेक्षा मजदूरी करके पेट पालना ज्यादा श्रेयकर है। नगरीय केन्द्रों के समीपस्थित गांवों में साक्षरता की दर सुदूरवर्ती गांवों की अपेक्षा अधिक है क्योंकि इन गांव वासियों को शैक्षिक विकास की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध हैं। परिवार के सन्तुलित विकास क लिए नर--नारी मे भेदभाव नही समझना चाहिए। स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा नीतिगत निर्णयों में उनकी सहभागिता आवश्यक है। जिन परिवारों में साक्षरता का स्तर ऊँचा पाया गया वहां नारी की साक्षरता क उच्चतर स्तर भी देखने को मिलता है।

अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, जैन, इसाई एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। यहां की सम्पूर्ण जनसंख्या में 90.30 प्रतिशत व्यक्ति हिन्दू, 8.42 प्रतिशत मुसलमान तथा शेष धार्मिक सम्प्रदायों यथा ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि का प्रतिशत क्रमशः 0.49,0.27,0.09,0.42 तथा 0.02 है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में धार्मिक जनसंख्या के स्परूप में विविधता है। गांवों में हिन्दुओं की संख्या 94.56 प्रतिशत नगरों (83.68 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक है। मुसलमानों की संख्या गांवों (5.10 प्रतिशत) की तुलना में नगरों (13.10 प्रतिशत) अधिक है। ईसाईयों की संख्सया गांवों (0.10 प्रतिशत) की अपेक्षा शहरों (1.10 प्रतिशत) में बहुत ज्यादा है।

जनपद में 34.95 प्रतिशत क्रियाशील जनसंख्या है जिसमें 4.8 प्रतिशत सीमान्तिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या है। सीमान्तिक क्रियाशील के अन्तर्गत मुख्यतः मौसमी श्रमिक आते है। क्रियाशील जनसंख्या में 46.55 प्रतिशत कृषक, 15.60 प्रतिशत

कृषक मजदूर, 3.45 प्रतिशत उद्योग एवं निर्माण कार्य में कार्यरत तथा 34.40 प्रतिशत जनसंख्या अन्य व्यवसायों यथा–पशुपालन, बागवानी, खनन कार्य, व्यापार व वाणिज्य, यातायात, संग्रहण, संचार तथा अन्य सेवा कार्यो में संलग्न है। इस प्रकार झाँसी जनपद में प्राथमिक व्यवसायिक वर्ग में कृषि महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं।

वस्तुतः जनसंख्या का उसके वकास स्तर से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः जनसंख्या एवं सीमित साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियन्त्रण हो । जनसंख्या नीति वस्तुतः एक समाजिक नीति होती है। जिसका प्रभाव सम्पूर्ण सामाजिक स्वरूप पर पड़ता है। शासन ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समय–समय पर जसंख्या नीति की घोषणा की व इसे कियान्वित किया लेकिन अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। नवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियन्त्रण के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रसार पर भी बल दिया गया ताकि उपचारत्मक तथा निरोधक माध्यमों का अधिक सार्थक रूप से लागू किया जा सके। फरवरी 2000 में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना बनाई गई जो निम्नाकिंत है–

1 - 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करना।

2 - प्रति हजार बच्चों पर शिशु मृत्युदर 30 से कम करना।

3 - जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भ का पंजीयन कराना।

4 - एड्स का प्रसार रोकना।

5 - संकामक रोगों को रोकना।

6 - शिशु मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख सन्तानों में एक सौ से कम करना।

7- सभी को सूचना, परामर्श तथा जनन क्षमता नियमन की सेवाएँ तथा गर्भ निरोधकों के विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराना।

निसन्देह जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु शासन स्तर से विविध प्रयास किए गए जिसके परिणामस्वरूप परिवार–आकार के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है फिर भी इस दिशा में सफलता काफी सीमित हैं। वास्तव में जनसंख्या पर नियन्त्रण तभी सम्भव है व जनसंख्या नीति तभी सार्थक सिद्ध होगी जब सरकार और जनता दोनों मिलकर इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाए। यह कदम कार्यक्रमों की पारदर्शिता से ही सम्भव हा सकेगा।

जनसंख्या में तीव्र वृद्धित्र, परिसम्पत्तियों का असमान वितरण, अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि, पूंजी प्रधान प्रविधियों पर जोर, कृषि कार्य की मौसमी प्रवृत्ति, श्रमिकों की गतिशीलता में कमी आदि कारणों से शोध क्षेत्र के अन्तर्गत बेरोजगारी में सतत् वृद्धि हो रही है। सर्वेक्षण बताता है कि क्षेत्र में केवल 23.4 प्रतिशत परिवारों के सदस्य अपने गांव के छोड़कर अन्यत्र वैकल्पिक रोजगार की खोज में जाने के इच्छुक पाए गए। लघु किसान परिवारों के 49.8 प्रतिशत लोग काम की तलाा में बाहर जाने के लि लालायित पाए गए। बेरोजगारी की सर्वोच्चदर (36.77 प्रतिशत) स्नातक तथा इससे अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में पायी गई, जबकि अशिक्षित व्यक्ति में बेरोजगारी की दर मात्र 3.97 प्रतिशत पायी गई। रोजगार कार्यालय में रोजगार हेतु पंजीकृत शिक्षित अभ्यर्थियों में मात्र 1.85 प्रतिशत अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हो सका, जो बहुत कम है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शासन ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लि अनेक कार्यक्रम कियान्वित किए किन्तु समस्या हल होने का नाम ही नहीं लेती। यदि निम्नलिखित क्षेत्रों में उपचारात्मक प्रयास किए जाय जो बहुत हद तक

सफलता प्राप्त हो सकती है।

1 - कृषि व उससे सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुविधाओं का प्रसार व सुधार कर रोजगार में वृद्धि।

2 - ग्रामीण गैर कृषि रोजगार यथा–ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्राम सड़क, भवन निर्माण तथा कृषि सेवा केन्द्रों का विकास, ग्रामीण औद्योगीकरण का विकास रोजगार में सहायक है।

3 - भूमि सुधार अनुत्पादक भूमि को सुविधायुक्त बनाकर कमजोर वर्गों को आवंटित करना।

4 - स्थानीय संसाधनों, आवश्यकताओं तथा स्थानीय लोगों की अनुकूल अनुक्रिया को ध्यान में रखकर ग्रामीण योजनाओं का क्रियान्वयन।

5 - श्रम की मांग तथा पूर्ति का स्थानिक स्तर पर गहन सर्वेक्षण के माध्यम से आंकलन।

6 - रोजगार तथा व्यवसाय मूलक शिक्षा प्रणाली।

7 - प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाओं का समान्वित रूप से तीव्र विकास आदि।

परिवार नियोजन वास्तव में परिवार का, परिवार के लिए, परिवार के द्वारा एक योजना है। पारिवारिक सुख–समृद्धि तथा जनसंख्या नियन्त्रण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । हालांकि परिवार नियोजन कार्यक्रम के सफल संचालन में अशिक्षा, भाग्यवादी दृष्टिकोण, बाल विवाह धार्मिक कट्टरवादिता आदि अनेक बाधाएँ हैं लेकिन शिक्षा के व्यापक प्रसार से इस महत्वपूर्ण योजना को सफलता मिल सकती है। सर्वेक्षण बताता है कि नियोजन कार्यक्रम पर जातीयता, शिक्षा एवं आयु

स्तर का प्रभाव परिलक्षित होता है। जातीयवर्ग के आधार पर नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन क सम्बन्ध में प्रोत्साहन वर्ग के अन्तर्गत ठाकुरों, ब्राह्मणों एवं वैश्यों क प्रमुख स्थान है जबकि हतोत्साहित वर्ग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का स्थान आता है। तटस्थ का भाव सबसे अधिक मुसलमानों में पाया गया।

कम उम्र के लोग अधिक सन्तान से बचने के लिए नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन कराने वालों को अधिक प्रोत्साहित करते हैं जबकि अधिक आयु वाले कम जाति, आयु एवं शिक्षा के आधार पर सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि अधिक सन्तान से बचने के लिए 50.0 प्रतिशत से अधिक लोगों की राय नसबन्दी/नलबन्दी कराने के पक्ष में है। अशिक्षितों से शिक्षितों का पक्ष नसबन्दी/नलबन्दी करानेमें अधिक पाया गया। हिन्दुओं में अनुसमचित जाति/जनजाति तथा गैर हिन्दुओं में मुसलमान नसबन्दी/नलबन्दी आपरेशन के मामले में पीछे पाए गए।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति लोगों के विश्वास के मामले में ज्ञात हुआ कि कम उम्र वाले उत्तरदाता 68.0 प्रतिशत विश्वास रखते है। परिवार नियोजन पर विश्वास न रखने वाले अधिकांशतः सामाजिक कारण से विश्वास नहीं रखते। इसके बाद आपरेशन के असफल होने के डर से अचित चिकित्स व्यवस्था का अभाव, शारीरिक कमजोरी तथा धार्मिक कारणों का भी विश्वास न रखने वालों पर प्रभाव पड़ता है। अतः लोगों के मन से इन आशंकाओं व चिकित्सीय कमियों को मिटाने व सुधारने की आवश्यकता है।

वस्तुतः जनसंख्या तथा संसाधन परस्पर सम्बन्धित है। वैसे संसाधन तथा जनसंख के मध्य पूर्ण सन्तुलन स्थापित करना एक कठिन कार्य है लेकिन जनसंख क अनुकूलतम होन सम्भव है। अनुकूलतम जनसंख्या, जनाधिक्य व कम जनसंख्या पर विचार करते हुए जनसंख्या–संसाधन के विभिन्न सिद्धान्तों का विश्लेषण कर

सैद्धान्तिक पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इन सिद्धान्तों में माल्थस, सैण्डलर, डब्बलडे, हेनरी जार्ज, डेविड रिकार्डो, मार्क्स आदि प्रमुख हैं।

निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप जनसंख्या–संसाधन में असन्तुलन व्याप्त है। भूमि पर जनसंख्या का दबाब निरन्तर बढ़ रहा है। अशिक्षा व गरीबी के कारण लोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में असमर्थ है। यहां के व्यक्तियों के भोजन में पोषण तत्वों की कमी होती है। मुख्यतः अन्न का इस्तेमाल भोजन में करते हैं। यही कारण है कि यहां के निवासी अधिकतर बीमार रहते हैं तथा उनकी कार्यक्षमता अपेक्षाकृत कम होती है।

जनसंख्या का आंकिक घनत्व, वृद्धि दर, कृण्येतर कार्यों में लगी जनसंख्या, साक्षरता तथा नगरीकरण के आधार पर मानक सूचकांक ज्ञात करने पर क्षेत्र को तीन जनसंख्या संसाधनों प्रदेशों (गयात्मक, सामान्य व समस्यात्मक) में बांटा गया है। गत्यात्मक प्रदेश के अन्तर्गत बड़ागांव विकासखण्ड आता है जिसमें झाँसी नगर समूह, बड़ागांव विकासखण्ड आता है जिसमें झाँसी नगर समूह, बड़गांव व बरूआसागर नगरीय केन्द्र सम्मिलित हैं। सम्भाव्य प्रदेश के अन्तर्गत पाँच विकासखण्ड (मोंठ, बंगरा, मऊरानीपुर, बबीना व चिरगांव) तथा समस्यात्मक प्रदेश में बामौर व गुरसंराय विकासखण्ड सम्मिलित हैं।

झाँसी जनपद के जनसंख्या नियोजन हेतु कृषि उत्पादन में सुधार, औद्योगीकरण, शैक्षिक विकास, आश्रित जनसंख भार में कमी शासन द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों में पारदर्शिता एवं जनता की सहभागिता आदि कारकों पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है। यहा की जनसंख्या अधिकांश भाग परम्परागत कृषि पद्धति पर आधारित है तथा औद्योगिक विकास की कमी है। अस्तु क्षेत्र के अधिकांश अविकसित समाज को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगीकरण का विकेन्द्रीकरण

ग्राम्य स्तर पर लघुउद्योगों का विकास किया जाय। साथ ही कृषि में तकनीक का अधिक प्रयोग करके खाद्यान्न उत्पादन पर बल दिया जाय। इस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का ढांचा प्रस्तुत कर यहां के अविकसित कृषि समाज की जनसंख्या समस्या को हल किया जा सकता है और तभी जनपद का चहुँमुखी विकास हो सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परिवार नियोजन सम्बन्धी जनसंख्या नियन्त्रण की नीति बनानी चाहिए, इस हेतु यहाँ कुछ सुझाव प्रस्तावित है।

(1) शासकीय कर्मचारियों पर इस बात के लिए दबाव डाला जाय कि इनके अधिकतम दो ही बच्चे हो।

(2) स्कूल कालेजों तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रो, आंगनवाड़ी व अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी पाठ्यक्रम की विशेषरूप से व्यवस्था की जाय। समय–समय पर इनका निरीक्षण किया जाय तथा उदासीन अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय।

(3) परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति समर्पित व्यक्तियों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए परिचय पत्र बनाए जाय। परिचय पत्र दिखाने पर उन्हें उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्तुओं को प्राथमिक से प्रदान किया जाय।

(4) राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों का पर्याप्त मात्रा में प्रचार व प्रसार किया जाय।

(5) मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान की जाय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो / उपकेन्द्रों को हर दृष्टि से प्रभावशाली बनाया जाय।

(6) लड़कों एवं लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक आयु कम से कम क्रमशः 25 व 21 वर्ष की जाय तथा इसका कड़ाई से अनुपालन कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

(7) स्वास्थ्य विभाग के अलावा सभी विभागों को जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के उपायों को जन–जन तक पहुँचाने में लगाया जाय, लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने के लिए किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न की जाय।

(8) परिवार नियोजन अपनाने वाले निर्धन व कमजोर किसानों को सन्तोष प्रद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त ऋण के व्याजदर में कम से कम 1 प्रतिशत की कमी की जाय।

(9) लड़का–लड़की को समान दर्जा दिलाने का प्रयत्न किया जाय। उनके खान–पान व अन्य व्यवस्था में कोई विभेद न रखा जाय।

(10) पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा परिवार नियोजन का अत्यधिक मात्रा में प्रचार–प्रसार किया जाय। जिन गांवों में साक्षरता व परिवार नियोजन में लक्ष्य के अनुकूल सफलता मिले उसे आदर्श गाँव का दर्जा देकर अत्यधिक विकसित किया जाय।

परिशिष्ट

परिशिष्ट - अ

झाँसी जनपद के निवासियों का प्रजननता रोजगार व परिवार नियोजन के प्रति दृष्टिकोण ज्ञात करने

के लिए प्रश्नावली :

1 (i) उत्तरदाता का नाम :.............................. उम्र :....................

(ii) गाँव/नगर :..................... तहसील :..................................

विकासखण्ड :..

(iii) आयु :.................... स्थान विशेष में निवास की अवधि :.............

(iv) धर्म :................................. जाति :..............................

(v) वैवाहिक स्थिति :

(i) विवाहित (ii) अविवाहित

(iii) तलाकशुदा (iv) परित्यक्त

(vi) शैक्षणिक स्तर :

(i) शिक्षित (ii) अशिक्षित

(vii) अन्तिम शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है?

(viii) व्यवसाय :

(i) कृषि (ii) नौकरी (iii) व्यापार

(iv) निजी व्यवसाय (v) मजदूरी (vi) अन्य

(ix) व्यवसाय निजी है/ सरकारी, कृपया स्पष्ट करें।

(i) क्या आप सरकारी नौकरी में हैं -

(ii) व्यवसाय का स्तर कैसा है-

(iii) व्यवसाय/ नौकरी से आमदनी कितनी हो जाती है-

(x) रोजगार की स्थिति ज्ञात करने सम्बन्धी प्रश्न :

(i) आपके घर में कितने व्यक्ति रोजगार प्राप्त है। पुरुष......स्त्री.....
(ii) रोजगार का स्तर कैसा है
(iii) क्या आप शिक्षित रोजगार हैं
(iv) क्या आप अशिक्षित रोजगार हैं
(v) आपके घर में बेरोजगार कितने हैं
(vi) रोजगार न मिलने का कारण
(vii) बेरोजगारी के सम्बन्ध में अपने विचार बताएँ

2. **आपके पास कितनी भूमि है** :.......................................

3. भूमि की किस्म कैसी है :..

4. आपकी वार्षिक आय क्या है : ....

5. **पारिवारिक स्थिति** :

(i) एकाकी परिवार (ii) संयुक्त परिवार (iii) अन्य

6. **परिवार के सदस्यों की कुल संख्या** :

(i) पुरूष (ii) स्त्री (iii) बच्चे

7. **परिवार के मुखिया का नाम** :.......................................

8. **विवाह की उम्र क्या है** : ....

9. **आपके कुल कितनी सन्ताने हैं** :

(i) जीवित लड़के (ii) मृत लड़के
(iii) जीवित लड़कियाँ (iv) मृत लड़कियाँ

10. प्रथम प्रसव के समय पत्नी की आयु : ....

11. द्वितीय प्रसव के समय पत्नी की आयु : ....

12. तृतीय प्रसव के समय पत्नी की आयु : ....

13. अन्य प्रसवों के समय पत्नी की आयु : ....

14. सन्तानों के मध्य समयान्तर : ....

15. आपके विचार में बच्चों के मध्य कितना समयान्तर होना चाहिए :

16. आपके मतानुसार आदर्श परिवार में सन्तानों की संख्या :

17. आपको क्या परिवार नियोजन के विषय में जानकारी है

18. यदि हाँ तो जानकारी का माध्यम बताइए : ....

19. क्या आप परिवार नियोजन की कोई विधि अपनाते हैं : ....

20. आपके मत में परिवार नियोजन का कौन सा साधन ठीक हैं : ....

21. क्या आप गर्भ निरोधक का प्रयोग करते हैं :

(i) नियमित (ii) अनियमित

22. आपके विचार में परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने में क्या कठिनाई है :.....

23. आप परिवार नियोजन क्यों अपनाते हैं :

(i) आर्थिक कारणों से, (ii) स्वास्थ्य सम्बन्धी करणों से,
(iii) जीवन स्तर बनाए रखने के कारण।

24. क्या आप परिवार नियोजन कार्यक्रम पर विश्वास करते हैं : ....

25. यदि विश्वास नहीं करते तो क्यों :

(i) आर्थिक/धार्मिक/सामाजिक
(ii) अस्पताल सुविधा का अभाव
(ii) चिकित्सीय व्यवस्था का ठीक न होना।
(iv) चिकित्सक/नर्स का व्यवहार अनुकूल नहीं।
(v) अन्य कारण

26. क्या आप कभी परिवार नियोजन केन्द्र गए हैं : ....

27. परिवार नियोजन के सम्बन्ध में क्या कभी आप परिवार में बैठकर बात करते हैं :

28. पत्नी से इस सम्बन्ध में कभी विचार-विमर्श किया है : ....

29. क्या आपरेशन कराने पर कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है : ....

30. आपरेशन कराने पर धन के अलावा क्या भूमि आदि भी मिली है : ....

31. परिवार नियोजन के प्रचार-प्रसार से आप कहाँ तक सन्तुष्ट हैं : ....

32. क्या आप परिवार नियोजन का अर्थ समझते हैं : ....

33. परिवार नियोजन के कौन से नारे आपको अधिक प्रभावित करते हैं : ......

34. क्या कम सन्तान होना धर्म के विपरीत हैं : ....

35. प्रजनन/परिवार नियोजन में शिक्षा का क्या प्रभाव है :.....................

36. प्रजनन/परिवार नियोजन में व्यवसाय का क्या प्रभाव है : ....

37. प्रजनन/परिवार नियोजन में मनोरंजन के साधनों का क्या प्रभाव है : ......

38. जनसंख्या वृद्धि के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं : ....

39. परिवार नियोजन के सम्बन्ध में आपके क्या विचार है : ....

40. जनसंख्या नीति के सम्बन्ध में अपने विचार बताएँ : ....

41. अन्य विचार/सुझाव : ....

परिशिष्ट (ब)

जनसंख्या का दशकीय अन्तर

तहसील/जनपद	कुल जनसंख्या 1901	कुल जनसंख्या 1911	दशकीय अन्तर 1901-1911	कुल जनसंख्या 1921	दशकीय अन्तर 1911-1921	कुल जनसंख्या 1931	दशकीय अन्तर 1921-1931
मोंठ	55638	55009	-629	50259	-4750	55482	5223
गरौठा	66963	72626	6663	76462	3837	85035	8573
मऊरानीपुर	100298	104278	3980	97440	6835	102106	4663
झाँसी	145371	166939	21568	149953	16986	175181	25228
योग जनपद	**368270**	**398852**	**30582**	**374114**	**24738**	**417804**	**43690**

परिशिष्ट (ब)
जनसंख्या का दशकीय अन्तर

तहसील/जनपद	कुल जनसंख्या 1941	दशकीय अन्तर 1931-41	कुल जनसंख्या 1951	दशकीय अन्तर 1941-51	कुल जनसंख्या 1961	दशकीय अन्तर 1951-1961
मौंठ	99801	44319	102663	2862	132792	20129
गरौठा	115362	30317	108668	-6674	134424	25936
मऊरानीपुर	109439	7333	113260	3821	145703	32443
झाँसी	198984	23803	232642	33658	301565	68923
योग जनपद	**523586**	**105782**	**557233**	**33647**	**714484**	**157251**

परिशिष्ट (ब) क्रमशः
जनसंख्या का दशकीय अन्तर

तहसील/जनपद	कुल जनसंख्या 1971	दशकीय अन्तर 1961-71	कुल जनसंख्या 1981	दशकीय अन्तर 1971-81	कुल जनसंख्या 1991	दशकीय अन्तर 1981-1991
मोंठ	174065	41273	216460	42395	264807	48347
गरौठा	171011	36587	209448	38437	248978	39530
मऊरानीपुर	182229	36526	231683	49454	293860	62177
झाँसी	342833	41268	479440	136607	622053	142613
योग जनपद	**870138**	**155654**	**1137031**	**266893**	**1429698**	**292667**

BIBLIOGRAPHY

BIBLIOGRAPHY

Books

Ackerman, E.A. (1959), "Geography and Demography" in The Study of Population - An Inventory and Appraisal, Edited by Philip M. Heuser and O.D. Duncon, University Press Chicago.

Agrawala, S.N. (1972), "India's Population Problems", Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., Bombay.

Agrawala, S.N. (1967), "India: The Land and People ", National Book Trust, New Delhi.

Agrawala, S.N. (1977), "Population", National Book Trust, India, New Delhi.

Ahmad, A. (1984), "Agricultural Stagnation Under Population Pressure: A Case Study of Bangladesh," Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi.

Andrei Rogers (1984), "Migration Urbanisation and Spatial Population Dynamics", Westview Press.

Aurousseau, M. (1923), "The Geographic Study of Population Groups", New York.

Barclay, G.W. (1938), "Techniques of Population Analysis", John Willey and Sons Inc., New York.

Beaujeu,G.J. (1961),"Population Geography", Longman, London.

Benjamin, B.P.R.,Cox and J. Peel (Eds. 1973),"Resources and Population", London.

Bhande, Asha A. and Kanitkar, Tara (1978), "Principles of Population Studies", Himalaya Publishing House, Bombay.

Bhattacharjee, P. J. and Shastri, G.N. (1976), "Population in India", New Delhi.

Bhattacharjee, A. (1978), "Population Geography of India", Shree Publishing House, New Delhi.

Bhawmik, K.L. (Ed. 1978),"Population Studies in Developing Nations", Society and Culture.

Bhende, A.A. And Tya, K.K. (1982), "Principles of Population Studies", Himalaya

Publishing House, Bombay.

Bogue, D.I. (1959),"Internal Migration" in The Study of Population: An Inventory and Appraisal, Edited by P.M. Hauser and O.D. Duncan, Chicago University Press.

Bogus, D.L. (1969), "Principle of Demography", John Willey & Sons, New York.

Borrie, W.D. (1970),"The Great Migration in the Growth and Control of Population", Weidenfield and Nicholson, London.

Bose, A. and Others (Eds. 1977), "Population Statistics in India", Vikas Publishing House, Delhi.

Bose, A. (1978), "Studies in India's Urbanisation 1901-71," Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., Bombay.

Bose,A. and Others (Eds. 1974), "Population in India's Development 1947-2000", Vikas Publishing House,Delhi.

Bose,A. (Ed. 1967), "Pattern of Population Change in India, 1951-61", Allied Publishers, Bombay.

Caroline, H. Bledsoe et al. (Eds.) 1999, Critical Perspectives on Schooling and Fertility in the Developing World, National Academy Press, Washington.

Cassen, R.H. (1978), "India: Population, Economy and Society", MacMillan Co., India.

Chandrasekhar, S. (1972), "Infant Mortality, Population Growth and Family Planning in India", George Allen and Unwin Ltd., London.

Chandrasekhar, S. (1979),"India's Population: Fact Problems and Policy", Allied Publishers, Bombay.

Chandna, R.C. (1986),"A Geography of Population", Kalyani Publishers, New Delhi.

Chandna, R.C. (1994), Jansankhya Bhoogol, Kalyani Publishers, Ludhiyana.

Chandna, R.C. & Sidhu, M.S. (1980), Introduction to Population Geography, Kalyani Publishers, New Delhi.

Clarke, J.I. (1965, 2nd edi. 1972), "Population Geography", Pergamon Press. New York.

Clarke, Colin (1968), "Population Growth and Land Use", MacMillan, Company, India.

Clarke, J.I. (1971), "Population Geography and the Developing World", Pergamon Press, Oxford.

Clarke, J.I. (1972), "Population Geography", Pergamon Press, Oxford, Second Edition.

Coale, A.J. and Hoover, A.M. (Eds. 1958), "Population Growth and Economic Development in Low Income Countries", Princeton University Press, Princeton.

Connell, J. and Others (Ed. 1976), " Migration from Rural Areas", Oxford University Press.

Cox, P.R. (1966), " Demography", The Cambridge University Press.

Dandekar, K. (1959), "Demographic Survey of Six Rural Communities", Bombay, Asia Publishing House.

Davis, K. (1951), "Population of India and Pakistan", Princeton University Press, Princeton.

Davis, K. (1963), "Social and Demographic Aspects of Economic Development in India", Edited by Simson Kuznets et al. Duke University Press, Durham.

Desai, P.B. (1975), " A Survey of Research in Demography", Popular Prakashan. Bombay.

Demko, George, I. et al. (1970), Population Geographhy: A Reader, Mc Graw-Hill Book Company, New York.

Dichinson, R.E. and Howarath, O.J.R. (1951), "The Making of Geography", Hutchinson's University Library, London.

Donald, J.B. (1969), "Principles of Demography", John Willey & Sons, New York.

Dutt, G.K. and Bhattacharya, N.D. (Eds. 1985), "Profiles of Population-A Selected Bibliography on Population, NATMO, Calcutta.

Dubey, R.N. (1992), Population, Environment and Regional Planning, Chugh Publications, Allahabad.

Duncan, E.R. (1977), Dimensions of world Food Problem, The Iowa State University Press, Iowa.

Forde, C.D.(1953) Habitat, Economy and Society, London.

Frinch and Triwartha, G.T. (1968), "Elements of Geography (Physical and Cultural)",

London,pp. 56-58.

Fuller, G. (Ed.1978), " Curriculum Guide for Population Geography", East-West Population, Hawii, pp.19-25.

Garnier, J.B. (1978) Geography of Population, Longman, London.

George, W.B. (1958), "Techniques of Population Analysis", John Wiley and Sons, New York.

Haggett, P. (1972), "Geography: A Modern Synthesis", Harper and Row, New York.

Hans, Raj (1978), "Fundamentals of Demography, Population Studies with Special Reference to India", Surjeet Publication, Delhi.

Harrison G.A. & Boyce A.J. (1972), The Structure of Human Population, Elarendon press, oxford, 1972.

Hauser, P.M. and Duncan, O.D. (Eds. 1959), "The Study of Population Geography", University Press, Chicago.

Hauser, P.M. (1961), "Population Perspectives", New Brunswick N.J., Rutgers University Press.

Henery, L. (1976), "Population Analysis and Models", Willner Brothers Ltd., Great Britain.

Hsu, Mei Ling (1973), "Cartographic Application in Population Studies", in Population Mapping, Edited by I.B.F. Kormoss and L.A. Burges Monsinski.

Husain Ishrat.Z. (1972), Population Analysis and Studies, Samaya publications Pvt. Ltd., India Year Book, 1990-91.

Jain, S.P. (1975),"Demography-AStatus Study of Population Research in India", Vol. II, Tata, McGraw-Hill, Publishing Company, New Delhi.

Jana, M.M. (1990), Population Planning and Regional Development in India, Chugh Publications, Allahabad.

Jain, S.P. (1977), "Indian Population and Development",National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

James, P.E. (1954), "The Geographic Study of Population, in American Geography-Inventory and Prospects, Edited by P.E. James and C.F. Jones, Association of American Geographers, University Press, Syracuse, pp. 106-122.

Johnston, R.J. (1978), Multivariate Statistical Analysis in Geography", Longman, London.

Jones, D.L. (1975), "People Populating", Faber & Faber, London.

Jones, H.R. (1981), "A Population Geography", Harper and Row, London.

Kohan, C.F. (1954), "Settlement Geography" (Ed.) An American Geography : Inventory and Prospects, Syracuse, P. 125.

Lal, H. (1986), " Jansankhya Bhoogol", Vasundhara Prakashan, Gorakhpur.

Lal, K.M. (1988), "Population Settlements Development and Planning", Chugh Publication, Allahabad.

Lee. E.S. (1958), "A Theory of Migration : Population Geography : A Reader", p. 290.

Mahto, K. (1974), "Pattern of Population Growth in Bihar ", Geographical Research Centre, Patna, Vol. 2.

Malthus, T.R. (1978), "An Essay on Principles of Population, as it Affects the Future Improvement of Society, First Eassay on Population", London, MacMillan, 1966.

Mamoria, C.B. (1961), "India's Population Problems", Kitab Mahal Pvt. Ltd.

Mnkhouse, F.J. (1952), "Population Maps and Diagrams", Matheun, London.

McGaugh, M. (1970)," A Geography of Population and Settlement", Brown, Dubugue, Iowa, West, Columbia.

Mehta, B.C. (1978), "Regional Population Growth-A Case Study of Rajasthan", Research Books, Jaipur.

Misra, Krishna Kumar (1994) Adhivas Bhoogol, Kusum Prakashan, Atarra.

Misra, H.N. (Edit.), (1987),Rural Geography, Contributions to Indian Geography, Vol. IX, Heritage Publishers, New Delhi.

Misra, R.P. (1988), Research Methodology: A Handbook., Concept Publishing Company, New Delhi.

Mishra, R.N. (1977), "The Lower Ganga-Ghaghra Doab: A Study in Population and Settlement", Sahitya Bhawan, Agra.

Mitra, A. (1978), "India,s Population: Aspects of Quality and Control", Abhinav Publication, New Delhi.

Mohammad, A. (1986), "Food and Nutrition in India", Rajesh Publications, New Delhi.

Monkhouse, F.J. and Wilbinson,H.R. (1972), "Maps and Diagrams", Mathuen & Co., Ltd., London.

Mukerjee,A.B. (1968), "Spatial Patterns of Literacy in Andhra Pradesh, India", Selected Papers, 21st International Geographical Congress.

Newell, C. (1988), Methods and Models in Demography, London, Belhavon.

Nortman, D.L. (1982), "Family Planning Programmes : The Population Council", New York.

Ojha, R. (1983), " Jansankhya Bhoogol", Pratibha Prakashan, Kanpur.

Paterson, W. (1969), Readings in Population", New York.

Rafiullah, S.M. (1983), "Regional Analysis of Population Structures," Concept Publishing Company, New Delhi.

Raj, H. (1986), "Population Studies", Surjeet Publications, New Delhi.

Rao, V.K.R. (1982), "Food Nutrition and Poverty in India", Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi.

Roy, B,K, (1980), "Geographic Distribution of Internal Migration of India", Census of India, New Delhi.

Schultz, T. Paul (Ed.), 1998, Economic Geography, Cheltenhan, U.K. Edward Elgar, 2 Vols.

Saxena, G.B. (1971), "Indian Population in Transition", Commercial Publication Bureau, New Delhi.

Sharma, R.C. (1975), "Population Trends, Resources and Environment: Hand Book of Population Education", Dehli.

Sharma, R.N. and Sharma, R.K. (1983),"Demography and Population Problem", Rajhans Prakashan Mandir, Meerut.

Siddique, F.A. (1984), "Regional Analysis of Population Structure - A Study of U.P., India", Concept Publishing Company, New Delhi.

Singh,B. (1947), "Population and Food Planning in India", Hind Kitab Ltd., Bombay.

Singh, H.P. (1971), "Resource Appraisal and Planning in Inidia", Rajesh

Publications, New Delhi.

Sinha, V.C. (1979), "Dynamics of India's Population Growth", National Publishing House, New Delhi.

Smith, T. Lyon (1960), "Fundamentals of Population Studies", Lippincott, New York.

Srinivasan, K. and Mukerji, S. (1981), "Dynamics of Population and Family Welfare (Ed.), Himalaya Publishing House, Bombay.

Taylor, P.J. (1977), "Quantitative Methods in Geography", Hughton Milton Co., Boston.

Thomlinson, R. (1965), "Population Dynamics, Causes and Consequences of World Demographic Changes", New York, Random House.

Thompson, W.S. (1951), "Population Progress in Far East", London, p. 54.

Thompson, W.S. and Lewis, D.T. (1965), "Population Problems", McGraw-Hill Book Co., New Delhi.

Tilara, K.S. (1979), "Principles of Demography (Hindi)", Publishing Centre Daliganj Railway Crossing, Sitapur Road, Lucknow, p. 163.

Trewartha, G.T. (1969), "Geography of Population: World Pattern", John wiley & sons, Inc. , New York, p. 137.

UNICEF (1998), The State of World's Children, Oxford University Press.

Valentey, D.I. (1978), "The Theory of Population", Progess Publishers, Mascow.

Vatsala, N. and Prukasan, C.P. (1983), "Population Policy Perspectives in Developing Countries", Himalayas House.

Verma, D.N. (1992), Population Patterns, The Institute of Geographers, India, Lucknow.

Verma, K.K. 1977., "Culture, Ecology and Population," National Publishing House, New Delhi.

Webb, J.W. (1969), "Population Geography",in Trends in Geography: An Introductory Survey, Edited by R.W. Cook and J.H. Johnson, Pergamon Press, London, pp.90-91.

Wilson, M.G.A. (1968), "Population Geography", T. Nelson. Melbourne.

Wood, R. (1979), "Population Analysis in Geography", Longman, London.

Wrigley, E.A. (1967), "Geography and Population", in Frontiers in Geographical Teaching, Edited by R.J. Chorley and P. Haggett, Methuen, London, pp. 62-80.

Wrong, D.H. (1967), "Population and Society", Random House, New York.

Zelinsky, W. (1966), " A Prologue to Population Geography", Prentice Hall, Englewood, Cliffs, N.J.

Articals

Ahmad, K.S. (1956), "Environment and Distribution of Population in India", I.G.J., Vol. XV,

Bhatt, L,S. (1961), "Population Studies - Need for Regional Approach", Bombay Geographical Magazine, Vol. 8-9.

Brush, J.E. (1968), "Spatial Pattern of Population in Indian Cities", Grographical Review, Vol. 58.

Coale, A.J. and Tye, C.Y. (1961), "The Significance of Age Patterns of Fertility in High Fertility Population" Milbank Memorial Fund, Qurterly No. 39(4), pp. 631-646. Coulson, R.C. (1968)," The Distribution of Population", A.A.A. Geographers, Vol. 58

Dayal, P. (1959), "Population Growth and Rural-Urban Migration in India, N.G.J.I. V. Pt. 4, Dec., pp. 179-185.

Franklin, S.H. (1956), "The Pattern of Sex-Ratio in New-Zealand", Economic Geography, Vol. 32.

Gosal, G.S. (1958), "The Occupational Structure of India's Rural Population: A Regional Analysis", N.G. J. I., Vol. 4, Pt. 3, pp. 137-148.

Gosal, G.S. (1961), "Literacy in India- An Interpretative Study", Rural Sociology, Vol. 29, pp. 262-277.

Gosal, G.S. (1961), "Internal Migration in India- A Regional Analysis", Indian Geographical Journal, Madras, 36, pp. 106-121.

Gosal, G.S. (1961), "Regionalism of Sex-Composition of India's Population", Rural Sociology, Vol. 26, pp. 122-157.

Gosal, G.S. (1962), "Regional Aspects of Population Growth in India", Pacific View Point, Vol. 3. pp. 87-99.

Gosal, G.S. and Krishnen, G. (1965), "Occupational Structure in Rural Punjab 1961", Indian Geographical Journal, Madras. Vol. 40.

Gosal, G.S. (1970), "Demographic Dynamism and Increasing Pressure of Population on Physical and Social Resources of Punjab" in Geography and A Crowding World, Edited by Wilbur Eelinsky and Others, Oxford University Press, New York.

Grigg, D. (1969), " A Note on World Population Distribution", J.G.A., Vol. 54.

Hoosen, D.J.M. (1960), "The Distribution of Population as the Essential Geographical Expression", Canadian Geographers, 17, pp. 10-20.

Kayastha, S.L. (1960), "Occupational Structure in Himalayan Beas Basin, N.G.S.I., Vol. VI, P. 1, pp. 14-18.

Khan, M.N. (1956), "Distribution of Population in Allahabad District, N.G.S.I., Vol. II. Pt. 4, pp. 213-216.

Krishnan, Gopal (1965), "Some Aspects of Population Growth in India 1961-71", Pacific Viewpoint, 16, pp. 207-215.

Krishnan, Gopal (1968), "Distribution and Density of Population in Orissa", N.G.J.I., Vol. 14, Pt. 4, pp. 250-257.

Lal, Hira (1979), "Population Potential and Spatial Distribution of Population in Eastern Uttar Pradesh", N.G.J. I., Vol. XXV, pt. 2, pp. 112-117.

Mamoria, C.B. (1957), "Growth of Population in India", Geog. Rev. of India, Dec. Vol. XIX, No. 4.

Mehta, S. (1978), "Population Regions: A Case Study of the Bist Doab (Punjab)", Manpower Journal, Vol. 9.

Pandey, O. (1941), "Techniques of Population Study", I.G.J., Vol. XVI, pp. 268-286.

Rai J.P. (1981), "Jansankhya Vishleshan: Bihar Ka Ek Pratik Adhyayan", Uttar Bharat Boogol Patrika, Gorakhpur, Vol. XVII, Pt. 2, pp. 122-128.

Reddi, N.B.K. (1970), "Urban Evolution Growth, Pattern and Urbanization Trends in the Krishna and Godavari Deltas", N.G.S.I., Vol. XVI, Pt. 3 & 4, p. 271.

Roy, B.K. (1979), "Internal Migration in India's Manpower Resources", N.G.J.I., Vol. XXV, Pt. 1, pp. 8-21.

Sen, J.C. (1963),"The Sex Composition of the Population of India", The Decean

Geographers, Vol. II.

Shastri, G.M. (1942), "An Appraisal of Population", I.G.J., Vol. XVII, pp. 110-114.

Siddiqui, F.A. (1978), "Agricultural Density and its Changing Pattern in Uttar Pradesh", The Geographers, Jan., Vol. XXV, No.1.

Singh, Onkar (1970), "Distribution and Growth of Population in Uttar Pradesh, India", The Geographical Viewpoint, Oct., pp. 25-38.

Singh, R.L. (1947), "Trend in Growth of Population in U.P. ", Bulletin of N.G.S.I., Varanasi, p.3.

Singh, R.L. (1956), "The Trend of Urbanisation in the Unland of Banaras", N.G.J.I., Vol. II, pt. 2.

Singh, S.P. (1959), "Population Growth and Rural-Urban Migration in India", N.G.J.I., Vol. V, Pt. 3, pp. 157-175.

Singh, U. (1958), "Demographic Structure of Allahabad", N.G.J.I. Vol. IV, Pt. 4, pp. 200-220.

Srivastava, M.P. (1957), "Review of Papers on Population Mapping", N.G.J.I., Vol. III, Pt. 2, pp. 89-92.

Stewart, C.T. (1960), "Migration as a Function of Population and Distance", American Sociological Review.

Stone, K.H. (1965), "The Development of a Focus for the Geography of Settlements", Economic Geography, 40, pp. 346-353.

Talwar, p.p. and Sawhney, N. (1984), "Population Policy in India and its Implications", in Population Policy in India, Edited by Ganhotra and Das, Blaokie and Son Publishers Pvt. Ltd., Bombay.

Trewartha, G.T. (1953), "A Case for Population Geography", Annals of the Association of American Geographers, Vol. 48, pp. 71-97.

United Nations (1961), "Methodology of Demographic Sample Surveys", ST/TAO/ Ser ct?4119, Series M. NC. 51, New York.

Verma, B.L. (1979), "Demographic Imbalances in Bundelkhand Region", N.G.J.I., Vol. XXV, Pt. 3, pp. 263-268.

Verma, S.D. (1956), "Density and Pattern of Population in the Punjab", N.G.J.I., Vol.

II, Pt. 4, pp. 193-202.

Zelinsky, W. (1962), " A Bibliographic Guide to Population Geography", Research Paper No. 80, University of Chicago.

Zelinsky, W. (1962), "Changes in the Geographical Patterns of Rural Population in the United States 1700-1960",. Geopraphical Review, Vol. 52, pp. 492-525.

Thakur, B. and Thakur, R. (1986), Statistical Techniques of Population and Settlement Mapping, Geographical Review of India, Vol. 44, No. 1, Calcutta.

Misra, K.K. and Pal, KetRam (1989), Bundelkhand (Uttar Pradesh) ke Pramukh Samsayayen avam Badhti Jansankhaya, Paper Presented in the National Seminar, 22-23 December, Sovenier, Atarra P.G. College, Atarra.

Zlotnik, H. (1998), International Migration 1965-96; An Overview, Population and Development Review, Vol. 24, No. 3, pp. 429-468.

Brockerholff,M. , and Brennan, E. (1998), The Poverty of Cities in Developing Regions, Population and Development Review, Vol. 24, No.1, pp. 75-114.

Filmer, Deon, Pritchett Lant (1999), The Effect of Household Wealth on Educational Attainment: Evidence from 35 Countries, Population and Development Review, New York, Vol. 25, No.1.

Misra, K.K., Socio- Economic and Environmental Problems in Banda- Hamirpur Districts, U.P., Indian National Geographer, Lucknow, Vol.6, No. 182, pp. 83-89.

Misra, K.K. (1998), Chhetriya Vikas ki Samsayayen, Gramin Vikas Samiksha, Ank 23, Prasth 130-138.

Misra, K.K. (1998), Bal Shramiko ki Stithi Evam Unake Samadhan ki Disha, Gramin Vikas Samiksha, Ank 24, Prasth 130-138.

Misra, K.K. (1997), Level of Literacy Among Dalit Population: A Case study of Atarra Tahsil, U.P., Geographical Review of India, Calcutta, Vol. 59, No.4, pp. 142-150.

Roy, Phanibhusan 1979, Methods of Describing Growth of Population, Geographical Review of India, Vol. 41, p.258.

Das, K.K. L. 1976, Population and Agricultural land use of Central Mithila, Bihar, Indian Geographical Studies, Bulletin No. 3,p.19.

Roy, Phanibhusan,1979 Methods of Describing Growth of Population, Geographical Review of India, vol. 41.

Thesis/Government Publications/Reports

Ghosh, Santwana (1973), "Population of Bihar: A Geographical Study", Unpublished Ph.D. Thesis, B.H.U.,Varanasi.

Gupta, R.P. (1982), "Population Geography of Rajasthan", Unpublished Ph.D. Thesis, B.H.U.,Varanasi.

Hanuman, Prasad (1986), "Azamgarh District : A Study in Population Geography", Unpublished Ph.D. Thesis. B.H.U.,Varanasi.

Mishra, D.K. (1987), "Population of Jaunpur District (U.P.): A Geographical Analysis " (Hindi), Unpublished Ph. D. Thesis, B.H.U., Varanasi.

Om Prakash (1973), "Population of Geography, Uttar Pradesh", Unpublished Ph.D. Thesis, B.H.U.,Varanasi.

Singh, J. (1974), "Population and Settlement in Baghelkhand", Unpublished Ph.D. Thesis, B.H.U.,Varanasi.

Josi, E.B., 1965, District Gazetteer, Jhansi, Lucknow.

Kabir, H., (ed.),1965, Gazetteer of India, Vol. I, New Delhi.

General Population Tables, Census of India, 1995 The Menasor of Publications, New Delhi.

United Nations- Report of the Asian Population Conference and Selected Papers (Held at New Delhi, India, 10-20 Dec., 1963) U.N. 1964.